



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 29, 2010/आश्विन 7, 1932

No. 247]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 29, 2010/ASVINA 7, 1932

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद के अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2010

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. 1-सौख(5)/61/2010.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (5ख) के अनुसरण में, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् के 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संपरीक्षित लेखाओं और रिपोर्ट की एक प्रति जनसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित की जाती है।

61वीं वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् (जिसे इसमें इसके पश्चात् "परिषद्" कहा गया है) को 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष की 61वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

प्रारंभ में परिषद्, उस सम्मान के लिए सदस्यों और छात्रों की सराहना करती है, जिसके साथ आज के समाज में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की वृत्ति को देखा जा रहा है, जिन्होंने उत्कृष्टता, स्वतंत्रता और अखंडता के द्वारा इस मशाल को जलाए रखा।

इस रिपोर्ट के माध्यम से, परिषद् और इसकी विभिन्न समितियों की वर्ष 2009-2010 की महत्वपूर्ण गतिविधियों और साथ ही भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के वर्ष 2009-2010 के लेखाओं की विशिष्टियों को उपदर्शित करने के साथ-साथ, परिषद् द्वारा इस अवसर पर इस रिपोर्ट में, इस अवधि के दौरान और जुलाई, 2010 के प्रथम सप्ताह तक, सदस्यों और छात्रों के संबंध में की गई प्रमुख पहलों, महत्वपूर्ण घटनाओं, सांख्यिकीय रूप-रेखाओं, आयोजित की गई संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के व्यौरों को भी समाविष्ट किया गया है। 1 जुलाई, 2010 को आईसीएआई द्वारा उसकी विद्यमानता के 62वें वर्ष में प्रवेश, राष्ट्र और अन्य पणधारियों की सेवा में छह दशकों लंबी और ऐतिहासिक यात्रा में एक अन्य मील के पत्थर को उपदर्शित करता है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, आईसीएआई ने ऐसी विभिन्न पहलों/कार्यक्रमों को प्रारंभ करने के लिए अथक प्रयास किया है, जिससे वृत्ति के गौरव में चार चांद लगे हैं और आईसीएआई उत्कृष्टता और अखंडता की उसी भावना के साथ राष्ट्र और अन्य पणधारियों को सेवा प्रदान करता रहेगा, जो पिछले कुछ दशकों से इस वृत्ति के मार्गदर्शक सिद्धांत रहे हैं।

भावना के साथ राष्ट्र और अन्य पणधर्मियों को सेवा प्रदान करता रहेगा, जो पिछले कुछ दशकों से इस वृत्ति के मार्गदर्शक सिद्धांत रहे हैं।

संसद् के एक अधिनियम द्वारा 1 जुलाई, 1949 को आईसीएआई की स्थापना से, लेखांकन वृत्ति में सदस्यता और छात्र आधार के निबंधनों में अद्वितीय विकास हुआ है। संस्थान, जिसे केवल 1,700 सदस्यों के साथ स्थापित किया गया था, आज विकास के ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जहां इसके सदस्यों की संख्या 1,64,000 और छात्रों की संख्या 8,90,000 को पार कर चुकी है। इस महान विकास यात्रा के दौरान, भारत में लेखांकन वृत्ति ने पुनःसंरचना, समुन्नति, मूल्य परिवर्धनों, नाना रूपकरण और वैश्विक एकीकरण के महत्वपूर्ण प्रक्रमों को पार किया है। अनेक वर्षों से, संस्थान ने वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता और अखंडता के अभिन्नक के रूप में और सर्वोत्तम लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों को तैयार करने के अपने मूल मिशन में साक्ष्य प्रगति की है, क्योंकि यह सदैव परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों से स्वयं को संतुलन रूप में अनुकूल बनाने की आवश्यकता के साथ स्वयं को परिवर्तित करता रहा है। आज भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट ने विश्व-प्रतिष्ठित के लेखा संबंधी मामलों में लगे एक वृत्तिक मात्र से स्वयं को एक सर्वांगीण और पूर्ण कारबार समाधान प्रदाता के रूप में संघर्षित कर लिया है। भारत में लेखांकन वृत्ति के अगुआ के रूप में आईसीएआई ने सदैव अपना ध्यान अपने सदस्यों की स्वीकार्यता, गरिमा और उनकी प्राणछवि को सुनिश्चित करने पर केन्द्रित किया है, जिससे कि उनके द्वारा समाज को दी जा रही उनकी सेवाओं की गुणवत्ता वैश्विक मानकों के अनुकूल हो।

हमारे देश की आर्थिक परिस्थितियों में हुए तीव्र परिवर्धनों, जो मुख्यतः उस वैश्विक मंदी के कारण थे, जो कई वर्षों की मेहनत के उपरान्त प्राप्त की गई वित्तीय आत्मनिर्भरता के आधार को नष्ट करने पर आमादा थी, ने एक बड़ी चुनौती और साथ ही इस महान वृत्ति के लिए एक सुअवसर भी प्रदान किया था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए आईसीएआई पूर्ण राष्ट्र की वित्तीय अवसंरचना के पुनर्निर्माण में लेखांकन वृत्ति की विशिष्ट तकनीकों को एकमात्र समाधान के रूप में प्रस्तुत करने के लिए आगे आया था। विश्व के विभिन्न एकाउंटेंसी संस्थानों के साथ एमओयू/एमआर के माध्यम से भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंसी वृत्ति के वैश्विकरण ने इस वृत्ति के सदस्यों के लिए वृत्तिक अवसरों का एक नया पिढा खोल दिया है और साथ ही संबद्ध देशों के साथ आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ किया है। पूर्ण चार्टर्ड एकाउंटेंसी पाठ्यधर्या की पुनःसंरचना करने के लिए नई-नई पहलें की गई हैं, जिससे कि इसे आज के क्रियाशील छात्र समुदाय के बीच अधिक आकर्षक और लोकप्रिय बनाया जा सके ताकि वे चार्टर्ड एकाउंटेंसी पाठ्यक्रम को शिक्षा की एक मुख्य धारा के रूप में स्वीकार कर सकें।

इस समय जब संस्थान अपनी विद्यमानता के 62वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, यह गर्व की बात है कि संस्थान को पूरे विश्व में एक प्रमुख लेखांकन निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त है। अपनी विद्यमानता के 62वें वर्ष में, हमारी आगे की यात्रा में यह उल्लेख करना अत्यंत संतोषप्रद और साथ ही उत्साहजनक है कि हमारे राष्ट्र के नेताओं ने राष्ट्रनिर्माण के प्रति आईसीएआई की पहलों और योगदानों को सदैव मान्यता दी है।

इस समय विश्व के हर कोने से भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट की सेवाओं की मांग प्राप्त हो रही है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने सदस्यों को अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए संस्थान ने विश्व के कुछ विख्यात एकाउंटेंसी संस्थानों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं और साथ ही विश्व भर में कुछ और देशों में संस्थान के पैटर प्रारंभ किए हैं।

संस्थान ने विश्व भर में हो रही प्रौद्योगिकी संबंधी उन्नतियों से कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए अनेक सक्रिय कदम उठाए हैं, जिनके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में की गई पहलें भी हैं, जिनके द्वारा सीपीटी की ऑनलाइन परीक्षा का संचालन और वेब-कास्ट/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संगोष्ठियों/कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

परिषद्, वृत्ति की छवि को, जिसे पणधर्मियों और साधारण जनता, दोनों द्वारा अत्यधिक गरिमापूर्ण माना जाता है, बनाए रखने और उसे और अधिक ओजस्वी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इस उद्देश्य के लिए, आईसीएआई इस समय मूल अधिनियम, अर्थात् चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 में आवश्यक संशोधन लाने के लिए कार्यरत है, जिससे कि वृत्ति के किन्हीं दुष्ट सदस्यों द्वारा वृत्तिक कदाचार के मामलों पर जनता की भावनाओं के अनुकूल कार्यवाही करने के लिए कठोर और त्वरित तंत्र उपलब्ध कराया जा सके। यह कदम एक सुदृढ़ और कड़ी

वृत्ति को, उसमें जांच और संतुलन के उसके स्वनिर्मित तंत्र के साथ सुदृढ़ता से बनाए रखने में कारगर सिद्ध होगा, जो राष्ट्र की आर्थिक संपदा और वित्तीय स्वास्थ्य के संरक्षण में और पणधारियों तथा विशिष्ट रूप से विनियामकों और साधारण जनता की दृष्टि में गरिमापूर्ण बनाए रखने में मदद करेगा।

अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानकों के साथ अभिसारण की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आईसीएआई विद्यमान सैंकड़ों लेखांकन मानकों का पुनःलेखन करने और विश्व भर के विभिन्न लेखांकन निकायों में प्रचलित सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों को उनमें समाविष्ट करने के लिए निरंतर कार्यरत है जिससे कि आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों, संपरीक्षा और आश्वासन मानकों को विश्व में विद्यमान सर्वोत्तम मानकों के समतुल्य बनाया जा सके।

परिषद् का यह दृढ़ विश्वास है कि हाल ही की वैश्विक मंदी की अवधि के दौरान भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंटों द्वारा प्रदर्शित ज्ञान और कौशल ने एक बार फिर से विश्वभर में होने वाले आर्थिक संकटों से जूझने में भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंसी वृत्ति की अनुकूलता पर पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। भारतीय लेखांकन मानकों के, जो विश्व भर में प्रचलित सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों को समाविष्ट करते हैं, विकास और अंगीकरण के माध्यम से आईसीएआई आज विश्व भर के विभिन्न लेखांकन निकायों के बीच अपना सिर ऊंचा करके खड़ा है।

1. परिषद्

32 निर्वाचित सदस्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित 8 सदस्यों वाली बीसवीं परिषद् का गठन 5 फरवरी, 2007 से तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। वर्ष 2008-2009 और वर्ष 2009-2010 के लिए परिषद् की संरचना पृथक-पृथक रूप से दर्शित की गई है। 21वीं परिषद् के लिए निर्वाचन दिसम्बर, 2009 में कराए गए थे। विधि के न्यायालय में फाइल की गई कुछ निर्वाचन याचिकाओं संबंधी मुकदमों को सफलतापूर्वक लड़ने के पश्चात् लगभग एक सप्ताह की देरी से 12 फरवरी, 2010 को नई परिषद् का गठन किया गया था।

2. परिषद् की समितियां

परिषद् ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 17 के निबंधनानुसार वृत्ति संबंधी विषयों के बारे में तीन स्थायी और विभिन्न अस्थायी समितियों का गठन 12 फरवरी, 2010 को किया। परिषद् ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की क्रमशः धारा 21क और धारा 21ख के उपबंधों के अनुसरण में एक अनुशासन बोर्ड और एक अनुशासन समिति का भी गठन किया है। इसके अतिरिक्त, तत्कालीन अनुशासन तंत्र के अंतर्गत आनेवाले अनुशासन संबंधी मामलों पर कार्यवाही करने के लिए एक अनुशासन समिति, जो एक स्थायी समिति है, उक्त अधिनियम की धारा 21घ के अधीन गठित की गई थी। वर्ष 2010-2011 के लिए विभिन्न अस्थायी समितियों का गठन करते समय, वर्ष 2009-2010 के लिए गठित कुछ समितियों को संयोजित किया गया था और बेहतर कार्यकरण के लिए उन्हें पुनःगठित किया गया था। 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, परिषद् की विभिन्न समितियों की 194 बैठकें आयोजित की गईं, जबकि 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 214 बैठकें आयोजित की गई थीं।

3. संपरीक्षक

सीए प्रमोद जैन, एफसीए और सीए पुष्पेन्द्र सुराना, एफसीए वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए आईसीएआई के संयुक्त संपरीक्षक थे। परिषद् उनकी सेवाओं की प्रशंसा करती है।

4. स्थायी समितियां

4.1 कार्यपालक - समिति

यह समिति सभी विनियामक कृत्यों, उदाहरणार्थ छात्रों/सदस्यों/फर्मों से संबंधित विभिन्न रजिस्टर रखने, सदस्यों के प्रवेश, हटाए जाने और उनके पुनःस्थापन के कार्य की देख-रेख करती है, जिसमें व्यवसाय प्रमाण-पत्र को जारी करने समेत सदस्यों से संबंधित विषयों पर, छात्रों से संबंधित सब विषयों पर जिनमें उन्हें अनुज्ञा देना, जहां अपेक्षित हो, छात्रों/सदस्यों/फर्मों की ओर से किए गए विलम्ब की माफी भी शामिल है, शाखाओं से संबद्ध विषयों, जिनमें नई शाखाएं खोलना, नए चैप्टर खोलना और विदेशों में कार्यालय खोलना तथा कर्मचारियों से संबंधित विषयों

आदि पर भी विचार करती है। समिति के कृत्यों में देश भर में सभी स्तरों पर अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं का विकास करना, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 और तदधीन बनाए गए विनियमों/नियमों में संशोधनों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना और संस्थान की नीति के परिधि-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी अन्य मामले के संबंध में प्रस्ताव रखना सम्मिलित हैं।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण विनिश्चय/सिफारिशें निम्नलिखित विषयों से संबंधित हैं :

- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स कल्याण निधि में आजीवन सदस्यों के अभिदायी व्यक्तियों की संख्या में अभिवृद्धि करने के लिए उपाय।
- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स छात्र कल्याण निधि के संग्रह में वृद्धि करना।
- छात्रों को शाखा स्तर पर अध्ययन सामग्री जारी करना।
- छात्रों के फायदे के लिए तथा संबंधित अनुदानों में वृद्धि करने के प्रयोजनों के लिए शाखाओं को अधिकाधिक शिक्षण कार्यक्रम-संगोष्ठियाँ, वक्तृता/विज प्रतियोगिता और अन्य क्रियाकलाप।
- भर्तृहार विश्वविद्यालय के साथ एमओयू के निबंधनानुसार पीएचडी कार्यक्रम करने वाले सदस्यों द्वारा संदाय की जाने वाली फीस निर्धारित करना।
- विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त संगोष्ठियों के लिए अनुदान में वृद्धि।
- शाखाओं में अतिरिक्त आईटीटी केन्द्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता।
- सीपीई चैप्टरों के स्तर पर आईटीटी केन्द्रों की स्थापना।
- अनुकूलन कार्यक्रमों के लिए विकलांग/शारीरिक रूप से निःशक्त छात्रों को फीस में छूट और अन्य रियायतें।
- उद्योग में राष्ट्रीय युवा सीए पुरस्कार के लिए प्रस्ताव।
- भावनगर, गांधीधाम, लातूर और वापी में डब्ल्यूआईआरसी की, तिरुमति में एसआईआरसी की और पाली, रतलाम और श्रीगंगानगर में सीआईआरसी की शाखाओं की स्थापना।
- विदेश में आर्टिकल्ड सहायकों के प्रशिक्षण के लिए दिशानिर्देश।
- अस्थाई समितियों/बोर्डों की कार्यसूची/कार्यवृत्त को वेबसाइट पर प्रदर्शित करना।
- प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं के पत्र-शीर्षों और साथ ही उनके द्वारा प्रकाशित न्यूजलेटर में एकसमानता।
- निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं के कृत्यों के संबंध में केन्द्रीय परिषद के निर्देशों में उपांतरण।
 - परिषद् और प्रादेशिक परिषदों के निर्वाचनों को लागू निर्वाचन आचार-संहिता का शाखाओं की प्रबंध समितियों के निर्वाचनों पर विस्तारण।
 - शाखाओं की प्रबंध समितियों के निर्वाचनों में एकल अंतरणीय प्रणाली के माध्यम से मतदान।
 - अध्यक्ष का पद धारण करने के पश्चात् प्रबंध समिति में पुनःनिर्वाचन के लिए शर्तें अधिरोपित करना।
 - परिषद्/प्रादेशिक परिषद् के सदस्यों का शाखाओं की प्रबंध समिति में केवल पदेन सदस्य के रूप में नामनिर्देशन।
- सर्वोत्तम शाखा के चयन के लिए मानदंड में पुनरीक्षण।

- शाखाओं के गठन के लिए सन्निधियों में पुनरीक्षण ।
- पश्चिमी क्षेत्र में पिंपरी चिंचवाड़ और दक्षिणी क्षेत्र में नल्लौर में छात्र सभा का गठन ।
- कतिपय चैप्टरों के नाम में परिवर्तन और विदेश में नए चैप्टरों की स्थापना ।
- ईआईआरसी की दुर्गापुर शाखा की अधिकारिता का विस्तार ।
- सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय का सृजन ।
- यूके और आस्ट्रेलिया में, संबंधित निकायों के साथ हस्ताक्षित परस्पर-समझ के ज्ञापनों के अधीन विनिर्दिष्ट आईसीएआई परीक्षाओं में रजिस्ट्रीकरण के लिए वृत्तिक निकायों के सदस्यों द्वारा संदेय फीस का अवधारण ।
- अच्छी छवि के प्रमाणपत्र के प्रारूप का सरलीकरण ।
- सर्टिफायड जनरल एकाउंटेंट्स, कनाडा, इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इन न्यूजीलैंड, इंस्टिट्यूट ऑफ सर्टिफिकेट पब्लिक एकाउंटेंट्स इन आयरलैंड, इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ नेपाल और मलेशियन इंस्टिट्यूट ऑफ एकाउंटेंट्स के साथ परस्पर मान्यता करारों/परस्पर-समझ ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की पहल ।
- आईएसए अर्हित सदस्यों को आईटी केन्द्रों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने के लिए आमंत्रण ।
- शाखाओं की प्रबंध समिति के सदस्यों के लिए अनुकूलन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रादेशिक परिषदों के अनुदान में वृद्धि ।
- तकनीकी पुनर्विलोककों और वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूहों के सदस्यों [केन्द्रीय/प्रादेशिक परिषदों और शाखा प्रबंध समिति के सदस्यों से भिन्न] को मानदेय में वृद्धि ।
- शारीरिक निःशक्तता के आधार पर संस्थान के अर्हतापत्र पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सदस्यों को बढी फीस में छूट ।
- प्रकाशनों को तैयार/विकसित करने में व्यष्टियों/संगठनों द्वारा दिए गए योगदान/की गई सेवाओं की अभिस्वीकृति ।
- सदस्यता पुनःप्रदान करने और साथ ही सदस्यता में प्रवेश के लिए विलंब से दिए गए आवेदनों को स्वीकार करने के संबंध में कतिपय निर्बंधन अधिरोपित करने के लिए प्रस्ताव ।
- संस्थान के प्रकाशनों को पुनः प्रकाशित और वेबसाइट पर रखने के लिए अनुमति हेतु नीति और प्रक्रिया का पुनर्विलोकन ।
- नई गठित अस्थायी समितियों के निर्देश-निर्बंधनों को अंतिम रूप प्रदान करना ।

4.2 वित्त समिति

वित्त समिति-परिषद् की स्थायी समितियों में से एक है - जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 में किए गए संशोधनों के कारण अस्तित्व में आई । उक्त समिति, अन्य बातों के साथ, सत्य और सही लेखाओं को रखे जाने, वार्षिक बजट तैयार करने, निधियों के निवेश, निधियों से राजस्व और पूंजी दोनों प्रकार के व्ययों के लिए आहरण करने से संबंधित और अनुषंगी गतिविधियों का नियंत्रण, कार्यान्वयन और अधीक्षण करती है ।

4.3 परीक्षा समिति

मई, 2009 में होने वाले लोक सभा और कुछ राज्यों में विधान सभाओं के निर्वाचनों के कारण मई, 2009 में होने वाली चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स परीक्षाओं को जून, 2009 मास तक आस्थगित किया गया था । तदनुसार, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वृत्तिक शिक्षा-II (पीई-II), वृत्तिक सक्षमता परीक्षा (पीसीई) और फाइनल (पुराना और नया पाठ्यक्रम)

परीक्षाओं को 1 से 15 जून, 2009 के दौरान विदेशों के अतिरिक्त देश भर में क्रमशः 146, 202 और 185 केन्द्रों पर आयोजित किया गया था। जून, 2009 में आयोजित पीई-2, पीसीई और फाइनल (पुराना और नया पाठ्यक्रम) परीक्षाएं देने वाले छात्रों की संख्या क्रमशः 18507, 59329 और 35350 थी।

वर्ष के दौरान आगामी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वृत्तिक शिक्षा-II (पीई-II), वृत्तिक सक्षमता परीक्षा (पीसीई), एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा (आईपीसीई) और फाइनल (पुराना और नया पाठ्यक्रम) परीक्षाओं को 5 से 19 नवम्बर, 2009 के दौरान विदेशों के अतिरिक्त देश भर में क्रमशः 173, 245, 178 और 198 केन्द्रों पर आयोजित किया गया था। नवम्बर, 2009 में आयोजित पीई-2, पीसीई, आईपीसीई और फाइनल (पुराना और नया पाठ्यक्रम) परीक्षाएं देने वाले छात्रों की संख्या क्रमशः 12809, 67474, 25723 और 38636 थी।

नवम्बर, 2009 की सीए परीक्षाओं के लिए भावनगर, भुज, नांदेड़, पनवेल, सतारा, संबलपुर और तिनसुकिया में नए परीक्षा केन्द्र खोले गए थे।

इसके अतिरिक्त, सामान्य प्रवीणता परीक्षा - पेपर-पेंसिल पद्धति और ऑन लाइन का सफलतापूर्वक संचालन किया गया था। पेपर-पेंसिल पद्धति सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) का आयोजन 28 जून, 2009 को देशभर में और विदेशों में 119 शहरों में अवस्थित 252 परीक्षा केन्द्रों में किया गया था और उक्त परीक्षा में 1,12,788 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। एक अन्य पेपर-पेंसिल पद्धति सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) का आयोजन 13 दिसम्बर, 2009 को देशभर में और विदेशों में 123 शहरों में अवस्थित 269 परीक्षा केन्द्रों में किया गया था और उक्त परीक्षा में 1,17,001 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। 13 दिसम्बर, 2009 को हुई सीपीटी परीक्षा के लिए 8 नए परीक्षा केन्द्र स्थापित किए गए थे, अर्थात् भावनगर, भुज, नांदेड़, पनवेल, सतारा, संबलपुर और तिनसुकिया में। ऑन लाइन सामान्य प्रवीणता परीक्षा (ऑन लाइन सीपीटी) का आयोजन नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार संस्थान के विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्रों में अवस्थित परीक्षा केन्द्रों में किया गया था :

क्रम सं.	ऑन लाइन सीपीटी की तारीख	ऐसे शहरों की संख्या और वे शहर जिनमें परीक्षा केन्द्र स्थापित किए गए थे	भाग लेने वाले अभ्यर्थी
1	25 अप्रैल, 2009	15- अहमदाबाद, बंगलोर, चंडीगढ़, चैन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, गुंटूर, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, पूणे, सूरत और विशाखापत्तनम	183
2	23 मई, 2009	19- अहमदाबाद, बंगलोर, चंडीगढ़, चैन्नई, दिल्ली, गुंटूर, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पूणे, रायपुर, सूरत, उदयपुर और विशाखापत्तनम	271
3	22-23 अगस्त, 2009	20- अहमदाबाद, बंगलोर, चैन्नई, नई दिल्ली, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद, पूणे, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, एर्नाकुलम, गुंटूर, इंदौर, लखनऊ, सूरत, त्रिवेंद्रम, उदयपुर और विशाखापत्तनम	818
4	26-27 सितम्बर, 2009	18-अहमदाबाद, बंगलोर, चैन्नई, नई दिल्ली, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद, पूणे, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, गुंटूर, इंदौर, लखनऊ, सूरत, उदयपुर और विशाखापत्तनम	717
5	24-25 अक्टूबर, 2009	20-अहमदाबाद, बंगलोर, चैन्नई, नई दिल्ली, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद, पूणे, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, एर्नाकुलम, गुंटूर, इंदौर, लखनऊ, सूरत, तिरुवनंतपुरम, उदयपुर और विशाखापत्तनम	787
6	21-22 नवम्बर, 2009	20-अहमदाबाद, बंगलोर, चैन्नई, नई दिल्ली, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद, पूणे, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, एर्नाकुलम,	1186

	मुंबई, इंदौर, लखनऊ, दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, उदयपुर और विस्तारप्रदान	
--	--	--

उपरोक्त छात्र परीक्षाओं के अलावा, अर्द्धसत्रिक परीक्षाओं का आयोजन भी किया गया था। इसमें 20 जून, 2009 को देशभर में 34 नगरों में 36 परीक्षा केंद्रों पर सूचना पद्धति संपरीक्षा - निर्धारण परीक्षा [आईएसए-एसी] का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। एक अन्य आईएसए-एसी का आयोजन 19 दिसम्बर, 2009 को देशभर में 40 नगरों में 42 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रबंध लेखांकन पाठ्यक्रम [(एएसबी)(भाग-I)], कर प्रबंध पाठ्यक्रम [(टीएमसी)(भाग-I)], बीमा जोखिम प्रबंध (आईआरएम) और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों और विश्व व्यापार संगठन [आईटीएस और डब्ल्यूटीओ] की परीक्षाओं का सफल आयोजन नवंबर, 2009 में किया गया था।

वर्ष के दौरान छात्रों की सुविधा के लिए जिन सुविधाओं का उपलब्ध कराया जाना जारी रखा गया उनमें: ओएमआर में परीक्षा आवेदन प्रत्यक्ष; संस्थान के सभी प्रादेशिक कार्यालयों और प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं और दिल्ली, कोलकाता तथा मुंबई के महानगरों में विभिन्न अवस्थानों पर परीक्षा आवेदन प्रत्यक्षों की उपलब्धता; अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश पत्रों की डाउन लोडिंग और डाउन लोडिंग की सुविधा के साथ वेबसाइट से परीक्षा परिणाम और साथ ही अंकों की उपलब्धता सम्मिलित हैं।

4.4 अनुशासन समिति

यह समिति संस्थान द्वारा प्रस्तुत वृत्तिक अर्हता की प्राप्ति और स्तर बनाए रखने में परिषद् की सहायता करती है। ऐसे सदस्यों के, जिनके मामले परिषद् द्वारा तत्कालीन अनुशासन तंत्र के अधीन समिति को 1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 के दौरान प्रथम दृष्टया राय के लिए विनिर्दिष्ट किए गए थे, विरुद्ध अनुशासनात्मक जांच करने के अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन में समिति ने 14 अवसरों पर अपनी बैठकों की थीं जो कुल मिलाकर 18 दिन चली थी और ये बैठकें देश के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले स्थानों पर की गई थी। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, समिति ने 52 मामलों में जांच की थी, जिनमें उसे पूर्व वर्षों में निर्दिष्ट मामले भी सम्मिलित थे।

इसके अतिरिक्त, नए अनुशासन तंत्र के अधीन अनुशासन बोर्ड द्वारा (धारा 21क के अधीन) क्रमशः शिकायत और “सूचना” के 138 और 165 मामलों में निदेशक (अनुशासन) की प्रथम दृष्टया राय पर विचार किया गया था। इसके अलावा अनुशासन बोर्ड द्वारा (धारा 21ख के अधीन) क्रमशः शिकायत और “सूचना” के 64 और 24 मामलों में निदेशक (अनुशासन) की प्रथम दृष्टया राय पर विचार किया गया था।

5. तकनीकी और वृत्तिक विकास

5.1 लेखांकन मानक बोर्ड

संसद् के एक अधिनियम के अधीन गठित भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई), जो देश का एक प्रमुख लेखांकन निकाय है, देश में एक उत्तम, विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाली लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। भारत में विद्यमान विविध लेखांकन विधियों और व्यवहारों में संगतता लाने के लिए आईसीएआई ने लेखांकन मानकों को तैयार करने के लिए वर्ष 1977 में लेखांकन मानक बोर्ड (एसबी) का गठन किया था। इसके गठन के प्रारंभ से ही, एसबी नए लेखांकन मानकों को तैयार करके और साथ ही समय-समय पर विद्यमान लेखांकन मानकों को पुनरीक्षित करके इस विषय में निरंतर कार्य कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय मानकों को, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएसबी) द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों (आईएस) और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के समरूप बनाना है। एसबी लेखांकन मानकों के एक समान उपयोग और उनके कार्यान्वयन से संबंधित विषयों पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए समय-समय पर विभिन्न उद्घोषणाएं भी जारी करता है।

आईसीएआई द्वारा तैयार किए गए लेखांकन मानकों को, कंपनी अधिनियम, 1956 में धारा 211(3क), (3ख) और (3ग) अंतःस्थापित करके अक्टूबर, 1998 में विधिक मान्यता प्रदान की गई है। अधिनियम की धारा

211(3ग) के अनुसार आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा लेखांकन मानक संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एन.ए.सी.ए.एस.) के परामर्श से विहित किया जा सकेगा। इस धारा के पंखुके के अनुसार, सरकार द्वारा लेखांकन मानकों की अधिसूचना जारी किए जाने तक, आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों को कंपनियों द्वारा अपनाया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2006 में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत के राजपत्र में अपनी तारीख 7 दिसम्बर, 2002 की अधिसूचना द्वारा कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 के अधीन लेखांकन मानक 1 से 7 और 9 से 29 को विहित किया था। ये मानक, इन लेखांकन मानकों के प्रकाशन की तारीख को (अर्थात् 7 दिसम्बर, 2002) या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली लेखांकन अवधियों के संबंध में प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त, 7 मार्च, 2008 की अधिसूचना द्वारा कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2008 के अधीन लेखांकन मानक (एस 15) के सीमित पुनरीक्षण को अधिसूचित किया गया था। केन्द्रीय सरकार द्वारा एनएसीएएस के परामर्श से 27 मार्च, 2008 की अधिसूचना द्वारा कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2008 के अधीन लेखांकन मानक (एस 11) के संशोधन को अधिसूचित किया था।

वैश्वीकरण और उदारीकरण के साथ, विश्व अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक बन गई हैं। विदेशी पूंजी बाजारों तक पहुंच की वांछ करने वाली फर्मों को प्रायः लेखाओं के दो सेट तैयार करने होते हैं; एक घरेलू अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए और दूसरा ऐसे विदेशी बाजार के अनुसार, जहां से पूंजी प्राप्त की जानी है। बहुमानक पूंजी आबंटन की मात्रा और दक्षता पर दबाव डालते हैं क्योंकि निवेशक विभिन्न अधिकारिताओं में कंपनियों की वित्तीय जानकारी की सुगमता से तुलना नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार, वैश्विक रूप से स्वीकार्य और उच्च गुणवत्ता वाले लेखांकन मानकों के एकल सेट की आवश्यकता प्रायः महसूस की जाती रही है। आईएसबी द्वारा जारी किए जा रहे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों को वैश्विक वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के रूप में अधिकाधिक मान्यता प्राप्त हो रही है। अनेक देशों ने विभिन्न अस्तित्वों के वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए या तो आईएफआरएस को अपना लिया है अथवा अपनाए जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। यद्यपि आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक मुख्यतः आईएसबी/आईएफआरएस पर आधारित हैं, फिर भी कतिपय मामलों में देश में विद्यमान आर्थिक परिस्थितियों के अलावा विधिक और विनियामक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लेखांकन मानकों में आईएसबी/आईएफआरएस से विचलन किया गया है।

हाल ही के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों से अभिसरण ने पूरे विश्व में जोर पकड़ा है। वर्तमान में 117 से अधिक देश आईएफआरएस के उपयोग की अपेक्षा करते हैं अथवा अनुमति देते हैं या उनसे अभिसरण की नीति को अपना रहे हैं। कतिपय अन्य देशों ने भी आईएफआरएस अपनाए के अपने आशयों की घोषणाएं की हैं, उदाहरणार्थ ब्राजील और कनाडा क्रमशः 2010 और 2011 से इन्हें अपनाएंगे। यूएसए का वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड (एफएसबी) और आईएसबी, यूएस जीएपी और आईएफआरएस के अभिसरण के लिए कार्य कर रहे हैं। यूएसए के प्रतिभूति और विनियम आयोग (एसईसीए) ने यह विनिश्चय किया है कि यूएस जीएपी और आईएफआरएस के बीच किसी समाधानप्रद विवरण को प्रस्तुत करने की अपेक्षा किए बिना आईएफआरएस से संगत वित्तीय विवरण फाइल करने की अनुमति प्रदान की जाए। इस परिदृश्य में, भारत जो एक महत्वपूर्ण उभरती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था है, के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ने कंपनियों के कतिपय वर्ग के संबंध में 1 अप्रैल, 2011 से आईएफआरएस से अभिसरण का विनिश्चय किया है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने भी ऐसा करने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। यह अभिसरण, अन्य बातों के साथ, भारतीय अस्तित्वों को विदेश से निम्न लागत की पूंजी प्राप्त करने में सहायता करेगा। यह चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को भी, भारतीय वृत्तियों के लिए विदेशों में बढ़ते हुए अवसरों का लाभ प्रदान करेगा।

आईएफआरएस के साथ अभिसरण के संबंध में विचार करने के लिए और भारत को आईएफआरएस-संगत बनाने के लिए एसबी ने आईएफआरएस के साथ अभिसरण की पद्धति का पता लगाने और ऐसे अभिसरण की प्राप्ति के लिए एक योजना अधिकथित करने की आज्ञा वाले एक कार्य बल को वर्ष 2006 में गठित किया था। इस कार्य बल ने एक अवधारणा पत्र तैयार किया था, जिसे एसबी और आईसीएआई की परिषद् ने स्वीकार कर लिया था। इस अवधारणा पत्र की प्रमुख सिफारिश यह थी कि 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली लेखांकन अवधियों के लिए बड़े आकार की कंपनियों और लोक हित संगठनों जैसे कि सूचीबद्ध अस्तित्वों, बैंकों और बीमा अस्तित्वों आदि के आईएफआरएस के साथ अभिसरण की अनुमति प्रदान की जाए।

तथापि, परिवर्तित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अभिसरण के विनिश्चय के कार्यान्वयन में सामने आने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए उपयुक्त उपांतरणों के साथ इस योजना पर पुनः विचार किया जा रहा है।

आईएफआरएस के साथ अभिसरण के विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए, एएसबी ने वर्ष 2011 से आईएफआरएस को सुगमता से लागू करने के लिए विभिन्न कृत्य करने हेतु एक समूह का गठन किया था। इस समूह ने (क) एएसबी की कार्य योजना तैयार करने और आईएएसबी के साथ परस्पर संपर्क करने के लिए; (ख) सरकार और विनियामक प्राधिकारियों से बातचीत करने के लिए; (ग) उद्योग संघ से परस्पर संपर्क करने के लिए, और (घ) आईएफआरएस पर शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए आगे चार उपसमूहों का गठन किया था जिससे कि एकाउंटेंट अभिसरण के लिए तैयार हो सकें।

सरकार और विनियामक प्राधिकरणों से बातचीत के लिए उपसमूह का गठन इस उद्देश्य से किया गया था कि वह आईएफआरएस के साथ अभिसरण के कारण उदभूत होने वाली विरोधाभासी विधिक और विनियामक अपेक्षाओं की पहचान करे और जहाँ उचित हो, विभिन्न विधियों और विनियमों में परिवर्तन करने के लिए सुसंगत प्राधिकरणों से बातचीत करे। इस उपसमूह ने कंपनी अधिनियम, सेबी नियमों और विनियमों के लिए आईएफआरएस को अपनाए जाने से संबंधित मुद्दों और इसके अतिरिक्त बीमा अस्तित्वों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से संबंधित मुद्दों की पहचान करने के लिए एक कोर समूह का गठन किया था। इस संबंध में कंपनी अधिनियम में अपेक्षित परिवर्तनों की पहले ही पहचान कर ली गई है और उन्हें भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय को अग्रेषित किया गया है। यह आशा की जाती है कि सरकार शीघ्र ही अधिनियम को संशोधित करेगी। अन्य विधिबोधों, जैसे कि बैंककारी विधि विनियम, बीमा विधियाँ और नियमितताएं, सेबी नियमों तथा विनियमों में अपेक्षित परिवर्तनों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

उद्योग संघों के साथ परस्पर संपर्क करने के लिए उपसमूह का गठन इस उद्देश्य के साथ किया गया था कि वह आईएफआरएस के कार्यान्वयन के संबंध में उद्योग/विनिर्दिष्ट मत प्राप्त करने के पश्चात् आईएफआरएस अपनाए जाने के लिए उद्योग को तैयार करने में उनका सहयोग प्राप्त करे। इस संबंध में, इस समूह ने एएसबी के सहयोग से विभिन्न उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की हैं। सभी संघों ने आईएफआरएस के साथ अभिकरण का समर्थन किया है।

शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी उपसमूह का गठन इस उद्देश्य से किया गया था कि वह तैयार करने वालों, संपरीक्षकों और अन्य लेखांकन वृत्तिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकताओं पर विचार करें। इस संबंध में, मुंबई, दिल्ली, बंगलोर, पूणे, कोलकाता और हैदराबाद में आईएफआरएस संबंधी एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस पहल के निबंधनानुसार आईएफआरएस के साथ अभिसारित भारतीय लेखांकन मानकों पर श्रृंखला कार्यशालाओं का उद्घाटन 29 अप्रैल, 2010 को नई दिल्ली में श्री आर. बंधोपाध्याय, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया था, जिसके अधीन दो प्रकार की परीक्षण कार्यशालाओं, अर्थात् दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं और एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं का 58 अवस्थानों पर आयोजन करने की योजना बनाई गई है।

पूर्वोक्त के अलावा, 1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 की अवधि के दौरान विभिन्न अवस्थानों, अर्थात् दिल्ली (6), मुंबई (6), बंगलोर (3), पूणे (1), हैदराबाद (2), कोलकाता (2), चेन्नई (2), देहरादून (1), दिल्ली में पीएफसी (1), जयपुर (1), अहमदाबाद (1) में आईएफआरएस संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के कुल 26 बैचों का आयोजन किया गया था। उक्त अवधि के दौरान आईएफआरएस संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए चार बार परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें 620 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था जिनमें से 510 को उत्तीर्ण घोषित किया गया था।

आईसीएआई ने ऐसे भारतीय-समतुल्य मानकों को, जो आईएएसबी द्वारा जारी सभी आईएएस/आईएफआरएस के तत्समान हैं, अगस्त, 2010 के अंत तक अंतिम रूप दिए जाने का लक्ष्य रखा है। 31 मई, 2010 तक संस्थान के लेखांकन मानक बोर्ड ने आईएफआरएस के साथ अभिसारित सभी लेखांकन मानकों के उदभासन प्रारूप को, जनता की टिप्पणियों के लिए अपनी वेबसाइट पर रख दिया था। इस जटिल लक्ष्य को पूरा करने के लिए लेखांकन मानक बोर्ड ने फरवरी, 2010 के मध्य से 20 जून, 2010 तक 9 बैठकें की थीं, जिनमें बोर्ड द्वारा गठित विभिन्न अध्ययन समूहों से प्राप्त प्रारूपों पर विचार किया गया था और उदभासन प्रारूपों को अंतिम

रूप दिया गया था। इस अवधि के दौरान बोर्ड ने 31 उदभासन प्रारूपों को अंतिम रूप दिया था, जबकि शेष प्रारूपों को फरवरी, 2010 से पहले अंतिम रूप दे दिया गया था।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लेखांकन मानक बोर्ड के अन्य क्रिया कलापों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

5.1.1 अंतरराष्ट्रीय लेखांकन बोर्ड (आईएसबी) के क्रियाकलापों में सहयोग और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर प्रतिक्रिया करना

बोर्ड विभिन्न स्तरों पर आईएसबी के साथ परस्पर क्रियाएं करता है जैसे कि :

- विश्व मानक - निर्धारकों, राष्ट्रीय मानक - निर्धारकों और प्रादेशिक मानक - निर्धारकों की बैठकों में आईएसबी के साथ सक्रिय भागीदारी।
- बोर्ड ने आईएसबी द्वारा जारी विभिन्न उदभासन प्रारूपों/परिचर्चा पत्रों को परिचालित किया था और अपनी वेबसाइट पर भी रखा था और उनके संबंध में विभिन्न पणधारियों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं।
- आईएफआरएस के साथ अभिसरण लंबित रहने के दौरान और अधिक प्रभावपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बोर्ड, समय-समय पर ऐसे अध्ययन समूहों का गठन करता है जो आईएसबी द्वारा जारी परिचर्चा पत्रों या उदभासन प्रारूपों का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण के पश्चात् ये समूह भारत-विनिर्दिष्ट आशंकाओं को सूचीबद्ध करते हुए अपनी टिप्पणियां भेजते हैं जिनका एसबी द्वारा उन्हें आईएसबी को भेजे जाने से पूर्व पुनर्विलोकन किया जाता है।

5.1.2 विनियामक निकायों के साथ परस्पर क्रिया

प्रमुख लेखांकन निकाय होने के कारण, आईसीएआई, एसबी के माध्यम से विभिन्न लेखांकन विषयों पर अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए समय-समय पर विभिन्न विनियामक निकायों से परस्पर क्रिया करता है।

पूर्वाक्त के अतिरिक्त, विभिन्न लेखाकरण मुद्दों पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पदधारियों के साथ नियमित बैठकों की गई थी।

5.1.3 अन्य परियोजनाएं

निम्नलिखित आईएसबी उदभासन प्रारूपों/परामर्श पत्रों पर टिप्पणियों को आईएसबी को अग्रेषित किया गया था :

वित्तीय लिखतें : वर्गीकरण और मापमान संबंधी उदभासन प्रारूप।

सूचना के लिए अनुरोध ("आशयित हानि मॉडल") वित्तीय आस्तियों का हानिकरण : आशयित नकद प्रवाह दृष्टिकोण।

दायित्व मापमान में प्रत्यय जोखिम पर परामर्श पत्र।

राइटस इश्यूज के वर्गीकरण पर उदभासन प्रारूप।

लेखांकन मानक बोर्ड के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

5.1.4 परिषद् द्वारा अनुमोदित मानक

परिषद् द्वारा 36 मानक, जिनके अंतर्गत आईएस 1, वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण के तत्समान एस 1, आईएस 20, सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता का प्रकटन के तत्समान एस 12, आईएस 24, संबंधित पक्षकार प्रकटन के तत्समान एस 18, आईएफआरएस 15, विक्रय के लिए धारित गैर चालू आस्तियां और छोड़ दिए गए प्रचालन, के तत्समान एस 24, आईएस 39, वित्तीय लिखतें : वर्गीकरण और

मापमान के तत्समान एस 30, आईएस 26, सेवानिवृत्ति कल्याण योजनाओं द्वारा लेखांकन और रिपोर्टिंग के तत्समान एस 36 सम्मिलित हैं।

5.1.5 जारी किए गए उद्घाटन प्रारूप

आईएफआरएस 4, बीमा संविदाएं के तत्समान एस 39

आईएफआरएस 1, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का पहली बार अपनाया जाना, के तत्समान एस 41।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिकथित अभिसरण संबंधी कार्य योजना के अनुसार, लघु और मध्यम कंपनियों (एसएमसी) से अधिसूचित किए गए ऐसे लेखांकन मानकों को अपनाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जिन्हें आईएफआरएस के साथ अभिसारित किया गया है (यद्यपि वे स्वैच्छिक रूप से ऐसा करने का विकल्प ले सकते हैं), अपितु उनके द्वारा केवल उन्हीं अधिसूचित किए गए लेखांकन मानकों का अपनाया जाना आवश्यक है जिन्हें आईएफआरएस के साथ अभिसारित नहीं किया गया है।

5.2 स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन संबंधी समिति

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ने वर्ष 2005 में स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों संबंधी एक समिति का गठन किया था। इस समिति को इस प्रमुख उत्तरदायित्व के साथ स्थापित किया गया था कि वह ऐसे क्षेत्रों का सृजन करेगी और पता लगाएगी, जिनमें स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एसएलबी) विकसित किए जाने की आवश्यकता है, एसएलबी तैयार करेगी, एसएलबी को संभव सीमा तक अंतरराष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानक बोर्ड द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानकों के साथ एकीकृत करेगी, एसएलबी के संबंध में कार्यान्वयन मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगी, एसएलबी का पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण करेगी, लेखांकन की प्रोद्भव प्रणाली को अपनाने में स्थानीय निकायों की सहायता करेगी और पणधारियों के बीच वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनके प्रस्तुतीकरण के लिए एसएलबी का संवर्धन करेगी।

सीएसएलबी द्वारा तैयार किए गए एसएलबी को क्रमशः शहरी विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित यूएलबी और पीएनआई के लिए स्थानीय निकायों हेतु बजट और लेखांकन मानक संबंधी तकनीकी समिति को संबंधित राज्य सरकार द्वारा उसके कार्यान्वयन की सिफारिश करने के लिए अंग्रेषित किया जाता है।

इसके प्रारंभ से ही, समिति ने स्थानीय निकायों के लिए 4 लेखांकन मानक (एसएलबी) अर्थात् स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एसएलबी) 3, 'विनियम व्यवहारों से राजस्व' और स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एसएलबी) 4, 'उधार लेने संबंधी लागत', स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एसएलबी) 5, 'संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर', स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एसएलबी) 6, 'रिपोर्टिंग तालीख के पश्चात् भी', जारी किए हैं। समिति के अन्य प्रकाशनों में 'स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों का प्राक्कथन', 'स्थानीय निकायों के लिए प्रोद्भवन लेखांकन : निर्वाचित प्रतिनिधि और पणधारी' विषय पर अंग्रेजी और हिन्दी में पुस्तिका तथा 'भारत में स्थानीय निकायों में लेखांकन सुधार और चार्टर्ड एकाउंटेंटों की भूमिका' सम्मिलित हैं।

'स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों का प्राक्कथन', स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक संबंधी समिति के उद्देश्यों और प्रचालन प्रक्रियाओं को अधिकथित करता है तथा स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों के विस्तार क्षेत्र और प्राधिकार को स्पष्ट करता है।

'स्थानीय निकायों के लिए प्रोद्भव लेखांकन : निर्वाचित प्रतिनिधि और पणधारी' शीर्षक वाली पुस्तिका निर्वाचित प्रतिनिधियों और पणधारियों को स्थानीय निकायों के लिए प्रोद्भव लेखांकन के फायदों के संबंध में प्रस्तावना संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए है। यह लेखांकन की दो प्रणालियों : पारंपरिक नकद लेखांकन प्रणाली और आधुनिक प्रोद्भव लेखांकन प्रणाली की विशेष विशेषियों को और उस रीति को अधिकथित करता है, जिसमें वे स्थानीय निकायों की आय, व्यय, आस्तियों और दायित्वों को प्रभावित करते हैं। प्रोद्भव लेखांकन के

संबंध में कुछ आशंकाओं को भी स्पष्ट किया गया है, जिससे कि इस प्रणाली और उसके उपयोग के बारे में उपधारणात्मक जानकारी की कमी को कम किया जा सके। समिति ने इस पुस्तिका की निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए इस अवधि के दौरान इस पुस्तिका का हिन्दी पाठ भी निकाला है।

समिति ने इस अवधि के दौरान 'भारत में स्थानीय निकायों में लेखांकन सुधार और चार्टर्ड एकाउंटेंटों की भूमिका' विषय पर एक प्रास्थिति पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें भारत में स्थानीय निकायों में लेखांकन सुधारों को अंगीकार करने संबंधी प्रास्थिति समाविष्ट की गई है। यह प्रास्थिति पत्र उस भूमिका को भी स्पष्ट करता है, जो चार्टर्ड एकाउंटेंट स्थानीय निकायों में लेखांकन सुधारों के कार्यान्वयन में निभा सकते हैं।

उपरोक्त के अलावा, सीएसएलबी द्वारा अंतरराष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानकों के तत्समान स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एसएलबी) तैयार करने के लिए पिछले और पूर्ववर्ती के दौरान प्रारंभ की गई विभिन्न परियोजनाएं प्रगतिशील हैं।

आईसीएआई शासकीय लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड (जीएसएबी) का सदस्य है और उसे जीएसएबी द्वारा समय-समय पर गठित उसकी विभिन्न उप समितियों में भी प्रतिनिधित्व प्राप्त है। आईसीएआई के प्रतिनिधि जीएसएबी की बैठकों में भाग लेते हैं और बोर्ड के तकनीकी क्रियाकलापों में योगदान करते हैं। इस अवधि के दौरान, सीएसएलबी ने शासकीय लेखांकन संबंधी समिति (जिसे अब एक अन्य समिति में समाविष्ट कर दिया गया है और उसे वर्ष 2010-2011 के लिए गठित समिति अर्थात् लोक वित्त और शासकीय लेखांकन संबंधी समिति के रूप में पुनर्गठित किया गया है) के साथ संयुक्त रूप से जीएसएबी द्वारा विचार किए जाने के लिए 'संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर' संबंधी आईजीएफआरएस के जीएसएबी के उद्भासन प्रारूपों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की थीं।

इस अवधि के दौरान समिति द्वारा किए गए महत्वपूर्ण क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :

5.2.1 इस अवधि के दौरान जारी स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एसएलबी) :

स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एसएलबी) 5, 'संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर'।

स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एसएलबी) 6, 'रिपोर्टिंग तारीख के पश्चात् की घटनाएं'।

5.2.2 इस अवधि के दौरान जारी अन्य प्रकाशन :

- 'स्थानीय निकायों के लिए प्रोदभवन लेखांकन : निर्वाचित प्रतिनिधि और पणधारी' शीर्षक वाली पुस्तिका का हिन्दी अंक।
- 'भारत में स्थानीय निकायों में लेखांकन सुधार और चार्टर्ड एकाउंटेंटों की भूमिका' विषय पर एक प्रास्थिति पत्र।

5.2.3 ऐसे प्रस्तावित एसएलबी का प्रारूप, जिन्हें समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है और जिन्हें टीका-टिप्पणियों के लिए संस्थान की परिषद् के सदस्यों और विनिर्दिष्ट बाहरी निकायों के बीच परिचालित किया जाना है :

- 'उपबंध, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां' संबंधी प्रस्तावित स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एसएलबी)।
- 'वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण' संबंधी प्रस्तावित स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एसएलबी)।
- 'गैर-विनिमय संव्यवहारों से राजस्व' संबंधी प्रस्तावित स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एसएलबी)।
- 'संनिर्माण संविदाएं' संबंधी प्रस्तावित स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एसएलबी)।

- 'सेगमेंट रिपोर्टिंग' संबंधी प्रस्तावित स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एएसएलबी) ।

5.2.4 ऐसे प्रस्तावित एएसएलबी का प्रारूप, जिन्हें विभिन्न अध्ययन समूहों द्वारा तैयार किया जा रहा है :

- नकद प्रवाह विवरण ।
- लेखांकन नीतियां, लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन और त्रुटियां ।
- सूचीयां ।
- विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों का प्रभाव ।

5.2.5 अन्य परियोजनाएं :

- प्रोदभवन लेखांकन के फायदों को विशिष्ट रूप से स्पष्ट करने वाली पुस्तिका का विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद ।
- "सेवा रियायत ठहराव: प्रदाता" विषय पर प्रस्तावित आईपीएसएस के उद्भासन प्रारूप पर टीका-टिप्पणियां तैयार करना ।

5.3 संपरीक्षा समिति

वर्ष 2001 में आईसीएआई ने संस्थान की रिपोर्टिंग प्रक्रिया और अपनी वित्तीय सूचना के प्रकटन और साथ ही आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता का पर्यावलोकन करने और साथ ही संस्थान के विकेन्द्रीकृत कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के संपरीक्षकों की स्वतंत्रता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए पहली बार अस्थाई समिति के रूप में केन्द्रीय संपरीक्षा समिति का गठन किया था ।

इसके प्रारंभ से ही, समिति संस्थान की रिपोर्टिंग प्रक्रिया में और सुधार लाने तथा संस्थान के कार्यकरण में बृहत्तर पारदर्शिता लाने और साथ ही आंतरिक नियंत्रणों को और अधिक कड़ा बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है । समिति संपरीक्षकों की नियुक्ति में और अधिक पारदर्शिता लाने और उन्हें संपरीक्षा का और अधिक व्यापक परिधि-क्षेत्र उपलब्ध कराने और उसी समय उन्हें उनके कार्य में और अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए भी प्रयासरत है । समिति संपरीक्षकों और साथ ही ऐसे विभागों जिनकी संपरीक्षा की जा रही है/समितियों/प्रादेशिक परिषदों/विकेन्द्रीकृत कार्यालयों/ शाखाओं/विदेशी कार्यालयों के साथ निरंतर परस्पर क्रिया करती है जिससे कि संपरीक्षकों द्वारा इंगित किन्हीं दोषों/कमियों, यदि कोई हों, को कूर किया जा सके । वर्ष 2009-2010 के दौरान समिति द्वारा की गई पहलों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- 1000 सदस्यों से अधिक सदस्य संख्या वाली शाखाओं में आंतरिक संपरीक्षकों की नियुक्ति ।
- सभी नए सृजित डीसीओ में आंतरिक संपरीक्षकों की नियुक्ति ।
- आंतरिक नियंत्रण तंत्र का सुदृढीकरण ।
- सभी सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रणाली संपरीक्षा का कार्यान्वयन ।

5.4 संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड

संपरीक्षा एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रयोजन सिद्ध करती है और जवाबदेही को सुदृढ करके तथा वित्तीय रिपोर्टिंग में विश्वास और निष्ठा पुनःस्थापित करके लोकहित की सेवा और संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । संपरीक्षा आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने, व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले संव्यवहारों की किस्म, संख्या और मूल्य में वृद्धि करने में सहायता करती है । तथापि, हाल ही के वर्षों में, कारबार परिस्थितियों और कारबार मॉडलों में बढ़ती जटिलता तथा उनके भौगोलिक प्रसार के कारण संपरीक्षा वृत्ति से जनता की आशाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है ।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) भी सक्रिय रूप से इन आशाओं के अनुरूप प्रतिक्रिया करने की गहन आवश्यकता को मान्यता प्रदान करता है। संस्थान अपने समर्पित बोर्ड (संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड) के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले संपरीक्षा संबंधी मानकों को तैयार करता है, उनका पुनर्विलोकन करता है, अन्य आश्वासनों, गुणवत्ता नियंत्रण और संबद्ध सेवाओं के संबंध में उपबंध करता है। यह संपरीक्षा में सामान्य और साथ ही उद्योग विनिर्दिष्ट मुद्दों पर मार्गदर्शक टिप्पणों को विकसित करता है। एक कड़ी सम्यक प्रक्रिया के पश्चात्, इन दस्तावेजों को संस्थान की परिषद् के प्राधिकार के अधीन जारी किया जाता है। संस्थान द्वारा जारी किए गए मानकों को संपरीक्षा संबंधी अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानकों को उनकी उच्च गुणवत्ता के लिए मान्यताप्राप्त है और उन्हें वैश्विक स्वीकार्यता भी प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए अपने स्वयं के अधिकार के अधीन तकनीकी गाइडों, प्रैक्टिस मैनुअलों, अध्ययनों और अन्य पत्रों को भी तैयार करता है। संपरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के कार्यान्वयन के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए बोर्ड क्लैरिटी परियोजना के अधीन जारी मानकों के संबंध में एक कार्यान्वयन गाइड भी निकाल रहा है। वर्ष 2007 से बोर्ड आईएएसबी की क्लैरिटी परियोजना से उद्भूत होने वाली आईएसए संबंधी नवीनतम घटनाओं पर निकटता से दृष्टि रखे हुए है। वस्तुतः जनवरी, 2010 में, आईसीएआई ने आईएसए के साथ सारवान अभिसारिता पूर्ण की है। आज की तारीख तक बोर्ड की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का एक व्यापक पर्यावलोकन निम्नानुसार है :

नियोजन और क्वालिटी नियंत्रण मानक

क्वालिटी नियंत्रण मानक

- क्वालिटी नियंत्रण संबंधी मानक (एसक्यूसी) 1, “ऐसी फर्मों के लिए जो संपरीक्षा करती हैं क्वालिटी नियंत्रण और ऐतिहासिक वित्तीय सूचना का पुनर्विलोकन और अन्य आश्वासन तथा संबंधित सेवाओं का नियोजन”।

नियोजन मानक

- संपरीक्षा संबंधी 37 मानक, जिनके अंतर्गत क्लैरिटी परियोजना के अधीन 35 मानक, पदों की शब्दावली और जारी किया गया 1 साधारण स्पष्टीकरण हैं। जारी किए गए मानक साधारण सिद्धांतों और उत्तरदायित्वों, जोखिम निर्धारण और निर्धारित जोखिमों के संबंध में प्रतिक्रिया, संपरीक्षा साक्ष्य, अन्य व्यक्तियों के कार्यों का उपयोग, संपरीक्षा निष्कर्ष और रिपोर्टिंग तथा विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित हैं। जारी किया गया साधारण स्पष्टीकरण पुनर्विलोकन नियोजनों, आश्वासन नियोजनों और संबंधित सेवाओं से संबद्ध है।

परीक्षा संबंधी विवरण और मार्गदर्शन टिप्पण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (1क) के अधीन और कंपनी (संपरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के संबंध में रिपोर्टिंग संबंधी 2 विवरण ; प्रस्तावित लाभांश, परिसमापकों के लेख, संपरीक्षकों की स्वतंत्रता (पुनरीक्षित), भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45डक के अधीन संपरीक्षकों के संबंध में शुल्क कास्ट और नियत आस्तियों, सूचियों, निवेश, दायित्व, राजस्व और पूंजी तथा आरक्षितियों सहित लेखापरीक्षा मुद्दों पर 28 मार्गदर्शन टिप्पण जारी किए गए थे।

उद्योग विनिर्दिष्ट मार्गदर्शन टिप्पण

- बैंकों की संपरीक्षा (पुनरीक्षित 2009 संस्करण)
- स्टॉक एक्सचेंजों के सदस्यों के लेखाओं की संपरीक्षा
- साधारण बीमा कारबार कर रही कंपनियों की संपरीक्षा
- जीवन बीमा कारबार कर रही कंपनियों की संपरीक्षा

अन्य प्रकाशन (गैर-आधिकारिक)

कार्यान्वयन गाइड

- एसक्यूसी 1 संबंधी कार्यान्वयन गाईड
- वित्तीय विवरणों की जोखिम आधारित संपरीक्षा संबंधी कार्यान्वयन गाईड

तकनीकी गाइड

- टेलीकाम उद्योग में संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड - राजस्व, नियत आस्तियां और संबंधित प्रचालन लागतें
- ई-कॉमर्स संबंधी तकनीकी गाइड - वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए विचारार्थ

अध्ययन

घनशोधन - किसी लेखाकार का परिप्रेक्ष्य संबंधी एक अध्ययन

बेसल II और जोखिम आधारित पर्यवेक्षण संबंधी एक अध्ययन

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन (गैर-आधिकारिक)

नियोजन और क्वालिटी नियंत्रण संबंधी प्रशिक्षण मैनुअल

लघु अस्तित्वों की संपरीक्षा संबंधी प्रैक्टिसनर गाइड

संपरीक्षा क्या है - वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा को समझना - पुनरीक्षित अंक

कंपनी (संपरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 संबंधी मुद्दे

5.4.1 वर्ष 2009-10

वर्ष 2009-10 के दौरान लेखांकन और आश्वासन मानक बोर्ड की 6 बैठकें हुई थी, जिनमें कुल 9 दिन की पूर्ण बोर्ड परिचर्चाएं हुई थी। इस वर्ष के दौरान, बोर्ड ने अपना ध्यान मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड द्वारा क्लारिटी परियोजना के अधीन जारी अंतरराष्ट्रीय संपरीक्षा मानकों (आईएसए) के साथ अभिसरण को पूरा करने पर रखा, क्योंकि बोर्ड ने वर्ष के प्रारंभ पर अभिसरण प्रक्रिया को 1 अप्रैल, 2010 तक पूरा करने की प्रतिबद्धता की थी। बोर्ड ने अपना वर्ष प्रगतिशील क्लैरिटी परियोजना के अधीन 16 नए/पुनरीक्षित संपरीक्षा संबंधी मानकों से प्रारंभ किया। वर्ष के दौरान बोर्ड ने 19 नए/पुनरीक्षित संपरीक्षा संबंधी मानक जारी किए जिससे कि आईएएसबी द्वारा जारी 36 नए/पुनरीक्षित आईएसए की तुलना में बोर्ड द्वारा जारी नए/पुनरीक्षित मानकों की संख्या 35 हो गई। इसके साथ ही बोर्ड ने मार्च, 2010 में एसए 600 को छोड़कर आईएसए के साथ अपनी अभिसरण प्रक्रिया को लगभग पूरा कर लिया था। वर्ष के दौरान जारी नए/पुनरीक्षित एसए का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

पुनरीक्षित एसए 200, “स्वतंत्र संपरीक्षक के सकल उद्देश्य और संपरीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार संपरीक्षा का संचालन”

एसए 200 (पुनरीक्षित) संस्थान द्वारा जारी संपरीक्षा संबंधी अन्य सभी मानकों का मूल मानक है। अप्रैल, 1985 में जारी तत्कालीन एसए 200 (एसए 1), “किसी संपरीक्षा को शासित करने वाले आधिकारिक सिद्धांत”, वर्ष 1985 में जारी एसए 200क (एसए 2) “वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा का उद्देश्य और विस्तार क्षेत्र” के अंतर्गत आने वाली अवधारणाओं को एक मानक, अर्थात् एसए 200 (पुनरीक्षित) में समाविष्ट किया गया है। पुनरीक्षित मानक एसए के अनुसार वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा करते समय स्वतंत्र संपरीक्षक के सकल उत्तरदायित्वों को सुस्थापित करता है। विशेष रूप से, यह स्वतंत्र संपरीक्षक के सकल उद्देश्यों को अधिकथित करता है और उन उद्देश्यों की पूर्ति में स्वतंत्र संपरीक्षक को समर्थ बनाने के लिए तैयार की गई संपरीक्षा की प्रकृति और विस्तार क्षेत्र को स्पष्ट करता है। यह एसए के विस्तार क्षेत्र, प्राधिकार और संरचना को भी स्पष्ट करता है और इसमें सभी संपरीक्षाओं में लागू स्वतंत्र संपरीक्षक के साधारण उत्तरदायित्वों को सुस्थापित करने वाली अपेक्षाएं भी सम्मिलित हैं, जिनके अंतर्गत एसए का अनुपालन करने की बाध्यता भी है। पुनरीक्षित एसए 200 किसी संपरीक्षक द्वारा किसी

अस्तित्व की संपरीक्षा करते समय ध्यान रखे जाने वाली अनिवार्य अपेक्षाओं का भी उपबंध करता है जैसे कि वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा से संबंधित आचार संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन, वृत्तिक शंकाएं, वृत्तिक विवेक, पर्याप्त समुचित संपरीक्षा साक्ष्य और संपरीक्षा जोखिम तथा एसए के अनुसार संपरीक्षा का संचालन। यह एसए 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय संपरीक्षाओं के लिए प्रभावी है।

पुनरीक्षित एसए 210, “संपरीक्षा नियोजनों के निबंधनों पर सहमति देना”

एसए 210, संस्थान द्वारा 2003 में जारी तत्कालीन संपरीक्षा और आश्वासन मानक (एएस 26) ‘संपरीक्षा नियोजनों के निबंधन’ का पुनरीक्षित पाठ है। यह नया मानक संपरीक्षक के प्रबंध और जहां उचित हो, शासन के लिए प्रभारी व्यक्तियों के साथ संपरीक्षा नियोजनों के निबंधनों पर सहमति देने, जिनके अंतर्गत यह स्थापित करना भी है कि किसी संपरीक्षा के लिए कतिपय पूर्व शर्तें, जिनके संबंध में उत्तरदायित्व प्रबंध में निहित होता है और जहां उचित हो, शासन के लिए प्रभारी व्यक्ति उपस्थित हों, के उत्तरदायित्व को अंतर्विष्ट करता है। यह मानक वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे की स्वीकार्यता, उस दशा में जहां संपरीक्षा की रिपोर्ट का प्रारूप विधियों या विनियमों द्वारा विहित किया गया है, संपरीक्षक के उत्तरदायित्व जैसे पहलुओं को विस्तार से स्पष्ट करता है। पुनरीक्षित एसए 210 संपरीक्षा नियोजन पत्र के विस्तृत प्रारूप का भी उपबंध करता है। यह एसए 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

पुनरीक्षित एसए 220, “वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए क्वालिटी नियंत्रण”

एसए 220, संस्थान द्वारा वर्ष 1999 में जारी तत्कालीन एसए 220 (एएस 17), ‘संपरीक्षा कार्य के लिए क्वालिटी नियंत्रण’ का पुनरीक्षित पाठ है। संस्थान द्वारा मार्च, 2008 में जारी एसक्यूसी 1 को फर्मों के स्तर पर लागू किया जाना है, वहीं इस एसए को नियोजन स्तर पर लागू किया जाना है। यह एसए यह अध्यापना भी करता है कि फर्म एसक्यूसी 1 को लागू कर रही है। यह मानक वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए क्वालिटी नियंत्रण प्रक्रियाओं के संबंध में संपरीक्षक के विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्वों से भी संबंधित है। जहां कही लागू हो यह नियोजन क्वालिटी नियंत्रण पुनर्विलोकक के उत्तरदायित्वों को भी उल्लिखित करता है। यह संपरीक्षा संबंधी क्वालिटी के लिए अगुवाई और उत्तरदायित्व, सुसंगत आचार संबंधी अपेक्षाएं, स्वीकार्यता और ग्राहक संबंधों का जारी रहना तथा संपरीक्षा नियोजन दलों का समनुदेशन, नियोजन कार्य पालन, मॉनिटरिंग और दस्तावेजीकरण संबंधी अपेक्षाओं जैसे पहलुओं पर भी मार्गदर्शन उपलब्ध करता है। यह एसए 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

एसए 265, “शासन और प्रबंध के लिए प्रभारी व्यक्तियों को आंतरिक नियंत्रण में कमियों की संसूचना देना”

इस एसए के अधीन संपरीक्षक का उद्देश्य किसी संपरीक्षा के दौरान उसकी जानकारी में आई आंतरिक नियंत्रण में किन्हीं कमियों के संबंध में और ऐसी बातों को, जिनके संबंध में संपरीक्षक के वृत्तिक विवेक के अनुसार प्रबंध या शासन के लिए प्रभारी व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है, उचित रूप से संसूचित करना है। यद्यपि, संपरीक्षा विषयों की संसूचना से संबंधित पहलुओं को पुनरीक्षित संपरीक्षा मानक (एसए) 260, शासन के लिए प्रभारी व्यक्तियों को संसूचना के अंतर्गत रख गया है, फिर भी यह मानक संपरीक्षक के द्वारा उत्तरदायित्व से विनिर्दिष्ट रूप से संबंधित है कि वह प्रबंध या शासन के लिए प्रभारी व्यक्तियों को आंतरिक नियंत्रण में ऐसी कमियों की उपयुक्त रूप से संसूचना दे, जो वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के दौरान उसकी जानकारी में आई हैं। यह मानक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

पुनरीक्षित एसए 450, “किसी संपरीक्षा के दौरान पहचान किए गए मिथ्या कथनों का मूल्यांकन”

यद्यपि एसए 450, “किसी संपरीक्षा के दौरान पहचान किए गए मिथ्या कथनों का मूल्यांकन” के तत्कालीन कोई पृथक मानक नहीं है, फिर भी एसए 450 के कुछ पहलू संस्थान द्वारा जनवरी, 1997 में जारी तत्कालीन संपरीक्षा और आश्वासन मानक (एएस 13) ‘संपरीक्षा भौतिकता’ में सम्मिलित थे। यह एसए संपरीक्षक के इस उत्तरदायित्व से संबंधित है कि वह संपरीक्षा के दौरान पहचान किए गए मिथ्या कथनों या ठीक न किए गए

मिथ्या कथनों का मूल्यांकन करे और यह एसए 320 से संबद्ध है जो संपरीक्षक के इस उत्तरदायित्व से संबंधित है कि वह किसी वित्तीय विवरण की संपरीक्षा की योजना और कार्यपालन में भौतिकता की अवधारणा का उपयोग करे। यह एसए 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

पुनरीक्षित एसए 501, “संपरीक्षा साक्ष्य - चयनित मदों के लिए विनिर्दिष्ट विचार”

एसए 501, संस्थान द्वारा वर्ष 2005 में जारी तत्कालीन एसए 501 (एएएस 34), ‘संपरीक्षा साक्ष्य - विनिर्दिष्ट मदों के लिए अतिरिक्त विचार’ का पुनरीक्षित पाठ है। यह पुनरीक्षित मानक संपरीक्षक द्वारा वित्तीय विवरणों की किसी संपरीक्षा में सूचियों, मुकदमों और अस्तित्व को अंतर्बलित करने वाले दावों और खंड सूचना के कतिपय पहलुओं के संबंध में एसए 330, एसए 500 (पुनरीक्षित) और अन्य सुसंगत एसए के अनुसार पर्याप्त रूप से समुचित संपरीक्षा साक्ष्य अभिप्राप्त करने में किए गए विनिर्दिष्ट विचारों से संबंधित है। पुनरीक्षित एसए 501 सूचियों, मुकदमों और अस्तित्व को अंतर्बलित करने वाले दावों और खंड सूचना की दशा में संपरीक्षा साक्ष्य अभिप्राप्त करने के लिए ब्यौरेवार प्रक्रियाओं का भी उपबंध करता है। यह एसए 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

पुनरीक्षित एसए 505, “बाह्य पुष्टिकरण”

एसए 505, संस्थान द्वारा वर्ष 2003 में जारी तत्कालीन एसए 505 (एएएस 30), ‘बाह्य पुष्टिकरण’ का पुनरीक्षित पाठ है। यह पुनरीक्षित मानक संपरीक्षक द्वारा एसए 330, एसए 500 (पुनरीक्षित) के अनुसार संपरीक्षा साक्ष्य अभिप्राप्त करने के लिए बाह्य पुष्टिकरण प्रक्रियाओं के उपयोग से संबंधित है। यह बाह्य पुष्टिकरणों के माध्यम से संपरीक्षा साक्ष्य अभिप्राप्त करने की प्रक्रियाओं का भी उपबंध करता है। यह किसी संपरीक्षक द्वारा कतिपय मामलों में जैसे कि जहां प्रबंध संपरीक्षक को पुष्ट अनुरोध भेजने की अनुमति देने से इंकार करता है, बाह्य पुष्टिकरणों के संबंध में प्रतिक्रिया न मिलने, बाह्य पुष्टिकरणों के परिणामों, प्रतिकूल पुष्टिकरणों के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के लिए भी उपबंध करता है। यह एसए 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

पुनरीक्षित एसए 520, “विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं”

एसए 520, संस्थान द्वारा दिसम्बर, 1997 में जारी तत्कालीन एसए 520 (एएएस 14), ‘विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं’ का पुनरीक्षित पाठ है। यह पुनरीक्षित मानक संपरीक्षक द्वारा सारवान प्रक्रियाओं (सारवान विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं) के रूप में विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं के उपयोग से संबंधित है और जैसे-जैसे ये प्रक्रियाएं संपरीक्षा के अंत तक पहुंचती हैं ये संपरीक्षक की वित्तीय विवरणों पर उसके सकल निष्कर्षों को तैयार करने में मदद करती हैं। यह एक सकल निष्कर्ष तैयार करने में और विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं के परिणामों का अन्वेषण करने में अपनाई जाने वाली सारवान विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं के औचित्य, विश्वसनीयता से संबंधित ब्यौरेवार अपेक्षाओं का भी उपबंध करता है। यह एसए 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

पुनरीक्षित एसए 620, “संपरीक्षक के विशेषज्ञ के कार्य का उपयोग”

एसए 620, संस्थान द्वारा दिसम्बर, 1991 में जारी तत्कालीन एसए 620 (एएएस 9), ‘किसी विशेषज्ञ के कार्य का उपयोग’ का पुनरीक्षित पाठ है। यह पुनरीक्षित मानक संपरीक्षक के लेखांकन या संपरीक्षा से भिन्न किसी अन्य विशेषज्ञ क्षेत्र में किसी व्यक्ति या संगठन के कार्य का उस समय उपयोग किए जाने के संबंध में उत्तरदायित्वों से संबंधित है, जब उस कार्य का उपयोग संपरीक्षक को पर्याप्त समुचित साक्ष्य अभिप्राप्त करने में सहायता देने के लिए किया जाता है। संपरीक्षक द्वारा उस समय अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का उपबंध करता है, जब किसी बाहरी विशेषज्ञ के कार्य का उपयोग करने का विनिश्चय किया जाता है। यह संपरीक्षक और बाहरी विशेषज्ञ के बीच किए जाने वाले करार में सम्मिलित किए जाने वाले विषयों का भी विस्तृत रूप से उपबंध करता है। यह एसए 1

अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

पुनरीक्षित एसए 700, “वित्तीय विवरणों पर राय बनाना और उनकी रिपोर्टें”

एसए 700, संस्थान द्वारा मार्च, 2003 में जारी तत्कालीन एसए 700 (एएस 28), ‘वित्तीय विवरणों पर संपरीक्षक की रिपोर्ट’ का पुनरीक्षित पाठ है। तत्कालीन एसए 700 (एएस 28) अनुपांतरित, उपांतरित और विषय पैरा के ब्यौरे से संबंधित था वहीं पुनरीक्षित एसए 700 केवल साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों पर अनुपांतरित राय से संबंधित है। यह संपरीक्षक के वित्तीय विवरणों के संबंध में राय बनाने के उत्तरदायित्वों से और वित्तीय विवरणों की किसी संपरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी की गई संपरीक्षक की रिपोर्ट के प्ररूप और अंतर्वस्तु से संबंधित है। यह किसी संपरीक्षक द्वारा विवरणों के संबंध में राय बनाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का भी उपबंध करता है। यह साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों पर संपरीक्षक की किसी भी प्रकार की रिपोर्ट में दिए जाने के लिए अपेक्षित संपरीक्षक रिपोर्ट के प्ररूप और अनिवार्य अंतर्वस्तु के लिए भी उपबंध करता है। यह वित्तीय विवरणों पर संपरीक्षक की रिपोर्ट के ब्यौरेवार प्ररूपों का भी उपबंध करता है। यह एसए 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

पुनरीक्षित एसए 705, “स्वतंत्र संपरीक्षक की रिपोर्ट में राय में उपांतरण”

यद्यपि एसए 705 के तत्समान कोई पृथक संपरीक्षा मानक नहीं है फिर भी साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों पर उपांतरित राय से संबंधित पहलुओं को संस्थान द्वारा मार्च, 2003 में जारी तत्कालीन एसए 700 (एएस 28), ‘वित्तीय विवरणों पर संपरीक्षक की रिपोर्ट’ में सम्मिलित किया गया था। एसए 705 ऐसी परिस्थितियों में समुचित रिपोर्ट जारी करने के संपरीक्षक के उत्तरदायित्व से संबंधित है, जब एसए 700 (पुनरीक्षित) के अनुसार राय बनाते समय संपरीक्षक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वित्तीय विवरणों पर संपरीक्षक की राय में उपांतरण करना आवश्यक है। यह उन परिस्थितियों का भी उपबंध करता है जब संपरीक्षक की राय में कोई उपांतरण अपेक्षित है और यह संपरीक्षक द्वारा दी जाने वाली संपरीक्षक की राय में उपांतरण की किस्म और जब राय में उपांतरण किया जाता है तो संपरीक्षक की रिपोर्ट के प्ररूप और अंतर्वस्तु का भी उपबंध करता है। इसमें राय में उपांतरणों के साथ संपरीक्षकों की रिपोर्टों के ब्यौरेवार प्ररूप भी अंतर्विष्ट हैं। यह एसए 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

पुनरीक्षित एसए 706, “स्वतंत्र संपरीक्षक की रिपोर्ट में मैटर पैराओं और अन्य मैटर पैराओं पर बल”

यद्यपि एसए 705 के तत्समान कोई पृथक संपरीक्षा मानक नहीं है फिर भी साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों के संबंध में मैटर पैराओं पर बल दिए जाने से संबंधित पहलुओं को संस्थान द्वारा मार्च, 2003 में जारी तत्कालीन एसए 700 (एएस 28), ‘वित्तीय विवरणों पर संपरीक्षक की रिपोर्ट’ में सम्मिलित किया गया था। एसए 706, जो उस समय संपरीक्षक के रिपोर्ट में अतिरिक्त संसूचना से संबंधित, जब संपरीक्षक, संपरीक्षक की रिपोर्ट में मैटर पैराओं और अन्य मैटर पैराओं पर बल देना आवश्यक समझता है। इसमें संपरीक्षक की रिपोर्ट के ब्यौरेवार प्ररूप भी अंतर्विष्ट हैं, जिनके अंतर्गत मैटर पैराओं और अन्य मैटर पैराओं पर बल देना भी है। यह एसए 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

पुनरीक्षित एसए 710, “तुलनात्मक सूचना - तत्समान आंकड़े और तुलनात्मक वित्तीय विवरण”

एसए 710, संस्थान द्वारा सितम्बर, 2002 में जारी तत्कालीन एसए 710 (एएस 25), ‘तुलनाएं’ का पुनरीक्षित पाठ है। यह पुनरीक्षित मानक वित्तीय विवरणों की किसी संपरीक्षा में तुलनात्मक सूचना के संबंध में संपरीक्षक के उत्तरदायित्वों से संबंधित है। इस एसए के अनुसार, तुलनात्मक सूचना की दो अवधारणाएं हैं, प्रथम तत्समान आंकड़े और द्वितीय तुलनात्मक सूचना। यह इन दो अवधारणाओं के संबंध में किसी संपरीक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली ब्यौरेवार प्रक्रियाओं का भी उपबंध करता है। इसमें संपरीक्षक की रिपोर्ट के उदाहरण भी अंतर्विष्ट हैं। यह एसए 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

एसए 800, “विशेष विचार - विशेष प्रयोजन ढांचों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा”

एसए 800 एक नया संपरीक्षा मानक है, जो उन एसए का विशेष प्रयोजन ढांचों के अनुसार तैयार किए गए किन्हीं वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा को लागू करने में विशेष विचारों से संबंधित है। यद्यपि 700 श्रृंखला को साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों के अधीन रिपोर्टिंग के मामले में लागू किया जाना है, वहीं 800 श्रृंखला को विशेष प्रयोजन वित्तीय विवरणों के अधीन रिपोर्टिंग के मामले में लागू किया जाना है। यह उन विचारों के लिए भी उपबंध करता है जो किसी संपरीक्षक को ध्यान में रखने होंगे जैसे कि वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे की स्वीकार्यता, संपरीक्षा की योजना और निष्पादन, राय बनाना और उसकी रिपोर्टिंग, वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे की स्वीकार्यता। इसमें विशेष प्रयोजन वित्तीय विवरणों पर संपरीक्षक की रिपोर्ट के ब्यौरेवार प्ररूप भी अंतर्विष्ट हैं। यह एसए 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

एसए 805, “विशेष विचार - एकल वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा और किसी वित्तीय विवरण के विनिर्दिष्ट तत्व, लेखा या मदें”

एसए 805 एक नया संपरीक्षा मानक है, जो उन एसए का एकल वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा और किसी वित्तीय विवरण के विनिर्दिष्ट तत्व, लेखा या मद की संपरीक्षा को लागू करने में विशेष विचारों से संबंधित है। यह उन विचारों के लिए भी उपबंध करता है जो किसी संपरीक्षक को ध्यान में रखने होंगे जैसे कि नियोजन की स्वीकार्यता, संपरीक्षा की योजना और निष्पादन, राय बनाना और उसकी रिपोर्टिंग। यह किसी वित्तीय विवरण के विनिर्दिष्ट तत्व, लेखा या मदों के उदाहरणों का भी उपबंध करता है। इसमें किसी एकल वित्तीय विवरण और किसी वित्तीय विवरण के किसी विनिर्दिष्ट तत्व पर संपरीक्षक की रिपोर्ट के ब्यौरेवार प्ररूप अंतर्विष्ट हैं। यह एसए 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

एसए 810, “संक्षिप्त वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट से संबंधित नियोजन”

एसए 810 एक नया संपरीक्षा मानक है, जो उस समय संपरीक्षक के उत्तरदायित्वों से संबंधित है जब वह एसए के अनुसार संपरीक्षित वित्तीय विवरणों से उद्भूत किन्हीं संक्षिप्त वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट करने का नियोजन स्वीकार करता है। इसके अंतर्गत नियोजन स्वीकार्यता, प्रक्रियाओं की प्रकृति, राय का प्ररूप, कार्य का समय तथा संपरीक्षित वित्तीय विवरणों पर संपरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के पश्चात् होने वाली घटनाएं, संक्षिप्त वित्तीय विवरणों पर संपरीक्षक की रिपोर्ट, संक्षिप्त वित्तीय विवरणों के साथ प्रस्तुत लेखाकरण, तुलनाओं, असंपरीक्षित अनुपूरक सूचना के आधार पर वितरण या उपयोग संबंधी निर्बंधन या पाठकों को सावधान करने, संक्षिप्त वित्तीय विवरण अंतर्विष्ट करने वाले दस्तावेजों में अन्य सूचना और संपरीक्षक के साथ सहबद्धता जैसे पहलू अंतर्विष्ट हैं। इसमें किन्हीं संक्षिप्त वित्तीय विवरणों पर रिपोर्टों के ब्यौरेवार प्ररूप अंतर्विष्ट हैं। यह एसए 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए प्रभावी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, बोर्ड ने निम्नलिखित नए/पुनरीक्षित पुनर्विलोकन नियोजन मानक (एसआरई) जारी किए हैं :

एसआरई 2400 (पुनरीक्षित), “वित्तीय विवरणों के पुनर्विलोकन संबंधी नियोजन”

एसआरई 2400 संस्थान द्वारा जनवरी, 2005 में जारी तत्कालीन एसआरई 2400 (एएस 33), ‘वित्तीय विवरणों के पुनर्विलोकन संबंधी नियोजन’ का पुनरीक्षित पाठ है। इस पुनरीक्षित मानक का प्रयोजन उस समय किसी व्यवसायी के वृत्तिक उत्तरदायित्वों के संबंध में मानक स्थापित करना और उसे मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है जब कोई ऐसा व्यवसायी जो किसी अस्तित्व का संपरीक्षक नहीं है, वित्तीय विवरणों के पुनर्विलोकन का नियोजन स्वीकार करता है और यह ऐसे पुनर्विलोकन के संबंध में व्यवसायी द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट के प्ररूप और अंतर्वस्तु के संबंध में भी मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। ऐसा कोई व्यवसायी, जो किसी अस्तित्व का संपरीक्षक है और जिसे अंतरिम वित्तीय सूचना का पुनर्विलोकन करने के लिए नियोजित किया गया है, ऐसा कोई पुनर्विलोकन एसआरई 2410 “अस्तित्व के स्वतंत्र संपरीक्षक द्वारा किया जाने वाला अंतरिम वित्तीय सूचना का पुनर्विलोकन” के अनुसार करेगा। इसमें किसी पुनर्विलोकन नियोजन के साधारण सिद्धांत, पुनर्विलोकन का विस्तार क्षेत्र, संतुलित आश्वासन, नियोजन के निर्बंधन, योजना, अन्य व्यक्तियों द्वारा निष्पादित कार्य, दस्तावेजीकरण, प्रक्रियाएं तथा साक्ष्य और निष्कर्ष

तथा रिपोर्टिंग जैसे पहलू अंतर्विष्ट हैं। इसमें वित्तीय विवरणों के पुनर्विलोकन के लिए नियोजन पत्र का नमूना, ऐसी दृष्टांतात्मक ब्यौरेवार प्रक्रियाएं, जिनका वित्तीय विवरणों के पुनर्विलोकन के किसी नियोजन में अनुसरण किया जा सकेगा, अनर्हित पुनर्विलोकन रिपोर्ट और अनर्हित से भिन्न पुनर्विलोकन रिपोर्टों के उदाहरण भी अंतर्विष्ट हैं। यह एसआरई 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों के पुनर्विलोकन के लिए प्रभावी है।

एसआरई 2410, “अस्तित्व के स्वतंत्र संपरीक्षक द्वारा किया जाने वाला अंतरिम वित्तीय सूचना का पुनर्विलोकन”

एसआरई 2410 एक नया मानक है जिसका प्रयोजन उस समय किसी संपरीक्षक के वृत्तिक उत्तरदायित्वों के संबंध में मानक स्थापित करना और उसे मार्गदर्शन उपलब्ध करना है जब कोई संपरीक्षक किसी संपरीक्षा ग्राहक के अंतरिम वित्तीय विवरणों के पुनर्विलोकन का नियोजन स्वीकार करता है और यह रिपोर्ट के प्ररूप और अंतर्वस्तु के संबंध में भी मार्गदर्शन उपलब्ध करता है। संपरीक्षा के विपरीत, कोई पुनर्विलोकन नियोजन मुख्यतः विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं और जांचों पर आधारित होता है, जो संपरीक्षक द्वारा की जाती है। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कंपनियों के त्रैमासिक असंपरीक्षित वित्तीय परिणाम चार्टर्ड एकाउंटेंटों द्वारा सीमित पुनर्विलोकन के अध्यक्षीन हैं। वित्तीय विवरणों के पुनर्विलोकन संबंधी नियोजनों से संबंधित एसआरई संपरीक्षकों द्वारा अपनाई जाने वाली ऐसी प्रक्रियाओं और जांचों के संबंध में व्यापक मार्गदर्शन उपलब्ध करता है। इसमें अंतरिम वित्तीय सूचना के पुनर्विलोकन के साधारण सिद्धांत, अंतरिम वित्तीय सूचना के संबंध में नियोजन का उद्देश्य, नियोजन के निबंधनों को स्वीकार करने, अंतरिम वित्तीय सूचना के पुनर्विलोकन के लिए प्रक्रियाएं, मिथ्या कथनों का मूल्यांकन, प्रबंध के प्रतिनिधि, संलग्न सूचना के लिए संपरीक्षक का उत्तरदायित्व, संसूचना, अंतरिम वित्तीय सूचना के पुनर्विलोकन की रिपोर्टिंग की प्रकृति, विस्तार और परिणाम तथा दस्तावेजीकरण जैसे पहलू अंतर्विष्ट हैं। इसमें अंतरिम वित्तीय सूचना के पुनर्विलोकन के लिए एक नियोजन पत्र का नमूना, ऐसी विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं, जिनपर कोई संपरीक्षक अंतरिम वित्तीय सूचना का पुनर्विलोकन करते समय विचार कर सकेगा, विभिन्न परिस्थितियों में दी जाने वाली अंतरिम वित्तीय सूचना संबंधी पुनर्विलोकन रिपोर्टों के दृष्टांतात्मक प्ररूप भी अंतर्विष्ट हैं। यह एसआरई 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए अंतिम वित्तीय सूचना के पुनर्विलोकनों के लिए प्रभावी है।

5.4.2 उदभासन प्रारूप

बोर्ड ने जनता की टीका-टिप्पणियों के लिए आश्वासन नियोजन संबंधी मानक (एसएई) 3000, “संपरीक्षाओं से भिन्न आश्वासन नियोजन और ऐतिहासिक वित्तीय सूचना का पुनर्विलोकन” के उदभासन प्रारूप भी जारी किए थे। प्रस्तावित एसएई 3000 और उससे संबंधित मुद्दे बोर्ड के विचाराधीन हैं।

5.4.3 अन्य तकनीकी साहित्य

बोर्ड ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित अन्य तकनीकी साहित्य भी जारी किये :

संपरीक्षा उदघोषणाओं की पुस्तिका (2009 संस्करण)

- 1 जुलाई, 2009 को यथाविद्यमान संपरीक्षा उदघोषणाओं का प्राधिकृत पाठ।
- संपरीक्षा संबंधी तकनीकी साहित्य की एक स्थान पर उपलब्धता।
- सदस्यों और साथ ही सभी वृत्तिकों और शिक्षाविदों के लिए पूर्ण संदर्भ।
- दो विशिष्ट अंक, एक मानकों और विवरणों के लिए और दूसरा मार्गदर्शक टिप्पणों के लिए।
- दोनों अंकों की अंतर्वस्तु प्रतिसंदर्भ के लिए प्रत्येक अंक में उपलब्ध कराई गई है।
- सीडी संलग्न है।

अंक 1 - मानकों और विवरणों का सार-संग्रह

- संपरीक्षा संबंधी विवरणों का सार-संग्रह जिसमें सभी नियोजन और क्वालिटी नियंत्रण मानकों का पाठ अंतर्विष्ट है।
- त्वरित संदर्भ और पर्यावलोकन के लिए प्रत्येक मानक और विवरण की अंतर्वस्तु प्रारंभ में दी गई है।
- क्लैरिटी परियोजना के अधीन जारी नौ (9) पुनरीक्षित/नए संपरीक्षा संबंधी मानकों का पाठ अंतर्विष्ट है, ये मानक 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के संबंध में लागू हैं। संदर्भ की सुगमता के लिए तत्समान एसए का पाठ भी अंतर्विष्ट किया गया है।
- क्लैरिटी परियोजना के अधीन जारी नौ (9) पुनरीक्षित/नए संपरीक्षा संबंधी मानकों का पाठ अंतर्विष्ट है, ये मानक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के संबंध में लागू हैं। संदर्भ की सुगमता के लिए तत्समान एसए का पाठ भी अंतर्विष्ट किया गया है।
- 1 जुलाई, 2009 को यथाविद्यमान - क्लैरिटी परियोजना के अधीन जारी आईएएसबी मानकों की तुलना में एएसबी मानकों की प्रास्थिति

अंक 2 - मार्गदर्शक टिप्पणों का सार-संग्रह

- संपरीक्षा पहलुओं पर 31 मार्गदर्शक टिप्पणों का पाठ अंतर्विष्ट है।
- त्वरित संदर्भ और पर्यावलोकन के लिए प्रत्येक मार्गदर्शक टिप्पण की अंतर्वस्तु प्रारंभ में दी गई है।

नियोजन और क्वालिटी नियंत्रण मानकों संबंधी प्रशिक्षण मैनुअल (2009 संस्करण)

- इस प्रशिक्षण मैनुअल का मुख्य उद्देश्य संपरीक्षा मानकों संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पृष्ठभूमि सामग्री उपलब्ध कराना है।
- संपरीक्षा मानकों के संबंध में व्यापक और सरल पठन सामग्री उपलब्ध कराता है।
- पुनरीक्षित प्राक्कथन के अनुसार सभी संपरीक्षा मानकों का पुनःसंख्यांकन और पुनःवर्गीकरण किया गया है।
- क्लैरिटी परियोजना के अधीन जारी पुनरीक्षित/नए जारी एसए का प्रस्तुतीकरण सम्मिलित है जो 1 अप्रैल, 2008 या 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी हैं।
- इसे पांच भागों में विभक्त किया गया है :
 - प्रस्तावना - यह पाठकों को संपरीक्षा के इतिहास और प्रकृति, संपरीक्षा मानकों के महत्व, आश्वासन नियोजनों के लिए ढांचे आदि का संक्षिप्त विवरण उपलब्ध कराता है।
 - प्रस्तुतीकरण - इसमें कुछ टीका-टिप्पणियों के साथ संपरीक्षा मानकों में निहित मूल सिद्धांतों का सार अंतर्विष्ट है।
 - एसए में दस्तावेजीकरण संबंधी अपेक्षाएं।
 - मामला अध्ययन और तकनीकी प्रश्न।
 - क्लैरिटी परियोजना के अधीन जारी पुनरीक्षित/नए जारी संपरीक्षा संबंधी मानकों का पाठ जो 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के संबंध में लागू हैं।
- सीडी संलग्न है।

5.4.4 ऐसी परियोजनाएं, जिनपर कार्य चल रहा है ।

इनके अतिरिक्त बोर्ड ने, वर्ष के दौरान अनेक अन्य परियोजनाएं भी प्रारंभ की हैं, जो अन्य के साथ, नियोजन और क्वालिटी नियंत्रण मानकों, कार्यान्वयन गाइडों और तकनीकी गाइडों - उद्योग विनिर्दिष्ट गाइडों सहित, से संबंधित हैं ।

5.4.5 अन्य पहलें और विकास

• विनियामक निकायों से परस्पर क्रिया

बोर्ड, समय-समय पर संपरीक्षा मानकों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों और संपरीक्षा संबंधी अन्य पहलुओं पर विचार करने के लिए विनियामकों और अन्य सरकारी संस्थाओं जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), भारत का नियंत्रक और महालेखा पक्षिक (सीएंडएजी) आदि से प्रतिक्रिया करता है ।

• आईएएसबी की गतिविधियों में सहयोग और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना

संस्थान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली घटनाओं में सक्रिय रूप से सम्मिलित रहता है । बोर्ड, अंतरराष्ट्रीय एकाउंटेंट्स संघ (आईएफएसी) का संस्थापक सदस्य होने के कारण अध्यक्ष के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (आईएएसबी) की राष्ट्रीय मानक निर्धारक समिति के संपर्क में रहा था और उसने उसकी बैठकों में उस समिति को महत्वपूर्ण अंतःनिवेश उपलब्ध कराए थे । 3-4 जून को डबलिन में हुई आईएएसबी एनएसएस की बैठक में अध्यक्ष, एएसबी और सचिव, एएसबी ने संस्थान का प्रतिनिधित्व किया था ।

• जागरूकता सृजित करना और सक्षमता का निर्माण

वर्ष 2009-10 के दौरान सदस्यों के बीच संपरीक्षा मानकों के संबंध में जागरूकता का सृजन करना बोर्ड का प्रमुख लक्ष्य था । इस प्रक्रिया में, सदस्यों के सामने आने वाले संपरीक्षा संबंधी मुद्दों पर परस्पर क्रिया को आसान बनाने तथा संस्थान द्वारा जारी किए जा रहे नवीनतम संपरीक्षा मानकों पर जानकारी प्रदान करने के लिए, बोर्ड ने संपरीक्षा मानकों और संपरीक्षा संबंधी पहलुओं पर इंदौर, हैदराबाद, विशाखापत्तनम, चेन्नई और नई दिल्ली में पांच संगोष्ठियों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सम्मेलनों का आयोजन किया था । इसके अतिरिक्त, बोर्ड अपने विद्यमान दो प्रकाशनों, अर्थात् “व्हाट इज एन ऑडिट - अंडरस्टैंडिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स” और “ट्रेनिंग मैनुअल ऑन एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स” को पुनरीक्षित करने की भी योजना बना रहा है ।

• भावी रणनीति और कार्यक्रम

चूंकि संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (एएसबी) ने अपनी क्लैरिटी परियोजना को पहले ही मार्च, 2010 में पूरा कर लिया है, इसलिए बोर्ड अब अपना ध्यान क्लैरिटी परियोजना के अधीन जारी नए/पुनरीक्षित संपरीक्षा मानकों (एसए) के संबंध में जागरूकता सृजित करने पर केन्द्रित करेगा । यह सदस्यों और विनियामकों के लिए संगोष्ठियों/सम्मेलनों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करेगा और सदस्यों की उन्हें बेहतर रूप से समझने और मानकों के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए नए/पुनरीक्षित एसए के संबंध में कार्यान्वयन गाइडें जारी करेगा । बोर्ड संपरीक्षा संबंधी और साथ ही साधारणतया उद्योग सेक्टर से विनिर्दिष्ट समकालीन मुद्दों पर सदस्यों का मार्गदर्शन करने के लिए अन्य संपरीक्षा साहित्य भी निकालेगा ।

5.5 बैंककारी, बीमा और पेंशन संबंधी समिति

बीमा और पेंशन संबंधी समिति को बैंककारी, बीमा और पेंशन संबंधी समिति के रूप में पुनःगठित किया गया है । समिति के निर्देश निर्बंधनों में, अन्य बातों के साथ, बैंककारी, बीमा और पेंशन के क्षेत्र में सक्षमता निर्माण के लिए अनुसंधान, बातचीत, नीति निर्माण में अंतःनिवेश, जानकारी का प्रसार आदि सम्मिलित हैं । यह समिति बीमा और जोखिम प्रबंध में एक अर्हत्तोर पाठ्यक्रम का भी संचालन करती है ।

5. 5.1 डीआईआरएम अर्हता वाले सीए के लिए वृत्तिक अवसरों का विकास करना

- आईआरडीए ने अपने 4 अगस्त, 2009 के परिपत्र द्वारा बीमाकर्ताओं के लिए यह आज्ञापक बनाया है कि वे प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म से अपनी निवेश प्रणालियों और प्रक्रिया की संपरीक्षा कराएं और आंतरिक संपरीक्षा के माध्यम से त्रैमासिक आधार पर अपने निवेश संव्यवहारों की संपरीक्षा कराएं या 1,000 करोड़ रुपये से अधिक प्रबंधाधीन आस्तियों वाले बीमाकर्ता चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के द्वारा समवर्ती संपरीक्षा कराएं। समिति ने संस्थान के सदस्यों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए आईआरडीए के परामर्श से 'टेक्निकल गाइड ऑन/कंकरेंट ऑडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शंस ऑफ इश्योरेस कंपनीज' निकाला है।
- डीआईआरएम अर्हता रखने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंटों का उपयोग करने का अनुरोध करते हुए विभिन्न बीमा कंपनियों के सीएमडी को डीआईआरएम मार्केटिंग पत्र भेजे गए थे।

5. 5.2 एक अर्होत्तर पाठ्यक्रम, अर्थात् बीमा और जोखिम प्रबंध में डिप्लोमा (डीआईआरएम) के माध्यम से सदस्यों को बीमा और पेंशन क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना तथा उन्हें तैयार करना

- समिति संस्थान के ऐसे सदस्यों के लिए जिन्होंने डीआईआरएम तकनीकी परीक्षा उत्तीर्ण की है, अनुकूलन पाठ्यक्रमों का आयोजन करती है जिससे कि उन्हें डीआईआरएम के अंतिम चरण को पूरा करने में समर्थ बनाया जा सके ताकि वे देश के विभिन्न भागों में बीमा और जोखिम प्रबंध में डिप्लोमा (डीआईआरएम) प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकें।
- डीआईआरएम पाठ्यक्रम कर रहे सदस्यों के फायदे के लिए जून, 2009 और नवम्बर, 2009 में आयोजित डीआईआरएम तकनीकी परीक्षाओं के सुझाए गए उत्तरों को तैयार किया गया था और वेबसाइट www.icai.org पर रखा गया था। इसके साथ ही नवम्बर, 2009 तक आयोजित डीआईआरएम तकनीकी परीक्षाओं के सुझाए गए उत्तरों को संस्थान की वेबसाइट के हाइपर लिंक http://www.icai.org/post.html?post_id=2432 पर रख दिया गया है।
- सदस्यों के बीच डीआईआरएम पाठ्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए, समिति निरंतर प्रयास कर रही है और उपयुक्त उपाय भी कर रही है। इसके परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2010 तक रजिस्ट्रीकरणों की संख्या 3707 तक पहुंच गई है। क्षेत्रवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्षेत्र	रजिस्ट्रीकरण	प्रतिशतता
मध्य	774	21
पूर्वी	410	11
उत्तरी	543	15
दक्षिणी	1175	31
पश्चिमी	805	22

- अर्होत्तर पाठ्यक्रम, अर्थात् बीमा और जोखिम प्रबंध में डिप्लोमा (डीआईआरएम) के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय हेतु ऑन लाइन सुविधा को www.icai.org पर प्रारंभ किया गया है।

5.5.3 बैंककारी, बीमा और पेंशन क्षेत्रों में अद्यतन जानकारी

संस्थान के सदस्यों के बीच ज्ञान और जागरूकता के प्रसार के लिए दैनिक आधार पर (रविवार और छुट्टी के दिनों को छोड़कर) बैंककारी, बीमा तथा पेंशन क्षेत्रों के संबंध में दैनिक अद्यतन जानकारी को www.icai.org पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

5.5.4 विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से बीककारी, बीमा, जोखिम प्रबंध और पेंशन के क्षेत्रों में संस्थान के सदस्यों के लिए सक्षमता निर्माण :

प्रकाशन

समिति बीमा, पेंशन और जोखिम प्रबंध के क्षेत्र में सदस्यों की मूल सक्षमताओं को विकसित करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए समकालीन विषयों पर प्रकाशन निकालती है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति द्वारा निम्नलिखित प्रकाशन जारी किए गए थे :

- बीमा कंपनियों के निवेश कृत्यों की आंतरिक/समवर्ती संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड
- सूक्ष्म बीमा
- मोटर यान तृतीय पक्षकार दावा प्रबंध

समिति द्वारा आयोजित बीमा और पेंशन क्षेत्रों संबंधी कार्यक्रम

- समिति ने, टेक्निकल गाइड ऑन रिस्क एंड सर्टिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ इश्योरेंस कंपनीज टेक्निकल गाइड ऑन इंटरनल/कंकरेंट ऑडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शंस ऑफ इश्योरेंस कंपनीज के संबंध में संस्थान के सदस्यों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों के लिए परस्पर क्रियाशील और गहन कार्यक्रमों का आयोजन करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए आईआरडीए के साथ संयुक्त रूप से 12 अक्टूबर, 2009, 28 नवम्बर, 2009 और 14 दिसम्बर, 2009 को क्रमशः मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में इंटरनल/कंकरेंट ऑडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शंस ऑफ इश्योरेंस कंपनीज विषय पर तीन कार्यशालाओं का आयोजन किया था, जिनमें भारी संख्या में संस्थान के सदस्यों के अलावा आईआरडीए और बीमा कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था।
- 'बीमा क्षेत्र में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के लिए उभरते वृत्तिक अवसर' विषय पर एक राष्ट्रीय सीपीई कार्यशाला का आयोजन 27 अगस्त, 2009 को चेन्नई में किया गया था और उसमें संस्थान के 280 सदस्यों ने भाग लिया था।
- 12 अक्टूबर, 2009 को मुंबई में बीमा कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों (सीएफओ/सीएमडी/सीईओ) की एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें बीमा उद्योग में जीएसटी आईएफआरएस के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों और बीमा उद्योग पर प्रत्यक्ष कर संहिता के प्रभाव विषयों पर उद्योग की चिंताओं से संबंधित उभरते मुद्दों पर चर्चा तथा विचार-विमर्श किया गया था।
- समिति प्रादेशिक परिषदों और प्रत्येक प्रादेशिक परिषद् की चयनित शाखाओं को, इन क्षेत्रों में सदस्यों और इन संबद्ध व्यक्तियों का डोमेन ज्ञान विकसित करने और बनाए रखने के लिए बीमा और पेंशन क्षेत्रों के संबंध में कार्यक्रमों के आयोजन के लिए वित्तीय, तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रही है। वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था :

क्रम सं.	संगठन/ इकाई का नाम	स्थान और तारीख	सम्मिलित किए गए विषय
1.	आईसीआई की एसआईआरसी की गुडगांव शाखा	16 मई, 2009 को गुडगांव में	<ul style="list-style-type: none"> • बीमा माध्यस्थता • पेंशन क्षेत्र में विकास • बीमा सर्वेक्षण और हानि निर्धारण (अभिलाभ नीति की हानि) • उभरते बीमा बाजार और सीए के लिए अवसर

2.	आईसीआई की सीआईआरसी की जयपुर शाखा	18 जुलाई, 2009 को जयपुर में	<ul style="list-style-type: none"> बीमा सर्वेक्षण और हानि निर्धारण बीमा दावों का निर्धारण जोखिम प्रबंध
3.	आईसीआई की सीआईआरसी की एचपी बरेली शाखा	2 अगस्त, 2009 को बरेली में	<ul style="list-style-type: none"> बीमा क्षेत्र में सीए की भूमिका बीमा सर्वेक्षण और हानि निर्धारण तृतीय पक्षकार बीमा और दावा प्रबंध साधारण बीमा कंपनियों की संपरीक्षा
4.	आईसीआई की सीआईआरसी की सहारनपुर शाखा	11 अगस्त, 2009 को सहारनपुर में	<ul style="list-style-type: none"> बीमा सर्वेक्षण और हानि निर्धारण बीमा क्षेत्र में हाल ही की घटनाएं और सीए के लिए अवसर बीमा क्षेत्र, आयकर में हाल ही की घटनाओं की दृष्टि में
5.	सीआईआरसी की सीआईआरसी की मथुरा शाखा	13 अगस्त, 2009 को मथुरा में	<ul style="list-style-type: none"> बीमा क्षेत्र में सीए की भूमिका और सदस्यों के लिए उपलब्ध वृत्तिक अवसर बीमा दावों का सर्वेक्षण और हानि निर्धारण अभिलाष नीति की हानि के विशेष संदर्भ में बीमा दलाली बीमा क्षेत्र में धन प्रतिशोधन
6.	सीआईआरसी की सीआईआरसी की रांची शाखा	23 अगस्त, 2009 को रांची में	<ul style="list-style-type: none"> साधारण बीमा कारबार के लेखांकन और संपरीक्षा संबंधी मुद्दे बीमा क्षेत्र में हाल ही की घटनाएं और सीए के लिए अवसर बीमा सर्वेक्षण और हानि निर्धारण

5.5.5 बीमा और पेंशन के क्षेत्रों में अनुसंधान क्रियाकलाप

- प्रत्यक्ष काराधान के मुद्दों पर बीमा कंपनियों से प्राप्त प्रश्नों का उत्तर संस्थान की प्रत्यक्ष कर संबंधी समिति की तकनीकी सहायता से दिया जा रहा है।

5.5.6 पीएफआरडीए के प्रयासों के लिए तकनीकी समर्थन

- समिति, आईसीआई के एक तकनीकी समूह की सहायता से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को निम्नलिखित क्षेत्रों में तकनीकी समर्थन उपलब्ध करा रही है :

- पेंशन निधि प्रबंधकों के लिए लेखांकन सनियमों का प्रारूपण ।
- पेंशन निधि प्रबंधकों से जानकारी प्राप्त करने और उसका मूल्यांकन करने के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप तैयार करना ।
- निधि प्रबंधकों के क्रियाकलापों की संपरीक्षा और पीएफआरडीए/ एनपीएस न्यास द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों और निदेशों के अनुपालन संबंधी रिपोर्ट ।
- पेंशन निधि प्रबंधकों से एकत्रित सूचना को प्राप्त करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए रिपोर्टिंग प्रारूपों को आईसीएआई के तकनीकी निदेशक के परामर्श से पीएफआरडीए को प्रस्तुत किया गया था । पीएफआरडीए ने रिपोर्टिंग प्रारूपों को स्वीकार कर लिया है और उनका पेंशन निधि प्रबंधकों से जानकारी एकत्रित करने के लिए उपयोग किया जा रहा है ।
- समिति ने पेंशन निधि प्रबंधकों के लिए लेखांकन सनियमों को, आईसीएआई के पीएफआरडीए संबंधी तकनीकी समूह द्वारा सुझाए गए उपांतरणों को करने के पश्चात् पीएफआरडीए को प्रस्तुत किया था । पीएफआरडीए ने पेंशन निधि प्रबंधकों के लिए लेखांकन संबंधी सनियमों और कार्यान्वयन के प्रति अपनी स्वीकृति को संप्रेषित किया है ।
- समिति निधि प्रबंधकों के क्रियाकलापों की संपरीक्षा के लिए और पीएफआरडीए/एनपीएस न्यास द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों और निदेशों के अनुपालन संबंधी रिपोर्ट के लिए संपरीक्षा सनियम तैयार करने हेतु आईसीएआई के संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड से समन्वय कर रही है ।
- समिति के प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् कार्यपालक समिति ने संस्थान के निःशक्तताग्रस्त सदस्यों के लिए संस्थान के विभिन्न अर्हतापश्च पाठ्यक्रमों के लिए संदेय रजिस्ट्रीकरण शुल्क में पचास प्रतिशत की सीमा तक छूट प्रदान करने का विनिश्चय किया है जिससे कि निःशक्तताग्रस्त सदस्यों को उद्योग विनिर्दिष्ट अर्हता अर्जित करने और अपने चयन के सुसंगत क्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम करने के लिए उत्प्रेरित किया जा सके ।
- बीमा कंपनियों के निवेश कृत्यों की आंतरिक/समवर्ती संपरीक्षा के संबंध में एक आलेख सीए जर्नल के जून, 2010 अंक में प्रकाशित किया गया था जिससे कि बीमा कंपनियों के निवेश कृत्यों की आंतरिक रूप से या समवर्ती रूप से संपरीक्षा करने की रीति के संबंध में जागरूकता और जानकारी का प्रसार किया जा सके ।
- तकनीकी समूह की सहायता से और तकनीकी निदेशक, आईसीएआई के परामर्श से, पेंशन निधि प्रबंधकों के लिए लेखांकन सनियम तैयार किए गए थे और उन्हें, उनपर विचार करने तथा उनका प्रयोग करने के लिए पीएफआरडीए को प्रस्तुत किया गया था ।
- समिति के सचिवालय ने बैंककारी, बीमा और पेंशन क्षेत्रों से संबंधित संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) की रायों का संकलन किया है जिससे कि इन क्षेत्रों में लेखांकन और संपरीक्षा की विशिष्टताओं को प्रदर्शित किया जा सके । ये राय ईएसी के परामर्श से वेबसाइट पर रखी जाएंगी ।
- छह दिवस की अवधि के अनुकूलन कार्यक्रम में आज्ञापक उपस्थिति बीमा और जोखिम प्रबंध पाठ्यक्रम में डिप्लोमा की पूर्णता के रूप में मानी जाती है, जिसके द्वारा तकनीकी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सदस्य, उद्योग के विशेषज्ञों से परस्पर क्रिया करके अपनी सैद्धांतिक जानकारी को वास्तविक जीवन के अनुभवों से पुष्ट कर सकें । वर्ष के दौरान समिति ने डीआईआरएम तकनीकी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सदस्यों के लिए डीआईआरएम अनुकूलन कार्यक्रमों के चार बैचों का संचालन किया था जिससे कि

सदस्य डीआईआरएम सदस्य नीचे दिए गए व्योसों के अनुसार बीमा और जोखिम प्रबंध में डिप्लोमा प्रदान किए जाने के लिए पात्र होने हेतु डीआईआरएम पाठ्यक्रम के अंतिम चरण को पूरा करने में समर्थ हो सकें ।

क्रम सं.	तारीख	स्थान
1	18-23 मई, 2009	होटल ब्राडवे, नई दिल्ली
2	5-10 अक्टूबर, 2009	सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स ट्रेनिंग कालेज (एसपीबीटी), मुंबई
3	3-8 मई, 2010	आईसीएआई सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण सह कक्ष प्रशिक्षण केन्द्र, मुंबई
4	17-22 मई, 2010	इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), नई दिल्ली

5.6 सीए फर्मों एवं लघु और मध्यम व्यवसायियों के लिए सक्षमता निर्माण संबंधी समिति

5.6.1 पर्यावलोकन

फरवरी, 2010 में पुनर्गठित सीए फर्मों के लिए सक्षमता निर्माण संबंधी समिति जो सीए फर्मों तथा लघु और मध्यम व्यवसायियों के लिए सक्षमता निर्माण संबंधी समिति के नाम से ज्ञात है, संस्थान की एक अस्थाई समिति है जिसे सीए अधिनियम, 1949 के विनियामक उपबंधों के अधीन बनाया गया है । इस समिति को स्थापित करने का उद्देश्य सीए फर्मों के समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए सीए फर्मों के सुदृढ़ीकरण और सक्षमता निर्माण को सुकर बनाना और सीए फर्मों के समेकन के लिए व्यापक दिशानिर्देश उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनकी सक्षमता को मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की अवधारणा तैयार करना और उनका कार्यान्वयन करना है । इस प्रकार समिति का उद्देश्य लघु और मध्यम व्यवसायियों के साथ-साथ सीए फर्मों का, उनके व्यवसायिक पोर्टफोलियों को पुनरुज्जीवित करने के लिए उनका सुदृढ़ीकरण करना है ।

समिति ने नेटवर्किंग, सामेलन और व्यवसाय के निगम रूप को स्थापित करने (एमसीएस कंपनी) के माध्यम से फर्मों के सुदृढ़ीकरण के संबंध में जागरूकता लाने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया है ।

5.6.2 मुख्य क्रियाकलाप :

- आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत 35 नेटवर्कों की, उन्हें स्थापित करने वाली 112 फर्मों को प्रतिक्रिया प्ररूप भेजकर स्थिति का पुनर्विलोकन किया था और उसके द्वारा उनके नेटवर्कों के कार्यकरण में उनके सामने आने वाली चुनौतियों/रूकावटों की पहचान की थी ।
- दिलचस्पी लेने वाले व्यवसायस्त सदस्यों के बीच एक सीए नेटवर्किंग पोर्टल www.caconnect.co.in के माध्यम से नेटवर्किंग, सामेलनों आदि के लिए पहचान और परस्पर क्रिया को सुकर बनाया था ।
- समिति ने अंत उपयोग्यताओं तक सुगम पहुंच के लिए संस्थान की वेबसाइट पर भारत में रजिस्ट्रीकृत नेटवर्कों के अध्ययन व्यापक डाटा की उपलब्धता को सुनिश्चित किया था ।
- समिति ने नेटवर्क, सामेलन - निर्विलयन और निगम वृत्ति प्ररूप संबंधी दिशानिर्देशों के पुनरीक्षण के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया था जिससे कि विद्यमान मार्गदर्शनों में बाधाओं की पहचान करके उन्हें दूर किया जा सके ।

- समिति ने सीए जर्नल में सक्षमता निर्माण संबंधी एक “प्रश्नावली” निकाली है जिसे संस्थान की वेबसाइट पर भी रखा गया था। उसके संबंध में सदस्यों से प्रतिक्रिया प्राप्त की जा रही है और अंतःनिवेशों के विश्लेषण पर विचार किया जा रहा है।
- समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सीए फर्मों की सक्षमता निर्माण संबंधी कार्यशालाओं की एक श्रृंखला सम्मिलित है।

5.6.3 समिति की अन्य पहलें

- समिति ने संस्थान की वृत्तिक विकास समिति के साथ संयुक्त रूप से बैंक शाखा संपरीक्षा 2009-10 नामक एक ई-पुस्तक जारी की थी जिसे बैंक संपरीक्षा के लिए पैनलबद्ध सभी सीए फर्मों को परिचालित किया गया था। इस पुस्तक में किसी बैंक शाखा की संपरीक्षा के लिए पूर्ण जानकारी तथा लेखांकन मानक नमूने अंतर्विष्ट हैं। सदस्यों में इस पुस्तक की काफी सराहना हुई है।
- समिति ने केंडीओसी सॉफ्टवेयर से युक्त एक संपरीक्षा टूल किट भी जारी की है, जिसका परिचालन निःशुल्क रूप से सभी सदस्यों और सीए फर्मों के बीच किया गया है। यह सॉफ्टवेयर उसमें अंतःनिर्मित तैयार लेखांकन मानक नमूनों के माध्यम से संपरीक्षा रिपोर्टों का सुगम और शीघ्रता से तैयार किया जाना सुकर बनाता है जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है और सेवा प्रदान किए जाने के समय में कमी आती है। यह सॉफ्टवेयर सीए फर्मों में दस्तावेजों के प्रबंध और अनुसंधानीय व्यवहारों में भी सहायता प्रदान करता है।
- समिति ने सभी सदस्यों के लिए एक बहुत ही उचित दर पर कैपिटलाइन टीपी कारपोरेट डाटाबेस (आनलाइन पाठ) की भी व्यवस्था की है, जो 24x7 पद्धति पर उनकी सुविधानुसार कंपनी के डाटाबेस तक पहुंच में सहायता करेगा। इस डाटाबेस का उपयोग अंतरण लागत को सस्ता और समतुल्य बनाएगा। सदस्यों ने इसे अनेक मामलों में काफी उपयोगी पाया है।
- एसएमपी की शिकायतों को दूर करने और उनकी व्यवहारिक कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए समिति सीए फर्मों के भागीदारों के साथ परस्पर क्रियाशील सत्रों का आयोजन करने का और नए वृत्तिक अवसरों की खोज करने के लिए विचार-विमर्श सत्रों के आयोजन का प्रस्ताव करती है। ऐसे कार्यक्रमों की श्रृंखला में, आगामी बैठक 12 जुलाई, 2010 को चेन्नई में और अगस्त, 2010 में दिल्ली में की जानी प्रस्तावित है।
- समिति ने सीए फर्मों के समेकन के फायदों के संबंध में सदस्यों को जागरूक करने के लिए नेटवर्किंग और व्यवसाय के निगम रूप के संबंध में बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों पर तैयार किए हैं। इन बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों को समिति के वेबपोर्टल पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
- एसएमपी के लिए वृत्तिक मुद्दों का समाधान करने हेतु समिति ने कम शुल्क के निबंधनों में न्यूनतम संपरीक्षा फीस की परिसीमा, किसी कानूनी संपरीक्षक को आंतरिक संपरीक्षक बनने के लिए निर्बंधित करने वाली स्वतंत्रता संबंधी मार्गदर्शक टिप्पणों और संपरीक्षा वृत्ति के गैर प्रमाणीकृत क्षेत्रों को सम्मिलित करने वाले विनियामक उपायों के पुनर्विलोकन की प्रक्रिया भी प्रारंभ की है।
- समिति राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से एसएमपी और सीए फर्मों को उनकी कार्यालय अवसंरचना की स्थापना और विस्तार के लिए कम ब्याज दर वाली बिना प्रतिभूति की विशेष ऋण स्कीम के अधीन वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कार्यरत है।
- समिति ने सीए फर्मों के भागीदारों के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा संबंधी चिंताओं का ध्यान रखते हुए समूह बीमा और पेंशन फायदे उपलब्ध कराने के लिए भी उपाय प्रारंभ किए हैं। यह भागीदारों को फर्म के साथ सहबद्धता बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा।
- समिति आईएफएसी और अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा विहित नेटवर्किंग संबंधी उपबंधों के संदर्भ से एसएमपी और मध्यम आकार की सीए फर्मों को विनियमित करने और उनका एलएलपी की दिशा में

संवर्धन करने तथा उनके विकास को तथा ब्रांड इक्विटी के साथ उनकी बहुस्थानीय उपस्थिति को सुकर बनाने के लिए उनकी सक्षमताएं तैयार करने के लिए भी प्रयासरत है।

5.7 सतत् वृत्तिक शिक्षा संबंधी समिति

वर्ष के दौरान, सतत् वृत्तिक शिक्षा संबंधी समिति (सीपीईसी) ने सीपीई कार्यक्रमों के प्रभावी आयोजन तथा साथ ही सीपीई कार्यक्रमों को अधिकाधिक सदस्यों तक पहुंचाने के लिए अनेक पहलें और महत्वपूर्ण विनिश्चय किए हैं।

5.7.1 सीपीई कार्यक्रमों को सरल और कारगर बनाने के लिए किए गए उपाय :

देशभर में सीपीई कार्यक्रमों के आयोजन को सरल और कारगर बनाने के लिए निम्नलिखित विनिश्चय किए गए हैं :-

- क) पूर्व प्रथा के अनुसार (यदि कोई आयोजन संयुक्त रूप से दो पीओयू द्वारा कराया जाता है, उसे कार्यक्रम आयोजित करने वाले पीओयू द्वारा सीपीई पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा), यथापूर्वस्थिति बनाए रखी जानी चाहिए और संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रमों के संबंध में सीपीई पोर्टल पर केवल अध्ययन सर्कलों में से किसी एक द्वारा ही ब्यौरे अपलोड करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- ख) पीओयू को सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख प्रणालीबद्ध रीति में रखना चाहिए और संबंधित कार्यक्रम के समाप्त होने के 48 घंटे के भीतर ही उपस्थिति संबंधी डाटा को सीपीई पोर्टल पर अपलोड करना चाहिए।
- ग) सही और सत्य उपस्थिति अभिलेख रखे जाने के लिए कड़ी मानीटरी की जानी चाहिए।
- घ) पीओयू को उपस्थिति अभिलेखित करने में और बैठकों के आयोजन की प्रक्रिया में सुधारों के लिए मूल्यवान सुझाव भेजने चाहिए।
- ङ) कार्यक्रमों का संचालन ऐसी रीति में किया जाना चाहिए जिससे कि सदस्यों के यात्रा समय को न्यूनतम रखा जाए।
- च) अध्ययन सर्कलों को अधिमानतः अपने कार्यक्रमों का आयोजन अपनी अधिकारिता के दो किलोमीटर के भीतर करना चाहिए।
- छ) अध्ययन सर्कलों को केवल अर्धदिवसीय या अधिकतम एक दिन के कम अवधि वाले कार्यक्रमों का ही संचालन करना चाहिए।
- ज) बायोमीट्री उपस्थिति प्रारंभ करने की सलाह पर विचार किया जाए।
- झ) सीपीई समिति ने अध्ययन सर्कलों के संयोजक/उपसंयोजक के पद की कालावधि के संबंध में एक महत्वपूर्ण विनिश्चय किया है। तदनुसार यह विनिश्चय किया गया है कि संयोजक/उपसंयोजक के रूप में तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति उस अध्ययन सर्कल का संयोजक/उपसंयोजक नहीं बना रहेगा। इसके अतिरिक्त, संयोजक/उपसंयोजक के लिए निर्वाचन प्रादेशिक परिषद्/शाखाओं के पदधारियों के निर्वाचन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुरूप होना चाहिए।

5.7.2 सदस्यों के लिए आज्ञापक सीपीई अपेक्षाएं

तीन वर्षों के ब्लाक (1.1.2008 से 31.12.2010) के लिए आईसीएआई के सदस्यों के लिए सीपीई क्रेडिट अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं :

- ऐसे सभी सदस्यों से, जो व्यवसाय का प्रमाणपत्र धारित कर रहे हैं (ऐसे सदस्यों को छोड़कर जो विदेशों में निवास कर रहे हैं), जब तक कि उन्हें छूट प्रदान न की जाए, यह अपेक्षा की जाती है कि वे :
 - (क) 3 वर्ष की प्रत्येक रोलिंग अवधि में न्यूनतम 90 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें, जिनमें से 60 सीपीई क्रेडिट घंटे ढांचागत पठन के होंगे।

(ख) प्रत्येक वर्ष में ढांचागत पठन के न्यूनतम 20 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।

- ऐसे सभी सदस्यों से, जो व्यवसाय का प्रमाणपत्र धारित नहीं कर रहे हैं या जो विदेशों में निवास कर रहे हैं (चाहे वे व्यवसाय का प्रमाणपत्र धारित कर रहे हैं अथवा नहीं), जब तक कि उन्हें छूट प्रदान न की जाए, यह अपेक्षा की जाती है कि वे :

(क) 3 वर्ष की प्रत्येक रोलिंग अवधि में ढांचागत/गैरढांचागत पठन के न्यूनतम 45 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।

(ख) प्रत्येक वर्ष में ढांचागत/गैरढांचागत पठन के न्यूनतम 10 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।

- ऐसे सभी सदस्यों से, (60 वर्ष से अधिक आयु के) जो व्यवसाय का प्रमाणपत्र धारित कर रहे हैं जब तक कि उन्हें छूट प्रदान न की जाए, यह अपेक्षा की जाती है कि वे :

(क) 3 वर्ष की प्रत्येक रोलिंग अवधि में (ढांचागत/गैर ढांचागत) न्यूनतम 70 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।

(ख) प्रथम वर्ष, अर्थात् 2008 में ढांचागत/गैर ढांचागत के न्यूनतम 10 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।

(ग) दूसरे और तीसरे वर्ष, अर्थात् 2009 और 2010 में ढांचागत/गैर ढांचागत के न्यूनतम 20 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।

- ऐसे सभी सदस्यों से, (60 वर्ष से अधिक आयु के) जो व्यवसाय का प्रमाणपत्र धारित नहीं कर रहे हैं जब तक कि उन्हें छूट प्रदान न की जाए, यह अपेक्षा की जाती है कि वे :

(क) 3 वर्ष की प्रत्येक रोलिंग अवधि में (ढांचागत/गैर ढांचागत) न्यूनतम 35 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।

(ख) प्रथम वर्ष, अर्थात् 2008 में ढांचागत/गैर ढांचागत के न्यूनतम 5 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।

(ग) दूसरे और तीसरे वर्ष, अर्थात् 2009 और 2010 में ढांचागत/गैर ढांचागत के न्यूनतम 10 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।

असंरचित सीपीई पठन क्रियाकलापों के संबंध में एक सलाह भी जारी की गई है। उक्त सलाह को संस्थान की वेबसाइट (www.icaai.org) और सीपीई पोर्टल (www.cpeicai.org) पर रखा गया है। यह सलाह सदस्यों के लिए मार्गदर्शन और निदेश का प्रयोजन सिद्ध करती है तथा इसमें असंरचित पठन क्रियाकलापों और उन्हें पूरा किए जाने संबंधी ब्यौरे सम्मिलित हैं।

5.7.3 घरेलू कार्यपालक विकास कार्यक्रम (आईएचडीपी) का आयोजन

समिति क्वालिटी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे कि पदधारियों के कौशल को पैना बनाया जा सके और कारबार गृहों की आवश्यकताओं को उनके हित क्षेत्रों में सस्ती लागत पर पूरा किया जा सके। समिति प्रत्येक मास देश भर में विभिन्न स्थानों पर समवर्ती सुसंगतता और विशेषकर आईएफआरएस के विषयों पर 4 से 5 ऐसे आयोजन करती है। इस वर्ष के दौरान दो हजार से अधिक पदधारियों ने अपने ज्ञान को अध्ययन बनाने के लिए ऐसे पाठ्यक्रमों का फायदा उठाया था।

5.7.4 टेली-कांफ्रेंसिंग कार्यक्रम

काफी लंबे समय से टेली-कांफ्रेंसिंग ज्ञान के प्रसार के लिए कम लागत की पद्धतियों में से एक है। वर्तमान समय में, समिति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), दिल्ली के सहयोग से चार्टर्ड एकाउंटेंट्स वृत्ति से सुसंगत और संबंधित विषयों पर एक या दो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करती है। अभी तक सम्मिलित किए गए विषयों में, पूंजी अभिलाषों की संगणना और सर्वेक्षण, तलाशी और अभिग्रहण आयकर अधिनियम के अधीन हानियों का मुजरा और उन्हें अग्रनीत करना - व्यवहारिक मुद्दे और सीआईटी (अपील) तथा आईटीएटी के समक्ष अपील प्रक्रियाएं, आयकर अधिनियम और एफसीआर अधिनियम के विशेष प्रतिनिर्देश से गैर लाभकारी संगठनों से संबंधित मुद्दों का विधिक अनुपालन और सावधि ऋण तथा कार्यकारी पूंजी प्राप्त करने के प्रतिनिर्देश से परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की कला, सीए वृत्ति के लिए चुनौतियां और आचार संबंधी अपेक्षाएं तथा वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 -

खंडवार विश्लेषण, लेखांकन मानकों के अनुपालन के संबंध में व्यवहारिक उपधारणा और पूंजी तथा वित्तीय बाजारों में चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए वृत्तिक अवसर, प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2009 - एक गहन विश्लेषण और कर व्यवहारों पर उसका प्रभाव, आय की विवरणी प्रस्तुत करना तथा निर्धारण प्रक्रिया - व्यवहारिक मुद्दे, आईएफआरएस के साथ अभिसरण, वित्त विधेयक, 2010 - खंडवार विश्लेषण, निगम शासन में सीए की भूमिका, बैंक की शाखाओं की कानूनी संपरीक्षा, पूंजी बाजारों में धन का सृजन है।

सदस्यों से निरंतर प्राप्त होने वाली उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, सीपीई समिति ने टेली-कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रमों की सीडी बनाना प्रारंभ कर दिया है। सदस्य प्रति यूनिट 50 रुपए के संदाय पर इन सीडीयों को प्राप्त कर सकते हैं और इन्हें देखकर सदस्य दो घंटे (गैर ढांचागत) सीपीई क्रेडिट का दावा भी कर सकते हैं।

5.7.5 आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रम

- लेखांकन/संपरीक्षा मानकों तथा आचार-संहिता पर सभी पांच क्षेत्रों में 9 जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था जिनकी मेजबानी विभिन्न शाखाओं ने की थी।
- 17 अप्रैल, 2010 को चेन्नई में कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से “निगम शासन, पूंजी बाजार और निवेशकों की संरक्षा” विषय पर एक बृहत ‘वृत्तिक उत्कृष्टता’ सीपीई कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

5.7.6 सीपीई कलेण्डर

समिति प्रत्येक वर्ष, पीओयू के लिए सीपीई कार्यक्रमों के संचालन में एकसमानता बनाए रखने को सुकर बनाने के विचार से इस क्षेत्र में होने वाली तीव्र घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सीपीई कार्यक्रमों के लिए विषयों का एक कलेण्डर जारी करती है। वर्ष 2010-2011 के लिए जारी उक्त कलेण्डर में निम्नलिखित बृहत शीर्षों के अधीन आने वाले अनेकों आबद्धकर विषय सम्मिलित थे (क) लेखांकन और संपरीक्षा, (ख) लागत और वित्तीय प्रबंध, (ग) सूचना प्रौद्योगिकी, (घ) कराधान, (ङ) कारबार प्रबंध, (च) निगम विधियाँ और निगम शासन, (छ) आचार-संहिता, (ज) वित्तीय और पूंजी बाजार, (झ) बीमा और जोखिम प्रबंध, (ञ) लोक वित्त, (अ) सॉफ्ट कौशल और अन्य के साथ, परामर्श और सलाहकारी सेवाओं तथा सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित अन्य विषय। पूर्वोक्त कलेण्डर, जिसमें वृत्तिक और समकालीन दिलचस्पी के वैकल्पिक विषय भी अंतर्विष्ट हैं, संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

5.8 निगम विधियों और निगम शासन संबंधी समिति

वर्ष 2009-2010 के लिए गठित निगम विधियों संबंधी समिति और निगम शासन संबंधी समिति को समामेलित करके वर्ष 2010-2011 के लिए एक नई समिति अर्थात् निगम विधियों और निगम शासन संबंधी समिति का गठन किया गया है। उक्त संबंधित समितियों द्वारा की गई पहलें निम्नानुसार हैं :

5.8.1 निगम विधि संबंधी समिति

• सुझाव/प्रतिवेदन

- कारपोरेट कार्य मंत्रालय को निम्नलिखित के संबंध में सुझाव/प्रतिवेदनों का प्रस्तुत किया जाना :
- प्रबंधकीय पारिश्रमिकों संबंधी प्रस्तावित सनियमों पर सुझाव।
- कंपनियों को एक समयबद्ध रीति में परिसमापन करने को सुकर बनाने के लिए कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 पर सुझाव।
- कंपनी विधेयक, 2009 पर सुझाव।

• दिल्ली के शासकीय परिसमापक के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण

समिति ने 20 अप्रैल, 2009 से 1 मई, 2009 के दौरान दिल्ली के शासकीय परिसमापक के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस संबंध में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए पृष्ठभूमि सामग्री तैयार तथा वितरित की गई थी। माननीय न्यायमूर्ति गीता मिश्र ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। उसके लिए संकाय के रूप में प्रमुख चार्टर्ड एकाउंटेंटों और समिति के अध्ययन समूह सदस्यों की सेवाओं का उपयोग किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिवस को पदधारियों को भाग लेने संबंधी प्रमाणपत्र प्रदान किए गए थे।

• सीमित दायित्व भागीदारी पर कार्यशाला

समिति ने जानकारी प्रदान करने, नीति विषयक मुद्दों के प्रसार ई-पोर्टल मुद्दों और एलएलपी के अन्य प्रचालनात्मक पहलुओं पर संस्थान के सदस्यों के लिए कोलकाता और कोयम्बटूर में सीमित दायित्व भागीदारी पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था। इस कार्यशाला का उद्देश्य अंत उपयोक्ताओं को एलएलपी अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों से संबंधित मुद्दों पर जानकारी देना था।

• निगम कार्य संबंधी मानक

समिति ने सदस्यों की समुचित मार्गदर्शन संबंधी आवश्यकता को मान्यता प्रदान करते हुए निगम कार्य संबंधी मानक तैयार करने के लिए उपाय प्रारंभ किए हैं। कारबार मूल्यांकन, संपरीक्षकों की नियुक्ति, सेवानिवृत्ति तथा हटाया जाना तथा एमसीए-21 प्रमाणन विषयों पर तीन निगम कार्य संबंधी मानक जारी किए गए हैं।

• मूल्यांकन पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

समिति ने आईसीएआई के सदस्यों और सीए की फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए नवम्बर, 2008 में मूल्यांकन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रारंभ किया था। वर्ष के दौरान दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में इस पाठ्यक्रम के 9 बैचों का आयोजन किया गया था। 429 सदस्यों ने सफलतापूर्वक इस पाठ्यक्रम को पूरा किया था।

• अध्ययन समूह

- समिति ने निगम विधियों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में निम्निखित अध्ययन समूहों का गठन किया था :
- प्रबंधकीय पारिश्रमिक के लिए प्रस्तावित सनियमों पर सुझाव देने के लिए अध्ययन समूह।
- कंपनी विधेयक, 2009 संबंधी अध्ययन समूह।
- कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 संबंधी अध्ययन समूह।

5.8.2 निगम शासन संबंधी समिति :

निगम शासन संबंधी समिति को स्थापित करने का आधारीक प्रयोजन यह था कि निगम शासन के समुचित स्तर को बढ़ावा दिया जाए, बेंचवार अधिकथित करने में सहायता उपलब्ध कराई जाए और वैश्विकरण को ध्यान में रखते हुए निगमों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों/समस्याओं के बारे में सक्रिय रूप से अनुसंधान किया जाए।

समिति निगम शासन के विभिन्न संघटकों में जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों/संगोष्ठियों का आयोजन करती रही है। देशभर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करने में समिति के प्रमुख क्षेत्रों में से एक क्षेत्र “स्वतंत्र निदेशक” है। ऐसे कुछ विषयों में, जिनपर समिति सम्मेलनों/संगोष्ठियों/विचार-गोष्ठियों का आयोजन करती है, निगम शासन की बैंच मार्किंग, निगम शासन-केन्द्र बिन्दु के रूप में, निगम शासन-स्तर में सुधार करना, निगम शासन-संवहनीय विकास की कुंजी, संपरीक्षा समिति के माध्यम से निगम शासन और निगम शासन में सीए की भूमिका सम्मिलित हैं।

समिति निगम शासन संबंधी राष्ट्रीय फाउंडेशन (एनएफसीजी) जिसकी स्थापना कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई है, से संबद्ध है और वह बहुधा समिति के कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है। एक अन्य प्रमुख पहल के भागरूप में समिति ने एनजीओ को बृहत्तर पारदर्शिता और बेहतर आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित करने में सहायता करने के लिए “कोड ऑफ गवर्नेंस फॉर एनजीओ” नामक एक प्रकाशन निकाला है।

• **आयोजित किए गए कार्यक्रम :**

वर्ष के दौरान, समिति ने निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया था :

- नवम्बर, 2009 में कोयम्बटूर में एनएफसीजी के साथ भागीदारी में निगम शासन संबंधी एक राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसकी मेजबानी आईसीएआई की एसआईआरसी की कोयम्बटूर शाखा ने की थी।
- दिसम्बर, 2009 में (‘भारत निगम सप्ताह’ के दौरान) भुवनेश्वर में एनएफसीजी के साथ भागीदारी में निगम शासन संबंधी एक राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसकी मेजबानी आईसीएआई की ईआईआरसी की भुवनेश्वर शाखा ने की थी।
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा 14-21 दिसम्बर, 2009 के दौरान मनाए जाने वाले ‘भारत निगम सप्ताह’ के भागरूप में, आईसीएआई ने एमसीए के साथ संयुक्त रूप से आईसीएआई की संबंधित शाखाओं की मेजबानी में और नीचे उल्लिखित स्थानों पर तथा विषयों पर अर्धदिवसीय राष्ट्रीय विचार सभा का आयोजन किया था।

स्थान	विषय
जयपुर	सामाजिक सशक्तिकरण के लिए निगम शासन
बड़ौदा	निगम शासन - संवहनीय विकास की कुंजी
एर्नाकुलम	सामाजिक सशक्तिकरण के लिए निगम शासन
चंडीगढ़	निगम शासन - संवहनीय विकास की कुंजी
नागपुर	निगम शासन - शैयस्थारक मूल्य का सृजन और प्रबंध।

- जनवरी, 2010 में, मुंबई में आईसीएआई की उद्योग में लगे सदस्यों की समिति (सीएमआईआई) के साथ संयुक्त रूप से निगम शासन की बेंचमार्किंग विषय पर एक विचार सभा।
- फरवरी, 2010 में इंदौर में एनएफसीजी के साथ भागीदारी में निगम शासन संबंधी एक राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसकी मेजबानी आईसीएआई की सीआईआरसी की इंदौर शाखा ने की थी।
- **पहलों/परियोजनाओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :**
 - निगम शासन संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विनियामकों के साथ परस्पर क्रियाएं।
 - निगम शासन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रारंभ करना।
 - निगम शासन संबंधी आईसीएआई संहिता तैयार करने के लिए आईसीएआई विशेषज्ञ सलाहकार समूह का गठन जिसमें विख्यात विशेषज्ञ सम्मिलित हों।
 - अनुसंधान - भारतीय निगम जगत में निगम शासन की सफलता/असफलता संबंधी मामला अध्ययन।
 - स्वतंत्र निदेशकों और संपरीक्षा समिति की भूमिका और उत्तरदायित्वों पर प्रकाशन निकालना।
 - निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
 - जलवायु में परिवर्तन/ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन क्रेडिट, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (एमडीजी) आदि जैसे उमस्ते दिलचस्पी के क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन।

- स्वतंत्र निदेशकों संबंधी कार्यशालाएं आयोजित करना ।
- एनएफसीजी के साथ भागीदारी में राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन करना ।

5.8.3 पुनःगठित निगम विधि और निगम शासन संबंधी समिति द्वारा किए गए क्रियाकलापों/पहलों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

समिति ने 11 मार्च, 2010 को हुई अपनी पहली बैठक में कंपनी विधेयक, 2009 संबंधी विषयों पर ब्यौरेवार चर्चा की थी और उस पर सुझावों को अंतिम रूप प्रदान किया था । इस प्रकार अंतिम रूप दिए गए सुझावों को संस्थान द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय और वित्त संबंधी संसदीय स्थाई समिति को अग्रेषित किया गया था । संसदीय स्थाई समिति ने संस्थान को एक मौखिक सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया है ।

1. सुझाव/प्रतिवेदन

क) कंपनी विधेयक, 2009

मई, 2010 में कंपनी विधेयक, 2009 पर आईसीएआई के सुझावों के संबंध में वित्त संबंधी संसदीय स्थाई समिति के समक्ष आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने एक मौखिक सुनवाई प्रस्तुत की थी ।

ख) निगम शासन स्वैच्छिक दिशानिर्देश, 2009

समिति ने इस दस्तावेज के विभिन्न पहलुओं पर ब्यौरेवार विचार-विमर्श किया था और साथ ही उसकी तुलना कंपनी विधेयक, 2009 के सूचीकरण करार संबंधी खंड 49, श्री नरेश चंद्रा की अध्यक्षता वाले सीआईआई कार्यबल की सिफारिशों और निगम शासन ढांचे को सुदृढ़ करने संबंधी आईसीएसआई की सिफारिशों के साथ की थी । समिति की टीका-टिप्पणियाँ/सुझावों के आधार पर आईसीएआई की ओर से एक औपचारिक प्रतिक्रिया दस्तावेज तैयार करके एमसीए को प्रस्तुत किया जाएगा ।

ग) प्रारूप अंतरराष्ट्रीय मानक आईएसओ 26000 (सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी मार्गदर्शन)

समिति उपरोक्त दस्तावेज के संबंध में एमसीए को प्रस्तुत किए जाने के लिए अपनी टीका-टिप्पणियाँ/सुझाव तैयार कर रही है ।

2. एमसीए 21 ई-शासन कार्यक्रम के अधीन प्रमाणीकृत फाइलिंग केन्द्र (सीएफसी) के लिए नवीकृत स्कीम

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने सीएफसी में नए रजिस्ट्रीकरण और विद्यमान सीएफसी के लिए सदस्यता पुनःप्रारंभ करने/नवीकृत करने के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के संग्रहण, उनपर कार्यवाही करने तथा उनका सत्यापन करने के लिए आईसीएआई की पहचान की है ।

चल रही पहलें/परियोजनाएं

- एनएफसीजी के साथ संयुक्त कार्यक्रमों के संचालन के लिए वर्ष 2010-2011 के लिए कार्य योजना :
समिति ने निगम शासन संबंधी राष्ट्रीय फाउंडेशन (एनएफसीजी) के साथ संयुक्त कार्यक्रमों के संचालन के लिए वर्ष 2010-2011 के लिए कार्य योजना तैयार की है ।
- निगम विधियाँ और निगम शासन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विनियामकों के साथ परस्पर क्रिया ।
- पब्लिक सेक्टर उद्यमों के लिए निगम शासन व्यवहारों का प्रकाशन ।
- पूर्वी क्षेत्र में सीमित दायित्व भागीदारी संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन ।
- बीमाकिक मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ।
- निगम शासन और स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका तथा अन्य संबद्ध विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन ।

- ईजी एक्जीट स्कीम और कंपनी विधि समझौता स्कीम के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन ।

5.9 प्रत्यक्ष कर समिति

5.9.1 केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को प्रतिवेदन

समिति ने सीबीडीटी को निम्नलिखित प्रतिवेदन किए हैं :

- (i) समिति ने इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रतिवेदन किया कि क्या टीडीएस के संबंध में भेजी जाने वाली रकम को पुराने चालान 281 का उपयोग करते हुए भेजा जा सकता है क्योंकि नए प्ररूप सं. 17 को मंत्रालय की वेबसाइट के संदाय गेटवे पर अपलोड नहीं किया गया था ।
- (ii) प्रतिदाय के मामलों में संवीक्षा निर्धारण को समय पर पूरा करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र समुचित उपाय करने, अधिमानी रूप से ऐसे निर्धारणों को पूरा करने के लिए अंतिम तारीख नियत करते हुए, के लिए समिति द्वारा सीबीडीटी को अनुरोध किया गया है । विकल्प के रूप में यह सुझाव दिया गया था कि इस शर्त को हटा दिया जाए कि प्रतिदाय ऐसे निर्धारण के पूरा होने के पश्चात् ही मंजूर किया जाएगा ।
- (iii) सीबीडीटी द्वारा जारी तारीख 21.5.2009 के परिपत्र के कारण निर्धारितियों को कुछ परेशानियां और व्यवहारिक कठिनाइयां हुई हैं और तदनुसार निम्नलिखित के संबंध में समुचित अनुदेश जारी करने का अनुरोध किया गया था :
 - (क) पूर्व के अनुसार निर्धारिती को, निर्धारिती पर अधिकारिता रखने वाले संबंधित निर्धारण अधिकारियों को प्ररूप आईटीआर-V प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए । आयकर विभाग से यह अपेक्षा की जाए कि वह इन प्ररूपों का संग्रहण करके उन्हें बंगलोर कार्यालय को भेजे ।
 - (ख) निर्धारिती को, उस मास के, जिसमें इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी प्रस्तुत की गई है, अंत से 30 दिन के भीतर आईटीआर-V प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए ।
- (iv) स्रोत पर निम्न कटौती या कटौती न करने के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त करने में सामने आने वाली मुश्किलों और व्यवहारिक कठिनाइयों पर विचार करने के लिए सीबीडीटी को अनुरोध किया गया है ।
- (v) सीबीडीटी को यह अनुरोध करते हुए एक प्रतिवेदन फाइल किया गया था कि वे समुचित मामलों में आयकर की विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख में उचित विस्तारण पर विचार करें ।
- (vi) चूंकि यह देखा गया था कि निर्धारण अधिकारी द्वारा आय की विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख के निकट बड़ी संख्या में मामलों की सुनवाई नियत की गई है, जो निर्धारितियों के लिए कठिनाई उत्पन्न करता है । सीबीडीटी को यह सुझाव दिया गया था कि वह निर्धारण अधिकारियों से अनुरोध करें कि वे आयकर की विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख के निकट मामलों की सुनवाई नियत न करें और जहां मामलों की तारीख पहले ही नियत कर दी गई है वहां उन्हें किसी पश्चातवर्ती तारीख को आस्थगित किया जाए ।
- (vii) सीबीडीटी को इस प्रभाव का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था कि वह इस तथ्य का सत्यापन करें कि कर संपरीक्षा किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा की गई है । यह सुझाव दिया गया था कि आईटीआर में एक ऐसा स्तंभ होना चाहिए, जिसमें कर संपरीक्षक से यह अपेक्षा की जाए कि वह यह प्रमाणित करें कि उसके द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट तारीख को कर संपरीक्षा की गई है या विकल्प के रूप में यह सुझाव दिया गया था कि आयकर विवरणी के साथ किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा अंकीय रूप से हस्ताक्षरित कर संपरीक्षा रिपोर्ट फाइल की जानी चाहिए ।

5.9.2 कारपोरेट कार्य मंत्रालय को अंतःनिवेश

समिति ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय को कर संपरीक्षा के क्षेत्र में दुर्यवहारों को रोकने के लिए आईसीएआई द्वारा किए गए उपायों से संबंधित ब्यौरेवार उत्तर प्रस्तुत किया था।

5.9.3 बजटपूर्व ज्ञापन - 2009 की प्रस्तुती

समिति ने बजटपूर्व ज्ञापन - 2009 तैयार किया था, जिसमें प्रत्यक्ष करों के संबंध में संस्थान के सुझाव अंतर्विष्ट थे और उसे माननीय वित्त मंत्री और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्यों को प्रस्तुत किया गया था।

5.9.4 बजट अवलोकन सत्र

वर्ष 2009-10 में दो संघीय बजट, अर्थात् 6 जुलाई, 2009 को संघीय बजट, 2009 और 26 फरवरी, 2010 को संघीय बजट, 2010 प्रस्तुत किए गए थे।

समिति ने इन दोनों अवसरों पर, अप्रत्यक्ष कर समिति और अंतरराष्ट्रीय कराधान समिति के साथ संयुक्त रूप से बजट अवलोकन सत्रों का आयोजन किया था। इन सत्रों में प्रत्यक्ष कर समिति, अप्रत्यक्ष कर समिति, अंतरराष्ट्रीय कराधान समिति के सदस्यों तथा परिषद् सदस्यों और वृत्ति के प्रमुख सदस्यों ने भाग लिया था। सदस्यों और आमंत्रितियों ने संबंधित वित्त विधेयकों के विभिन्न खंडों पर विचार-विमर्श किया था और इन बजटों के संबंध में संस्थान के मतों के ब्यौरे प्रस्तुत करते हुए प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गई थी।

5.9.5 बजट 2009 और 2010 - जर्नल के लिए लेख

समिति ने वृत्ति के विख्यात सदस्यों से प्रत्यक्ष करों से संबंधित बजट प्रस्ताव - 2009 और 2010 पर लेख आमंत्रित किए थे। संबंधित लेखों को संस्थान के जर्नल - दि चार्टर्ड एकाउंटेंट में प्रकाशित किया गया था, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित थे :

उपहार के कराधान के लिए नए उपबंध

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 - प्रत्यक्ष कर की साधारण विशिष्टियां

वित्त विधेयक, 2010 - प्रत्यक्ष कर की साधारण विशिष्टियां

वित्त विधेयक, 2010 - एलएलपी और एमएटी में संपरिवर्तन में परिवर्तन करने के लिए प्रस्ताव

वित्त विधेयक, 2010 द्वारा कटौतियों में संशोधन संबंधी विवादक

संघीय बजट में उपयोक्ता मित्र प्रस्ताव

5.9.6 संघीय बजट, 2009 संबंधी कार्यशालाएं

• 6 जुलाई, 2009 को प्रस्तुत संघीय बजट 2009

समिति ने 17 जुलाई, 2009 को अप्रत्यक्ष कर समिति और अंतरराष्ट्रीय कराधान समिति के सहयोग से संघ बजट-2009-10 पर एक कार्यशाला का आयोजन किया था। अन्य के साथ, श्री एस.एस.एन. मूर्ति, अध्यक्ष, सीबीडीटी, श्री आशुतोष दीक्षित, संयुक्त सचिव (टीपीएल-2), सीबीडीटी और श्री आनंद केडिया, निदेशक (टीपीएल 3 और 4), सीबीडीटी ने इस कार्यशाला की शोभा बढ़ाई थी। उद्योग के वरिष्ठ वृत्तिकों ने भी कार्यशाला में भाग लिया था। इस कार्यशाला पर एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी।

• 26 फरवरी, 2010 को प्रस्तुत संघीय बजट 2010

समिति ने 23 मार्च, 2010 संघ बजट 2010-11 के प्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्तावों पर एक कार्यशाला का आयोजन किया था। अन्य के साथ, श्री आशुतोष दीक्षित, संयुक्त सचिव (टीपीएल-1), सीबीडीटी, श्री सुनील गुप्ता, संयुक्त सचिव (टीपीएल-2), सीबीडीटी, श्री मुनीश कुमार, निदेशक (टीपीएल-2), सीबीडीटी और श्री राजेश कुमार

भूत, निदेशक (टीपीएल-3), सीबीडीटी ने इस कार्याशाला की शोभा बढ़ाई थी। उद्योग के वरिष्ठ वृत्तिकों ने भी कार्यशाला में भाग लिया था।

5.9.7 संघीय बजट 2010 का सीधे वेबकास्ट और कमेन्ट्री

समिति ने 26 फरवरी, 2010 को सीधे वेबकास्ट का आयोजन किया था, जिसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर समिति के सदस्यों द्वारा संबोधित किया गया था। वेबकास्ट और प्रत्यक्ष कर के क्षेत्रों में प्रस्तावित परिवर्तनों पर कमेन्ट्री को संस्थान की वेबसाइट पर रखा गया था।

5.9.8 बजट-पश्च ज्ञापन की प्रस्तुती

समिति ने क्रमशः वित्त मंत्री और सीबीडीटी के पदधारियों को बजट-पश्च ज्ञापन - 2009 और 2010 प्रस्तुत किया था, जिसमें बजट 2009 और 2010 पर संस्थान के सुझाव अंतर्विष्ट थे। बजट-पश्च ज्ञापन - 2009 और 2010 को संस्थान की वेबसाइट पर भी रखा गया था।

5.9.9 खंड 17क के प्ररूप उगघ के संबंध में मार्गदर्शन

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2009 के द्वारा प्ररूप सं. उगघ में एक नया खंड 17क अंतःस्थापित किया था। समिति ने नए अंतःस्थापित खंड 17ग के संबंध में मार्गदर्शन को अंतिम रूप दिया था और उसे 25 अगस्त, 2009 को वेबसाइट पर रखा गया था।

5.9.10 आयकर विभाग द्वारा प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित विशेष शिविर में आईसीआई द्वारा कर संबंधी प्रश्नों का उत्तर

आयकर अपर आयुक्त के कार्यालय से, विशेष शिविरों में निर्धारितियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर विशेषज्ञ उत्तर देने के लिए प्रत्यक्ष कर विशेषज्ञों की निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराने के अनुरोध के अनुसरण में 28-31 जुलाई, 2009 के दौरान प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित विशेष शिविरों में संस्थान द्वारा एक पटल उपलब्ध कराया गया था।

5.9.11 प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2009 जारी किए जाने के अनुसरण में क्रियाकलाप

वित्त मंत्रालय ने 12 अगस्त, 2009 को प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2009 जारी किया था। इस संबंध में आईसीआईए के सुझाव मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए हैं।

• प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2009 पर व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन

समिति ने प्रस्तावित विधि पर विचार-विमर्श प्रारंभ करने और उसके संबंध में जागरूकता बनाने के लिए वित्त मंत्रालय के सहयोग से निम्न रूप से प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2009 पर व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया था :

- मुंबई में 29 अगस्त, 2009 को
- बंगलोर में 31 अगस्त, 2009 को
- कोलकाता में 31 अगस्त, 2009 को

सीबीडीटी के विभिन्न पदधारियों ने इस नए प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने के पीछे औचित्य पर विचार किया था।

• प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2009 पर अध्ययन समूहों का गठन

समिति ने प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2009 से उद्भूत होने वाले विषयों की पहचान करने और उनके संबंध में सरकार को समुचित सिफारिशें करने के लिए विभिन्न स्थानों पर अध्ययन समूहों और उप समूहों का सृजन किया था। इन समूहों ने उन्हें आर्बिटित प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2009 के अध्यायों पर विचार करने के लिए

अपने-अपने क्षेत्रों में बैठकें की थी। इन उपसमूहों के संयोजकों से प्राप्त अंतर्निवेशों का कार्यालय द्वारा संकलन किया गया था और समिति के विचारार्थ रखा गया था।

5.9.12 भारतीय लेखांकन मानकों (एएस) के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ अभिसरण के कारण उदभूत होने वाले प्रत्यक्ष कर मुद्दों की पहचान के लिए समूह का गठन

भारतीय लेखांकन मानकों (एएस) के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ अभिसरण के कारण उदभूत होने वाले प्रत्यक्ष कर मुद्दों की पहचान के लिए एक समूह का गठन किया गया है। इस समूह में परिषद् के सदस्य और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य सम्मिलित हैं।

5.9.13 संगोष्ठियां और सम्मेलन

- 25 अगस्त, 2009 को इंदौर में प्रत्यक्ष कर संबंधी एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था।
- प्रत्यक्ष कर और आई.एफ.आर.एस. पर एक आवासीय कर्मशाला का आयोजन 17 मई, 2009 और 18 मई, 2009 को त्रिचूर में किया गया था।
- 30 मई, 2009 को कानपुर में प्रत्यक्ष कर पर राष्ट्रीय कर संगोष्ठी
- 27 जून, 2009 को रायपुर में प्रत्यक्ष कर पर राष्ट्रीय कर संगोष्ठी
- 27 जून, 2009 को सलेम में प्रत्यक्ष कर पर पूर्ण दिवसीय कार्यशाला
- 10 जुलाई, 2009 और 11 जुलाई, 2009 को कोलकाता में प्रत्यक्ष कर पर एक अखिल भारतीय सम्मेलन
- 1 अगस्त, 2009 और 2 अगस्त, 2009 को अहमदाबाद में राष्ट्रीय कर अभिसमय
- 18 अगस्त, 2009 को मदुरै में क्षमता निर्माण पर एक दिवसीय कार्यशाला
- 21 अगस्त, 2009 को हैदराबाद में अवसंरचना और संकर्म संविदा उद्योग पर सेमिनार का आयोजन किया गया
- 22 नवंबर से 26 नवंबर, 2009 को मुंबई और सिंगापुर में आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया
- 19 और 20 दिसंबर, 2009 को गुवाहाटी में एक अखिल भारतीय सम्मेलन
- प्रत्यक्ष कर पर 13 फरवरी, 2010 और 14 फरवरी, 2010 को इंदौर में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी
- 5 मार्च, 2010, 6 मार्च, 2010 और 10 मार्च, 2010 को क्रमशः मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता में केंद्रीय बजट पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

5.10 आर्थिक और वाणिज्यिक विधियों और व्यापार विधियों तथा डब्ल्यू.टी.ओ. संबंधी समिति

फरवरी, 2010 में, दो पूर्ववर्ती समितियों अर्थात् आर्थिक और वाणिज्यिक विधियों संबंधी समिति और व्यापार विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ. संबंधी समिति के दायित्व के साथ आर्थिक, वाणिज्यिक विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ. पर एक नए नाम वाली समिति अस्तित्व में आई।

समिति का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय विधिक परिदृश्य और सर्वोत्तम व्यवहारों और डब्ल्यू.टी.ओ. युग से उद्भूत होने वाली व्यवहारों की तुलना में विभिन्न आर्थिक, वाणिज्यिक विधियों, तद्वर्ती जारी नियमों/विनियमों/अधिसूचनाओं की समीक्षा करके राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधियों और नयाचारी और उनकी दिवक्षाओं तथा प्रशासन से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी के आधार का सृजन करना और संबंधित प्राधिकारियों को उचित संशोधन/उपांतरणों

का, जहां कहीं ठीक समझा जाए, सुझाव देते हुए प्रतिवेदन करना है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विषय सम्मिलित हैं :

- द्रुतगति से बदलने वाले विश्व व्यापार परिदृश्य में संस्था के सदस्यों को चुनौतियों का सामना करने और नई विश्व व्यापार व्यवस्था में उनकी विशेषज्ञता के विस्तार क्षेत्र को विस्तारित करने के लिए लाभ व्युत्पन्न करने हेतु तकनीकी रूप से उन्हें सज्जित करने के लिए सक्षमता निर्माण के लिए प्रयास करना और भारत के आर्थिक विकास में योगदान करना ।
- संबंधित प्राधिकारियों को उचित संशोधनों/उपांतरणों का, जहां कहीं ठीक समझा जाए, सुझाव देते हुए प्रतिवेदन करना ।
- आर्थिक, वाणिज्यिक विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ. समझौते पर तकनीकी मार्गदर्शन, पृष्ठभूमि सामग्रियों/रिपोर्टों, संदर्शिकाओं, टीकाओं, संदर्भों, प्रकाशनों आदि को विकसित और प्रकाशित करना ।
- विश्लेषण, ज्ञान के प्रसार, नीति के प्रतिपादन के लिए इनपुट, आई.सी.ए.आई. सदस्यता के लिए व्यावसायिक रुचि के क्षेत्रों में संदर्भों के बहुकार्यात्मक कार्य करना और संभावित व्यावसायिक अवसरों के घटकों को सहारा देना ।
- संगोष्ठियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे अन्य तरीकों से जो प्रभावी समझी जा सकें संस्थान के सदस्यों के बीच आर्थिक, वाणिज्यिक विधियों, बौद्धिक संपदा अधिकारों, ट्रिप्स, प्रति-पाटन क्षेपण निवारण विधियों, विदेशी व्यापार नीति विषयों आदि पर विशेषज्ञता के आधार को विकसित करना ।

समिति की महत्वपूर्ण उपलब्धियां और आरंभ किए गए प्रयोग निम्नलिखित हैं :-

5.10.1 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ. में अर्हता पश्च पाठ्यक्रम/माध्यस्थता पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों और विश्व व्यापार संगठन में अर्हता पश्च पाठ्यक्रम चार्टर्ड एकाउन्टेंटों को गतिशील और चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण के अनुकूल होने और प्रतिक्रिया करने के लिए आवश्यक और वांछनीय सक्षमताओं के विकास की ओर अभिमुख करने के लिए है। इस पाठ्यक्रम को सदस्यों की ओर से भी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। पाठ्यक्रम में पूरे देश से 330 से अधिक सदस्य रजिस्ट्रीकृत हो चुके हैं। समिति उक्त पाठ्यक्रम की पुनर्संरचना की प्रक्रिया में है और कारपोरेट कार्य मंत्रालय से भी संपर्क में है।
- समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ. में अर्हता पश्च पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत सदस्यों के लिए वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम (पी.सी.पी.) कक्षाओं में पहले और दूसरे चरण का आयोजन क्रमशः 10 जुलाई, 2010 से 15 जुलाई, 2010 तक और 29 जुलाई, 2010 से 12 अगस्त, 2010 तक नई दिल्ली में किया गया है।
- समिति पूरे देश में सदस्यों के बीच पाठ्यक्रम का प्रचार करने के लिए प्रयत्न करती रही है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ. में इस प्रकार सज्जित सदस्यों के लिए व्यावसायिक अवसरों को सृजित करने के लिए पाठ्यक्रम का उद्योग, सरकार और अन्य संभावित प्रयोक्ता-समूहों में प्रोत्साहन करने का भी प्रयत्न करती रही है।
- माध्यस्थता पर प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम उसके सदस्यों को आनुकूलिक विवाद निवारण तंत्र पर सुग्राही बनाने की दृष्टि से आरंभ किया गया था। पाठ्यक्रम के 7 बैचों का पहले ही संचालन किया जा चुका है और चालू वर्ष में और बैचों की योजना बनाई जा रही है। समिति ने पूरे देश में अपने सदस्यों को माध्यस्थता के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए माध्यस्थता पर दो दिवसीय उन्नत स्तर की कार्यशाला का भी आयोजन करने का निर्णय लिया है।

- वर्तमान में मध्यस्थों के आई.सी.ए.आई. पैनल में 314 सदस्य हैं और देश के भीतर और वैश्विक स्तर पर मध्यस्थों के रूप में नियुक्ति के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेंटों की उपलब्धता के बारे में प्रयोक्ता निकायों को अवगत कराने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यू.आई.पी.ओ.) से भी मध्यस्थों को आई.सी.ए.आई. पैनल के सदस्यों को उनके विशेषज्ञों की सूची में प्रविष्टि करने का विचार करने के लिए निवेदन किया गया है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय निकायों जैसे यूरोप में माध्यस्थम् के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आई.सी.ए. ई.) और मध्यस्थों के चार्टर्ड संस्थान, यू.के. (सी.आई.ए.आर.बी.) को भी शैक्षिक सहयोग के लिए प्रस्ताव किया गया है।

5.10.2 ई-न्यूजलैटर

समिति द्वारा आर्थिक, वाणिज्यिक, व्यापार विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ. से संबंधित उभरते विषयों को सम्मिलित करने वाले ई-न्यूजलैटर को भी प्रकाशित किया जा रहा है।

5.10.3 डब्ल्यू.टी.ओ. सचिवालय द्वारा लेखांकन सेवाओं पर तैयार किया गया डब्ल्यू.टी.ओ. दस्तावेज सं. एस./सी./डब्ल्यू./316 पर राय।

समिति ने विभिन्न सदस्य-राज्यों द्वारा विभिन्न पद्धतियों के अधीन लेखांकन के क्षेत्र में वचनबद्धता के संबंध में बहुत अधिक विश्लेषण और अनुसंधान किया। समिति ने मोड-3 वचनबद्धता में संभावित उदासीकरण की रूपरेखा देते हुए अपना उत्तर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और कार्पोरेट मामले मंत्रालय को प्रस्तुत किया और डब्ल्यू.टी.ओ. दस्तावेज सं. एस./सी./डब्ल्यू./316 का आई.सी.ए.आई. की प्रतिक्रिया का उपांतर्गत मसौदा प्रस्तुत किया।

5.10.4 प्रकाशन

- समिति “फेमा पर रैफरेंस (विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999)”, “विशेष आर्थिक जोन” के नाम से अपने पूर्ववर्ती प्रकाशनों और माध्यस्थम पर उसके प्रकाशन को संशोधित करने की प्रक्रिया में है।
- अपने पूर्ववर्ती प्रकाशनों का संशोधन करने और “कृषि और वाणिज्य क्षेत्र में एसियान देशों के साथ अधिमानिक व्यापार समझौता के लाभों पर अध्ययन, सीमापार विलयन और अधिग्रहण पर अध्ययन” के नाम वाले कुछ और नए प्रकाशनों को लाने और आर्थिक, वाणिज्यिक, व्यापार विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ. से संबंधित अन्य विषयों को लाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

5.10.5 कार्यशालाएं/संगोष्ठियां/सम्मेलन

समिति ने निम्नलिखित कार्यशालाओं/सम्मेलनों का आयोजन किया :

- प्रतिस्पर्धा/उपभोक्ता विधियों में व्यावसायिक अवसरों के संबंध में 28 मई, 2010 को मुंबई में कार्यशाला
- गैस-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के संबंध में 5 मई, 2010 को कोलकाता में कार्यशाला
- फेमा-अंतर्बाध्यता और बहिर्बाध्यता निवेशों पर 25 और 26 जून, 2010 को मुंबई में कार्यशाला
- 17 और 18 जुलाई, 2010 को चेन्नई में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन

5.10.6 विभिन्न सरकारी विभागों/मंत्रालयों के साथ अन्योन्यक्रिया

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, सीडबी, सी.सी.आई. और विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के साथ सदस्यों के लिए और अधिक व्यावसायिक अवसरों की खोज करने के लिए अन्योन्यक्रिया होती आई है। समिति का कुछ और सरकारी विभागों/मंत्रालयों के साथ इस संबंध में अपना संवाद जारी रखने का आशय है।

महाराष्ट्रीय सरकार को आम-भाषी स्कीम को शुरू करने और फर्मों के रजिस्ट्रार कार्यालय, महाराष्ट्र के साथ दस्तावेजों के अनुपालन/रजिस्ट्रीकरण के लिए ऑनलाइन तंत्र के संबंध में प्रतिवेदन किया गया है ।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय को नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) नीति से उद्भूत विषयों के बारे में इस निवेदन के साथ अवगत कराया गया है कि इस संबंध में मामले को समुचित रूप से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ उठाया जाए ।

5.10.7 तत्कालीन आर्थिक और वाणिज्यिक विधियों संबंधी समिति

आर्थिक और वाणिज्यिक विधियों संबंधी समिति (सी.ई.सी.एल.) का फरवरी, 2008 में आर्थिक और वाणिज्यिक विधियों के क्षेत्र में उभरती हुई व्यावसायिक अवसरों पर अधिक स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करने के विशिष्ट उद्देश्य से और आर्थिक और वाणिज्यिक विधियों को बनाने/संशोधन करने के क्षेत्र में वैधानिक प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए गठन किया गया था ।

उक्त समिति की महत्वपूर्ण उपलब्धियां और आरंभ किए गए कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं :-

- समिति ने भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2009 पर अपनी टिप्पणियों/सुझावों को संसदीय स्थायी समिति को प्रस्तुत किया । तत्कालीन अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल की स्थायी समिति के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई हुई थी ।
- समिति ने धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 पर 18 मई, 2009 को पुणे में संगोष्ठी का आयोजन किया और एक राष्ट्रीय सी.ए. सम्मेलन, 2009 - एनरिचिंग पोर्टेशियल डिलीवरिंग एक्सीलेंस का 28 और 29 नवंबर, 2009 को कटक में आयोजन किया था ।
- “विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 पर एक अध्ययन” शीर्षक वाली पुस्तक का पुनरीक्षित संस्करण मुद्रित किया गया है । समिति ने अपने नए प्रकाशनों जैसे “धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 पर एक अध्ययन” “आर्थिक और वाणिज्यिक विधियों में व्यावसायिक अवसरों पर पुस्तिका” और “वाणिज्यिक और अन्य दस्तावेजों के प्रारूप, हस्तांतरण, स्टैपिंग और रजिस्ट्रेशन पर एक अध्ययन” को अंतिम रूप देने में पहल की थी ।
- कार्यशाला में भाग लेने वालों के मध्य वितरण के लिए उन्नत स्तर कार्यशालाओं और एस.ई.जेड. विधियों पर उचित पृष्ठभूमि सामग्री तैयार करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । माध्यस्थता पर प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम के लिए भी पृष्ठभूमि सामग्री को पुनरीक्षित और अद्यतन किया जा रहा है ।

5.10.8 व्यापार विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ. संबंधी समिति

व्यापार विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ. पर समिति का गठन विशिष्टतया मामलों और सेवाओं और सामान्यतया डब्ल्यू.टी.ओ. प्रणाली सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के क्रियान्वयन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, सहित व्यापार विधियों से संबंधित सभी मामलों में भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान की सुविज्ञता और प्रभुत्व को स्थापित और सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था और संस्थान के सदस्यों के मध्य इन विषयों में सुविज्ञता के आधार का सृजन और विस्तार ऐसे तरीकों और साधनों से करने के उद्देश्य से किया गया था जो बहुत अधिक प्रभावी समझे जाएं जिससे इन संबंधों में राष्ट्रीय कथित और अकथित अकांक्षाओं, संबद्धताओं और जरूरतों को पूरा किया जाए ।

उक्त समिति की महत्वपूर्ण उपलब्धियां और आरंभ किए गए कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं :-

- समिति ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ. (आई.टी.एल. तथा डब्ल्यू. टी.ओ.) में अर्हता पश्च पाठ्यक्रम नवंबर, 2004 में आरंभ किए । पाठ्यक्रम के आरंभ से पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकरण के लिए देश के सभी भागों से आवेदन आ रहे हैं । पूरे देश से 330 से अधिक सदस्यों को पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकृत किया गया है । पाठ्यक्रम की व्यापक संरचना को केंद्रित दृष्टिकोण देने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों

और डब्ल्यू.टी.ओ. में अर्हता पश्च पाठ्यक्रम के पाठ्य-विवरण, पाठ्यक्रम संरचना, अध्ययन सामग्री और विरचना को पुनःसंरचित करने का प्रस्ताव है।

- जमीनी स्तर पर डब्ल्यू.टी.ओ. पर सदस्यों के मध्य जानकारी का सृजन करने की दृष्टि से और उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ. में अर्हता पश्च पाठ्यक्रम के लिए अभ्यर्थियों की संख्या का विस्तार करने के लिए सभी क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं का निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग मांगा गया है :-
 - सदस्यों को पाठ्यक्रम के बारे में सूचना उपलब्ध कराकर आई.सी.ए.आई. के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ. में अर्हता पश्च पाठ्यक्रम को लोकप्रिय बनाना।
 - कार्यक्रमों को आयोजित करके सदस्यों के मध्य डब्ल्यू.टी.ओ. पर जानकारी सृजित करना।
- 15 मई, 2009 को आई.सी.ए.आई., नई दिल्ली में भारत में विभिन्न दूतावासों के व्यापार अधिकारियों के साथ परस्पर-क्रिया की गई थी, जिसमें विभिन्न दूतावासों जैसे, बेलारूस, जर्मनी, आइसलैंड, मलावी, मालदीव, प्रागुए, पाकिस्तान, ट्यूनिशिया और श्रीलंका के प्रतिनिधि उपस्थित थे। आगे, 26 मई, 2009 को आई.सी.ए.आई., नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायुक्त के साथ भी परस्पर-क्रिया की गई थी।
- समिति ने अधिमान्य व्यापार समझौतों के फायदों पर एक अध्ययन प्रकाशित किया है। विभिन्न कार्यक्रमों के लिए एक मानक पृष्ठभूमि सामग्री भी लाई गई है।
- समिति द्वारा निम्नलिखित जानकारी कार्यक्रम/कार्यशालाएं/संगोष्ठियां/अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन दौरे आयोजित किए गए थे :
 - वृत्तिक उत्कृष्टता और समृद्धि पर वृत्तिक विकास समिति के साथ संयुक्त रूप से और आई.सी.ए.आई. की सी.आई.आर.सी. की भिलाई शाखा की मेजबानी में 15 फरवरी, 2009 को भिलाई में हीरक जयंती राष्ट्रीय परिसंवाद।
 - आई.सी.ए.आई. की सी.आई.आर.सी. की भिलाई शाखा के साथ संयुक्त रूप से 4 से 8 मई के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के लिए थाइलैंड का दौरा।
 - गेट्स - लेखा के लिए वाद विषय पर सदस्यों के लिए 26 मई, 2009 को नई दिल्ली में इंटरएक्टिव कार्यशाला जिसका प्रसारण मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और कानपुर में संस्थान के कार्यालयों में भी वीडियो-कान्फ्रेंसिंग द्वारा किया गया था।
 - “लेखा व्यवसायियों के लिए उभरते प्रतिमान” पर आई.सी.ए.आई. की एन.आई.आर.सी. और आई.सी.ए.आई. की सी.आई.आर.सी. की गाजियाबाद शाखा की मेजबानी में 15-16 अगस्त, 2009 को साहिबाबाद (गाजियाबाद) में राष्ट्रीय सम्मेलन।
 - “लेखापालों के लिए उभरते प्रतिमान” पर आई.सी.ए.आई. की डब्ल्यू.आई.आर.सी. की कोल्हापुर शाखा की मेजबानी में 20-22 अगस्त, 2009 के दौरान कोल्हापुर में राष्ट्रीय सम्मेलन।
 - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ. में अर्हता पश्च पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकृत सदस्यों के लिए नई दिल्ली में 15 दिनों के दो चरणों में 1 जुलाई, 2009 से 15 जुलाई, 2009 और 29 जुलाई 2009 से 12 अगस्त, 2009 के दौरान 30 दिवसीय वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम (पी.सी.पी.) का पहला बैच।
 - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ. में अर्हतापश्च पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकृत सदस्यों के लिए नई दिल्ली में 15 दिनों के दो चरणों में, 5 नवम्बर 2009 से 19 नवम्बर, 2009 और 5 जनवरी, 2010 से 19 जनवरी, 2010 के दौरान 30 दिवसीय वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम (पी.सी.पी.) का दूसरा बैच।

○ प्रतिपादन सहायिकी और रक्षोपाय - विधि और प्रक्रिया अवसर तथा चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए 'चुनौतियाँ' पर 5 फरवरी, 2010 को नई दिल्ली में इंटरएक्टिव कार्यशाला ।

- समिति ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार - व्यापार विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ. पर समिति के ई-कम्यूनिटी शीर्षक वाले ई-न्यूजलेटर के अप्रैल, 2009 तथा जुलाई, 2009 के अंक जारी किए ।

5.11 नैतिक मानक बोर्ड

कभी-कभी यह महसूस किया जाता है कि व्यावसायिक नैतिकता की क्या आवश्यकता है जब विधि और उसके अनुपालन के परिणाम पहले से ही निर्धारित हैं । विधि और नैतिकता का उद्देश्य एक ही है । परंतु लोगों को सही व्यावसायिक आचार बनाए रखने को प्रोत्साहित करने के लिए नैतिकता अपेक्षित है । 1958 में प्रकाशित हार्वर्ड लॉ रिव्यू में प्रसिद्ध हार्ट-फ्यूलर वाद-विवाद में न्यायाधीश हार्ट और फ्यूलर एक बिंदु पर सहमत हुए थे कि नैतिकता रहित कोई तंत्र लोगों की निष्ठा के योग्य नहीं हो सकता और ऐसे तंत्र को दमन पर ही निर्भर रहना है । जब दमनकारी प्रणाली ध्वस्त होती है तब तंत्र भी उसके साथ ध्वस्त हो जाता है । इसलिए विधि का नैतिकता से अनुप्रमाणन और मार्गदर्शन अवश्य होना चाहिए । कोई विधि जो इस प्रकार अनुप्रमाणित और मार्गदर्शित नहीं है, अन्यायोचित होगी और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल होगी ।

आज व्यवसाय और कारबार के अपरिहार्य भाग के रूप में नैतिकता अपेक्षित है । सर्वेनस आक्सली विधि के भाग रूप में, निदेशकों को एक नैतिकता घोषणा पर हस्ताक्षर करने होते हैं । भारत में सभी निदेशक सूचीकरण समझौते के खंड 49 की अपेक्षा के अनुरूप व्यवसाय आचार और नैतिक संहिता के अनुपालन के लिए प्रतिवर्ष प्रतिज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं ।

आई.सी.ए.आई. के नैतिक मानक बोर्ड व्यवसाय और नैतिकता के बीच उपर्युक्त संबंधों पर ध्यान देता है और व्यावसायिक नैतिकता के उच्चतम मानकों का आई.सी.ए.आई. के सदस्यों के मध्य प्रसार करने का कार्य कर रहा है । यह सदस्यों के लिए नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है और उनके मध्य विभिन्न तरीकों से नैतिकता की जानकारी का सृजन करता है । सदस्यों के लिए नैतिक संहिता, जो बोर्ड का प्रकाशन है, के दो भाग हैं : भाग-क, जो सिद्धांत आधारित है और भाग-ख, जो नियम आधारित है, एक दूसरे के पूरक घटक हैं और व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम में से एक संहिता का प्रतिनिधित्व करते हैं । बोर्ड का मिशन श्रेष्ठता, स्वाधीनता, सत्यनिष्ठा के आदर्शों को दीर्घकाल से हृदय में संजोए रखते हुए सदस्यों के लिए नैतिकता और नैतिक व्यवहार की समसामयिक और प्रगतिशील संहिता को उत्सर्जित करने का कार्य करना और सदस्यों की गरिमा और हितों की रक्षा करना भी है । इसके साथ-साथ बोर्ड उसको निर्दिष्ट नैतिक वाद विषयों का परीक्षण कर उन पर सुझाव भी देता है । यह अपने प्रकाशनों 'नैतिक संहिता', 'नैतिक वाद विषयों पर एफ.ए.क्यू.', 'संपरीक्षकों की स्वतंत्रता पर मार्गदर्शन टिप्पण' और संपरीक्षा रिपोर्ट के संशोधन पर मार्गदर्शन टिप्पण को समय-समय पर पुनरीक्षित और संशोधित करता है । बोर्ड सदस्यों के लिए मूलभूत सिद्धांतों, जैसे सत्यनिष्ठा, विषय निष्ठा, सुयोग्यता और व्यावसायिकता में जन चेतना और विश्वास को प्रोत्साहित करता है । यह किसी अस्तित्व के संपरीक्षक के रूप में अन्यायपूर्ण रूप से हटाए जाने के विरुद्ध सदस्यों की शिकायतों का परीक्षण और निपटान भी विकसित प्रक्रिया के अनुसार करता है और सदस्यों के हित की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाता है ।

5.11.1 विभिन्न वाद विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय

- सदस्यों के मध्य नैतिक विषयों की चेतना पैदा करने के अपने प्रयत्न में बोर्ड ने 'अपनी नैतिकता जाने' शीर्षक वाले पूरे पृष्ठ को सी.ए. पत्रिका में आरंभ किया है जिसका प्रकाशन सितंबर, 2009 से नियमित रूप से किया जा रहा है ।
- सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधिनियमन के कारण चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 और कंपनी अधिनियम, 1956 में आवश्यक संशोधनों के किए जाने की अपेक्षा का बोर्ड द्वारा प्रस्ताव किया गया था । परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित बोर्ड की सिफारिशें अगस्त, 2009 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय को अधिनियम में संशोधनों के लिए भेजी गई थी ।

- बोर्ड द्वारा परिषद् के निदेश पर बहु-विषयक भागीदारी (एम.डी.पी.) पर बहुलकताओं का गठन किया गया था। उक्त बहुलकताओं का परिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया था।
- बोर्ड ने निर्णय किया कि :-
 - कर संपरीक्षा और सॉक्स प्रमाणन केवल कानूनी संपरीक्षकों द्वारा किया जाना है।
 - तंत्र की रुपरेखा और आउटसोर्सड कारबार प्रक्रियाओं का रोजमर्रा समर्थन केवल आंतरिक संपरीक्षक द्वारा किया जाना है।
 - कर प्रतिनिधित्व, परामर्शी सलाहकारी, आई.एफ.आर.एस. रुपांतरण और स्रोत निर्माण दोनों द्वारा किया जा सकता है।
- पूर्ववर्ती निर्णयों में यथा अंगीकृत पूर्ण स्वाधीनता के सिद्धांत के अनुरूप, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखाओं में से किसी एक शाखा की समानांतर संपरीक्षा को स्वीकार करना अनुज्ञेय नहीं है जिसने उसी बैंक की 3 भिन्न-भिन्न शाखाओं की कानूनी संपरीक्षा संचालित की है।
- किसी विशिष्ट वर्ष के लिए किसी अस्तित्व के आंतरिक संपरीक्षक को उसी अस्तित्व के कर परामर्शी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
- आई.सी.ए.आई. चार्टर्ड अकाउंटेंटों से सरकारी कंपनियों/संगठनों/पी.एस.यू. /निगम द्वारा संपरीक्षा कार्य के लिए एम्पेनलमेंट संबंधी कोटेशन/बोलियों के आमंत्रण में दखल नहीं दे सकता क्योंकि चार्टर्ड एकाउंटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2006 ने विनिर्दिष्ट रूप से व्यवसाय कर रहे चार्टर्ड एकाउंटेंटों को चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के भाग 1 के खंड (6) के परंतुक (ii) द्वारा निविदाओं को स्वीकार करने के लिए अनुज्ञात किया था।

5.12 विशेषज्ञ सलाहकार समिति

विशेषज्ञ की राय

उद्यमों में निरंतर आर्थिक प्रगति और विकास जनित जटिल कारबार संव्यवहार के साथ लेखा व्यवसायी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते समय अक्सर कठिनाइयों का सामना करते हैं, विशेषकर विभिन्न अद्वितीय और जटिल कारबार स्थितियों में लेखा और संपरीक्षा सिद्धांतों के अनुप्रयोग और क्रियान्वयन में। ऐसे परिदृश्य में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध करने के लिए, संस्थान की विशेषकर सलाहकार समिति, उनके द्वारा विभिन्न लेखा और संपरीक्षा मानकों के अनुप्रयोग और निर्वचन मार्गदर्शन टिप्पण और संस्थान की अन्य उद्घोषणाओं की बाबत विषयों में उठाए गए प्रश्नों का, इस प्रयोजन के लिए बनाई गई सलाहकार लेखा नियमों के अनुरूप उत्तर देती है। समिति लेखा और/या संपरीक्षा सिद्धांतों और सहबद्ध विषयों से संबंधित शंकाओं का निपटान करती है और सामान्य नियम के तहत ऐसी शंकाओं पर ध्यान नहीं देती है जो केवल विभिन्न अधिनियमों के विधिक निर्वचन और व्यावसायिक कदाचार को समाहित करते विषयों को सम्मिलित करती है। यह उन शंकाओं का उत्तर भी नहीं देता है जो किसी ऐसे मामले से संबद्ध है जो संस्थान के अनुशासन बोर्ड या अनुशासनिक समिति, विधि के किसी न्यायालय, आय-कर प्राधिकारियों या सरकार के किसी अन्य समुचित विभाग के समक्ष लंबित हैं। सलाहकार सेवा नियमों तक संस्थान की वेबसाइट से पहुंचा जा सकता है या वे नई दिल्ली में संस्थान के मुख्य कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय, उपयोज्य लेखा/संपरीक्षा मानकों, मार्गदर्शन टिप्पणों और संस्थान की अन्य उद्घोषणाओं और राय को अंतिम रूप देने की तारीख को, शंका की परिस्थितियों के अधीन उपयोज्य सुसंगत विधियों और विनियामक वातावरण के आधार पर शंका के तथ्यों और परिस्थितियों पर समिति के सदस्यों की राय या विचार है। इसलिए, समिति द्वारा राय को अंतिम रूप दिए जाने की तारीख के पश्चात् किन्हीं संशोधनों और/या अन्य परिवर्धनों को ध्यान में रखने के पश्चात् ही उनके विरुद्ध उल्लिखित प्रत्येक राय को अवश्य पढ़ा और लागू किया जाना चाहिए।

यद्यपि समिति द्वारा दी गई राय या प्रकट किया गया कोई विचार समिति के सदस्यों की राय या विचार का घोटक है न कि आई.सी.ए.आई. की परिषद् की आधिकारिक राय का, यह एक प्रामाणिक मार्गदर्शन वहन करता है जिसको विभिन्न सरकारी/विनियामक निकायों जैसे, भारत का नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक (सी. एंड ए.जी.) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, आदि द्वारा भलिभांति मान लिया गया है।

01.04.2009 से 30.06.2010 की अवधि के दौरान समिति ने संस्थान के सदस्यों से प्राप्त 43 रायों और विनियामकों/सरकारी प्राधिकारियों से भिन्न-भिन्न लेखा विषयों पर प्राप्त 4 रायों को अंतिम रूप दिया। विभिन्न विषयों जिन पर समिति ने उस अवधि के दौरान राय दी, विदेशी विनिमय दर रूपभेद पर लेखा, अवमूल्यन, राजस्व मान्यता, सेगमेंट रिपोर्टिंग, संघटन के परिणामस्वरूप निरूपण, आस्थगित कर, सन्निर्माण अवधि के दौरान व्ययों का निरूपण, आदि थे।

समिति द्वारा जारी रायों को राय सार-संग्रह में भी प्रकाशित किया जाता है। अब तक सार-संग्रह के छब्बीस भागों को विक्रय के लिए जारी किया जा चुका है। श्रृंखला में सार-संग्रह के अगले भाग संकलनाधीन हैं और विक्रय के लिए शीघ्र ही जारी किए जा सकते हैं। राय सार-संग्रह के पच्चीस भागों में अंतर्विष्ट 1000 से अधिक रायों को अंतर्विष्ट करने वाली और आसान संदर्भ के लिए प्रयोक्ता अनुकूल लक्षणों वाली सी.डी. को बाद वाले भागों में अंतर्विष्ट राय को सम्मिलित करने के लिए उन्नत किया जा रहा है।

समिति द्वारा अंतिम रूप प्रदान की गई कुछ राय संस्थान की पत्रिका 'द चार्टर्ड आकउंटेंट' की प्रत्येक प्रति में प्रकाशित होती हैं। समिति की अभिनव राय संस्थान की वेबसाइट पर भी रखी गई हैं।

5.13 वित्तीय बाजारों और निवेशकों की सुरक्षा संबंधी समिति

निवेशकों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करने, उन्हें शिकायत दूर करने के लिए तंत्र के बारे में सूचित करने और तुलनपत्रों और अन्य वित्तीय कथनों खासकर टिप्पणों और अन्य प्रकटीकरण पर आधारित मूलभूत विश्लेषणों की महत्ता के बारे में शिक्षित करना समिति के केंद्रीभूत क्षेत्रों में से एक है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आई.ई.पी.एफ.) भारत सरकार के तत्वावधान में पूंजी बाजार के संबंध में निवेशकों को शिक्षित करने का कार्य इस समिति को सौंपा है। समिति पूंजी बाजार के विभिन्न अवयवों में ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से देशभर में कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन करती रही है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, समिति विभिन्न अन्य कार्यक्रमों जैसे पूंजी बाजार पर संगोष्ठियों, निवेशक शिखर वार्ता, प्राइवेट साम्या कार्यशाला और जीविका परामर्श कार्यक्रमों आदि के संचालन में क्रियाशील भूमिका अदा कर रही है। समिति ने विभिन्न प्रकाशनों जैसे निवेशक चेतना पर पुस्तिकाएं और पैम्फलेट, पूंजी बाजार विनियमों पर पुस्तिका, प्राइवेट साम्या पर पृष्ठभूमि सामग्री और निगम अभिशासन के प्रमाणन पर मार्गदर्शन टिप्पण (पुनरीक्षित) को भी प्रकाशित किया है।

5.13.1 परियोजनाएं

- विनियामक प्राधिकारियों - आर.बी.आई., सेबी तथा एम.सी.ए. के साथ अंतरापृष्ठ - नीति/परिचर्चा पत्रों पर प्रस्तुतीकरण/सुझाव

समिति ने निवेशक चेतना और सुरक्षा संबंधित कार्यक्रमों पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय की निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि समिति की तीन बैठकों में संस्थान का प्रतिनिधित्व किया। समिति ने बी.एस.ई./एन.एस.ई./सेबी को भी अंतर्राष्ट्रीय व्योहारों के अनुसूच स्टॉक एक्सचेंज के लिए व्यापार अवकाश की संख्या में कमी से संबंधी विषयों पर प्रतिवेदन किया है।

- प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम - फोरेक्स और कोषागार प्रबंधन

समिति ने फोरेक्स और कोषागार प्रबंधन पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का दूसरा बैच/तीसरा बैच क्रमशः नई दिल्ली और मुंबई में संचालित किया। समिति अब इन पाठ्यक्रमों का विस्तार आगे अन्य महानगरों में करने का प्रस्ताव कर रही है।

5.13.2 आयोजित कार्यक्रम

- एन.आई.आर.सी. की अमृतसर शाखा की मेजबानी में 24 और 25 अप्रैल, 2009 को अमृतसर में वित्तीय बाजारों के क्षेत्र में उभरती प्रवृत्तियों पर सम्मेलन ।
- आई.सी.ए.आई. की लुधियाना शाखा के साथ संयुक्त रूप से 11 और 12 जुलाई, 2009 को लुधियाना में पूंजी बाजारों पर दो दिवसीय कार्यशाला ।
- 17 और 18 जुलाई, 2009 को नई दिल्ली में पूंजी बाजार पर हीरक जयंती सम्मेलन ।
- 1 और 2 अगस्त, 2009 को बंगलुरु में निजी साम्या पर दो दिवसीय संगोष्ठी ।
- संस्थान ने वर्ष 2009-10 के दौरान भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि के तत्वावधान में 76 निवेशक चेतना कार्यक्रमों का आयोजन किया था ।

5.13.3 प्रकाशन

- निगम कारपोरेट अभिशासन के प्रमाणन पर विद्यमान मार्गदर्शन टिप्पण (सूचीकरण समझौते के खंड 49 में यथा अनुबंधित) का संशोधन

संशोधित मार्गदर्शन टिप्पण 2009 का प्रकाशन किया गया था ।

5.14 वित्तीय रिपोर्टिंग पुनरीक्षण बोर्ड

आई.सी.ए.आई. ने, देश में वित्तीय रिपोर्टिंग व्यूहों के सुधार के लिए अपने प्रयत्नों को जारी रखते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग पुनरीक्षण बोर्ड (एफ.आर.आर.बी.) का गठन किया था । एफ.आर.आर.बी. विभिन्न उद्यमों के सामान्य प्रयोजन वाले वित्तीय विवरणों और उन पर संपरीक्षक की रिपोर्ट की स्वतंत्रता से या किसी विनियामक निकाय (यो) द्वारा उसको निर्देशन पर पुनरीक्षण करता है, या जहां मीडिया रिपोर्ट द्वारा गंभीर लेखा अनियमितताओं को उजागर किया गया है, वहां, जहां तक संभव हो, निम्नलिखित का अवधारण करने की दृष्टि से पुनरीक्षण करता है :

- क) वित्तीय विवरणों को तैयार करना और प्रस्तुतीकरण में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों का अनुपालन ;
- ख) उद्यमों से सुसंगत विनियामक निकायों, विधियों और नियमों तथा विनियमों द्वारा विहित प्रकटन अपेक्षाओं का अनुपालन ;
- ग) उद्यमों और साथ ही संपरीक्षकों की रिपोर्टिंग बाध्यताओं का अनुपालन ;

एफआरआरबी की प्रचालन प्रक्रियाओं के अनुसार, साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों का और उन पर संपरीक्षक की रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करते समय तकनीकी पुनर्विलोकक और वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूह बोर्ड की सहायता करते हैं । पुनर्विलोकन के लिए चयन किए गए साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों का और उन पर संपरीक्षक की रिपोर्टों का प्रारंभिक पुनर्विलोकन, बोर्ड द्वारा रखे गए पैनल में से चयन किए गए तकनीकी पुनर्विलोककों द्वारा किया जाता है । साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों का और उन पर संपरीक्षक की रिपोर्टों की तकनीकी पुनर्विलोककों द्वारा दी गई प्रारंभिक पुनर्विलोकन रिपोर्टों पर, बोर्ड द्वारा उनकी अंतिम रूप से समीक्षा किए जाने से पूर्व वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूहों द्वारा विचार किया जाता है और उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है ।

5.14.1 साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उनपर संपरीक्षकों की रिपोर्ट का पुनर्विलोकन

बोर्ड ने, वर्ष 2009-10 के दौरान विशेष मामलों सहित 76 मामलों का पुनर्विलोकन किया है ।

5.14.2 वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूहों का गठन

बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए तेरह (13) वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूहों का गठन किया था, जो साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उनपर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर तकनीकी पुनर्विलोककों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक पुनर्विलोकन रिपोर्टों पर विचार करेंगे तथा उन्हें अंतिम रूप देंगे ।

5.14.3 प्रकाशन

- वित्तीय विवरण तैयार करने वाले व्यक्तियों और संपरीक्षकों के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए बोर्ड ने 'ए स्टडी ऑन कंप्लायंस ऑफ काइनेन्शियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स' को प्रकाशित करने का विनिश्चय किया है, जिसमें लागू लेखांकन/संपरीक्षा मानकों तथा मार्गदर्शक टिप्पणों और साथ ही सुसंगत विधियों और कानूनों के संदर्भ में विभिन्न वित्तीय रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अनुपालन पहलुओं पर बोर्ड द्वारा किए गए अनिवार्य संप्रेक्षण अंतर्विष्ट होंगे। इस अध्ययन में बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2006-07 से संबंधित साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों के पुनर्विलोकन के दौरान किए गए संप्रेक्षण सम्मिलित हैं।
- पुनर्विलोकन के दौरान पाए गए प्रमुख अननुपालनों, अननुपालनों संबंधी टिप्पण से आईसीएआई के सदस्यों और अन्य-संबद्ध व्यक्तियों को अवगत कराने के लिए, बोर्ड द्वारा उन्हें आईसीएआई के जर्नल 'दि चार्टर्ड एकाउंटेंट' के दिसम्बर, 2009 और जनवरी, 2010 अंकों में प्रकाशित किया गया था।

5.14.4 प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का संचालन

कार्य की बढ़ती मात्रा से निपटने के लिए बोर्ड को, उसके साथ पैनलबद्ध तकनीकी पुनर्विलोककों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता महसूस हुई थी। तदनुसार, बोर्ड ने उद्यमों के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों के पुनर्विलोकन के लिए संस्थान के सदस्यों को प्रशिक्षण देने और अंततः उन्हें बोर्ड के साथ पैनलबद्ध करने के लिए विभिन्न प्रादेशिक शाखाओं में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया था। इस अवधि के दौरान बोर्ड ने चार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया था, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

- 13 जून, 2009 को चेन्नई में, जिसका उद्घाटन माननीय सीए के. रहमान खान, एफसीए, उपसभापति राज्यसभा द्वारा किया गया था और इसमें वृत्ति के विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न फर्मों के 273 व्यक्तियों ने भाग लिया था।
- 14 अगस्त, 2009 को कोलकाता में, जिसमें 67 व्यक्तियों ने भाग लिया था।
- 19 जनवरी, 2010 को इंदौर में, जिसमें 78 व्यक्तियों ने भाग लिया था।
- 23 जनवरी, 2010 को मुंबई में, जिसमें 47 व्यक्तियों ने भाग लिया था।

इस प्रकार, बोर्ड 90 और तकनीकी पुनर्विलोककों को पैनलबद्ध करने में समर्थ रहा था। इस समय, 214 तकनीकी पुनर्विलोकक बोर्ड के साथ पैनलबद्ध हैं।

5.15 अप्रत्यक्ष कर समिति

5.15.1 बजट संबंधी क्रियाकलाप

• बजट 2009 पर बजट अवलोकन सत्र

प्रत्यक्ष कर समिति ने प्रत्यक्ष कर समिति तथा अंतरराष्ट्रीय कराधान समिति के सहयोग से संघीय बजट - 2009 पर 6 जुलाई, 2009 को एक बजट अवलोकन सत्र का आयोजन किया था। सदस्यों और अन्य आमंत्रितियों ने वित्त विधेयक, 2009 पर गहन परिचर्चा की थी और बजट - 2009 के संबंध में संस्थान के मत के ब्यौरे देते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी।

• बजट 2010 पर बजट अवलोकन सत्र

अप्रत्यक्ष कर समिति ने प्रत्यक्ष कर समिति तथा अंतरराष्ट्रीय कराधान समिति के साथ संयुक्त रूप से बजट - 2010-11 के प्रस्तावों का विश्लेषण करने के लिए 26 फरवरी, 2010 को एक बजट अवलोकन सत्र का

आयोजन किया था। बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात् इसके प्रस्तावों पर सदस्यों ने ब्यौरेवार चर्चा की थी और उन्हें हाईलाइट्स के रूप में सारांशित किया गया था और वेबसाइट पर रखा गया था। इसके अतिरिक्त, समिति ने बजट प्रस्ताव से उद्भूत होने वाले मुद्दों पर ब्यौरेवार टिप्पण तैयार किए थे और उन्हें वेबसाइट पर रखा गया था। समिति ने प्रत्यक्ष कर समिति के साथ संयुक्त रूप से उस दिन एक सीधे वेबकास्ट का आयोजन भी किया था।

● **संघीय बजट 2009 पर कार्यशाला**

समिति ने 17 जुलाई, 2009 को प्रत्यक्ष कर समिति के सहयोग से संघीय बजट-2009 पर एक कार्यशाला का आयोजन किया था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के श्री बी. श्रीधर, तत्कालीन सदस्य (बजट), श्री विवेक जोहरी, संयुक्त सचिव, (टीआरयू) और श्री गौतम भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव, (टीआरयू) ने इस कार्यशाला को संबोधित किया था।

● **बजट - 2010 के अप्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्तावों पर कार्यशाला**

समिति ने 16 मार्च, 2010 को सीबीईसी के पद्धारियों के साथ अप्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के लिए संघीय बजट - 2010 पर एक कार्यशाला का आयोजन किया था। श्री गौतम भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव, (टीआरयू) और सीए सुशील सोलंकी, आयुक्त, सीबीईसी ने इस कार्यशाला को संबोधित किया था। सदस्यों ने बजट प्रस्तावों से उद्भूत होने वाले संभावित मुद्दों की ओर सीबीईसी के प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित किया था। इस कार्यशाला की काफी सराहना हुई थी।

5.15.2 संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशाला/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

- 4 अगस्त, 2009 को सतत वृत्तिक शिक्षा समिति के साथ संयुक्त रूप से, डोंडीवलों में अप्रत्यक्ष कर संबंधी एक कार्यशाला का आयोजन किया था जिसकी मेजबानी आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की ठाणे शाखा द्वारा की गई थी।
- प्रत्यक्ष कर समिति के साथ संयुक्त रूप से 1 और 2 अगस्त, 2009 को एक राष्ट्रीय कर अभिसमय।
- 16 अगस्त, 2009 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में अप्रत्यक्ष करों संबंधी एक राष्ट्रीय संगोष्ठी।
- 26 अगस्त, 2009 को त्रिवेंद्रम में अंतरराष्ट्रीय कराधान समिति के साथ संयुक्त रूप से करों संबंधी एक राष्ट्रीय संगोष्ठी।
- 28 अगस्त, 2009 का कोलकाता में वैट, सेनवैट, सेवाकर और जीएसटी संबंधी एक राष्ट्रीय संगोष्ठी।

● **सेवा कर पर तीन दिवसीय आधारिक स्तर पाठ्यक्रम**

तीन दिवसीय आधारिक स्तर पाठ्यक्रम का आयोजित करने का मूल विचार समिति द्वारा वर्ष 2008 के दौरान आरंभ किया गया था, जब सुसंगत समय पर वित्तीय विधि समिति के स्थान पर दो पृथक समितियों—एक अप्रत्यक्ष कर और अन्य प्रत्यक्ष कर समिति का सृजन किया गया था। चूंकि अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में तीव्र गति से विकास हो रहा था इसलिए अप्रत्यक्ष कर समिति ने देश भर में सेवा कर पर तीन दिवसीय आधारिक स्तर पाठ्यक्रम को आयोजित करने के इस क्रियाकलाप को जारी रखना उचित समझा। समिति ने 2009-10 के दौरान “सेवा कर पर तीन दिवसीय आधारिक स्तर पाठ्यक्रम” संबंधी दो कार्यक्रमों का आयोजन किया था, एक धनबाद में जिसकी मेजबानी सीआईआरसी की धनबाद शाखा द्वारा की गई थी और दूसरा एसआईआरसी की पालघाट शाखा में।

● **सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम**

समिति ने भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) समूह ‘क’, 60वें बैच के

परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए “अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में वित्तीय और लेखांकन उपकरणों का उपयोग” विषय पर एक दो सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 1 जून से 12 जून, 2009 के दौरान राष्ट्रीय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और स्वापक अकादमी, एनएसीईएन कॉम्प्लेक्स, फरीदाबाद में किया गया था। इस पाठ्यक्रम में 130 आईआरएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने भाग लिया था और इस कार्यक्रम को काफी सराहना प्राप्त हुई थी।

5.15.3 प्रकाशन

● बजटपश्च ज्ञापन, 2009

समिति ने 20 जुलाई, 2009 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों को बजटपश्च ज्ञापन, 2009 प्रस्तुत किया था। इसके अतिरिक्त इस बजटपश्च ज्ञापन को आईसीएआई के वेबसाइट पर भी रखा गया था।

● बजटपूर्व ज्ञापन, 2010

प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं से प्राप्त सुझावों के आधार पर, समिति ने बजटपूर्व ज्ञापन - 2010 तैयार किया था, जिसमें संस्थान के सुझाव अंतर्विष्ट थे और उसे सरकार को प्रस्तुत किया गया था।

● बजटपश्च ज्ञापन, 2010

समिति ने सरकार को बजटपश्च ज्ञापन, 2010 प्रस्तुत किया था जिसमें बजट-2010 के अप्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रस्तावों के संबंध में संस्थान के सुझाव अंतर्विष्ट थे। इस बजटपश्च ज्ञापन को आईसीएआई की वेबसाइट पर भी रखा गया था।

● गार्ड टू गोवा वैट ऑडिट - नया प्रकाशन

चूंकि सदस्य राज्य वैट से संबंधित मामलों को भी देखते हैं, इसलिए राज्य वैट संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन निकालने का विनिश्चय किया गया था। इस संबंध में, समिति द्वारा गोवा वैट संबंधी एक कार्य समूह का गठन किया गया था। इस कार्य समूह ने “गार्ड टू गोवा वैट ऑडिट” नामक प्रकाशन निकालने के लिए समिति को “गार्ड टू गोवा वैट ऑडिट” का एक आधारीक प्रारूप उपलब्ध कराया था जिसे समिति द्वारा अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् प्रकाशित किया गया था।

● गार्ड टू कर्नाटक वैट ऑडिट - नया प्रकाशन

इसी प्रकार, “गार्ड टू कर्नाटक वैट ऑडिट” निकालने के लिए समिति द्वारा कर्नाटक वैट संबंधी एक कार्य समूह का गठन किया गया था और उक्त कार्य समूह ने इस प्रकाशन का एक आधारीक प्रारूप उपलब्ध कराया था जिसे समिति द्वारा अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् प्रकाशित किया गया था।

● भारत में माल और सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में सिफारिशें

सरकार द्वारा देश में माल और सेवा कर प्रारंभ किए जाने के लिए की जाने वाली कार्यवाहियों, और 10 नवम्बर, 2009 को सरकार द्वारा भारत में माल और सेवा कर संबंधी प्रथम परामर्श पत्र को जारी किए जाने को ध्यान में रखते हुए समिति ने जनवरी, 2010 में भारत में माल और सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत की थीं।

5.15.4 अन्य

● बजट - 2009 संबंधी लेखों का सीए जर्नल में प्रकाशन

समिति ने अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में वृत्ति कर रहे वृत्ति के सदस्यों से बजट - 2009 में अप्रत्यक्ष करों संबंधी प्रस्तावों पर लेख आमंत्रित किए थे। इस प्रकार संस्थान के जर्नल - दि चार्टर्ड एकाउंटेंट में ‘बजट 2009 -

सर्विस टैक्स प्रस्पेक्टिव' और 'बजट 2009 - इनडायरेक्ट टैक्सेशन - डेविल इन फाइन प्रिंट ?' शीर्षक वाले लेख प्रकाशित किए गए थे ।

● बजट - 2010 संबंधी लेखों का सीए जर्नल में प्रकाशन

26 फरवरी, 2010 को बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात्, साधारण व्यवहार के रूप में समिति ने सदस्यों से वित्त विधेयक - 2010 में अप्रत्यक्ष करों संबंधी उपबंधों पर लेख आमंत्रित किए थे । इस प्रकार संस्थान के जर्नल - दि चार्टर्ड एकाउंटेंट में 'अमेंडमेंट इन सेनटेड क्रेडिट रूल्स, 2004', 'सर्विस टैक्स प्रोपोजल्स अंडर दि फाइनेंस बिल, 2010' और 'कंसट्रक्शंस सर्विसेज' शीर्षक वाले लेख प्रकाशित किए गए थे ।

5.16 सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति

5.16.1 पर्यावलोकन

वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी, पूर्व में कारबार समर्थकर्ता की अल्प भूमिका से परिवर्तित होकर चयनित कारबार प्रचालक के रूप में उभरी है । सूचना प्रौद्योगिकी ने आधुनिक कारबार संव्यवहार में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं क्योंकि उद्यम और सरकारें अपने प्रचालनों के बेहतर प्रबंध और अपने ग्राहकों/नागरिकों को ई-सेवाओं/ई-शासन पहलों - ई-बैंकिंग/ई-सेवा/ई-संदाय /ई-शासन/ई-आरक्षण/ई-उपापन/ई-निविदाएं जैसी मूल्यवर्धित सेवाओं का प्रस्ताव करने के लिए बड़ी मात्रा में सूचना प्रौद्योगिकी को अपना रही हैं ।

नए डब्ल्यूटीओ को देखते हुए और विश्व के एक वैश्विक गांव में परिवर्तन के साथ भारतीय कारबार परिदृश्य में अधिकाधिक आईटी समर्थ सेवाएं (आईटीईएस) सम्मिलित हो रही हैं, जैसे कि ईआरपी, कारबार प्रक्रिया बाहरी स्रोत (बी.पी.ओ)/सूचना प्रक्रिया बाहरी स्रोत (केपीओ) ।

संस्थान की परिषद् ने, नियमित रूप से सूचना प्रौद्योगिकी चुनौतियों का मूल्यांकन करने और उचित शिक्षा तथा विकासशील कार्यक्रमों जैसे कि अर्हतापश्च पाठ्यक्रमों/सम्मेलनों/ संगोष्ठियों/ व्यवहारिक कार्यशालाओं के माध्यम से उन्हें वृत्ति के लिए लाभप्रद वृत्तिक अवसरों के रूप में संपरिवर्तन करने और साथ ही अध्ययन गाईडों, संसाधनों, ई-लर्निंग/ कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण पद्धतियों को तैयार करने के लिए वर्ष 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति का गठन किया था ।

समिति की प्रथम पहल, सीए को सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अर्हतापश्च पाठ्यक्रम (पीक्यूसी) के माध्यम से आईएस संपरीक्षा/प्रणाली और प्रक्रिया संपरीक्षा आश्वासन (एसपीए) मूल्यवर्धित सेवाएं प्रस्तावित करने के लिए सुसज्जित करना था, जिनके लिए दिनोंदिन मांग बढ़ती जा रही है । सीए अधिकाधिक रूप से इन सेवाओं का प्रस्ताव अपने ग्राहकों, विशेषकर बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं/ स्टॉक ब्रोकरों आदि को कर रहे हैं, जहां यह कानूनी अपेक्षा है ।

मांग, विशेषकर आईएस सदस्यों की मांग पर विचार करते हुए समिति ने संकर्मों की दक्षता और प्रभावकारिता में वृद्धि करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग संबंधी व्यवहारिक कार्यशालाओं की प्रस्थापना करना प्रारंभ कर दिया है, जिससे कि सीए एक उपकरण के रूप में आईटी का उपयोग करके अपने ग्राहकों को मूल्यवर्धित सेवाओं का प्रस्ताव कर सकें ! समिति कंप्यूटर से सहायता प्राप्त संपरीक्षा तकनीकों/साधारण संपरीक्षा सॉफ्टवेयर विषय पर त्वरित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सीएएटी विषय पर सीपीई पाठ्यक्रम की प्रस्थापना भी करती है और साथ ही उसने सीएएटी संसाधन सीडी भी जारी की है ।

समिति ने वृत्ति के विकास के लिए अग्रिम क्षेत्र के रूप में ईआरपी परामर्श की पहचान की है और इस क्षेत्र में उभरते अधिकाधिक वृत्तिक अवसरों को ध्यान में रखते हुए उसने एसएपी एफए और एसएपी एमए और माइक्रोसॉफ्ट डाइनेमिक्स एनएवी संबंधित पाठ्यक्रमों की प्रस्थापना करना आरंभ कर दिया है ।

समिति ने संस्थान की सतत वृत्तिक शिक्षा समिति के साथ “ बैंक शाखा संपरीक्षा -एक पर्यावलोकन” विषय पर ई-लर्निंग/कंप्यूटर आधारित लर्निंग पद्धति प्रारंभ की है और “सीएएटी/जीएएस का उपयोग करना - एक प्रस्तावना” और “ एमएसएक्सेल का सीएएटी/जीएएस के उपकरण के रूप में उपयोग करना” विषय पर एक मोड्यूल जारी किया है । समिति ने सेवा कर और आईएफआरएस संबंधी ई-लर्निंग पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए थे ।

समिति सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सीए की सक्षमताओं को विकसित करने और उनके लिए वृत्तिक अवसर तैयार करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है।

समिति ने संस्थान की सतत वृत्तिक शिक्षा समिति के सहयोग से, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वृत्ति सूचना प्रौद्योगिकी से सुसज्जित है, संस्थान की पहल के भाग रूप में वरिष्ठ सदस्यों के लिए कंप्यूटर मूल्यांकन पाठ्यक्रम भी आरंभ किया है। इस पाठ्यक्रम के बैचों का आयोजन, संस्थान द्वारा स्थापित आईटीटी केन्द्रों में किया जाता है।

समिति ने “सूचना प्रौद्योगिकी के समय में न्यायिक लेखांकन और कपट की पहचान करने संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम” प्रारंभ किया है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य कपटों की पहचान में लेखांकन, संपरीक्षा सिद्धांतों का उपयोग करके निगम/कारखाने कपटों का पता लगाने, पारिणामिक हानि का लेखा-जोखा करने, मुकदमेबाजी के लिए समर्थन/ बाहरी काउंसिल उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित अन्वेषणात्मक कौशल विकसित करना है। इस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के पहले बैच का आयोजन जनवरी, 2009 में मुंबई में किया गया था।

5.16.2 पहले

5.16.2.1 परियोजना परिवर्तन (आईसीएआई में ई-शासन का संवर्धन)

समिति ने परियोजना ‘परिवर्तन’ की परिकल्पना इस विचार से की है कि यह आईसीएआई के कार्यकरण को एक नए रास्ते पर ले जाएगा जो देश के विद्यमान चार्टर्ड एकाउंटेंट और चार्टर्ड एकाउंटेंट बनने के इच्छुक व्यक्तियों को एक सीए परिवार के रूप में एक साथ लाएगा। इसका उद्देश्य एक ऐसी एकल एकीकृत प्रणाली का सृजन करना है जो चार्टर्ड एकाउंटेंटों और छात्रों के भौगोलिक अवस्थानों पर ध्यान न देते हुए इन्टरनेट के माध्यम से उनके पूरे समुदाय की एकसाथ सेवा करे। इस परियोजना के अधीन सदस्यों और छात्रों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए पूर्व में नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, बंगलोर, एर्नाकुलम और जयपुर में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। इन्फोसिस टेक्नोलॉजिस लिमिटेड, जो आईटी के क्षेत्र में विश्व की अग्रणी कंपनी है, आईसीएआई को विश्व का एक विश्वस्तरीय उच्च प्रौद्योगिकी वाला एक लेखांकन निकाय बनने में सहायता कर रही है।

5.16.2.2 प्रकाशन

समिति ने सदस्यों के फायदे के लिए और इन नए क्षेत्रों में सदस्यों की विशेषज्ञता विकसित करने के लिए पांच नए प्रकाशन भी जारी किए हैं, अर्थात् “टेक्निकल गाइड ऑन सिस्टम्स ऑडिट ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स”, “टेक्निकल गाइड ऑन इनफ़ोरमेशन सिस्टम्स ऑडिट”, “डाटा एनालिसिस फॉर ऑडिटर्स - प्रैक्टिकल केस स्टडीज ऑन यूजिंग सीएएटी”, “टेक्निकल गाइड ऑन आईटी माइग्रेशन ऑडिट” और “एक्सबीआरएल - ए प्राइमर”।

5.16.2.3 अंतरराष्ट्रीय पहले

समिति ने आईसीएआई और श्रीलंका चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएसएल) के बीच हस्ताक्षरित परस्पर समझ ज्ञापन के अनुसार आईसीएसएल के सदस्यों के लिए आईएसए पाठ्यक्रम के आयोजन को सुकर बनाया था।

5.16.2.4 नवीन समिति पोर्टल

समिति ने अपने नए सीआईटी पोर्टल को आरंभ किया है जो अतिरिक्त विशिष्टियों के साथ और अधिक उपयोक्ता मित्र और दक्ष है। इसे विजुअल स्टुडियो 2008 में विकसित किया गया है और यह आरएसएस प्रसुविधा से सुसज्जित है, जिसका उपयोग करके उपयोक्ता इस साइट पर नवीनतम अद्यतन प्राप्त कर सकते हैं। नए पोर्टल में आईएस संस्था, साइबर खतरों और पुनर्विलोकन संबंधी ऑन लाइन ई-लर्निंग मॉड्यूल सम्मिलित हैं। सदस्य इस पोर्टल को <http://cit.icai.org> पर देख सकते हैं।

5.16.2.5 बैंकों और आरबीआई पदधारियों के लिए न्यायिक लेखांकन पाठ्यक्रम

समिति ने संस्थान के सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में कॉलेज ऑफ एग्रिकल्चरल बैंकिंग (सीएबी), पूणे को आरबीआई पदधारियों के लिए न्यायिक लेखांकन पाठ्यक्रम का संचालन करने में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के प्रति स्वीकृति प्रदान कर दी है और तदनुसार इस पाठ्यक्रम का संचालन किया गया था।

5.16.2.6 सूचना प्रणाली संपरीक्षा (आईएसए) पीक्यूसी के लिए नई पाठ्यचर्या और पृष्ठभूमि सामग्री

आईटी समिति ने पुनरीक्षित आईएसए पृष्ठभूमि सामग्री जारी की थी और उसका उपयोग 1 अप्रैल, 2010 से आईएसए वृत्तिक प्रशिक्षण (पीटी) के बैचों द्वारा किया जा रहा है और यह नवम्बर, 2010 और दिसम्बर, 2010 में आईएसए निर्धारण परीक्षा (एटी) में पुनरीक्षित पाठ्यचर्या के साथ पात्रता परीक्षा को सुकर बनाएगा।

5.16.2.7 सूचना प्रणाली संपरीक्षा पर अर्हता पश्च पाठ्यक्रम

सूचना प्रणाली संपरीक्षा (आईएसए) पर अर्हता पश्च पाठ्यक्रम सदस्यों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय बना रहा। इस पाठ्यक्रम में देशभर के सदस्यों के लिए विकास और संवर्धन हेतु एक अद्वितीय केन्द्र उपलब्ध कराने की क्षमता है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान समिति ने 60 केन्द्रों में आईएसए वृत्तिक प्रशिक्षण के 60 बैचों का आयोजन किया था और लगभग 61 केन्द्रों में आईएसए पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया था। निम्नलिखित सारणी में संख्या संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं :

विशिष्टियाँ	रजिस्ट्रीकरण	ईटीउत्तीर्ण
1 अप्रैल, 2009 को	28,935	19,760
वर्ष के दौरान	1,989	1,225
31 मार्च, 2010 को	30,579	20,985

5.16.2.8 आईटी समिति द्वारा प्रस्थापित विभिन्न पाठ्यक्रमों के रजिस्ट्रीकरण संबंधी आंकड़े

सीएएटी, एसएपी ईआरपी पाठ्यक्रम, माइक्रोसॉफ्ट एनएवी डायनेमिक्स और न्यायिक लेखांकन तथा आईटी और सीएएटी का उपयोग करके कपट का पता लगाने संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में 31 मार्च, 2010 को रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की संख्या के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	31 मार्च, 2010 को रजिस्ट्रीकरण
1.	सीएएटी	3,205
2.	एसएपी ईआरपी पाठ्यक्रम	355
3.	माइक्रोसॉफ्ट एनएवी डायनेमिक्स	74
4.	एफएएफडी	33

5.17 आंतरिक संपरीक्षा संबंधी समिति

प्रभावी निगम शासन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सुदृढ़, कुशल और स्वतंत्र आंतरिक संपरीक्षा कृत्य आधारभूत अपेक्षा है। आंतरिक संपरीक्षा को निगम शासन के चार स्तंभों में से - बोर्ड, प्रबंध और बाह्य संपरीक्षकों के साथ एक स्तंभ के रूप में माना जाता है। किसी संगठन के भीतर जोखिमों का निर्धारण और मानिटरि करने और स्थापित किए गए नियंत्रणों की प्रभाविकता के संबंध में आश्वासन उपलब्ध कराने के उत्तरदायित्व से लैस आंतरिक संपरीक्षक निगम जवाबदेही के क्षेत्र में अग्रणी की भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार, आंतरिक संपरीक्षकों को अधिकाधिक संगठनात्मक सफलता सुनिश्चित करने की कुंजी के रूप में मान्यता प्राप्त हो रही है।

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी क्रियाकलाप पिछले कुछ समय से भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के ध्यान का प्रमुख केन्द्र बने हुए हैं, जिसने 5 फरवरी, 2004 को आंतरिक संपरीक्षा संबंधी एक अस्थायी समिति का गठन किया था। इस समिति का प्रमुख उद्देश्य भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की देश में आंतरिक संपरीक्षा के ज्ञान

के संवर्द्धक, स्रोत और प्रबंधकर्ता के अग्रज के रूप में छवि को मजबूत करना है। इस समिति का मूल विचार संस्थान के सदस्यों को आंतरिक संपरीक्षा के क्षेत्र के संबंध में और अधिक प्रभावी तथा कुशल मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध कराने में समर्थ बनाना है जिससे कि ग्राहकों की नियंत्रण और जोखिम प्रबंध प्रक्रियाओं के प्रणालीकरण और सुदृढीकरण के द्वारा उनकी शासन प्रक्रिया को प्रणालीकृत और मजबूत बनाया जा सके।

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी समिति द्वारा भारत में आंतरिक संपरीक्षा की वृद्धि और विकास में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए समिति को नवम्बर, 2008 में “आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड” के रूप में पुनर्नामित किया गया था। इस प्रकार समिति से बोर्ड में संपरिवर्तन संस्थान द्वारा आंतरिक संपरीक्षा के क्षेत्र में एक नई भावी योजना के निर्माण के प्रति एक कदम है, जो सक्रिय कारगर परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न की जा रही चुनौतियों को पूरा करने में समर्थ बनाएगा। बोर्ड आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों और तकनीकी गाईडों/अध्ययनों/मैनुअलों के रूप में उच्च स्तरीय तकनीकी साहित्य निकालने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है जो आंतरिक संपरीक्षकों की ग्राहकों और/या नियोजकों को प्रभावी और कुशल आंतरिक संपरीक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करते हैं।

5.17.1 आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक

संस्थान आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक निकालता रहा है क्योंकि ये मानक आंतरिक संपरीक्षकों की स्थिति को सुदृढ़ करने और उनके लिए कार्यपालन संबंधी बैचमार्क बनाने में कारगर सिद्ध होंगे। ये मानक आंतरिक संपरीक्षकों के लिए सर्वोत्तम व्यवहारों की एक संहिता उपलब्ध कराते हैं। संस्थान ने 31 मार्च, 2009 तक 16 आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक जारी किए हैं, जिनमें आंतरिक संपरीक्षा को शासित करने वाले मूल सिद्धांत, दस्तावेजीकरण, विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं, आंतरिक संपरीक्षा साक्ष्य, रिपोर्टिंग, उद्यम जोखिम प्रबंध आदि सम्मिलित हैं।

इस अवधि के दौरान, आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड ने निम्नलिखित एसआईए जारी किए हैं :

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 17, किसी आंतरिक संपरीक्षा में विधियों और विनियमों का विचार

यह आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) आंतरिक संपरीक्षा में किसी आंतरिक संपरीक्षक द्वारा विधियों और विनियमों पर विचार करने से संबंधित है। यह एसआईए ऐसे अन्य नियोजनों को भी लागू होता है, जिनमें किसी आंतरिक संपरीक्षक को विनिर्दिष्ट विधियों या विनियमों के अनुपालन के संबंध में पृथक रूप से जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नियोजित किया जाता है।

5.17.2 तकनीकी मार्गदर्शन

मानक निकाले जाने के अलावा, बोर्ड आंतरिक संपरीक्षा संबंधी उद्योग विनिर्दिष्ट मार्गदर्शनों का सूत्रीकरण करने के लिए भी तेजी से कार्य कर रहा है। बोर्ड ने तेल और गैस उद्योग, एलुमीनियम उद्योग, दूर संचार उद्योग, स्टॉक ब्रोकरों, अमूर्त आस्तियों आदि की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन जारी किए हैं। इन तकनीकी मार्गदर्शनों का मूल उद्देश्य, सदस्यों और साथ ही अन्य पाठकों की सुसंगत उद्योग में किए जाने वाले मूल प्रचालनों को समझने में सहायता करना है। ये तकनीकी मार्गदर्शन किन्हीं विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के संबंध में किसी आंतरिक संपरीक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली ब्यौरेवार प्रक्रियाओं को भी समाविष्ट करते हैं।

इस अवधि के दौरान आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड द्वारा निम्नलिखित तकनीकी मार्गदर्शन जारी किए गए हैं :

1. बैंकों के खजाना संबंधी कृत्यों की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन

इस तकनीकी मार्गदर्शन का प्रयोजन पाठकों के लिए बैंकों के खजाना संबंधी कृत्यों की भूमिका और उत्तरदायित्वों को समझने और उसके मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करना है और साथ ही यह की जाने वाली आंतरिक संपरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति के अवधारण में भी सहायता करता है। यह तकनीकी मार्गदर्शन खजाना/बाजार जोखिम के विनिर्दिष्ट संदर्भ से मूलभूत नियंत्रणों और आंतरिक संपरीक्षा से भी संबंधित हैं।

2. शैक्षिक संस्थाओं की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन

यह तकनीकी मार्गदर्शन विभिन्न किस्मों की शैक्षिक संस्थाओं के लिए सुसंगत प्रचालनात्मक और आंतरिक संपरीक्षा संबंधी पहलुओं पर सारवान संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराता है।

3. सन्निर्माण उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन

यह तकनीकी मार्गदर्शन सन्निर्माण उद्योग के विशिष्ट पहलुओं के संबंध में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों के संदर्भ से किसी आंतरिक संपरीक्षा की सकल अवधारणा और की जाने वाली प्रक्रियाओं के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है।

इसके अतिरिक्त बोर्ड ने कतिपय उद्योगों/क्षेत्रों, जिनके अंतर्गत चीनी उद्योग, बीपीओ उद्योग, गैर लाभकारी संगठन, अवसंरचना, विद्युत, मनोरंजन, विद्युत वितरण कंपनियों, होटल और पर्यटन, विमानन, समाचार पत्र, सॉफ्टवेयर विकसित करने आदि की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन तैयार करने से संबंधित परियोजनाएं भी आरंभ की हैं।

बोर्ड की अन्य चालू परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :

- बैंकों के लिए उद्यम रिपोर्ट
- आंतरिक संपरीक्षा चार्टर संबंधी अध्ययन
- कपट अन्वेषणों संबंधी अध्ययन
- कृत्यकारी प्रधानों के साथ आंतरिक संपरीक्षकों के समन्वयन संबंधी अध्ययन
- कार्यान्वयन मार्गदर्शन
 - एसआईए 4, रिपोर्टिंग
 - एसआईए 7, आंतरिक संपरीक्षा में क्वालिटी आश्वासन

5.17.3 सम्मेलन और अन्य कार्यक्रम

आंतरिक संपरीक्षा के क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं के संबंध में जागरूकता बनाने के विचार से, बोर्ड ने प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं के सहयोग से निम्नलिखित संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया है :

- (क) हैदराबाद में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी संगोष्ठी
- (ख) पटना में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी राष्ट्रीय संगोष्ठी
- (ग) देहरादून में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी संगोष्ठी
- (घ) विशाखापत्तनम में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी संगोष्ठी
- (ङ) मुंबई में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी संगोष्ठी - प्रबंध के लिए उपकरण
- (च) दिल्ली में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी संगोष्ठी और ईआरएम

5.17.4 पाठ्यक्रम

बोर्ड ने मुंबई और नई दिल्ली, प्रत्येक में एक-एक उद्यम जोखिम प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में संस्थान के सदस्यों को आवश्यक तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञता प्रदान करना और उनके कौशल का निर्माण करना और इस प्रकार उद्यम जोखिम प्रबंध के विभिन्न पहलुओं में उन्हें अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार करना और इस क्षेत्र को एक अंतर्निहित क्षमता वाले क्षेत्र के रूप में विकसित करना सम्मिलित है।

पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों की वृत्तिक और व्यक्तिगत पूर्व व्यस्तताओं को ध्यान में रखते हुए इस पाठ्यक्रम को इस प्रकार तैयार किया गया है कि यह एक कक्षा अध्यापन, ई-लर्निंग और साथ ही स्वअध्ययन का एक संतुलित मिश्रण है। कक्षा अध्यापन को छह सप्ताह के कक्षा समय ढांचे के अंतर्गत पूरा किया जाएगा जिसमें छह शनिवारों को कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।

5.17.5 अन्य

बोर्ड ने आधुनिक संगठनों की विकास संबंधी आवश्यकताओं और आंतरिक संपरीक्षा कृत्य की परिवर्तनशील भूमिका को मुख्य रूप से उपदर्शित करते हुए “आंतरिक संपरीक्षा क्या है” शीर्षक वाला एक ब्राशर भी जारी किया था।

5.18 अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी समिति

वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप विश्व एक छोटे गांव की भांति हो गया है जिसके कारण संप्रभु देशों की सीमाओं के आस-पास मानवों, पूंजी और मालों के संचलन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। सीमा पार संव्यवहारों में घरेलू संव्यवहारों से भिन्न कर विवक्षाएं अंतर्विष्ट होती हैं। किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसी कर विवक्षाओं की जानकारी से लैस होगा। यह भी महसूस किया गया था कि यह आवश्यकता केवल महानगरों तक ही सीमित नहीं थी, अपितु यह पूर्ण देश में एक समान थी।

सीमा पार संव्यवहारों की सदैव बढ़ती संख्या से संबंधित कर विवक्षाओं को बेहतर रूप से समझने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2009 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय कराधान पर एक पृथक समिति का गठन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य सदस्यों के बीच अंतरराष्ट्रीय कराधान की जानकारी का प्रसार करना था जिससे कि सेवाओं के उपयोक्ताओं/प्राप्तकर्ताओं के लिए एक अच्छे सलाहकार के रूप में उनकी सक्षमता को सुदृढ़ किया जा सके। इसका उद्देश्य सदस्यों को अंतरराष्ट्रीय कराधान की बेहतर समझ हेतु सशक्त करना और इस जानकारी को व्यवहारिक परिस्थितियों में लागू करने की सक्षमता का निर्माण करना है।

5.18.1 क्रियाकलाप

- समिति ने अपने प्रयासों में एक भलीभांति संरचित अवधारणा लाने के विचार से मुंबई, हैदराबाद और नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी अर्हतापश्च प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को प्रारंभ किया और उसके तीन बैचों को सफलतापूर्वक पूरा किया। इन पाठ्यक्रमों के मूल्यवर्धन के लिए, इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारण परीक्षा का आयोजन किया गया था और उत्तीर्ण व्यक्तियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए थे। यह तथ्य उत्साहवर्धक है कि भाग लेने वाले व्यक्तियों ने इस विषय में व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले वृत्ति के विख्यात सदस्यों और इन विषयों से संबंधित वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए मूल्यवान अनुभव की सहायता से उत्कृष्ट मूल्यवर्धन प्राप्त किया है। ये प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम सदस्यों के बीच काफी लोकप्रिय हैं और देश के अनेक भागों से इन पाठ्यक्रमों के आयोजन के लिए मांग बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त विदेशी सदस्यों से प्राप्त हुई मांग के अनुसरण में इस पाठ्यक्रम को विदेशों में चयनित केन्द्रों में प्रारंभ करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।
- प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2009 के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी सामेति के सुझावों को आईसीएआई द्वारा सरकार को प्रस्तुत ज्ञापन में समुचित रूप से सम्मिलित किया गया था।
- समिति ने, अपने क्रियाकलापों के आधार को व्यापक बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संघ की सदस्यता को स्वीकार किया है।
- दूरस्थ और छोटे स्थानों में अवस्थित सदस्यों के लिए इस पाठ्यक्रम की उपलब्धता को सुकर बनाने के लिए समिति ने अंतरराष्ट्रीय कराधान में शिक्षा प्रदान करने की ई-पठन पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। तदनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के सहयोग से, अंतरण कीमत निर्धारण विषय पर एक ई-पठन मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है।

उपरोक्त क्रियाकलापों के अलावा, समिति ने निम्नलिखित प्रकाशन भी निकाले : ‘इंटरनेशनल टैक्सेशन - बैकग्राउंड मैटेरियल’ और ‘एबीसी ऑन डबल टैक्स अवायर्ड्स एग्रिमेंट्स’

5.19 उद्योग में सदस्यों के लिए समिति

5.19.1 पर्यावलोकन

उद्योग में लगे सदस्यों के लिए समिति आईसीएआई तथा विभिन्न हैसियत से उद्योगों में कार्य कर रहे चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के बीच निकट संपर्क बढ़ाने में लगी हुई है जिससे कि सरकारी संगठनों तथा अभिकरणों के साथ

गहन तथा व्यापक नातेदारी के विकास के माध्यम से ज्ञान, विशेषज्ञता, कौशल तथा व्यक्तिगत कैरियर विकास में सहायता दी जा सके ताकि उन्हें नियोजन के अधिकतम अवसर प्रदान करने के लक्ष्य को साथ-साथ पूरा करते समय व्यापार, वाणिज्य, उद्योग जगत तथा शासन को हर संभव अधिकतम अपावरण प्रदान किया जा सके।

समिति, उद्योग में अवसरों का पता लगाने में संस्थान के सदस्यों को सहायता प्रदान करती है। इस संबंध में, समिति संस्थान के सदस्यों तथा छात्रों के निम्नलिखित तीन प्रवर्गों के संबंध में सेवाएं प्रदान करने में लगी है :

- (i) कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के माध्यम से नए अर्हित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट।
- (ii) अनुभवी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट - जो वर्तमान में उद्योग में सेवा कर रहे हैं।
- (iii) अर्धअर्हित लेखांकन वृत्तिक।

सभी उपरोक्त सेवाएं प्लेसमेंट पोर्टल www.cmii.icai.org, और <http://Jobs4CAs.icai.org> के माध्यम से प्रशासित की जा रही हैं। आईसीएआई प्लेसमेंट पोर्टल वृत्तिकों (अर्हित और साथ ही अर्धअर्हित, दोनों) को अंतरराष्ट्रीय बेहतर पद्धति उन्मुखी वित्त तथा लेखांकन संस्कृति और भारतीय उद्योग के लिए क्षमता निर्माण के उद्देश्यों के साथ विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान करता है।

5.19.2 संस्थान के सदस्यों के फायदे के लिए आयोजित कैरियर सहायता कार्यक्रम

- वर्ष के दौरान सदस्यों के लिए कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों के आयोजन को अनेक केन्द्रों/स्थानों पर जारी रखा गया - एक कार्यक्रम अगस्त-सितम्बर, 2009 के दौरान और दूसरा फरवरी-मार्च, 2010 के दौरान आयोजित किया गया था। इन कार्यक्रमों में प्रस्तावित अधिकतम वेतन 70 लाख रुपए और न्यूनतम प्रस्तावित वेतन 3 लाख रुपए था। कुल 2436 अभ्यर्थियों को नौकरी प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।
- ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने मई, 2009, अक्टूबर, 2009 और जनवरी, 2010 में वृत्तिक कौशल विकास (साधारण कौशल) संबंधी त्रैमासिक आवासीय कार्यक्रम पूरा किया था, विशेष कैम्पस नियोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उपरोक्त विशेष कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों में क्रमशः 7, 13 और 6 संगठनों ने भाग लिया था और क्रमशः 28, 45 और 16 अभ्यर्थियों को नौकरियों का प्रस्ताव दिया गया था।
- लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) तथा मध्यम आकार की चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों के लिए अनन्य रूप से तैयार किए गए कैम्पस नियोजन कार्यक्रम
- लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) और लघु तथा मध्यम आकार की चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों के लिए अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंट हेतु कैम्पस नियोजन कार्यक्रम को देशभर के 13 केन्द्रों में जून, 2010 के दौरान आयोजित किया गया था जिससे कि सीए के प्रत्येक संभव नियोजक तक कैम्पस नियोजन कार्यक्रम की पहुंच बनाई जा सके। कुल मिलाकर 69 संगठनों ने 133 अभ्यर्थियों को नौकरी संबंधी प्रस्ताव दिए थे।

5.19.3 एच आर बैठकें

उद्योग के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने के प्रयास के रूप में, समिति ने (1) बंगलोर (2) चेन्नई, (3) कोलकाता, (4) मुंबई और (5) नई दिल्ली में एच आर बैठकों की एक श्रृंखला का आयोजन किया है।

5.19.4 आईसीएआई जॉब पोर्टल <http://Jobs4CA.icai.org>

समिति ने 21 अगस्त, 2009 को आईसीएआई के जॉब पोर्टल को प्रारंभ किया था। उक्त जॉब पोर्टल को उद्योग के लिए उनकी रिक्तियों को भरे जाने तथा चार्टर्ड एकाउंटेंट के लिए नौकरियां प्राप्त करने के एक मंच के रूप में तैयार और विकसित किया गया है।

5.19.5 नियोजन पोर्टल www.cmii.icaai.org की पुनःडिजाइनिंग

उद्योग में लगे सदस्यों संबंधी समिति ने नियोजन पोर्टल www.cmii.icaai.org की पुनःडिजाइनिंग की है, जिससे कि इसे और अधिक उपयोक्ता मित्र तथा कंपनियों और चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए संस्थान से परस्पर क्रिया करने के लिए अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके।

5.19.6 उद्योग में लगे सदस्यों के लिए सीपीई अध्ययन सर्कल का सृजन

उद्योग में लगे सदस्यों की सीपीई अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए समिति ने एक सक्रिय उपाय के रूप में उद्योग में लगे सदस्यों के लिए सीपीई अध्ययन सर्कलों हेतु संनियम तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समिति ने विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग में लगे सदस्यों के लिए 30 सीपीई अध्ययन सर्कल रजिस्ट्रीकृत किए हैं। ये सर्कल देश के विभिन्न भागों, अर्थात् बंगलोर (5), चेन्नई (2), दिल्ली (1), गुडगांव (2), हुगली (1), कोलकाता (1), मुंबई (6), नई दिल्ली (3), नोएडा (2), नंगमबक्कम (1), पूणे (2), सूरत (हजीरा) (1), तमिलनाडु (1), त्रिची (1), विशाखापत्तनम (1) में अवस्थित हैं।

5.19.7 उद्योग में लगे संस्थान के सदस्यों के बीच सक्षमता विकसित करना

• प्रकाशन

क. समिति ने नए अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंटों के फायदे के लिए उन्हें साक्षात्कार दल का सामना करने और उसी समय उन्हें सामान्य ज्ञान और उनसे सुसंगत विषयों के संबंध में जानकारी बनाने में समर्थ बनाने के लिए 'हैंडबुक फॉर न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड एकाउंटेंट्स' के दो संस्करण निकाले हैं।

ख. समिति ने समिति के ई-न्यूजलेटर - 'कारपोरेट कम्युनिकी' के तीन अंक जारी किए हैं।

ग. उद्योग में सेवास्त सदस्यों से सुसंगत प्रकाशनों को प्राधिकृत करने के लिए हित अभिव्यक्ति के लिए समिति द्वारा निमंत्रण जारी किए गए थे।

घ. समिति अपने प्रत्येक कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के पूरा होने के पश्चात् कैरियर वॉच शीर्षक के अधीन दि चार्टर्ड एकाउंटेंट जर्नल में लेख प्रस्तुत करती है।

• वृत्ति के गणमान्य नेताओं के साथ वेबकास्टिंग

समिति ने, सीए केकी मिस्त्री, सीईओ, एचडीएफसी समूह और सीए उत्तम प्रकाश अग्रवाल, सुसंगत समय पर पदाध्यक्ष के साथ 14 दिसंबर, 2009 को भारतीय, अर्थव्यवस्था में नवीनतम प्रवृत्तियों और चार्टर्ड एकाउंटेंटों की भूमिका से संबंधित मुद्दों पर वेबकास्टिंग कार्यक्रम का आयोजन किया था।

• आयोजित कार्यक्रम

समिति ने उद्योग में लगे सदस्यों को तैयार तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के अपने प्रयास में, विभिन्न विषयों, जिनके अंतर्गत व्यक्तित्व का विकास और वृत्तियों के लिए लक्ष्य तय करना, सूचना प्रौद्योगिकी, निजी साम्या, उत्कृष्टता का संवर्धन करने के लिए सक्षमताओं का विकास, अंतरराष्ट्रीय कराधान, आईएफआरएस और एक्सबीआरएल भी हैं, पर संस्थान के क्षेत्रों में सफलतापूर्वक 24 कार्यक्रमों का आयोजन किया था।

5.19.8 उद्योग में लगे सदस्यों के लिए सीपीई अपेक्षाएं

01.01.2008 से ऐसे सभी सदस्यों के लिए जो वृत्ति नहीं कर रहे हैं, सीपीई अपेक्षाओं को आज्ञापक बनाया गया है, जिसके अनुसार "ऐसे सभी सदस्यों से, जो व्यवसाय प्रमाणपत्र धारित नहीं कर रहे हैं या विदेश में निवास कर रहे हैं (चाहे वे व्यवसाय प्रमाणपत्र धारित कर रहे हैं अथवा नहीं) से, जब तक कि उन्हें छूट प्राप्त न हो, यह अपेक्षा की जाती है कि वे :

(क) प्रत्येक तीन वर्ष की रोलिंग अवधि में संरचित / गैर-संरचित पठन में न्यूनतम 45 सीपीई प्रत्यय घंटों को पूरा करें

(ख) प्रत्येक वर्ष में संरचित/गैर-संरचित पठन में न्यूनतम 10 सीपीई प्रत्यय घंटों को पूरा करें।

5.19.9 उद्योग में कार्य कर रहे सदस्यों के आंकड़े

संस्थान की कुल सदस्यता की तुलना में उद्योग में लगे सदस्यों की कुल संख्या निम्नानुसार है :

निम्नलिखित तारीख को	उद्योग में लगे सदस्य [वृत्ति नहीं कर रहे और अंशकालिक रूप से वृत्ति कर रहे सदस्यों का योग]	कुल सदस्यता
1 अप्रैल, 2005	56677	123546
1 अप्रैल, 2006	62920	130946
1 अप्रैल, 2007	70897	139841
1 अप्रैल, 2008	76502	145481
1 अप्रैल, 2009	83238	153600
1 अप्रैल, 2010	88054	161516

5.19.10 सीएफओ गिल्ड और उद्योग गिल्ड में सदस्य

सीएफओ गिल्ड

इस गिल्ड में ऐसे सदस्य सम्मिलित हैं, जो उद्योग में उच्च पदों (सीईओ/सीएफओ / खजाना प्रधान/विश्लेषकों का प्रधान, जीएम या उच्च पंक्ति) के पदों पर आसीन हैं। ऐसी किसी गिल्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा मंच विकसित करना है जहां विभिन्न संगठनों के अत्यधिक बुद्धिजीवी और योग्य व्यक्तियों के समूह के व्यक्ति विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकें। वे उद्योग की दृष्टि में चार्टर्ड एकाउंटेंटों की छवि को सुधारने की योजना और नीतियां तैयार कर सकते हैं। इस गिल्ड में अब तक 3510 सदस्य रजिस्ट्रीकृत हैं।

उद्योग गिल्ड में सदस्य

ऐसी किसी गिल्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उद्योग में सेवारत हमारे संस्थान के सदस्यों का उद्योगवार डाटाबेस विकसित करना और बनाए रखना है। यह गिल्ड एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करता है, जहां वृत्ति से संबंधित विभिन्न साधारण मुद्दों और विशेषकर उद्योग में लगे सदस्यों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इस गिल्ड में अब तक 536 सदस्य रजिस्ट्रीकृत हैं।

5.19.11 महत्वपूर्ण पहलें

• संतोषप्रद सर्वेक्षण

समिति ने नियोजकों और अभ्यर्थियों के बीच संतोषप्रद सर्वेक्षण कराने के लिए ऑन लाइन प्रश्नोत्तर जारी किए थे, जो नीचे दिए गए हैं :

क. चयनपूर्व प्रश्नोत्तर - अभ्यर्थी के लिए

ख. चयनपश्च प्रतिक्रिया प्ररूप - अभ्यर्थी के लिए

ग. कंपनी प्रतिक्रिया प्ररूप

इस सर्वेक्षण का उद्देश्य बढ़ते संघर्ष के कारणों का विश्लेषण करना था।

• सर्वेक्षण के परिणाम

प्रत्युत्तर देने वाले अधिकांश व्यक्तियों ने अभिवृद्धि और विकास प्रथम कारक के रूप में और जॉब प्रोफाइल को द्वितीय कारक के रूप में श्रेणीबद्ध किया था। संगठन का ब्रांड मूल्य तृतीय स्थान पर था और तैनात करने का अवस्थान, प्रतिकर और कार्यसमय क्रमशः 4, 5 और 6 स्थान पर थे।

किसी संगठन के साथ संबद्ध होने के लिए अभिवृद्धि और विकास को प्रमुख कारक माना गया था, जिसके पश्चात् क्रमशः जॉब प्रोफाइल, संगठन का ब्रांड मूल्य, तैनात करने का अवस्थान, प्रतिकार और कार्यसमय थे।

• **गैर-पारंपरिक स्थानों में कार्यरत उद्योग में लगे सदस्यों की मान्यता :**

समिति ने उद्योग में लगे ऐसे सदस्यों को विशिष्ट रूप से दर्शित करने के लिए एक अनुसूची पत्र की थी, जो ऐसे क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जो चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की वृत्ति के अनुरूप पारंपरिक नहीं हैं। गैर पारंपरिक क्षेत्रों, जैसे कि विपणन, सॉफ्टवेयर का विकास, जोखिम प्रबंध, विधिक, सामाजिक-आर्थिक और प्रबंध परामर्श में चार्टर्ड एकाउंटेंटों के चयनित अनुभवों को कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों संबंधी ब्राशर में सम्मिलित किया गया था और आईसीएआई की वेबसाइट और सीए जर्नल में भी रखा गया था।

• **सीए वृत्ति के निगम उद्यमियों को मान्यता**

समिति ने, संस्थान के जर्नल में प्रकाशन के लिए उद्योग में लगे चार्टर्ड एकाउंटेंटों के महत्त्व के बारे में प्रमुख उद्योगपतियों से कोट आमंत्रित किए थे।

5.19.12 तीसरा वार्षिक निगम मंच

समिति ने 29 जनवरी से 31 जनवरी, 2010 के दौरान गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई में अपने अनुूठे वार्षिक निगम मंच का आयोजन किया था।

आईसीएआई मंच में कुछ उच्च प्रोफाइल समवर्ती आयोजन सम्मिलित थे, जिनके संलग्न निम्नलिखित थे :-

- कैरियर असेंट - मिड नियोजन कैम्पस
- कैरियर कैम्पस नियोजन कार्यक्रम
- लेखांकन पर जोर - आईसीएआई द्वारा प्रमाणित लेखांकन तकनीशियनों के लिए कैरियर मेला
- निगम सभा - उत्कृष्टता की खोज
- पूंजी फायदा - निवेश और क्रय मार्ग
- वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार
- आईसीएआई पुरस्कार 2009 - निगम सीए अवीवर अक्कलेम
- सीए पाठ्यक्रम के आशावादी छात्रों के लिए आईसीएआई का सीए कैरियर परामर्शी कार्यक्रम

नियोजन संबंधी आयोजन (29-30) जनवरी, 2010 के परिणाम			
क्रम सं.	आयोजन का नाम	चयनित अभ्यर्थियों की सं.	प्रस्तावित सीटीसी (प्रतिवर्ष)
1	कैरियर असेंट	32	6 लाख रु. - 13 लाख रु.
2	लेखांकन पर जोर	1	24000\$ - 30000\$ अंतरराष्ट्रीय नौकरी के लिए

निगम सभा के रजिस्ट्रीकरण

कार्यक्रम का नाम	भाग लेने वालों की सं.
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति, आईसीएआई और आईसीएन के साथ संयुक्त रूप से आयोजित साइबर खतरे और सूचना प्रणाली सुरक्षा और एक्सबीआरएल संबंधी सभा	190
आईसीएआई के महिला स्टीअरिंग समूह के साथ संयुक्त रूप से आयोजित इन्स्पायरिंग टूडे फॉर टूमरो (अखिल भारतीय वृहत महिला सम्मेलन) विषयक सभा	53
निगम शासन संबंधी समिति के साथ संयुक्त रूप से आयोजित निगम शासन बेंचमार्किंग विषयक सभा	110

लेखांकन मानक बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से आयोजित आईएफआरएस की चुनौतियां और कार्ययोजना विषयक सभा

234

पूँजी फायदा

वित्तीय और निवेश उत्पादों तथा चार्टर्ड एकाउंटेंटों की सेवाओं को उपदर्शित करने के लिए 29-31 जनवरी, 2010 के दौरान एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसमें भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस/बीएसई/फिडीलिटी एमएफ/एचडीएफसी/आइडियल ई-लाइव/केडीके सॉफ्टवेयर/ एलजी /एमसीएक्स- एफटीकेएमसी/ युनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज ने भाग लिया था और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में निगम नेता और निर्णय करने वाले व्यक्ति आए थे।

वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कारों का आयोजन 30 जनवरी, 2010 को किया गया था।

आईसीएआई पुरस्कार, 2009 - निगम सीए अचीवर्स अवकलेम : उद्योग में लगे ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंटों को, जिन्होंने उत्कृष्टता उपदर्शित की है, मान्यता प्रदान करने के लिए 31 जनवरी, 2010 को आईसीएआई पुरस्कार 2009 समारोह का आयोजन किया गया था। माननीय ज्यूरी में निम्नलिखित सम्मिलित थे :-

क्रम सं.	नाम	पदनाम	कंपनी का नाम
1	श्री आदेश गुप्ता	कार्यकारी निदेशक/सीईओ	लिबर्टी ग्रुप लि०
2	श्री अक्षय मुद्रा	मुख्य वित्त अधिकारी	आईडिया सैलुलर लि०
3	कुमारी अरुणा शर्मा	महानिदेशक	दूरदर्शन
4	श्री अरविंद खीचा	संयुक्त उपाध्यक्ष (वाणि.)	श्री सीमेंट लिमिटेड
5	श्री भारत बंका	एमडी एंड सीईओ	आदित्य बिड़ला प्राइवेट इक्विटी
6	श्री गौतम वोरा	प्रबंध भागीदार	यूएलजेके ग्रुप
7	श्री के. उल्लास कामथ	उप प्रबंध निदेशक	ज्योति लेबोरेट्रीज लि०
8	श्री कमल के. सिंह	अध्यक्ष और सीईओ	रोल्टा इंडिया लि०
9	श्री एम.एम. मियाजीवाला	मुख्य वित्त अधिकारी और कार्यकारी उपाध्यक्ष (वित्त)	वोल्टास लि०
10	श्री महेश एस. गुप्ता	समूह प्रबंध निदेशक	अशोक पीरामल ग्रुप
11	श्री मोतीलाल ओसवाल	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लि०
12	श्री पी.आर. धारीवाल	प्रबंध निदेशक और सीईओ	एस्सार स्टील कैरीबियन लि०
13	श्री रमेश डी. घंडक	प्रबंध निदेशक और सीईओ	कईसी इंटरनेशनल लि०
14	सीए. उत्तम प्रकाश अग्रवाल	सुसंगत समय पर पदासीन अध्यक्ष	आईसीएआई
15	सीए. वी.सी. दारक	पूर्व केन्द्रीय परिषद् सदस्य	आईसीएआई
16	श्री वेणुगोपाल नंदलाल धूत	अध्यक्ष	वीडियोकोन इंडस्ट्रीज लि०
17	श्री विजय शाह	प्रबंध निदेशक	पीरामल ग्लास लि०
18	श्री योगेश अग्रवाल	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	आईडीबीआई बैंक

पुरस्कार विजेता

क्रम सं.	पुरस्कार का प्रवर्ग और विजेता का नाम	वर्तमान पदनाम	उस संगठन का नाम जहां सेवारत है
1	बिजनेस अचीवर - निगम		

	सीए. अरुण कुमार नंदा	कार्यकारी निदेशक और अध्यक्ष	महिन्द्र एंड महिन्द्रा लि०
II	बिजनेस अचीवर - एसएमई		
	सीए. परेश जमनादास राजदे	मुख्य प्रबंध निदेशक	सुविधा इंफोसर्व प्रा० लि०
III	सीएफओ - विनिर्माण		
	सीए. तरुण जैन	सीएफओ	वेदांता रिसोर्सेज पीएलसी
IV	सीएफओ - इंजी. एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर		
	सीए. अजय सेठ	ईडी (वित्त) एंड सीएफओ	मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड
V	सीएफओ - पब्लिक सेक्टर		
	सीए. जी.एन. नायर	निदेशक-वित्त	सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन
VI	सीएफओ - सर्विस सेक्टर		
	सीए. मुकुल गुप्ता	सीएफओ	ओम लाजिस्टिक लि०
VII	सीएफओ - एफएमसीजी/हेल्थ केयर/रिटेल सेक्टर		
	सीए. आर शंकरैया	सीएफओ	जुबीलेंट औरगेनोसिस लि०
VIII	सीएफओ - सूचना प्रौद्योगिकी/ मीडिया संचार और मनोरंजन सेक्टर		
	सीए. युनूस जुल्फीकार बुकवाला	वित्त प्रधान	कैपजेमिनी इंडिया प्रा० लि०
IX	सीएफओ - वित्तीय क्षेत्र		
	सीए. राकेश जैन	निदेशक और सीएफओ	आईसीआईसीआई लोमबार्ड जेनरल इश्युरेंस कं० लि०
X	सीएफओ - अवसरचनना और संनिर्माण		
	सीए. वर्धन धारकर	सीएफओ	केईसी इंटरनेशनल लि०
XI	प्रोफेशनल अचीवर - विनिर्माण		
	सीए. मुकेश बाबु अग्रवाल	वित्त प्रधान	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड
XII	प्रोफेशनल अचीवर - इंजी. एंड पूंजी माल सेक्टर		
	सीए. डी.डी. गोयल	मुख्य महाप्रबंधक - वित्त	मारुति सुजुकी इंडिया लि०
XIII	प्रोफेशनल अचीवर - सेवा सेक्टर		
	सीए. विकास खेमानी	कार्यकारी अध्यक्ष संस्थागत साम्या	एडेलविस सिक्यूरिटीज लि०
XIV	प्रोफेशनल अचीवर - पब्लिक सेक्टर		
	सीए. श्रीनिवास गुरजदा	निदेशक	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय
XV	प्रोफेशनल अचीवर - महिला		
	सीए. रूपशिखा सैकिया बोरा	महाप्रबंधक - खजाना	ऑयल इंडिया लिमिटेड

5.19.13 नई पहलें

समिति की नई पहलों में निम्नलिखित सम्मिलित थे :

- उद्योग में लगे युवा सीए के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2010
- उद्योग में लगे सदस्यों के लिए अध्ययन दौर
- कतिपय उद्योगों के विनिर्दिष्ट मुद्दों का समाधान करने के लिए उद्योग विनिर्दिष्ट समूहों का गठन
- उद्योग में लगे सदस्यों के फायदे के लिए व्यापार और उद्योग के सर्वोच्च संघों के सहयोग से कार्यक्रमों का आयोजन

- समिति और उद्योग में लगे ऐसे सदस्यों के, जो विदेश में निवास कर रहे हैं, बीच परस्पर क्रिया में अभिवृद्धि जिससे कि उन्हें बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें और भारतीय लेखांकन वृत्ति की बाहर तक पहुंच में वृद्धि के लिए उनके अंतःनिवेश प्राप्त किए जा सकें।
- आईसीएआई द्वारा जारी उद्भासन प्रारूपों संबंधी प्रतिक्रिया में उद्योग में लगे सदस्यों को अंतर्बलित करना
- बड़े उद्योगपतियों/सीईओ/सीएफओ/ के साथ बैठक
- मुफसिल नगरों में चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए नौकरियों का सृजन
- उद्योग में लगे सदस्यों के लिए नए प्रकाशन निकालना
- खाड़ी देशों में स्थित निगमों के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आईसीएआई के सदस्यों के नियोजन के लिए आयोजन करना।

5.20 पियर रिव्यू बोर्ड

वर्ष 2002 में आईसीएआई की परिषद् द्वारा गठित पियर रिव्यू बोर्ड का मुख्य उद्देश्य अधिप्रमाणन सेवाओं की गुणवत्ता का संवर्धन करने, उसे बनाए रखने और उसमें अभिवृद्धि के लिए एक तंत्र स्थापित करना है। बोर्ड, जिसमें कारपोरेट कार्य मंत्रालय, सीएंडएजी, सेबी और सीआईआई जैसे सरकारी और अन्य निकायों से प्रतिनिधि और परिषद् के सदस्य सम्मिलित हैं, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से अग्रसर हो रहा है कि पुनर्विलोकनों को बेहतर ग्लोबल व्यवहारों के अनुसार किया जाता है।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने अपने तारीख 5 अप्रैल, 2010 के परिपत्र सं. सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/1/2010 के द्वारा सूचीबद्ध अस्तित्वों के लिए 1 अप्रैल, 2010 से यह आज्ञापक बना दिया है कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत सीमित पुनर्विलोकन/कानूनी संपरीक्षा रिपोर्ट केवल उन संपरीक्षकों द्वारा तैयार की जाएगी, जिन्होंने स्वयं को पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया के अध्वधीन किया है और जो संस्थान के 'पियर रिव्यू बोर्ड' द्वारा जारी प्रमाणपत्र धारण कर रहे हैं।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने भी पियर रिव्यू बोर्ड के कार्य को मान्यता प्रदान की है क्योंकि यह आवेदन प्रारूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों से उनकी पियर पुनर्विलोकन प्रास्थिति के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे मांगता है, ताकि पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए संपरीक्षा आबंटित की जा सके। इसके अतिरिक्त, पिछले कुछ वर्षों से सीएंडएजी वार्षिक रूप से संस्थान से उन फर्मों के ब्यौरे मांग रहा है, जिन्हें पियर रिव्यू बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।

इस क्रम में कि पुनर्विलोकनकर्ताओं द्वारा सुसंगतता और एकरूपता के साथ पुनर्विलोकन किया जाता है, बोर्ड पुनर्विलोकनकर्ताओं को प्रेक्टिस यूनिटों को पुनर्विलोकन के लिए उनको समनुदेशित करने से पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रशिक्षण माड्यूल जो "ट्रेनिंग माड्यूल फॉर पियर रिव्यूअर्स" नामक पुस्तक के रूप में इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया है, पुनर्विलोकनकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है तथा प्रशिक्षण सुसाध्यक के लिए मार्गदर्शन भी देता है कि पुनर्विलोकनकर्ताओं का प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है।

पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया का उद्देश्य तीन चरणों में क्रमबद्ध रीति से चार्टर्ड एकाउंटेंटों की सभी फर्मों को सम्मिलित करना है। चरण 1 में सम्मिलित पी.यू. का 5 क्रमबद्ध रीति से चयन किया गया है तथा जो अमी प्रक्रम 2 के अंतर्गत सम्मिलित है, उनका 4 चरणों के लिए चयन किया गया है। प्रक्रम 3 के अधीन पीयू का चयन उसके फेज 1 के अधीन भी किया गया है। इस प्रकार, पियर रिव्यू कार्य के लिए कुल 10293 पीयू का चयन किया गया था।

5.20.1 बोर्ड की पहलें

सदस्यों को नवीनतम और अद्यतन जानकारी उपलब्ध करने के लिए बोर्ड ने सदस्यों के फायदे के लिए एफएक्यू का अद्यतन और बेहतर पाठ निकाला था।

बोर्ड की अंतिम स्वच्छ, अर्हित और अनुवर्ती रिपोर्टों पर विचार करने वाली उपसमिति ने वर्ष के दौरान बैठकें की थी और पियर रिव्यू बोर्ड ने जून, 2010 तक 4441 प्रेक्टिस युनिटों को पियर पुनर्विलोकन प्रमाणपत्र जारी किए हैं।

बोर्ड ने पियर पुनर्विलोकन संबंधी विवरण का पुनर्विलोकन करने के लिए अपने उप-समूह का गठन किया है।

बोर्ड ने, प्रेक्टिस युनिटों को दिए जाने वाले प्रश्नोत्तरों को, उनमें उनकी फर्मों के ब्यौरे उल्लिखित करके पुनरीक्षित करने का विनिश्चय किया है, इसके पश्चात् उन्हें क्वालिटी नियंत्रण संबंधी मानक (एसक्यूसी) को ध्यान में रखते हुए प्रेक्टिस युनिट का आगे और पियर पुनर्विलोकन करने के लिए पुनर्विलोकक को भेजा जाएगा।

5.21 वृत्तिक विकास समिति

वृत्तिक विकास समिति को भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा वर्ष 1962 में एक गैर-स्थायी समिति के रूप में स्थापित किया गया था। वृत्तिक विकास समिति आईसीएआई की सर्वाधिक सक्रिय समितियों में से एक है, जिसने सदैव अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आईसीएआई के सदस्यों के लिए पर्याप्त अवसरों की खोज करने, उन्हें व्युत्पन्न करने, विकसित करने और उपलब्ध कराने के लिए अथक प्रयास किए हैं। यह वृत्तिक विकास आवश्यकताओं को अवधारित करती है और वृत्ति को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों और मुद्दों की पहचान करती है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह समिति ऐसे नए और विद्यमान क्षेत्रों में खोजबीन/क्रियाएं करके, जहां सदस्यों के वृत्तिक कौशल को और अधिक उत्पादक और फायदाप्रद रीति में उपयोग किया जा सकता है, संस्थान के सदस्यों के लिए और अधिक वृत्तिक अवसरों का सृजन करने के लिए प्रयास कर रही है। इस समिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रयास किए हैं कि वृत्ति के सभी सदस्यों को समान अवसर उपलब्ध हों। वृत्तिक विकास में अभी तक जांचे-परखे नहीं गए क्षेत्रों की पहचान करने के अलावा वृत्तिक विकास समिति समाज के विभिन्न तबकों में बहुप्रकार के उपयोक्ताओं के साथ संपर्क प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने और उन्हें चार्टर्ड एकाउंटेंटों की भूमिका के संबंध में शिक्षित करने के लिए प्रयास कर रही है। विद्यमान और नए क्षेत्रों में चार्टर्ड एकाउंटेंटों के कौशल में वृद्धि करने के विचार से, यह हित के समकालीन क्षेत्रों में संगोष्ठियों, कार्यशालाओं का भी आयोजन करती है।

वृत्तिक विकास समिति ने वर्ष के दौरान अनेक महत्वपूर्ण पहलें की हैं जैसे कि विभिन्न सरकारी विभागों और विनियामक निकायों के विभिन्न पदधारियों से की गई बैठकें आदि। बैठकों के अलावा समिति ने सदस्यों के कौशल में सुधार लाने के उद्देश्य से, उन्हें नए नियमों और विनियमों से अवगत कराने के लिए और इस प्रकार सदस्यों और विनियामकों को एक-दूसरे के करीब लाने के लिए संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का भी आयोजन किया था।

इस रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति की प्रमुख उपलब्धियां/प्रयास नीचे दिए गए हैं :

- वित्त राज्यमंत्री और वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पदधारियों के साथ कानूनी संपरीक्षकों की नियुक्ति में प्रबंधकीय स्वायत्तता से संबंधित मुद्दों पर बैठक।
- सेबी ने वर्ष 2008-09 से लागू परस्पर निधियों की निरीक्षण संपरीक्षा के लिए फीस का पुनरीक्षण किया था, जो अन्य प्रबंधाधीन आस्तियों के आकार पर निर्भर करते हुए 70,000 रुपये से 8,50,000 रुपये हो गई है।
- वृत्तिक हित के विभिन्न मुद्दों, जिनके अंतर्गत बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा के लिए बैंक शाखा संपरीक्षा पारिश्रमिक का पुनरीक्षण, आर्बटन और एलाटमेंट, एनबीएफसी से संबंधित मुद्दे आदि हैं, पर भारतीय रिजर्व बैंक के पदधारियों से बैठकें की गईं।
- वृत्तिक हित के विभिन्न मुद्दों, जैसे कि कानूनी संपरीक्षकों के लिए संपरीक्षा फीस का पुनरीक्षण, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के संपरीक्षकों की नियुक्ति और उनका पारिश्रमिक तथा आर.आर.बी. के संपरीक्षकों के लिए संपरीक्षा मैनुअल पर विचार करने के लिए नाबार्ड के पदधारियों से बैठकें की गईं।

- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय के पदधारियों के साथ वृत्तिक हित के मुद्दे पर बैठक की गई थी ।

और अधिक वृत्तिक अवसरों की खोज करने के लिए निम्नलिखित को प्रतिवेदन भेजे गए थे:

- भारत सरकार के माननीय ग्रामीण विकास मंत्री को, उन्हें विभिन्न प्रकार की संपरीक्षकों/समनुदेशनों के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान से चार्टर्ड एकाउंटेंटों के पैनेल का उपयोग करने के लिए अनुरोध करते हुए ।
- गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री को, उन्हें विभिन्न प्रकार की संपरीक्षकों/समनुदेशनों के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान से चार्टर्ड एकाउंटेंटों के पैनेल का उपयोग करने के लिए अनुरोध करते हुए ।
- सचिव, वित्त विभाग, झारखंड को, उन्हें झारखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन वैट संपरीक्षा के लिए संपरीक्षक के रूप में केवल चार्टर्ड एकाउंटेंटों की नियुक्ति करने का अनुरोध करते हुए ।
- भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष को, जुलाई, 2007 और दिसंबर, 2009 में जारी परिपत्रों के संदर्भ में कर संपरीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में, जिनके द्वारा सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों को, उनके बोर्ड/एसीबी के अनुमोदन से शाखा/प्रधान कार्यालय के स्तर पर युक्तियुक्त फीस पर किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म को उनके कर संपरीक्षक के रूप में नियुक्त करने की अनुमति प्रदान की गई थी । इस विषय पर एसबीआई के बरिष्ठ पदाधिकारियों से बातचीत की गई थी और उन्हें इस बात के लिए मनाया गया था कि वे कर संपरीक्षा विद्यमान शाखा संपरीक्षकों से कराएं । तथापि, इस प्रक्रिया में, एसबीआई ने शाखा संपरीक्षा फीस की दर को विद्यमान 15% से 7.5% कर दिया ।
- अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारत संचार निगम लि० को, निविदा में अपमानजनक पद के उपयोग के संबंध में ।
- अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड को, तारीख 16 सितंबर, 2009 के परिपत्र सेबी/आईएमडी/परिपत्र सं. 8/176988/2009 के पुनरीक्षण के संबंध में, ताकि डीआईएसए अर्हता को, परस्पर निधियों और आस्ति प्रबंध कंपनियों की प्रणाली संपरीक्षा करने के लिए मान्यताप्राप्त अर्हता के रूप में सम्मिलित किया जा सके ।
- निदेशक, महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड को, चार्टर्ड एकाउंटेंटों की महाराष्ट्र में कृषि उत्पाद विपणन समिति के संपरीक्षकों के रूप में नियुक्ति के संबंध में ।
- माननीय राज्यपाल, मध्य प्रदेश को, किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा तैयार की गई संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 39(2) के संबंध में और एक बैठक का आयोजन भी किया गया था ।
- अध्यक्ष, अग्रिम बाजार आयोग को, वस्तु एक्सचेंजों के सदस्यों की लेखाबहियों की कार्यमालन संपरीक्षा/निरीक्षण के संबंध में और तत्पश्चात सदस्य, अग्रिम बाजार आयोग से एक बैठक की गई थी ।
- सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को, उन्हें सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ अभिसरण हेतु परामर्शी की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव के लिए उसकी वेबसाइट पर रखे गए विज्ञापन आरएफपी सीबीआई/सीएडी/बीएस/आरएफपी-सीओएनएस/1/ 2009-10 में उल्लिखित निर्बंधनकारी मानदंड पर पुनः विचार करने का अनुरोध करते हुए ।

- आयुक्त और रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, महाराष्ट्र राज्य को विभिन्न प्रकार की सोसाइटियों की कानूनी संपरीक्षा के लिए संपरीक्षा फीस मान के पुनरीक्षण के संबंध में ।
- पूर्वोक्त के अलावा, और अधिक वृत्तिक अवसरों का सृजन करने और पूर्व में विद्यमान अवसरों के अनछुए क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित संगमों और प्राधिकरणों के साथ भी बैठकों की गई थी :
 - प्रधान निदेशक, रेलवे और कार्यकारी निदेशक (लेखांकन सुधार), रेलवे
 - सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय
 - कार्यकारी निदेशक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
 - उप राज्यपाल, आरबीआई और कार्यकारी निदेशक, डीबीएस, आरबीआई
 - नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय
- साम्यापूर्ण वृत्तिक अवसरों को सुनिश्चित करने और अधिकाधिक कार्य उपलब्ध कराने की वृहत मांग के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित प्राधिकरणों को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स/चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों के पैनल उपलब्ध कराए गए थे :
 - ओरियंटल बीमा कंपनी लिमिटेड
 - वित्त आयुक्त और प्रधान सचिव, चंडीगढ़
 - आयकर आयुक्त का कार्यालय, कानपुर
 - केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (चेन्नई)
 - केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (बंगलोर)
 - केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (नई दिल्ली)
 - संयुक्त आयुक्त, मुख्य आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क और सेवाकर, लखनऊ
 - आयकर मुख्य आयुक्त, कानपुर
 - महाप्रबंधक (वित्त), टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
 - तुलनपत्र की तकनीकी संवीक्षा के लिए आरओसी द्वारा वृत्तिकों को पैनलबद्ध करने के लिए 18 आरओसी
 - अध्यक्ष, सर्वहित आवास कल्याण संघ, दिल्ली
 - आयकर संयुक्त आयुक्त, गोरखपुर
 - यूपी विद्युत निगम लिमिटेड, लखनऊ
 - एक्सिस बैंक लिमिटेड
 - देना बैंक, मुंबई
 - हमदर्द वक्फ लेबोरेट्री, नई दिल्ली
 - उत्तम शासन संबंधी केन्द्र, हैदराबाद
 - मैसर्स फाइनेंशियल ट्रान्जेक्शन हाऊस, साऊथी अरब
 - सहकारी सोसाइटियों का अपर रजिस्ट्रार, चेन्नई
 - प्रादेशिक अधिकारी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, कानपुर
- अपने सदस्यों के कौशल और योग्यता में सुधार करने के लिए विनिर्दिष्ट सहायता उपलब्ध कराने के मार्गों और उपायों पर विचार करने के अपने प्रयासों में, समिति ने इस अवधि के दौरान निम्नलिखित सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन किया :
 - नई दिल्ली में पब्लिक सेक्टर बैंकों के बोर्ड में चार्टर्ड एकाउंटेंट निदेशकों की एक परस्पर क्रियाशील बैठक
 - बंगलोर और मेरठ में गैरबैंककारी वित्तीय कंपनियों के संपरीक्षकों के लिए कार्यशाला
 - गोवा में वृत्तिक विकास और समृद्धि संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन

- चंडीगढ़ में “ सीए-कोर ऑफ ग्लोबल इकोनोमी - प्रैक्टिस एंड इनोवेशंस” विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- वाराणसी, जयपुर, रांची, रायपुर, पटना और भोपाल में राज्य पीएसयू के संपरीक्षकों के लिए आईसीएआई, सीएंडएजी के कार्यालय और राज्य पीएसयू के सीएमडी/निदेशक (वित्त) को सम्मिलित करते हुए त्रिपक्षीय कार्यशालाएं

5.22 लोक वित्त और शासकीय लेखांकन संबंधी समिति

पूर्व में गठित लोक वित्त और शासकीय लेखांकन संबंधी समिति को आमेलित किया गया है और वर्ष 2010-11 के लिए एक पुनःसंरचित समिति, अर्थात् लोक वित्त और शासकीय लेखांकन संबंधी समिति का गठन किया गया। उक्त दो समितियों के क्रियाकलाप/पहलें निम्नानुसार हैं।

5.22.1 लोक वित्त संबंधी समिति

लोक वित्त संबंधी समिति, संस्थान के निगम क्षेत्र और साधारण जनता से परे चार्टर्ड एकाउंटेंटों की वृत्तिक सेवाओं को उपलब्ध कराके अपनी सामाजिक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए सरकार के राष्ट्र निर्माण में भागीदारी करने के संस्थान के मिशन में अग्रसर होने का अवसर प्रदान करती है।

तदनुसार, समिति वित्तीय नीति संबंधी अध्ययन, अनुसंधान और रिपोर्ट, वित्तीय योजना, राजस्व और व्यय, लोक ऋण प्रबंध, विकासात्मक योजनाओं, कल्याण योजनाओं, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में वृद्धि, वित्तीय संसाधनों और केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर आय और धन के वितरण पर ध्यान केन्द्रित करती है।

समिति सरकारी अधिकारियों, नौकरशाहों और लोक प्रदाय प्रणाली में अंतर्बलित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पाठ्यक्रमों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन भी करती है।

अपनी अवधारणा को और अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाने के लिए समिति राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ नियमित बातचीत करती है और साथ ही पीएसयू के सीईओ, नगरपालिका निकायों के आयुक्तों और भारत में विकासात्मक कार्यक्रमों का वित्तपोषण करने वाले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषकों से परस्पर क्रिया करती है।

वर्ष के दौरान समिति की प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं :-

- 1 अप्रैल, 2009 को समिति ने अपनी छठी बैठक में माननीय प्रोफेसर अतुल शर्मा, सदस्य, तेरहवां वित्त आयोग को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था और उन्होंने भारत में संघीय वित्त संरचना और भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति पर विचार-विमर्श किया था।
- 15 और 16 मई, 2009 को अगरतला, त्रिपुरा में अगरतला नगर परिषद् के अधिकारियों के अनुकूलन के लिए आउटकम बजट और प्रोदमवन आधारित लेखांकन प्रणाली के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया था।
- 26 मई, 2009 को समिति की सातवीं बैठक की गई थी, जिसमें दिल्ली के मननीय वित्त मंत्री, डा. ए.के.वालिया को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। डा. वालिया ने दिल्ली में अपनी प्रमुख उपलब्धियों को विशिष्ट रूप से उल्लिखित करते हुए महानगरों और उप-शहरों में अवसंरचना विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर सदस्यों के साथ परिचर्चा की थी।
- 18 जून, 2009 को मुंबई में श्री अशोक चव्हाण, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक की गई थी, जिसमें संस्थान के उपाध्यक्ष और समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और राज्य में लोक वित्त से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया था।
- 20 और 21 अगस्त, 2009 को कोहिमा, नागालैंड में कोहिमा और दीमापुर नगर परिषद् के अधिकारियों के लिए नगरपालिका प्रशासन और प्रोदमवन लेखांकन पर कार्यशाला का आयोजन किया था।

- 14 से 18 सितंबर, 2009 के दौरान पोर्ट ब्लेयर, अंदमान और निकोबार में अंदमान और निकोबार प्रशासन के वित्त और लेखा विभाग, पीआरआई के सचिवों और अन्य अधिकारियों के लिए लेखा, नगर पालिका और पीआरआई प्रशासन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था।
- 17 से 20 नवम्बर, 2009 के दौरान आईजोल, मिजोरम में वित्त विभाग, मिजोरम सरकार के अधिकारियों के लिए प्रोदमवन लेखांकन, खजाना प्रबंध और शहरी स्थानीय निकायों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था।
- 11 जनवरी, 2010 को समिति ने अपनी आठवीं बैठक बुलाई थी, जिसमें श्री महाबल मिश्रा, संसद सदस्य को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। उन्होंने सामाजिक कार्यों और दिल्ली में निचले स्तर के लिए किए गए संवर्धन संबंधी अपने अनुभवों को बांटा था तथा नरेगा और अन्य सरकारी स्कीमों के बेहतर कार्यान्वयन में चार्टर्ड एकाउंटेंटों की सहायता मांगी थी।

5.22.2 शासकीय लेखांकन संबंधी समिति

शासकीय लेखांकन संबंधी समिति को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ वर्ष, 2008 में गठित किया गया था :

- वर्तमान शासकीय लेखांकन प्रणाली का पुनर्विलोकन करना और उसके आधार पर उसमें सुधारों का सुझाव देना।
- समाज में, विशिष्ट रूप से पणधारियों में जिनके अंतर्गत अन्य लोगों के साथ सरकारी कर्मचारी, सीएंडएजी के कर्मचारी, वृत्ति के सदस्य, मीडिया, एनजीओ और साधारण नागरिक भी हैं, शासकीय लेखांकन के प्रति जागरूकता सृजित करना।
- केन्द्र, राज्य, जिला स्तर पर सरकारी निकायों, स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करना।
- आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के साथ समुचित अंतरापृष्ठ सुकर बनाना तथा ऐसी पद्धतियां विकसित करना जो लेखांकन सुधार प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का उपयोग समर्थ बनाएंगी।
- नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी), लेखा महानियंत्रक (सीजीए) और विभिन्न अन्य मंत्रालयों के साथ शासकीय लेखांकन प्रणाली के ढांचे में सुधारों को विकसित करने के लिए सहायता और समन्वय करना।
- केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को लोक सेवा प्रदाय तंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता की वृद्धि करने में सहायता करना।
- केन्द्रीय और राज्य सरकारों को ऐसे लेखांकन सुधारों का सुझाव देना, जो कर आधार को व्यापक बनाने तथा राजस्व संग्रहण के बेहतर प्रशासन और तैनाती तंत्र में सहायता करेंगे, परिणाम मापमान और समुन्नत एमआईएस, रिपोर्टिंग और बजट संबंधी नियंत्रण तंत्रों की प्रक्रिया में सहायता करेंगे।
- वृत्ति के भीतर शासकीय लेखांकन के संबंध में अध्ययन को बढ़ावा देना तथा उसके संबंध में जागरूकता तैयार करना और वृत्ति को, शासकीय लेखांकन सुधारों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सरकार को सहायता प्रदान करने में समर्थ बनाने के लिए सक्षमता निर्माण उपाय करना तथा इस प्रयोजन के लिए अध्ययन करना, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना, पृष्ठभूमि सामग्री आदि का प्रकाशन करना।

5.22.3 किए गए क्रियाकलाप

- शासकीय लेखांकन की वर्तमान स्थिति, सरकार के लिए प्रोदमवन लेखांकन के फायदे, अन्य देशों के अनुभव, सरकार में प्रोदमवन लेखांकन के कार्यान्वयन के लिए रणनीतियां और पूर्व शर्तें आदि विषयों को सम्मिलित करते हुए कार्यालय ने एक प्रारूप प्रास्थिति पत्र तैयार किया है। इसे शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

- समिति को सीएडंएजी कार्यालय से, सीएजी के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आईपीएसएस पर एक मॉड्यूल के संचालन के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था। समिति ने 24-25 अगस्त, 2009 के दौरान आईसीआईएसए, नोएडा में सीएजी के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आईपीएसएस पर उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया था, इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों ने इसकी अत्यधिक सराहना की थी।
- शासकीय लेखांकन संबंधी समिति की कार्य योजना 2009-10 के अंतर्गत आने वाले सुसंगत कार्य बिन्दु में से एक, अर्थात् 'लेखांकन सुधारों के कार्यान्वयन में केन्द्रीय और राज्य सरकारों की सहायता करना' के संदर्भ में, सभी राज्य सरकारों को, उन्हें आईसीआईआई की शासकीय लेखांकन संबंधी समिति से परिचित कराते हुए और उनसे प्रोदमवन लेखांकन के कार्यान्वयन से संबंधित प्रश्नों को आमंत्रित करते हुए पत्र भेजे गए थे। राज्य सरकारों से उत्तर भी प्राप्त हो रहे हैं।
- समिति ने जीएसएबी के प्रोदमवन उदभासन प्रारूप (आईडी) 2, जो "संपत्ति संयंत्र और उपस्कर" से संबंधित है, पर शासकीय लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड (जीएसएबी) द्वारा विचार किए जाने के लिए ब्यौरेवार और बृहत टीका-टीप्पणीयां दी गई है। समिति ने जीएसएबी के प्रोदमवन उदभासन प्रारूप (आईडी), जो 'सूची' से संबंधित है, पर शासकीय लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड (जीएसएबी) द्वारा विचार किए जाने के लिए टीका-टीप्पणीयां का प्रारूप तैयार किया था।
- समिति द्वारा 15-20 पृष्ठों की शासकीय लेखांकन संबंधी पुस्तिका, जिसमें शासकीय लेखांकन की वर्तमान प्रणाली, वर्तमान प्रणाली की कमियां, यदि प्रोदमवन लेखांकन को कार्यान्वित किया जाता है तो सरकार को क्या फायदा होगा, आदि सम्मिलित होंगे, को प्रकाशित करने के लिए किए गए विनिश्चय के अनुसार पुस्तिका के आधारिक प्रारूप को तैयार किया जा रहा है। इस पुस्तिका के लक्षित पाठक राज्य और केन्द्रीय स्तर के मंत्रालय होंगे।
- समिति ने "खाद्य, खाद और तेल बंधपत्रों के लिए लेखांकन" विषय पर एक अध्ययन का भी प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित अध्ययन में वर्तमान पद्धति, वर्तमान प्रणाली में त्रुटियां और कमियां तथा विद्यमान व्यवहारों में सुधार के लिए सिफरिशें सम्मिलित हो सकेंगी। इस अध्ययन में सरकार के परिप्रेक्ष्य से और साथ ही खाद्य, खाद और तेल बंधपत्रों को जारी करने वाली कंपनियों के परिप्रेक्ष्य से सभी पहलू सम्मिलित हो सकेंगे। यह अध्ययन इस प्रयोजन के लिए बनाए जाने वाले समूह द्वारा किया जाएगा। इस समूह में समिति के सदस्य और खाद्य, खाद और तेल उद्योग से कुछ अनुभव प्राप्त व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।

5.23 अनुसंधान

अनुसंधान एक ऐसा आधार है, जिस पर कोई भी वृत्ति विकास करके समृद्ध हो सकती है। वृत्ति के लिए अनुसंधान के महत्व को समझते हुए, परिषद् ने वर्ष 1955 में हुई अपनी 17वीं बैठक में एक गैर-स्थायी समिति के रूप में अनुसंधान समिति का गठन किया था। इसकी स्थापना से ही, अनुसंधान समिति अनथक रूप से संस्थान के सदस्यों की वृत्तिक दिलचस्पी के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर लेखांकन और संपरीक्षा के क्षेत्रों में मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रही है। यह समिति साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन और/या संपरीक्षा सिद्धांतों और व्यवहारों पर, जिन्हें वृत्ति द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के मूल्यवर्धन के लिए तैयार किया गया है, मार्गदर्शक टिप्पणों, तकनीकी गाइडों, अध्ययनों, मानोग्राफों आदि का प्रकाशन करती है। यह सदस्यों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के मार्गदर्शन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में समवर्ती रूप से अनुमोदित अनुसंधान परियोजनाएं प्रारंभ करती है। अनुसंधान समिति वित्तीय विवरणों की प्रस्तुती में सुधार लाने के विचार से 'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीआईआई पुरस्कार' के लिए गौरवान्वित वार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन करती है। ये पुरस्कार वित्तीय सूचना को तैयार करने और उसकी प्रस्तुती में उत्कृष्टता को मान्यता प्रदान करते हैं और साथ ही उसका प्रोत्साहन करते हैं तथा वे और अधिक जवाबदेही और सुविज्ञ निर्णय के प्रयोजन के प्रति समर्पित हैं।

5.23.1 समिति की उपलब्धियां

इस अवधि के दौरान समिति ने निम्नलिखित प्रकाशनों का विमोचन किया :

एएस 28 के प्रयोजनों के लिए भावी नकद प्रवाह के प्राक्कलन और बट्टा दरों, आस्तियों के हानिकरण संबंधी तकनीकी गाइड

लेखांकन मानक (एएस) 28, 'आस्तियों का हानिकरण' ऐसे सिद्धांतों को विहित करता है जिन्हें किसी उद्यम को यह सुनिश्चित करने के लिए लागू करना होगा कि उसकी आस्तियों को, उनकी वसूलनीय रकम से अनधिक पर अग्रणीत किया जाए। इस प्रयोजन के लिए एएस 28 'उपयोग में मूल्य' के मापमान के सिद्धांतों को अधिकथित करता है, जिसके लिए नकद प्रवाहों और समुचित बट्टा दरों का प्राक्कलन अपेक्षित है। तथापि, इस बात की आवश्यकता महसूस की गई थी कि 'उपयोग में मूल्य' के मापमान के संबंध में अनेक पहलुओं पर मार्गदर्शन अपेक्षित है। अतः, संस्थान की अनुसंधान समिति ने ऐसे पहलुओं के संबंध में 'एएस 28 के प्रयोजनों के लिए भावी नकद प्रवाह के प्राक्कलन और बट्टा दरों, आस्तियों के हानिकरण' संबंधी इस तकनीकी गाइड को तैयार किया।

गैर लाभकारी संगठनों (एनपीओ) के लिए लेखांकन संबंधी तकनीकी गाइड

वर्ष 2006 में इस प्रकाशन के पूर्ववर्ती संस्करण के जारी किए जाने के पश्चात् से संस्थान द्वारा जारी/पुनरीक्षित लेखांकन मानकों को सम्मिलित करने के विचार से, अनुसंधान समिति ने इस तकनीकी गाइड को निकाला था। यह तकनीकी गाइड एनपीओ के लिए लेखांकन तथा वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे का सुझाव देने का एक प्रयास है। इसका प्रयोजन एनपीओ के प्रचालनों में उसकी जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। यह तकनीकी गाइड वित्तीय विवरणों के प्रमुख कारकों - आय, व्यय, आस्तियां और दायित्व, के एनपीओ के संदर्भ में एनपीओ से सुसंगत लेखांकन मानकों के अनुसार लेखांकन को स्पष्ट करती है।

विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड) के विकास संबंधी क्रियाकलापों के लिए लेखांकन संबंधी तकनीकी गाइड

विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड) के विकास में अंतर्वर्तित क्रियाकलापों की विशिष्ट और जटिल प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अनुसंधान समिति ने इस तकनीकी गाइड को जारी किया है, जो (एसईजेड) के विकास संबंधी क्रियाकलापों के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है। इस तकनीकी गाइड को, अन्य बातों के साथ, एसईजेड विकासकर्ताओं द्वारा किए गए संव्यवहारों के संबंध में सुसंगत लेखांकन मानकों को लागू करने आदि को स्पष्ट करने के विचार से तैयार किया गया है। यह एसईजेड की अधिसूचना से पूर्व और उसके पश्चात् उपगत व्ययों और साथ ही पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन संबंधी व्ययों के लिए लेखांकन संबंधी कार्यवाही को स्पष्ट करती है और साथ ही एसईजेड की अधिसूचना के लिए पट्टे पर ली गई भूमि के संबंध में उपगत व्ययों के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है।

5.23.2 प्रगति में महत्वपूर्ण परियोजनाएं

वर्ष के दौरान पूरी की गई परियोजनाओं के अलावा, समिति की कतिपय अन्य परियोजनाओं पर भी कार्य चल रहा है, जो निम्नानुसार है :

- (i) समिति ने तेल और गैस उत्पादन संबंधी क्रियाकलापों के लेखांकन पर मार्गदर्शक टिप्पण के पुनरीक्षण की परियोजना को आरंभ किया है। यह पहल तेल और गैस उद्योग में हुई हाल ही की घटनाओं और विधियों में संशोधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई है।
- (ii) समिति ने अपनी टेलीकम प्रचालकों के लिए राजस्व मान्यता संबंधी तकनीकी गाइड के माध्यम से अपनी टेलीकम प्रचालकों के लिए राजस्व की मान्यता में अंतर्वर्तित विनिर्दिष्ट मुद्दों पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का कार्य भी हाथ में लिया है।

समिति रिपोर्टों के निर्धारण के समय वार्षिक रिपोर्टों के मूल्यांकन में उसके द्वारा पाई गई सामान्य असंगतताओं की सुची को संकलित करने के लिए प्रक्रिया कर रही है जिससे कि सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत लेख के लिए पुरस्कार दिया जा सके और वह सर्वोत्तम व्यवहारों पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रकाशन भी तैयार कर रही है।

5.23.3 वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार

वित्तीय रिपोर्टिंग तथा वार्षिक रिपोर्टों को तैयार करने और उनकी प्रस्तुती में बेहतर मानकों का संवर्धन करने के लिए, संस्थान ने अपनी अनुसंधान समिति के माध्यम से वर्ष 1958 से वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार प्रारंभ किए थे जो अलबत्ता उस समय “सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत लेखा प्रतिस्पर्धा” के नाम से ज्ञात थे और उसके पश्चात् उन्हें वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता रहा है।

इस प्रतिस्पर्धा का उद्देश्य, वृहत्तर जवाबदेही और सूचित निर्णय लेने के मिशन से वित्तीय जानकारी को तैयार करने और उसकी प्रस्तुती में उत्कृष्टता को मान्यता प्रदान करना और बढ़ावा देना है। ये पुरस्कार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों और अन्य उद्घोषणाओं तथा साथ ही विधिक और कानूनी अपेक्षाओं के प्रभावी अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभ किए गए हैं। वर्ष 2008-09 में प्रतिस्पर्धा विभिन्न उद्योगों के कृत्यक प्रवर्गीकरण के आधार पर सात प्रवर्गों के अधीन आयोजित की गई थी।

शील्ड पैनल, जो अनुसंधान समिति की एक उपसमिति है, इन उपक्रमों की वार्षिक रिपोर्टों और लेखाओं में अंतर्विष्ट वित्तीय और अन्य जानकारी पर बहुत बारीकी से विचार करती है। पुरस्कारों की स्कीम के अनुसार प्रत्येक प्रवर्ग में सर्वोत्तम प्रविष्टि तथा अगली सर्वोत्तम प्रविष्टि के लिए क्रमशः 1 स्वर्ण शील्ड और 1 रजत शील्ड प्रदान की जाती है। प्रत्येक प्रवर्ग में सराहनीय प्रविष्टि के लिए पट्टिकाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा ऐसे किसी अस्तित्व को हाल ऑफ फेम पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसे पिछले पांच वर्ष के दौरान समान प्रवर्ग में निरंतर स्वर्ण शील्ड प्राप्त हुई है।

वर्ष 2008-09 के लिए समारोह में कुल मिलाकर 16 पुरस्कार - 5 स्वर्ण शील्डें, 6 रजत शील्डें और 5 पट्टिकाएं, जिन्हें नीचे दिए गए व्यौरों के अनुसार वितरित किया गया था :

5.23.4 वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार

वर्ष 2008-09 के लिए पुरस्कार विजेता

प्रवर्ग	पुरस्कार	अस्तित्व का नाम	निम्नलिखित समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखा
I	विनिर्माण और व्यापार उद्यम (जिसके अंतर्गत प्रसंस्करण, खनन, पौधा रोपण, तेल और गैस उद्यम भी हैं)	स्वर्ण शील्ड	एसीसी लिमिटेड
		रजत शील्ड	डा. रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड
		उत्कृष्ट वार्षिक रिपोर्ट के लिए पट्टिका	हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड
II	बैंककारी और वित्तीय संस्थाएं (जिनके अंतर्गत एनबीएफसी, परस्पर निधियां, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, निवेश बैंक, एचएफसी आदि हैं)	स्वर्ण शील्ड	एक्सिस बैंक लिमिटेड
		रजत शील्ड	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
		उत्कृष्ट वार्षिक रिपोर्ट के लिए पट्टिका	कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड
III	सेवा क्षेत्र (जिसके अंतर्गत होटल, परामर्शी, परिवहन, स्टॉक एक्सचेंज, आरएंडडी, निजी अस्पताल हैं)	स्वर्ण शील्ड	पुरस्कार न देने का विनिश्चय किया
		रजत शील्ड	बांबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
		उत्कृष्ट वार्षिक रिपोर्ट के लिए पट्टिका	पुरस्कार न देने का विनिश्चय किया

		रिपोर्ट के लिए पट्टिका	विनिश्चय किया	
IV	बीमा क्षेत्र	स्वर्ण शील्ड	आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड	31 मार्च, 2009
		रजत शील्ड	बिड़ला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	31 मार्च, 2009
		उत्कृष्ट वार्षिक रिपोर्ट के लिए पट्टिका	इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	31 मार्च, 2009
V	सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और मनोरंजन उद्यम	स्वर्ण शील्ड	न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	31 मार्च, 2008
		रजत शील्ड	पुरस्कार न देने का विनिश्चय किया	
		उत्कृष्ट वार्षिक रिपोर्ट के लिए पट्टिका	पर्सिसटेंट सिस्टम्स लिमिटेड	31 मार्च, 2009
VI	अवसंरचना और सन्निर्माण क्षेत्र (जिनके अंतर्गत विद्युत उत्पादन और प्रदाय, पत्तन न्यास, मैट्रो, मार्ग आदि हैं)	स्वर्ण शील्ड	पुरस्कार न देने का विनिश्चय किया	
		रजत शील्ड	नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	31 मार्च, 2009
		उत्कृष्ट वार्षिक रिपोर्ट के लिए पट्टिका	लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड	31 मार्च, 2009
VII	अन्य (धारा 25 की कंपनियाँ, शिक्षा संस्थाएँ, एनजीओ, पूर्ण अस्पताल और अन्य संगठन हैं)	स्वर्ण शील्ड	दि अक्षय पात्रा फाउंडेशन	31 मार्च, 2009
		रजत शील्ड	विद्या डेयरी	31 मार्च, 2009
		उत्कृष्ट वार्षिक रिपोर्ट के लिए पट्टिका	पुरस्कार न देने का विनिश्चय किया	

वर्ष 2008-09 के लिए “वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार” प्रतियोगिता के पुरस्कार विजेताओं को गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई में जनवरी, 2010 में आयोजित ‘आईसीएआई पुरस्कार’ समारोह में सम्मानित किया गया था। इस समारोह में वरिष्ठ सरकारी पदधारियों, विख्यात व्यक्तियों, उद्योगपतियों, बड़े पब्लिक और प्राइवेट उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों ने भाग लिया था।

5.23.5 अनुसंधान प्रस्तावों के लिए निमंत्रण

संस्थान के अनुसंधान क्रियाकलापों में भागीदारी में वृद्धि करने और साथ ही वास्तविक अनुसंधान योग्यता को एक मंच प्रदान करने के लिए, अनुसंधान समिति ने सदस्यों और अन्य, जैसे कि प्रबंध संस्थाएँ आदि से लेखांकन और अन्य सहबद्ध क्षेत्रों, उदाहरणार्थ चैन डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए लेखांकन, स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में लेखांकन, विद्युत उत्पादन और वितरण कंपनियों के लिए लेखांकन, विमानन उद्योग में लेखांकन, पोत परिवहन कंपनियों के लिए लेखांकन, प्रबंध नियंत्रण प्रणालियाँ, भारतीय संदर्भ में सामाजिक लागत फायदा विश्लेषण पद्धतियाँ आदि के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान परियोजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे।

5.24 विजन और परिप्रेक्ष्य समिति

पूर्व में गठित विजन समिति तथा परिप्रेक्ष्य समिति को आमेलित किया गया है और वर्ष 2010-2011 के लिए एक पुनःसंरचित समिति अर्थात् विजन और परिप्रेक्ष्य समिति का गठन किया गया है। उक्त दो समितियों के क्रियाकलाप/पहलें निम्नानुसार हैं :

5.24.1 विजन समिति

विजन समिति को लक्ष्य वर्ष के रूप में वर्ष 2021 के संदर्भ से विजन दस्तावेज तैयार करने का कार्य सौंपा गया था, जिसे वर्ष परिषद् वर्ष 2008-09 में आईसीएआई का विजन और लक्ष्य पायलट दस्तावेज - 2021 प्रस्तुत किया गया था। परिषद् ने पायलट दस्तावेज में अधिकथित भावी योजना पर सहमति प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त परिषद् वर्ष 2009-10 के दौरान परिषद् को उसे और अधिक बेहतर बनाने का कार्य और इस प्रकार अधिकथित विजन को प्राप्त करने के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार करने और विद्यमान परिषद् अर्थात् 21 परिषद् के कार्यकाल के दौरान किए जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों की पहचान करने का कार्य सौंपा गया था।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां और पहलें : वर्ष 2009-10

समिति ने विद्यमान परिस्थितियों के आलोक में पायलट दस्तावेज में अधिकथित विजन को बेहतर बनाने के लिए उसके निष्कर्षों और पहचान की गई आवश्यकताओं, यदि कोई हो, को अधिमार्ग्य ठहराने के लिए और उस बेहतर विजन को पूरा करने के लिए अपेक्षित कार्रवाइयों का निर्धारण करने के लिए विभिन्न पणधारियों के साथ परस्पर क्रियाशील कार्यशालाओं का आयोजन किया था।

समिति ने परिषद् के और प्रादेशिक परिषदों के पूर्व अध्यक्षों, पूर्व और वर्तमान सदस्यों, उद्योग क्षेत्र के वरिष्ठ वृत्तिकों और राष्ट्रीय तथा साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर के अन्य व्यक्तियों की भागीदारी से कार्यशालाओं का आयोजन किया था। इन कार्यशालाओं का आयोजन हरिद्वार, चेन्नई, कानपुर, पूणे और नई दिल्ली में किया गया था।

5.24.2 परिप्रेक्ष्य योजना समिति

परिप्रेक्ष्य योजना समिति राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली ऐसी सभी घटनाओं पर विचार करती है, जो वृत्ति के लिए बनाए गए विनियमित क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावनाएं रखती हैं और इसके अलावा ध्यान आकर्षित करने वाले मुद्दों पर विचार करके चार्टर्ड एकाउंटेंसी वृत्ति की अन्य क्षेत्रों में भूमिका क संवर्धन करने के लिए मार्ग और उपायों का सुझाव देती है। वर्ष 2009-2010 के दौरान समिति द्वारा आरंभ किए गए क्रियाकलापों/पहलों में निम्नलिखित सम्मिलित थे :

- **वित्तीय क्षेत्र में सुधारों संबंधी रिपोर्टें** : वर्ष 2009 की अंतिम तिमाही में जारी निम्नलिखित रिपोर्टों का ब्यौरेवार अध्ययन किया गया था और उस संबंध में उसकी सिफारिशों को परिषद् को प्रस्तुत किया गया था -

क) वित्तीय क्षेत्र के संबंध में रघुराम जी राजन समिति की रिपोर्ट, योजना आयोग

ख) वित्तीय क्षेत्र निर्धारण के संबंध में डा. राकेश मोहन समिति की रिपोर्ट, आरबीआई और भारत सरकार

समिति ने सकल आर्थिक विकास में लेखांकन वृत्ति के सहयोग और विशिष्ट रूप से आईसीएआई की भूमिका को विशिष्ट रूप से दर्शित करते हुए एक श्वेतपत्र तैयार किया था।

- **तृतीय देश संपरीक्षकों के संपरीक्षा कार्यकलापों के लिए संक्रमणकालीन अवधि से संबंधित यूरोपीय आयोग का निर्णय** : इस समिति ने कतिपय तृतीय देश संपरीक्षकों और भारत सहित संपरीक्षा अस्तित्वों के संपरीक्षा कार्यकलापों के लिए संक्रमणकालीन अवधि से संबंधित यूरोपीय आयोग के तारीख 29 जुलाई, 2008 के निर्णय पर भी विचार किया था। इस विषय पर परिषद् के स्तर पर विचार-विमर्श किया जा रहा है क्योंकि यह यूरोपीय आयोग उपबंध भारत के भीतर लेखांकन वृत्ति की घरेलू विनियामक संरचना के प्रतिकूल होगा और साथ ही भारत इंक. के लिए इसके दीर्घकालिक दुष्परिणाम होंगे।

- पृथक प्रकोष्ठ के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मामलों पर कार्यवाही करने की अपेक्षा : बढ़ते एमआरए और वैश्वीकरण को ध्यान में रखते हुए समिति ने यह और प्रस्ताव किया था कि अंतरराष्ट्रीय अधिकारिता से संबंधित शिकायत मामलों या अंतरराष्ट्रीय लेखांकन निकायों/ विनियामकों से परिषद् को चर्चा के लिए प्राप्त मामलों पर कार्यवाही करने के लिए एक पृथक प्रकोष्ठ की स्थापना की जाए ।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- एफएटीएफ दल के साथ परस्पर क्रिया : समिति ने वित्त मंत्रालय के फाइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा प्रारंभ की गई उस परस्पर मूल्यांकन कार्यवाही, जिसके परिणामस्वरूप भारत को एफएटीएफ की सदस्यता प्राप्त हो सकती थी, के भाग रूप में धन शोधन संबंधी वित्तीय कार्य योजना बल (एफएटीएफ) के भारत का दौरा करने वाले दल को भारतीय लेखांकन वृत्ति की स्थिति के संबंध में प्रस्तुतीकरण भी किया था और साथ ही आईसीएआई द्वारा धन शोधन के अपराधों को रोकने तथा आतंकवाद के वित्त पोषण के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए की गई पहलों के बारे में विशिष्ट रूप से बतलाया था ।

लेखांकन वृत्ति को विश्वभर में होने वाली घटनाओं के आलोक में समरूप बनाने के लिए और एकाउंटेंटों के लिए एक सक्रिय मंच उपलब्ध कराने के लिए समिति ने दो सम्मेलनों - पहला 26-27 जून, 2009 के दौरान विजयवाड़ा में “लेखांकन वृत्ति के उभरते प्रतिमान: मुद्दे और परिप्रेक्ष्य” विषय पर हीरक जयंती राष्ट्रीय सम्मेलन; और दूसरा 17-18 जुलाई, 2009 के दौरान हैदराबाद में “नए अवसरों की खोज” विषय पर अखिल भारतीय हीरक जयंती सम्मेलन का आयोजन किया था ।

5.24.3 विजन और परिप्रेक्ष्य योजना समिति

पुनःसंरचित विजन और परिप्रेक्ष्य योजना समिति, जो तत्कालीन दो समितियों, अर्थात् विजन समिति और परिप्रेक्ष्य योजना समिति को आमेलित करके बनाई गई है, वृत्ति की विश्वसनीयता संवर्धन करने और उभरते क्षेत्रों में उसके लिए एक बेहतर स्थान बनाने और साथ ही उसकी पहुंच को विस्तारित करने के लिए, ताकि वह सोसाइटी के लिए अधिक मूल्यवान सिद्ध हो सके, दीर्घकालिक विजन की प्राप्ति के लिए नीतिगत कार्य योजना में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली घटनाओं का पुनर्विलोकन करती है ।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां और पहले : 2009-10

विजन कार्यवाही में प्रत्येक पणधारी को अंतर्फलित करने के विचार से, विजन और परिप्रेक्ष्य योजना समिति, भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न भौगोलिक स्थानों से विचार प्राप्त करने और विभिन्न स्तर की घटनाओं और परिप्रेक्ष्यों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से 25 प्रमुख नगरों में विजन कार्यशालाओं का आयोजन कर रही है । अहमदाबाद, बड़ौदा, नागपुर, नासिक, हैदराबाद, मंगलोर, चेन्नई, एर्नाकुलम, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, जलन्धर, चंडीगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव, भुवनेश्वर, कोलकाता और गुवाहाटी में पहले ही इन कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है । ये कार्यशालाएं शीर्षस्थ स्तर पर विनियामकों, विख्यात व्यक्तियों और साथ ही परिषद् के पूर्व और विद्यमान सदस्यों और वृत्ति के सदस्यों से विजन विकास प्रक्रिया के संबंध में उनके अंतःनिवेशों के साथ भागीदारी की वांछ करती है ।

वित्तीय कार्ययोजना बल (एफएटीएफ), जो जी-20 द्वारा देशों को धन शोधन संबंधी पहलुओं का निर्धारण करने और उनके संबंध में समर्थ बनाने के लिए गठित एक अंतरराष्ट्रीय समूह है, ने दिसम्बर, 2009 में आईसीएआई के साथ अपनी परस्पर क्रिया के पश्चात् मार्च, 2010 में अपनी मूल्यांकन कार्यवाही को पूरा कर लिया था और उसने भारत में प्रति धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण संबंधी परस्पर मूल्यांकन रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है, जिसमें डीएनएफबीपी वृत्तिकों, जिनके अंतर्गत चार्टर्ड एकाउंटेंट भी हैं, का मूल्यांकन सम्मिलित है । यह उल्लेख करना उत्साहजनक है कि भारत को एफएटीएफ के गणमान्य क्लब की सदस्यता प्रदान की गई है, जो भारत को आतंकवाद के वित्त पोषण के संबंध में रियल टाइम डाटा तक पहुंच बनाने में समर्थ बनाएगी और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के तंत्र और अधिक मजबूत करेगी ।

5.25 जनसंपर्क संबंधी क्रियाकलाप

वर्ष 2009-2010 में जनसंपर्क संबंधी क्रियाकलापों में अत्यधिक वृद्धि हुई थी क्योंकि संस्थान ने घरेलू और वैश्विक रूप से वृत्ति के ब्रांड निर्माण में अभिवृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी हीरक जयंती को मनाया था। इस ऐतिहासिक वर्ष में मीडिया के साथ परस्पर क्रिया और संस्थान के भीतर - उसके सदस्यों, शाखाओं और प्रादेशिक कार्यालयों के बीच परस्पर क्रिया में वृद्धि हुई थी। इस वर्ष के दौरान किए गए पीआर क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :

- संस्थान ने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन का सामना करने के लिए व्यक्ति और सरकारी नीति स्तर, दोनों पर जागरूकता और समाधानों का प्रसार करने के लिए भारत में एक वृहत पहल के रूप में “प्लैनेट अलर्ट” को प्रारंभ किया था। आईसीएआई के सुसंगत समय पर पदासीन अध्यक्ष और श्री राहुल बोस, अलर्ट राजदूत, प्लैनेट अलर्ट ने जोखिम में फंसे ग्रह के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस वृहत आंदोलन को आरंभ किया था। इस हरित पहल को मीडिया में व्यापक स्तर पर कवरेज प्राप्त हुई थी।
- 3 से 5 जुलाई, 2009 के दौरान आगरा में “विंड ऑफ चैलेंजिंग-ग्लोबल स्ट्रेटिजिज फॉर एकाउंटिंग प्रोफेशन” शीर्षक वाले एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें 3 एमओयू/संयुक्त उद्घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस सम्मेलन में 2100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था जिसमें 25 देशों से 200 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। इस संपूर्ण आयोजन को व्यापक मीडिया कवरेज प्राप्त हुई थी।
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अवधारणा “भारत निगम सप्ताह” के प्रारंभ से, संस्थान ने मंत्रालय की साधारण जनता को वर्तमान बाजार में पणधारियों के हितों की संरक्षा के लिए स्थापित प्रक्रियाओं, संरचनाओं और व्यवहारों के संबंध में अवगत कराने के लिए ज्ञान के प्रसार और साथ ही पणधारियों को निगत शासन के फायदों का लाभ उठाने के लिए शासन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने की पहल में भागीदारी की थी। भारत निगम सप्ताह के दौरान, महामहिम श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की माननीय राष्ट्रपति ने संस्थान को भारत इंक के निगम शासन सन्धियों के अधिमान्यकरण में दिए गए उसके मूल्यवान सहयोग के लिए “उत्कृष्टता की मान्यता पुरस्कार” किया था। इस आयोजन को व्यापक मीडिया कवरेज प्राप्त हुई थी।
- आईसीएआई ने 29 से 31 जनवरी, 2010 के दौरान मुंबई में अपने वार्षिक आईसीएआई निगम मंच - असेंट टू पिनेकल का आयोजन किया था, जिसमें श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, संघ के माननीय कोयला, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्यमंत्री, सीए कुमारमंगलम बिड़ला, समूह अध्यक्ष, आदित्य बिड़ला ग्रुप और अनेकों अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए थे। इस संपूर्ण आयोजन को व्यापक मीडिया कवरेज प्राप्त हुई थी।
- मार्च, 2010 में समिति द्वारा संस्थान के उद्योग में लगे सदस्यों के लिए आयोजित कैम्पस नियोजन कार्यक्रम अत्यधिक सफल रहा था और मीडिया ने देशभर में नए चार्टर्ड एकाउंटेंटों को प्रस्थापित उच्च वेतन पैकेजों को विशिष्ट रूप से बताया था।
- संस्थान ने 1 मार्च, 2010 को नई दिल्ली में अपने सदस्यों के लिए एक विशेष संबोधन का आयोजन किया था, जिसमें श्री सलमन खुर्शीद, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारपोरेट कार्य मंत्रालय, ने वृत्ति के सदस्यों को संबोधित किया था। इस आयोजन को व्यापक मीडिया कवरेज प्राप्त हुई थी।
- संस्थान ने 31 मार्च, 2010 को सीबीईसी के साथ एक परस्पर समझ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। मीडिया ने इस एमओयू के महत्व को हाईलाइट किया था क्योंकि यह चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए अनेकों नए अवसर खोलेगा। सीए अब केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के निर्धारितियों को एसीईएस के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रूप से उनकी विवरणियों और अन्य दस्तावेजों को फाइल करने के लिए सेवा उपलब्ध करा सकते हैं।
- 29 अप्रैल, 2010 को नई दिल्ली में आईएफआरएस के साथ अभिसारित भारतीय लेखांकन मानकों संबंधी एक श्रृंखला-कार्यशालाओं के संबंध में एक उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह का

उदघाटन श्री आर. बंधोपाध्याय, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, ने किया था। इस आयोजन को व्यापक मीडिया कवरेज प्राप्त हुई थी।

- मीडिया परस्पर क्रियाओं में आमने-सामने साक्षात्कारों के माध्यम से सारवान वृद्धि हुई थी, जिनमें मीडिया को निरंतर आईएफआरएस के क्षेत्र में होने वाली नवीनतम घटनाओं, पाठ्यचर्या, वृत्ति, प्रारंभ होने वाले नए पाठ्यक्रमों, सीए के लिए नए दिशानिर्देशों, विदेशी प्रतिनिधियों के दौरों, अन्य क्रियाकलापों और आयोजनों आदि से अवगत कराया गया था।
- लेखों और साथ ही परस्पर क्रियाशील बैठकों/राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तर पर जारी प्रेस विज्ञप्ति और विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से आज के आधुनिक संदर्भ में चार्टर्ड एकाउंटेंसी वृत्ति की संभावनाओं और विस्तार क्षेत्र का संवर्धन किया गया था।
- संस्थान के भीतर विभिन्न विभागों और प्रादेशिक कार्यालयों तथा शाखाओं को, संस्थान और और उसके कार्यालयों/संबद्ध संगठनों के बीच संचार संपर्क विकसित करने के विचार से साधार-तंत्र संबंधी समर्थन उपलब्ध कराया गया था।
- जनसंपर्क क्रिया के भागरूप में, संस्थान और उसकी विभिन्न समितियों द्वारा आयोजित विभिन्न संगोष्ठियों/कार्यक्रमों/आयोजनों/पुस्तक विमोचनों को मुद्रण और इलेक्ट्रानिक मीडिया ने उचित कवरेज प्रदान करने संबंधी कार्यवाही की गई थी।
- प्रेस और मीडिया को सतत परस्पर क्रियाओं और विशेष रूप से परिषद् की प्रत्येक बैठक के आयोजन के पश्चात् वृत्ति में होने वाली नवीनतम घटनाओं से अवगत कराना जारी रखा गया था।
- आईसीएआई की वेबसाइट, आईसीएआई के आयोजनों से संबंधित कवरेज के लिए एक सुगम माध्यम बनी रही थी, जिसपर संस्थान द्वारा उसके सदस्यों और छात्रों के लिए की गई विभिन्न पहलों के संबंध में सभी प्रेस कवरेज को सम्यक् रूप से प्रदर्शित किया जाता है।

6. अंतरराष्ट्रीय कार्य समिति

6.1 अन्य लेखांकन निकायों द्वारा भारतीय अर्हता को मान्यता

चयनित विदेशी लेखांकन निकायों द्वारा संस्थान की अर्हताओं के मूल्यांकन के लिए उनके साथ निरंतर संवाद की प्रक्रिया का तेजी से चलते रहना ताकि विदेशी निकायों की अर्हता का भाग बनने वाले प्रशिक्षण और परीक्षा से संस्थान के सदस्यों को छूट प्राप्त हो जाए। लंबी प्रक्रिया होने के कारण, जिसमें अर्हता, प्रशिक्षण, सतत वृत्तिक शिक्षा और अनुशासनात्मक अपेक्षाओं का मूल्यांकन और देशीय संवेदनशीलताएं भी अंतर्बलित हैं, प्रक्रिया के परिणाम धीमे हैं, फिर भी संस्थान अपने प्रयासों से इसे शीघ्र ही समाप्त करने के लिए सक्रिय है। संस्थान ने इंग्लैंड और वेल्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान और जीबूटी विश्वविद्यालय के साथ परस्पर समझ ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। सीपीए, आस्ट्रेलिया के साथ परस्पर मान्यता कथार (एमआरए) पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। अर्हता मान्यता की प्रक्रिया कनाडा, सिंगापुर, बहरीन, आयरलैंड आदि के लेखांकन निकायों के साथ चर्चा के विभिन्न प्रक्रमों पर है।

6.2 अंतरराष्ट्रीय मंचों में आईसीएआई का प्रतिनिधित्व

आईसीएआई द्वारा अदा की गई महत्वपूर्ण भूमिका का प्रमाण उसके अंतरराष्ट्रीय लेखांकन निकायों अर्थात् इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एकाउन्टेन्ट्स (आईएफएसी), कन्फेडरेशन ऑफ एशियन एंड पेसिफिक एकाउन्टेन्ट्स (सीएपीए) और साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ एकाउन्टेन्ट्स (एसएएफए) की विभिन्न कृत्यकारी समितियों के अलावा उनके शासन बोर्डों में नामनिर्देशन से मिलता है। इस समय आईसीएआई का प्रतिनिधि एसएएफए के अध्यक्ष का पद धारित किए हुए है। संस्थान को इस समय निम्नलिखित में इसके नामनिर्देशितियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त है :-

आईएफएसी की समितियाँ

- बोर्ड सदस्य के रूप में
- लघु और मध्यम प्रेक्टीशनर समिति
- विकासशील राष्ट्र समिति
- आईएफएसी अनुपालन सलाहकार पैनल
- अंतरराष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानक बोर्ड

सीएपीए

- बोर्ड सदस्य के रूप में

एसएएफए

- बोर्ड सदस्य के रूप में
- शिक्षा, प्रशिक्षण और सीपीडी संबंधी समिति
- लेखांकन और लेखांकन मानकों संबंधी समिति
- वृत्तिक आचार संहिता और स्वतंत्रता संबंधी समिति
- पारदर्शिता, जवाबदेही और शासन में सुधार संबंधी समिति
- कारबार में वृत्तिक एकाउन्टेन्टों संबंधी समिति
- क्वालिटी नियंत्रण संबंधी समिति
- लघु और मध्यम व्यवसायियों संबंधी समिति
- वित्तीय और टैरिफ व्यवस्था के सुव्यवस्थीकरण संबंधी समिति
- एसएएफए संविधान के पुनर्विलोकन के लिए कार्यबल
- अध्यक्ष, आईसीएआई, बोर्ड सदस्य के रूप में
- सचिव, स्थायी सचिव के रूप में

6.3 एमओयू/एमआरए

आईसीएआई ने 18-19 मई, 2009 के दौरान मुंबई में अफ्रीका दिवस समारोह के उपलक्ष्य में 18 मई, 2009 को जिबूटी विश्वविद्यालय, जिबूटी गणराज्य के साथ परस्पर समझ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस एमओयू पर जिबूटी राष्ट्रियों को लेखांकन के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने और जिबूटी में लेखांकन निकाय को संस्थागत बनाने के लिए परस्पर सहयोग से कार्य करने हेतु हस्ताक्षर किए गए थे।

आईसीएआई ने “विंड ऑफ चैलेंजिज-ग्लोबल स्ट्रेटजिज फॉर एकाउंटिंग प्रोफेशन” शीर्षक वाले एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर आगस्त में 3 जुलाई, 2009 को आस्ट्रेलिया चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएए) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। इस सम्मेलन का उद्घाटन सर डेविड ट्वीडी, अध्यक्ष, आईएसबी ने किया था। उक्त अवसर पर, अर्नस्ट अलमॉड, अध्यक्ष, एआईसीपीए और प्रो० शिल्डर, अध्यक्ष, आईएएसबी भी उपस्थित थे। दोनों संस्थाओं ने मिलकर एक परस्पर समझ ज्ञापन तैयार करने का विनिश्चय किया था, जिससे कि एक दूसरे की अर्हता, प्रशिक्षण को मान्यता प्रदान की जा सके और एक सेतु तंत्र विहित करके अच्छी छवि वाले सदस्यों को प्रवेश दिया जा सके और साथ ही दोनों ओर से वृत्तिकों के आदान-प्रदान में वृद्धि की जा सके।

आईसीएआई ने 3 से 5 जुलाई, 2009 के दौरान “विंड ऑफ चैलेंजिज-ग्लोबल स्ट्रेटजिज फॉर एकाउंटिंग प्रोफेशन” शीर्षक वाले एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर आगस्त में 4 जुलाई, 2009 को सर्टिफाइड जनरल एकाउंटेंट्स एसोसिएशन ऑफ कनाडा के साथ एक संयुक्त उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों निकायों ने सदस्यों, छात्रों और उनके संगठनों के सर्वोत्तम हित में एक परस्पर रूप से फायदाप्रद संबंध विकसित करने के लिए मिलकर कार्य करने की वांछा की थी।

आईसीएआई ने 3 से 5 जुलाई, 2009 के दौरान “विंड ऑफ चैलेंजिज-ग्लोबल स्ट्रेटिजिज फॉर एकाउंटिंग प्रोफेशन” शीर्षक वाले एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के अंतिम दिवस पर आगरा में 5 जुलाई, 2009 को बहरीन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग और फाइनेंस के साथ एक संयुक्त उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। यह उद्घोषणा आईसीएआई और बहरीन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग और फाइनेंस के बीच निकट कार्य संबंधों को स्थापित करने में सहायता करेगी और दोनों निकायों को लेखांकन, वित्तीय इंजीनियरी, निगम शासन और समान क्षेत्रों में एक-दूसरे के पास उपलब्ध वृत्तिक विशेषज्ञता से लाभ उठाने का अवसर प्राप्त होगा।

इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंटेंट्स, सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय वार्तालाप के और चरणों को प्रारंभ करने हेतु उपायों संबंधी पहलें की गई हैं ताकि दोनों देशों के बीच एमओयू को अंतिम रूप दिया जा सके और इस संबंध में सरकार द्वारा की गई पहलों का भी समर्थन किया जा सके। सीआईसीए और सीपीए आयरलैंड के साथ भी एमओयू को अंतिम रूप दिए जाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

6.4 विदेशों में चैप्टर प्रारंभ करना

आईसीएआई ने अपना 21वां चैप्टर सिंगापुर में जनवरी, 2010 में खोला।

आईसीएआई द्वारा आयरलैंड, थाईलैंड और रास अल खाइमा में अपने चैप्टरों को खोलने के लिए बातचीत की जा रही है।

संस्थान स्विटजरलैंड, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रिका में आईसीएआई के चैप्टर खोलने के लिए बातचीत तथा सक्रिय उपाय कर रहा है। संस्थान के विदेशी चैप्टर भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट वृत्ति को अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और स्वयं को एक विश्वस्तरीय वित्तीय सक्षमता, उत्तम शासन और प्रतिस्पर्धात्मकता के मूल्यवान न्यासी के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य के प्रति यह एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।

6.5 भारत आने वाले प्रतिनिधिमंडल

• कनाडा से प्रतिनिधिमंडल का दौरा

श्री लेले हैंडफील्ड, उपाध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय और कारपोरेट कार्य और श्री बलदेव, उपाध्यक्ष, वित्त और प्रशासन, कनाडा का प्रमाणित साधारण लेखाकार संघ ने 13 अप्रैल, 2009 को परस्पर मान्यता कशर करने के लिए आईसीएआई और सीजीए कनाडा के बीच द्विपक्षीय बातचीत पर विचार-विमर्श करने के लिए आईसीएआई का दौरा किया था। इस बैठक का उद्देश्य सीजीए कनाडा और आईसीएआई के तुलनात्मक विश्लेषण पर चर्चा करना तथा एमआरए संबंधी बातचीत को अग्रसर करना था।

• बहरीन से प्रतिनिधिमंडल का दौरा

डा० जार्ज जोसफ, बहरीन गणराज्य के भारत में राजदूत ने 17 और 18 अप्रैल, 2009 के दौरान आईसीएआई का दौरा किया था और बहरीन में लेखांकन वृत्ति के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर और लेखांकन वृत्ति के संस्थाकरण में संस्थान द्वारा निभाई जा सकने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में आईसीएआई के प्रतिनिधियों के साथ परस्पर क्रिया की थी। बहरीन में आईसीएआई का कार्यालय आरंभ करने के लिए सक्रिय उपाय किए गए हैं।

• कनाडियाई चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान से प्रतिनिधिमंडल का दौरा

सीए जिलन खलील, निदेशक सीए अर्हता की अगुवाई में कनाडियाई चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान से एक प्रतिनिधिमंडल ने, जिसमें सीए पाले मेसीकोट, प्रधानाचार्य, सीए अर्हता भी सम्मिलित थे, ने 8 जून से 10 जून, 2009 के दौरान, दोनों संस्थानों के बीच वृत्तिक अर्हता के आपसी मान्यता कशर की संभावनाओं पर गहन विचार-विमर्श करने के लिए आईसीएआई का दौरा किया था।

• अमरीकी सीपीए संस्थान से प्रतिनिधिमंडल का दौरा

श्री अर्नी एलमोंट, अध्यक्ष, एआईसीपीए ने, आगरा में आईसीएआई के हीरक जयंती अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में

प्रमुख भाषण देने के लिए 30 जून, 2009 से 04 जुलाई, 2009 के दौरान भारत का दौरा किया था। इस दौरे के दौरान, उन्होंने सीएंडएजी, सीजीए, वित्त मंत्रालय और कारपोरेट कार्य मंत्रालय से भी बैठकें की थी।

• आईसीए से प्रतिनिधिमंडल का दौरा

2009 में एमओयू पर हस्ताक्षर के पश्चात् आईसीएआई और आईसीए के बीच सृजित सहबद्धता को और मजबूत करने के लिए श्री ग्राहम मेयर, सीईओ, आस्ट्रेलिया चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान और श्री बिल पामर, निदेशक एशिया, आईसीए से युक्त एक प्रतिनिधिमंडल ने 12 और 13 अप्रैल, 2010 के दौरान आईसीएआई का दौरा किया था। भारत में अपने दौरे के दौरान, उन्होंने भारत के उपनियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय और साथ ही आईसीएआई के कृत्यकारियों के साथ बैठकें की थीं। इन बैठकों के अनुक्रम में प्रतिनिधिमंडल को दो संस्थानों के बीच संयुक्त सहयोग को अग्रसर करने और परस्पर फायदे के लिए भविष्य में और निकटता से साथ मिलकर कार्य करने की संभावनाओं का पता लगाने और प्रत्येक निकाय की संबंधित अधिकारिता के भीतर उसके समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए विचार-विमर्श को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ था।

• जापान से प्रतिनिधिमंडल का दौरा

उपरोक्त के अतिरिक्त, श्री नोरीआकी शीमाजुकी, अध्यक्ष, आंतरिक कार्य समिति, जापान आईएफआरएस परिषद् के नेतृत्व में एक जापानी प्रतिनिधिमंडल ने आईएफआरएस के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग विकसित करने के लिए 22 अप्रैल, 2010 को आईसीएआई का दौरा किया था। आईसीएआई जैपनिज इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंटेंट के साथ दोनों देशों के बीच हुई परस्पर समझ को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत श्री सलमान खुशीद, माननीय कारपोरेट कार्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री आर. बंधोपाध्याय, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय और आईसीएआई के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में आईसीएआई के अधिकारियों की उपस्थिति में हुई थी। आईसीएआई आईएफआरएस के साथ अभिसरण में अंतर्वर्तित महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करेगा और परस्पर रूप से सहमत परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से आम सहमति तैयार की जाएगी।

• आईएफएसी से प्रतिनिधिमंडल का दौरा

श्री रॉबर्ट बंटिंग, अध्यक्ष, आईएफएसी, श्री ईयान बाल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आईएफएसी और श्री मैथ्यू बोहुन, तकनीकी प्रबंधक, शासन और प्रचालन से युक्त आईएफएसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने हैदराबाद, भारत में वर्ष 2014 में होने वाली प्रस्तावित 19वीं विश्व एकाउंटेंट कांग्रेस के लिए 10-12 मई, 2010 के दौरान भारत का दौरा किया था। इस प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के कृत्यकारियों और सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ भी दिल्ली में बैठकें की थीं।

• जियामन नेशनल एकाउंटिंग इंस्टिट्यूट से प्रतिनिधिमंडल का दौरा

श्री जांग जुन, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र में पीएचडी, जियामन नेशनल एकाउंटिंग इंस्टिट्यूट के नेतृत्व में जियामन नेशनल एकाउंटिंग इंस्टिट्यूट के एक प्रतिनिधिमंडल ने, जिसमें जांग मिंग, उप महानिदेशक, कार्मिक और शिक्षा विभाग, वित्त मंत्रालय, शेनयी, निदेशक, साधारण कार्यालय, जियामन नेशनल एकाउंटिंग इंस्टिट्यूट, जांग जियालिन, प्रोफेसर, जियामन नेशनल एकाउंटिंग इंस्टिट्यूट, सीएओ यांजई, सहबद्ध प्रोफेसर, जियामन नेशनल एकाउंटिंग इंस्टिट्यूट और ये हूई, उप वरिष्ठ स्टाफ, सूचना प्रबंध विभाग, जियामन नेशनल एकाउंटिंग इंस्टिट्यूट ने आईसीएआई के कृत्यकारियों से परस्पर क्रिया करने और संस्थान के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए 11 जून, 2010 को आईसीएआई का दौरा किया था।

6.6 अफ्रीका दिवस समारोह

आईसीएआई और भारतीय-अफ्रीकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 18-19 मई, 2009 के दौरान मुंबई में अफ्रीका दिवस मनाया था। अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न देशों के राजनयिक अफ्रीका के विकास के लिए कार्य रणनीति तैयार करने के लिए एकत्रित हुए थे। राजयिकों ने अफ्रीका महाद्वीप के विकास के लिए भारत के प्रयासों

की प्रशंसा की थी और यह विश्वास अभिव्यक्त किया था कि भारत और अफ्रीका के बीच यह प्रगतिशील संबंध नई उंचाईयां छुएंगे।

इन संबंधों के संवर्धन के उपलक्ष्य में, आईसीएआई और जीबूटी विश्वविद्यालय के बीच, जीबूटी राष्ट्रियों को लेखांकन के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने और जीबूटी में लेखांकन निकाय के संस्थाकरण हेतु एक साथ कार्य करने के लिए एक परस्पर समझ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। माननीय श्री एस.सी.जमीर, राज्यपाल, महाराष्ट्र, माननीय श्री मुसलिया मुदावाडी, केन्या के उप प्रधानमंत्री और श्री जयंतराव पाटिल, गृह मंत्री, महाराष्ट्र सरकार ने इस समारोह की शोभा बढ़ाई थी।

6.7 एक अंतरराष्ट्रीय लेखांकन तकनीशियन फेडरेशन की स्थापना

आईसीएआई पूरे विश्व में लेखांकन तकनीशियन की वृत्ति का संवर्धन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय लेखाकार फेडरेशन (आईएफएसी) की तर्ज पर अंतरराष्ट्रीय लेखांकन तकनीशियन फेडरेशन (आईएफएसी) की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। आईएफएटी का उद्देश्य क्वालिटी लेखांकन शिक्षा, प्रशिक्षण, नैतिक अपेक्षाओं, सीपीडी, अनुशासनात्मक अपेक्षाओं और वृत्ति को दूर तक ले जाने संबंधी ऐसे क्रियाकलापों के माध्यमों से, जो पूरे विश्व के सभी पणधारियों की आवश्यकताओं को पूरा करें, एक अर्द्ध-कौशल प्रमाणन के रूप में लेखांकन वृत्ति को विकसित करने और मजबूत बनाने के लिए ढांचा उपलब्ध कराना है।

6.8 भारत सरकार द्वारा गठित विशेष समूहों को योगदान

आईसीएआई सक्रिय रूप से क्रमशः वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और कारपोरेट कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में गठित विशेष कार्य बलों, अर्थात्, भारतीय-यूके लेखांकन कार्यबल और कारपोरेट कार्य संबंधी भारतीय यूके कार्यबल के क्रियाकलापों में भाग लेता है और योगदान करता है।

6.9 सम्मेलन

3 से 5 जुलाई, 2009 को आगरा, उत्तर प्रदेश में “लेखांकन वृत्ति-विनियामक अनुपालन से परे” विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में देशभर से 2100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और 25 अन्य देशों से लगभग 200 विदेशी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। इस तीन दिवसीय सम्मेलन में उभरते और समकालीन महत्व के विभिन्न मुद्दों, अर्थात् अंतरराष्ट्रीय मानकों का सुमेलन, वित्तीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, प्रत्याशा संबंधी दूरी को समाप्त करना, वित्तीय बाजार और परे पर विचार-विमर्श किया गया था।

7. अन्य गतिविधियां

7.1 मानव संसाधन विकास

किसी संगठन को विकास के नए दौर में स्थापित करने के लिए, उस संगठन के लिए यह आवश्यक है कि उसके पास ईमानदार, समर्पित और सक्षम मानव संसाधन हों। इस मद्दे परिषद् ने न केवल अपना ध्यान अपने उच्च कार्यनिष्पादन करने वाले कार्य बल को अपने पास बनाए रखने पर केन्द्रित करना जारी रखा, अपितु इस क्षेत्र के सर्वोत्तम और सर्वाधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों को संगठन में लाने के लिए उपाय प्रारंभ किए। इस तथ्य को मान्यता प्रदान करते हुए भी प्रशिक्षण, सक्षमता के स्तर में वृद्धि और व्यक्तित्व के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है, आईसीएआई के परिसरों के भीतर और बाहर आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पाठ्यक्रमों में भागीदारी करने पर जोर देना जारी रखा। शायद पहली बार संस्थान में उपलब्ध अधिकाधिक तकनीकी/शैक्षणिक व्यक्तियों को आईएफएसी की समितियों की बैठकों के लिए तैनात किया गया था जिससे कि व्यष्टियों की शैक्षिक उत्कृष्टता में आगे और वृद्धि की जा सके।

कौशल और ज्ञान में और अधिक वृद्धि करने तथा सदस्यों, छात्रों तथा अन्य संबद्ध व्यक्तियों को क्वालिटी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संस्थान में व्यवहारिक परिवर्तन लाने के लिए संस्थान के दिल्ली स्थित मुख्यालय और अन्य प्रादेशिक कार्यालयों में विभिन्न विषयों पर ढांचागत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

प्रशिक्षण कार्यक्रम - अप्रैल, 2009 से आगे

क्रम सं.	कार्यक्रम की तारीख	अवधि (दिन/घंटे)	शीर्षक	भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या	मानव घंटों की संख्या
दिल्ली कार्यालय					
01.	29 अप्रैल, 2010	1 घंटा	आईएफआरएस के साथ अभिसारित भारतीय लेखांकन मानकों संबंधी श्रृंखला/कार्याशालाओं का उद्घाटन समारोह	सभी चार्टर्ड एकाउंटेंट 69	69X1= 69 घंटे
02.	07 जून, 2010 से 08 जून, 2010	8 घंटे	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मानकों संबंधी अनुकूलन पाठ्यक्रम	सभी चार्टर्ड एकाउंटेंट 69	69X8=552 घंटे
चेन्नई कार्यालय					
01.	02 मई, 2009	आधा दिन	टैली के मूलभूत सिद्धांत	20	20X4=80 घंटे
02.	15 जून, 2010 से 18 जून, 2010	4 दिन	पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए 13वां राष्ट्रीय अभिसमय	01	1X4X8=32 घंटे

पूर्वोक्त ऐसे क्षेत्रों, विषयों/विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों से अतिरिक्त हैं जिनमें विभिन्न समितियों/विभागों के व्यक्ति अधिकारियों द्वारा पृथक रूप से भाग लिया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त, 27 फरवरी, 2010 को संस्थान के मुख्यालय में सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक पारिवारिक मिलन - सह - होली मिलन का आयोजन किया गया था जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और परिषद् के अन्य सदस्यों ने भी भाग लिया था।

रिपोर्ट की अवधि के अंतिम छह मास के दौरान क्षेत्र की सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने के अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, संकाय/शैक्षण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए समयबद्ध भर्ती कार्यक्रम चलाए गए थे। इस प्रकार की गई पहलों से वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं और 131 से अधिक मानव संसाधनों को नियोजित किया गया है, जो आईसीएआई के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी/शैक्षणिक पदों के लिए हैं। इसके अतिरिक्त 62 प्रबंध प्रशिक्षुओं को समुचित स्तरों पर प्रविष्टि प्रदान की गई है।

शिकायत समाधान, समय पर परामर्शी सेवाओं, विकसित प्रसुविधा प्रबंध आदि के उद्देश्य से रिपोर्ट की अवधि के दौरान की गई और मानव संसाधन पहलों में बेहतर और क्वालिटी संकर्म वातावरण, साप्ताहिक विभागीय बैठकें, आवधिक कर्मचारी परामर्शी सेवा, शिकायत समाधान तथा कठिनाइयों को दूर करने वाले उपायों के साथ नए मास की शुरुआत करना सम्मिलित है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, समितियों और समूहों, अर्थात् मानव संसाधन और प्रशासन समिति, वेतन संरचना के पुनरीक्षण संबंधी एचआर समूह और विभिन्न स्तरों/अवस्थानों पर संगठनात्मक सदस्य संख्या के सदस्य संख्या के पुनर्विलोकन और अनावश्यक सदस्यों की तुलना में अपेक्षित सदस्य संख्या की पहचान करने के माध्यम से कर्मचारिवृंद की संख्या के अवधारण संबंधी एचआर समूह, द्वारा विभिन्न पहलों की गई हैं, जो न केवल समिति/विभाग की अपेक्षाओं और कर्मचारिवृंद की उपलब्धता का सुमेलन करती हैं अपितु मानव संसाधनों को प्रतिकर भी सुनिश्चित करती हैं। इस प्रकार की गई पहलों से यह प्रत्याशा की जाती है कि वे शीघ्र ही परिणाम दर्शित करेंगी।

7.1.2 आईटीटी प्रयोगशालाओं/शाखाओं के लिए डीजल जेनरेटर सेट का उपापन

संस्थान के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार, आज की तारीख तक शाखाओं द्वारा स्थापित भिन्न-

भिन्न आईटीटी प्रयोगशालाओं में अबाधित विद्युत प्रदाय के लिए अपेक्षा के अनुसार विभिन्न क्षमता के 77 डीजी सेटों के लिए आदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार, डीजी सेट के उपबंध की सुविधा को संस्थान के सीपीई चैप्टरों के अधीन स्थापित/स्थापित की जाने वाली आईटीटी प्रयोगशालाओं को भी विस्तारित किया गया है। अधिकांश स्थानों पर प्रतिष्ठापन और कार्य प्रारंभ करने संबंधी कार्य पूरा हो गया है और डीजी सेटों का उपयोग आरंभ कर दिया गया है। शेष अवस्थानों के संबंध में यह आशा की जाती है कि डीजी सेट सितम्बर, 2010 के अंत तक प्रचालन करने लगेंगे।

7.1.3 लेखांकन संग्रहालय

प्राचीनतम तुलन पत्र जैसी दुर्लभ और ऐतिहासिक चित्रों तथा लेखांकन के विकास के दस्तावेजी साक्ष्यों से युक्त लेखांकन संग्रहालय का, जो संस्थान के सी-1, सेक्टर-1, नोएडा स्थित परिसर में अवस्थित है, उदघाटन किया गया था। संग्रहालय के लिए भारतीय लेखांकन संग्रहालय के नाम का उपयोग करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय, खाद्य और लोक वितरण, भारत सरकार के तारीख 30 अप्रैल, 2009 के पत्र द्वारा मान्यता/अनुमति प्रदान की गई है।

7.1.4 प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार

वर्ष के दौरान क्रय और उपापन करने के लिए, क्रय नीति का पुनर्विलोकन किया गया था और एक पुनःसंरचित क्रय नीति को सुस्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त, ऐतिहासिक/ पुरातत्वीय महत्व के सभी अभिलेखों को प्रतिधारित करने की आवश्यकता के संबंध में एक परिसमापन/व्ययन नीति तैयार की गई है और विधिक तथा अन्य अपेक्षाओं के संदर्भ में अन्य अभिलेखों को प्रतिधारित करने की नीति भी स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त, सेवा प्रदाताओं के बने रहने या अन्यथा का पुनर्विलोकन भी प्रारंभ किया गया था।

7.1.5 प्रधान कार्यालय के मुख्य भवन का नवीकरण

संस्थान के प्रधान कार्यालय के सामने के प्रांगण के नवीकरण के साथ प्रधान कार्यालय के मुख्य भवन के भूतल पर स्थित स्वागत कक्ष का नवीकरण भी किया गया था। संस्थान के प्रधान कार्यालय के मुख्य भवन की अवसंरचना को मजबूत करने और उसकी मरम्मत करने संबंधी कार्य भी पूरा किया गया था।

7.1.6 विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों/विभागों को किए गए प्रतिवेदन

वर्ष 2009-10 के दौरान गठित प्रतिवेदन समिति के माध्यम से अनेक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए थे तथा वर्ष के दौरान किए गए प्रतिवेदन निम्नानुसार हैं :

- भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई को, बैंकों को संपरीक्षक नियुक्त करने में दी गई स्वायत्तता का विरोध करते हुए।
- भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई को, उनकी लाइसेंसियेट, एसोशिएटशीप और फ़ैलोशीप परीक्षाओं में आईसीएआई के सदस्यों को छूट देने के संबंध में।
- वाणिज्यिक कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2008 और अधिनियम के अधीन वैट संपरीक्षा उपबंधों के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने और साथ ही 30 जून, 2009 तक संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का साधारण विस्तारण प्राप्त करने के लिए।
- पूर्त आयुक्त (महाराष्ट्र राज्य), मुंबई को चार्टर्ड एकाउंटेंटों को सोसाइटियों तथा न्यासों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित मामलों में उपसंज्ञात होने की अनुज्ञा देने हेतु अनुरोध करने के लिए।
- गोवा सरकार के लिए दोहरे प्रवेश और प्रोदमवन आधारित लेखांकन प्रणाली आरंभ करने के संबंध में गोवा के मुख्यमंत्री को।
- प्रमाणीकरण प्राधिकारियों का नियंत्रक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार को प्रमाणीकरण प्राधिकारियों की संपरीक्षा अवसंरचना के लिए संपरीक्षकों को पैलबद्ध करने के लिए।
- नया प्रत्यक्ष सं. 17 के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को।
- संपरीक्षा वर्ष 2007-08 के संबंध में संवीक्षा मामलों में प्रतिदाय के विलंब के कारण निर्धारितियों के सामने आई असम्यक कठिनाइयों के संबंध में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को।

- अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह, खादी और प्रोमोद्योग बोर्ड को, उन्हें बजट संबंधी संसाधन लेखा और कंसोर्टियम बैंक क्रेडिट एकाउंट को तैयार करने, उनकी पुनःसंरचना तथा संपरीक्षा के लिए कोटेशन सूचना में संशोधन करने और उसे आचार-संहिता के समरूप बनाने का अनुरोध करते हुए ।
- वित्त मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और विक्रय कर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई को महाराष्ट्र में व्यवहारियों के वैट के सीएसटी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के मामले में उल्लंघन के संबंध में ।
- सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार को, नेत्रहीन चार्टर्ड एकाउंटेंटों के वित्त और लेखा क्षेत्रों में सरकारी नियोजन को आज़ापक बनाकर उनके सशक्तिकरण के लिए ।
- सभी मुख्यमंत्रियों को, उन्हें दोहरे प्रवेश प्रोदमवन आधारित लेखांकन प्रणाली प्रारंभ करने का सुझाव देते हुए ।
- भारतीय रिजर्व बैंक को, उन्हें बैंक शाखा संपरीक्षक पैनल के लिए आईसीएआई को जिलों की अद्यतन सूची उपलब्ध करने का अनुरोध करते हुए ।
- विधि और न्यायपालिका विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई को फर्मों के रजिस्ट्रार के कार्यालय, महाराष्ट्र, मुंबई के साथ दस्तावेजों के अनुपालन/रजिस्ट्रीकरण के लिए आम माफी स्कीम और ऑन लाइन प्रणाली प्रारंभ करने का अनुरोध करते हुए ।
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 14क और 14कक के अधीन विशेष संपरीक्षा के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंटों के नामांकन का प्रस्ताव करते हुए ।
- पब्लिक सेक्टर और निजी सेक्टर की संपरीक्षा फीस के बीच अंतर के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को ।
- सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्रालय, भारत सरकार को, एसटीपीआई को वार्षिक कार्यपालन रिपोर्ट (एपीआर) को प्रस्तुत करने में समय विस्तारण का अनुरोध करते हुए ।
- मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के अधीन स्कीमों की संपरीक्षा के संबंध में मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी को ।
- स्रोत पर भिन्न कर कटौती या कर की कटौती न करने संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त करने में आने वाली वास्तविक मुश्किलों और व्यवहारिक कठिनाइयों के संबंध में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को ।
- सीबीडीटी के तारीख 21.5.2009 के परिपत्र सं.03/2009 में दिए गए निदेशों के संबंध में संपरीक्षा वर्ष 2009-10 के लिए आयकर विवरणियां फाइल करने में सामने आने वाली मुश्किलों और व्यवहारिक कठिनाइयों के संबंध में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को ।
- बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा के लिए पारिश्रमिक के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को ।
- भारत के उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को, उन्हें अन्य सरकारी प्राधिकारियों को पैनल अग्रेषित करते समय आवर्त संबंधी मानदंड पर ध्यान न देने का अनुरोध करते हुए ।
- पब्लिक सेक्टर उपक्रमों की संपरीक्षा फीस के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को।
- प्रधान सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश सरकार को, उन्हें ग्राम पंचायत - डीपीआरओ फैजाबाद के संपरीक्षकों की नियुक्ति के लिए निकाली गई निविदा को रद्द करने का अनुरोध करते हुए ।
- विक्रयकर व्यवसायियों संबंधी संस्थान के सृजन के लिए अध्यादेश न जारी करने का अनुरोध करते हुए विक्रय कर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य को ।
- वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार को, उन्हें बैंकों को संपरीक्षक नियुक्त करने में दी गई स्वायत्तता पर पुनःविचार करने का अनुरोध करते हुए ।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को, उन्हें विभिन्न प्रकार की संपरीक्षाओं/समनुदेशनों के संचालन के लिए आईसीएआई के चार्टर्ड एकाउंटेंटों के पैनल का लाभ उठाने का अनुरोध करते हुए ।
- पब्लिक सेक्टर बैंकों की केन्द्रीय कानूनी संपरीक्षा के लिए आबंटन की प्रक्रिया के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को ।
- प्राइवेट सेक्टर बैंकों की संपरीक्षा के विस्तार क्षेत्र में वृद्धि करने और अन्य संबद्ध विषयों के संबंध में वित्त मंत्री, भारत सरकार को ।

- वित्त और वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल को मध्य प्रदेश में वैट अधिनियम के कार्यान्वयन के अनुसरण में आने वाली मुश्किलों और कठिनाइयों संबंधी ज्ञापन के संबंध में ।
- परस्पर निधियों की प्रणाली संपरीक्षा के लिए डीआईएसए अर्हता को मान्यता देने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) को ।
- भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई को, कानूनी बैंक शाखा संपरीक्षाओं के आबंटन की वर्तमान प्रणाली पर पुनर्विचार करने के लिए ।
- वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को, उन्हें इस तथ्य के संबंध में सत्यापन प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए कि कर संपरीक्षा एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा की गई है, आयकर विवरणी में शुद्ध लाभ का सुझाव देते हुए ।
- कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक को, उन्हें बैंकों की कानूनी संपरीक्षा के लिए संपरीक्षा परिधानिक में वृद्धि करने का अनुरोध करते हुए ।
- मुख्य महाप्रबंधक, पर्यवेक्षण विभाग, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को, उन्हें प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के संपरीक्षकों की फीसों में पुनरीक्षण का अनुरोध करते हुए ।
- उप महाप्रबंधक, सेबी (बाजार मध्यवर्ती विनियम और पर्यवेक्षण विभाग) को, उन्हें यह अनुरोध करते हुए कि क्रेडिट रेटिंग अभिकरणों (सीआरए) के लिए आंतरिक संपरीक्षा केवल चार्टर्ड एकाउंटेंटों द्वारा ही की जाए ।
- विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को, व्यापार बोर्ड में आईसीएआई के प्रतिनिधि के नामांकन का अनुरोध करते हुए ।
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड को उन्हें सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सलाहकार परिषद् और कमीशनरी की प्रादेशिक सलाहकार समितियों में आईसीएआई के प्रतिनिधि के नामांकन का अनुरोध करते हुए ।

7.1.7 किए गए प्रयासों का परिणाम

- भारतीय बीमा संस्थान ने लाइसेंसिएट, एसोशिएट और फेलोशिप पाठ्यक्रमों की कुछ परीक्षाओं में छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है ।
- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नए प्रारूप सं. 17 पर स्पष्टीकरण जारी किया था ।
- संघ सरकार ने अपने बजट प्रस्ताव 2009-10 में धारा 14क और धारा 14कक में संशोधन को सम्मिलित किया था, जिसके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त को विशेष संपरीक्षा करने हेतु किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त किया गया था ।
- वित्त और वाणिज्य मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार को एक प्रतिवेदन द्वारा मध्य प्रदेश में वैट अधिनियम के कार्यान्वयन के कारण आई समस्याओं और कठिनाइयों संबंधी ज्ञापन में दिए गए सुझावों पर सकारात्मक रूप से विचार किया गया था ।
- सेवा कर आयुक्त द्वारा जारी संसूचना के अनुसरण में, आईसीएआई के अध्यक्ष को प्रादेशिक सलाहकार समिति, सेवा कर कमीशनरी, नई दिल्ली में नामनिर्दिष्ट किया गया था ।
- विभिन्न कमीशनरियों से प्राप्त अनुरोध के अनुसरण में डिब्रूगढ़, कोचीन, शिलांग, कानपुर, जयपुर और चंडीगढ़ कमीशनरी में नामनिर्देशन किए गए हैं ।

7.2 अवसंरचना संबंधी पहलें

वर्ष 2009-2010 के दौरान, संस्थान की अवसंरचना और अवसंरचनात्मक कार्यों की देखभाल, उस वर्ष में गठित अवसंरचना समिति द्वारा की जाती है । इन कार्यों को अब वर्ष 2010-2011 के लिए गठित अवसंरचना त्वरण समूह को सौंप दिया गया है ।

7.2.1 प्लॉट सं.ए.29, सेक्टर-62, नोएडा में आईसीएआई काम्पलेक्स का उदघाटन

1 जुलाई, 2009 को प्लॉट सं.ए.29, सेक्टर-62, नोएडा में आईसीएआई काम्पलेक्स के प्रशासनिक ब्लॉक का उदघाटन आईसीएआई के पदासीन अध्यक्ष द्वारा श्री अर्नेस्ट ए. अलमोंटी, अध्यक्ष, अमेरिकन इंस्टिट्यूट ऑफ

सर्टिफायड पब्लिक एकाउंटेंट्स (एआईसीपीए) और आईसीएआई के पदासीन उपाध्यक्ष की उपस्थिति में किया गया था। तत्पश्चात् 17 जनवरी, 2010 को पूर्ण काम्पलेक्स का उद्घाटन आईसीएआई के पदासीन अध्यक्ष द्वारा आईसीएआई के अध्यक्ष और श्री आर. बंधोपाध्याय, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की उपस्थिति में किया गया था।

7.2.2 हाटीसूर, कोलकाता में आईसीएआई के भवन का शिलान्यास समारोह

12 दिसम्बर, 2009 को हाटीसूर, कोलकाता में आईसीएआई के भवन का शिलान्यास आईसीएआई के पदासीन अध्यक्ष द्वारा किया गया था। प्रस्तावित कैम्पस 15 कोटा की भूमि पर स्थित होगा।

7.2.3 बांद्रा-कुर्ला काम्पलेक्स (बीकेसी), मुंबई में संनिर्माण का प्रारंभ

संकर्म प्रारंभ करने संबंधी मामले का, जो पूर्व में न्यायाधीन था, निपटारा हो गया है और संकर्म सौंप दिया गया है और अब संनिर्माण कार्य जोर-शोर से चल रहा है।

7.2.4 हैदराबाद में उत्कृष्टता केन्द्र के आवासीय ब्लॉक का उद्घाटन

हैदराबाद स्थित संस्थान के उत्कृष्टता केन्द्र के आवासीय ब्लॉक का उद्घाटन 2 जुलाई, 2009 को आईसीएआई के पदासीन अध्यक्ष द्वारा सीए शांतिलाल डागा, सुसंगत समय पर केन्द्रीय परिषद् सदस्य की उपस्थिति में किया गया था।

7.2.5 बंगलोर में संस्थान के सीए रामेश्वर ठाकुर उत्कृष्टता केन्द्र का शिलान्यास समारोह

15 अगस्त, 2009 को आईसीएआई के पदासीन अध्यक्ष ने बंगलोर में संस्थान के सीए रामेश्वर ठाकुर उत्कृष्टता केन्द्र का शिलान्यास किया था। प्रस्तावित कैम्पस आवासीय किस्म का होगा और एक 10 एकड़ के प्लॉट पर संनिर्मित किया जाएगा। वास्तुविद के चयन को अंतिम रूप दे दिया गया है और चर्चा-बाहरी का संनिर्माण चल रहा है।

7.2.6 जयपुर में उत्कृष्टता केन्द्र का शिलान्यास समारोह

11.09.08 को जयपुर में संस्थान के उत्कृष्टता केन्द्र का शिलान्यास संघ के तत्कालीन कारपोरेट कार्य मंत्री द्वारा मुख्य अतिथि, राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री की उपस्थिति में किया गया था। प्रस्तावित कैम्पस आवासीय किस्म का होगा और वह 25 एकड़ की भूमि में फैला होगा। वास्तुविद का अंतिम रूप से चयन कर लिया गया है और संविदाकर के चयन के लिए प्रक्रिया की जा रही है।

7.2.7 आबू रोड में प्रस्तावित उत्कृष्टता केन्द्र का शिलान्यास समारोह

21 जनवरी, 2010 को आईसीएआई के पदासीन अध्यक्ष द्वारा आबू रोड में संस्थान के उत्कृष्टता केन्द्र का शिलान्यास किया गया था। प्रस्तावित कैम्पस आवासीय किस्म का होगा और एक 10 एकड़ के प्लॉट पर संनिर्मित किया जाएगा।

7.2.8 राजकोट में उत्कृष्टता केन्द्र के लिए भूमि का क्रय

संस्थान के उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना के लिए स्थानीय नगर निगम से 7985 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की भूमि का क्रय किया गया था।

7.4 हीरक जयन्ती समिति

संस्थान के हीरक जयन्ती समारोहों का प्रबंध करने के लिए हीरक जयन्ती समिति का गठन एक विशेष प्रयोजन समिति के रूप में किया गया था। इस समिति के अनिवार्य कार्यों में सम्मेलनों, संगोष्ठियों और मीडिया के माध्यम से वृत्ति से सहबद्ध सभी पणधारियों को सम्मिलित करते हुए, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी मंचों में राष्ट्र निर्माण में आईसीएआई की भागीदारी को विशिष्ट रूप से दर्शित करते हुए आम जनता के बीच “उत्कृष्टता के 60 वर्षों संबंधी समारोह” संदेश का जोर-शोर से प्रचार करना सम्मिलित था।

महत्वपूर्ण पहलें

7.4.1 आगरा में 3-5 जुलाई, 2009 के दौरान “चुनौतिपूर्ण परिस्थितियाँ-लेखाकरण वृत्ति के लिए वैश्विक रणनीतियाँ” विषय पर आईसीएआई हीरक जयंती अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में उभरते और समकालीन महत्व के मुद्दों पर विचार किया गया था, अर्थात् अंतरराष्ट्रीय मानकों से संगतता, वित्तीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, प्रत्याशाओं में कमी को पूरा करना, वित्तीय बाजार और उनसे परे। सम्मेलन के कारण, आगरा में, जहाँ सदस्यों की संख्या लगभग 500 है, आईसीएआई के लगभग संपूर्ण सदस्य एकत्रित हुए, इस सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के नब्बे प्रतिशत से अधिक व्यक्ति देश के अन्य भागों से आए थे और साथ ही इसमें दक्षिण पूर्व एशिया और अधिकांश विकसित देशों में से लगभग 25 देशों से 200 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। 5 जुलाई, 2009 को, अर्थात् अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के अंतिम दिन, आगरा गो ग्रीन दौड़ का आयोजन किया था, जो चार्टर्ड एकाउंटेंटों और छात्रों को जीवन के सभी क्षेत्रों से आने वाले ऐसे व्यक्तियों, जो पर्यावरण की संरक्षा के प्रति चिंतित हैं, के साथ लाने के लिए एक बड़ी पहल थी। इस दौड़ में अन्य के साथ राहुल बोस जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भाग लिया था। इस दौड़ में 3000 से अधिक छात्रों और सदस्यों तथा उनके परिवारों ने भाग लिया था।

7.4.2 अपने साठ वर्ष के ऐतिहासिक जीवन और इस रिपोर्टाधीन वर्ष को आईसीएआई के हीरक जयंती वर्ष के रूप में मनाते हुए, आईसीएआई ने 11 जुलाई, 2009 को नई दिल्ली में अपने सदस्यों के लिए “व्यवसायिकता - आर्थिक विकास का एक उपकरण” विषय पर आईसीएआई हीरक जयंती सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन सीए के, रहमान खान, राज्य सभा के माननीय उप सभापति ने किया था।

7.4.3 आईसीएआई ने अपनी हीरक जयन्ती समिति और निगम शासन समिति के माध्यम से 14-21 दिसम्बर 2009 के दौरान भारत निगम सप्ताह का आयोजन करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय से भारीदारी की थी, इस सप्ताह का आयोजन भारतीय निगमों और संघों, जैसे कि आईसीएआई/ आईसीएसआई/ आईसीडब्ल्यूआई/ सीआईआई/ फिक्की/ एसोचेम/ पीएसयू आदि के देश के सामाजिक - आर्थिक विकास में किए गए योगदान को मान्यता देने के लिए किया गया था।

अंततः इस सप्ताह का समापन 21 दिसम्बर, 2009 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक भव्य फिनाले समारोह में किया गया था, जिसमें महामहिम श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल, भारत की माननीय राष्ट्रपति ने आईसीएआई और अन्य संस्थाओं को, उनकी उत्कृष्टता और देश के विकास में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए पुरस्कृत किया था। आईसीएआई की शाखाओं अर्थात् नागपुर, बड़ौदा, एर्नाकुलम, जयपुर, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर शाखाओं ने निगम सप्ताह के दौरान संगोष्ठियों के माध्यम से भारत निगम सप्ताह में भाग लिया था।

7.4.4 यद्यपि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को हम सीए दिवस के रूप में मनाते हैं, किन्तु इस वर्ष के महत्व को देखते हुए, जो हीरक जयंती का महत्वपूर्ण वर्ष है, यह विनिश्चय किया गया है कि आईसीएआई के योगदान को दर्शित करने वाले आयोजनों का आयोजन करके/में सहयोग करके विभिन्न समकालीन और उभरते क्षेत्रों में आईसीएआई की भूमिका को स्थापित किया जाए। जुलाई, 2009 से जून, 2010 के बीच की अवधि को विभिन्न क्रियाकलापों के लिए मास-वार समर्पित किया जाए, जो निम्नानुसार हैं:

गतिविधि	मास
गो ग्रीन	जुलाई, 2009
शिक्षा पहल और आईटी प्रशिक्षण	अगस्त, 2009
करियर परामर्श	सितम्बर, 2009
सशक्तिकरण	अक्टूबर, 2009
कृषि	नवम्बर, 2009
जन जागरूकता	दिसम्बर, 2009

7.5 प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति

प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति ने वर्ष 2009-10 के दौरान मास्टर इन बिजनेस फाइनेंस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

की कक्षाओं का आयोजन किया था ।

आईआईएम, आईआईटी, एनआईबीएम, एक्सएलआरआई से प्रमुख और सुविज्ञ संकाय सदस्यों, उद्योग और वृत्ति से वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउंटेंटों तथा विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ प्रोफेसरों आदि ने पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या के विभिन्न समकालीन विषयों पर परिचर्चा की थी ।

इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले व्यक्तियों को परियोजना रिपोर्टें तैयार किए जाने के लिए विभिन्न विषय समनुदेशित किए गए थे और उन्हें विशेषज्ञों के समक्ष परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था ।

गहन सत्रों और समूह चर्चाओं का आयोजन भी किया गया था ।

इस समिति को संभावित अभ्यर्थियों से अति उत्तम प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है, जो इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अत्यधिक उत्साहित हैं ।

8. अन्य मामले

8.1 आईसीएआई का वार्षिक समारोह

आईसीएआई का 60वां वार्षिक समारोह 11 फरवरी, 2010 को नई दिल्ली में हुआ था । प्रोफेसर सुगाता शॉ, संघ की माननीय राज्यमंत्री, शहरी विकास मंत्रालय इस समारोह की मुख्य अतिथि थी और श्री राजकुमार धूत, माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा) और श्री एस.एस.एन. मूर्ति, अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सम्मानित अतिथि थे । उक्त समारोह में वर्ष 2008-09 के लिए 'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार', आईसीएआई द्वारा संचालित परीक्षाओं में मेधावी छात्रों को पुरस्कार तथा मेडल और आईसीएआई की उत्कृष्ट प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं को शील्ड तथा प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए थे । इस समारोह में सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, सदस्यों, छात्रों, आईसीएआई के अधिकारियों तथा कर्मचारियों सहित बहुत बड़ी संख्या में आमंत्रितियों ने भाग लिया । मुख्य अतिथि ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स वृत्ति पर प्रशंसा की बौछार लगा दी ।

8.2 1 जुलाई, 2010 - चार्टर्ड एकाउंटेंट दिवस समारोह

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स दिवस समारोह 1 जुलाई, 2010 की प्रातः संस्थान के मुख्यालय में अध्यक्ष द्वारा संस्थान के ध्वजारोहण और स्वर्गीय श्री जी.पी.कापड़िया, संस्थान के पहले अध्यक्ष, के बुत को मालार्पण से प्रारंभ हुआ था । तत्पश्चात् सांय काल में इस दिवस की गरिमा के अनुरूप विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक भव्य आयोजन किया गया था । सीए के. रहमान खान, माननीय उप सभापति, राज्य सभा और श्री सलमान खुर्शीद, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने सम्मानित अतिथियों के रूप में इस समारोह की शोभा बढ़ाई थी और सदस्यों, छात्रों और अन्य गणमान्य/आमंत्रित व्यक्तियों को संबोधित किया था । श्री आर. बघोपाध्याय, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय भी इस समारोह में उपस्थित हुए थे और उन्होंने एक विशेष संबोधन प्रस्तुत किया था । यह समारोह वास्तव में विशेष था क्योंकि इसमें सीए अजित सिंह, एस. भंडारी, जो नवम्बर, 1949 में हुई पहली सीए फाइनल परीक्षा में प्रथम आए थे, को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था और उन्हें उक्त समारोह में सम्मानित किया गया था, जो अपने आप में अभूतपूर्व था । इस समारोह में बड़ी संख्या में सदस्य और छात्र उपस्थित हुए थे जैसा कि समारोह में भाग लेने वाले गणमान्य वक्ताओं ने इंगित भी किया था । इस समारोह के पश्चात् सीए टी.वी. मोहनदास पाई, बोर्ड सदस्य, इंफोसिस टेक्नालॉजिज लिमिटेड द्वारा भारत में लेखांकन वृत्ति के भविष्य पर एक विशेष संबोधन, प्रत्यक्ष कर संहिता संबंधी पुनरीक्षित परिचर्चा पत्र पर एक पैनल परिचर्चा का आयोजन भी किया गया था, जिसमें गणमान्य पैनलबद्ध व्यक्तियों ने इस विषय पर परिचर्चा को आगे बढ़ाया था ।

8.3 केन्द्रीय परिषद पुस्तकालय

केन्द्रीय परिषद पुस्तकालय इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व से जुड़ा है, पूर्णतया कंप्यूटरीकृत और क्रियाशील है । पुस्तकों, पत्रिकाओं और लेखों के डाटाबेस सहित पुस्तकालय सामग्री की खोज, विषय, लेखक, शीर्षक, प्रसंग, प्रमुख-शब्द और प्रकाशक-वार की जा सकती है अभिलेख इंटरनेट ऑन लाइन सेवा www.icaai.org पर “नो युरर इंस्टीट्यूट-सैंडल काउंसिल लाइब्रेरी” के अधीन उपलब्ध है । निर्देश सेवा विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं और विद्वानों को तथा विशेष मामले के रूप में आईसीएआई का सीपीटी पाठ्यक्रम

करने वाले छात्रों को प्रदान की जाती है। आईसीएआई के प्रत्येक निदेशालय को दिए गए केन्द्र पुस्तकालय के साथ, संस्थान के नोएडा कार्यालय और विश्वास नगर छात्र पुस्तकालय को भी केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय द्वारा पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय www.icaai.org पर “नो युअर इंस्टीट्यूट-सेंट्रल काउंसिल लाइब्रेरी” के माध्यम से विभिन्न पुस्तकालय वेब सेवाएं उपलब्ध कराती है। ये सेवाएं स्व-स्पष्टीकारक हैं। इनमें से कुछ लिंक जैसे कि ऑन लाईन जर्नलों की सूची, ई-पुस्तकें, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स जर्नलों से लेख और पुस्तकें, जर्नलों का ऑन लाईन डाटाबेस तथा पुस्तकालय में लेख पूर्वोक्त ऑन लाइन डाटाबेस में आगे और सर्च उपलब्ध कराते हैं। “सजेस्ट बुक्स/जर्नल कॉलम्स” के अधीन कोई भी व्यक्ति संस्थान को नई पुस्तकें/जर्नलों का सुझाव दे सकता है। यह उल्लेखनीय है कि “दि एकाउंटेंट्स ब्राउजर” पिछले 10 वर्षों के संग्रह के साथ महत्वपूर्ण/वृत्तिक लेखों की अनुक्रमणिका है।

पूर्वोक्त के अतिरिक्त, पुस्तकालय ने केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय परिसरों और विभिन्न विभागों में, छात्रों, सदस्यों, संकाय सदस्यों और अनुसंधान विद्वानों द्वारा अपेक्षित सामग्री के लिए सर्च को सुकर बनाने के लिए अनेक आईसीएआई डाटाबेस प्रतिष्ठापित किए हैं। केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय के डाटाबेस को सभी प्रादेशिक पुस्तकालय डाटाबेस के साथ जोड़ने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर - लिबर्टी अर्जित किया गया है। केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय, सभी समितियों और साथ ही आईसीएआई द्वारा प्रस्थापित विद्यमान पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक प्रकाशन/पुस्तकों का भी उपापन कर रहा है।

वेबसेवाएं :

www.icaai.org पर उपलब्ध वेब सेवाएं निम्नलिखित हैं :-

- ऑन लाईन जर्नलों की सूची
- ई-बुक लिंक्स
- चार्टर्ड एकाउंटेंट जर्नल (1951-2000) से लेख
- चार्टर्ड एकाउंटेंट जर्नल (2001-2007) से लेख
- केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय - केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय में पुस्तकों, जर्नलों और लेखों के डाटाबेस के लिए एक पूर्ण ऑनलाईन सर्च
- केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय में डब्ल्यूटीओ विषय पर उपलब्ध पुस्तकों की सूची
- एकाउंटेंट्स ब्राउजर, पिछले 10 वर्षों के वृत्ति संबंधी लेखों का संग्रह
- केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय - नई दिल्ली - सम्मेलन/संगोष्ठी
- पुस्तकालय में उपलब्ध सीडी
- चार्टर्ड एकाउंटेंट अनुक्रमणिका जुलाई, 2002 - जून, 2007
- सिफारिश की गई पुस्तकों की सूची
- पुस्तकालय प्रतिभूति निक्षेप नियम
- पुस्तकालय समाचार और मत
- केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय द्वारा मंगाए जाने वाले जर्नलों की सूची
- पुस्तकालय सेवा - सदस्यों से सदस्यता
- पुस्तकालय सेवा - छात्रों से सदस्यता
- पुस्तकालय में उपलब्ध फोटोग्राफ
- हाल ही में हुई परिवृद्धियां - केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय में क्रय की गई पुस्तकें
- पुस्तकालय में उपलब्ध एसएफए पुस्तकें/प्रकाशन
- सुझाई गई पुस्तकें/जर्नल

पुस्तकालय में प्रतिष्ठापित ऑन लाईन डाटाबेस निम्नानुसार है :-

पुस्तकालय	सीटीआर	आईटीआर ऑनलाईन	एक्सकस	ई-ज्यूरिक्स
साफ्टवेयर - लिबर्टी	ऑनलाईन		ऑनलाईन	
इंडलॉ डाट काम	डेलनेट	इंडियास्टेट डाट काम	टेक्समैन	

8.4 संपादकीय बोर्ड

आज के तेजी से बढ़ते हुए सार्वभौमिक युग में, विभिन्न विषयों, नए-नए उभरते क्षेत्रों, वृत्ति के पहलुओं और चुनौतियों से आईसीएआई के सदस्यों और चार्टर्ड एकाउंटेंट पत्रिका के अन्य पाठकों को अद्यतन बनाए रखने के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए संपादकीय मंडल ने 2009-2010 के दौरान अनेकों महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं।

यह आईसीएआई का ब्रांड अम्बेसेडर है और सदस्यों, छात्रों तथा बाह्य श्रोताओं के लिए संस्थान के प्रोफाइल को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। आज चार्टर्ड एकाउंटेंट विश्व की ख्याति प्राप्त पत्रिकाओं से टक्कर ले रहा है चाहे वह अंतर्वस्तु की गुणवत्ता हो, गहन ट्रापिकल कवरेज, परस्पर क्रियात्मक फीचर, अंतरराष्ट्रीय मानक ले आउट/डिजाइनिंग, पेपर क्वालिटी, बाहरी आवरण या समय से लोगों तक पहुंच हो, सबसे अधिक विश्वसनीय और पाठक मैत्रिक के रूप में इसकी मान्यता लगातार बढ़ती जा रही है। यदि हमारे पाठकों की प्रतिक्रिया से यह सब उपदर्शित होता है तो यह न केवल सदस्यों के लिए बल्कि सहयुक्त वृत्तिकों, संस्थाओं और भारत तथा विदेशों में आर्थिक जगत के हर वर्ग में अद्यतन वृत्तिक ज्ञान का उपकरण बन गया है।

इसकी व्यापक पहुंच और पाठन आधार की दृष्टि से इस पत्रिका का कुल परिचालन, आज 1,91,000 से अधिक हो गया है।

अंतर्वस्तु और ई-जर्नल :

- 1 अप्रैल, 2009 और 31 मार्च, 2010 के दौरान, विभिन्न विषयों पर कुल 163 लेखों का मुद्रण किया गया था।
- जर्नल में कुछ नए फीचर - 'नो युवर इथिक्स', 'इंटरनेशनल टैक्सेशन', 'इश्युरेंस', 'आउटसोर्सिंग', 'करियर/प्रोफेशनल अवेन्यू', 'फॉरेन ट्रेड', 'वर्ल्ड ट्रेड ऑरगेनाइजेशन' आदि प्रारंभ किए गए थे। कुछ विद्यमान फीचर, जैसे कि 'फ्राम द प्रेजिडेंट', 'लीगल अपडेट', 'नेशनल अपडेट' और 'इंटरनेशनल अपडेट' को, सदस्यों को बेहतर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए समृद्ध बनाया गया था। जर्नल के प्रसार में और अधिक वृद्धि करने के लिए यह विनिश्चय किया गया था कि जर्नल की प्रत्येक तिमाही में वृत्तिक दिलचस्पी के 20 क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाए।

आईसीएआई के स्वर्णिम 60 वर्ष के जीवन के उपलक्ष्य में एक अद्वितीय 180 पृष्ठ का जुलाई, 2009 अंक निकाला गया था और उसमें आईसीएआई के इतिहास के दुर्लभ गर्वपूर्ण क्षणों और संस्थान की उत्साहवर्द्धक प्रास्थिति और छवि को व्यापक रूप से समाविष्ट किया गया था।

जनवरी, 2010 में 'महिला सशक्तिकरण और वृत्ति' विषय पर एक और दुर्लभ अंक निकाला गया था जिसमें महिलाओं द्वारा लिखे गए अत्यधिक ज्ञानी महिलाओं और वृत्ति उन्मुख लेखों को सम्मिलित किया गया था।

मार्च, अगस्त और सितम्बर, 2009 में क्रमशः 'बैंक संपरीक्षा', 'सीमित दायित्व भागीदारी/संघीय बजट' और 'एक्सबीआरएल' तथा मार्च, 2010 में संघीय बजट 2010-11 विषयों पर विशेष अंकों का प्रकाशन किया गया था।

- ऑनलाइन जर्नल, जिसे एक अद्वितीय यूआरएल, www.ejournal.icai.org, के साथ आईसीएआई की वेबसाइट पर रखा गया था, उसे किसी उपलब्ध विनिर्दिष्ट सॉफ्टवेयर की अपेक्षा के बिना तीव्र और सुगम ब्राउज़िंग और सर्च सुविधा के साथ और अधिक सक्रिय तथा प्रयोक्ताभिन्न बनाने के लिए और समुन्नत तथा नवीकृत किया गया था। ई-जर्नल के प्रत्येक अंक को, समय से आनलाइन उपलब्ध करा दिया गया था। आईसीएआई वेबसाइट पर जर्नल पृष्ठ और संपादकीय बोर्ड पृष्ठ को व्यापक रूप से समुन्नत और अद्यतन किया गया था।

ले आउट और डिजाइन :

- अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार संपूर्ण जर्नल के ले आउट और डिजाइन तथा फोंट टाइप फेंस को और अधिक समुन्नत किया गया था ।
- आवरण पृष्ठ और अंदरूनी पृष्ठों के मास्ट हेड और आधारिक टेम्पलेट में और सुधार किया गया था ।

अन्य पहलें

- जर्नल के पठन में अतिरिक्त सुगमता प्रदान करने के लिए, सदस्यों को, यदि वे वांछा करते हैं तो उनके आवास के पते पर उनकी जर्नल की प्रति प्राप्त करने का विकल्प दिया गया था ।
- वृत्तिक संपादकों के पैनल में विस्तार किया गया था जिससे कि वृत्तिक भाषा संपादन के पश्चात् आईसीएआई प्रकाशनों के शीघ्र जारी होने को सुकर बनाया जा सके ।

8.5 उच्च स्तरीय समिति

सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड में एक बहुत बड़ी रकम को अंतर्विष्ट करने वाले निगम कपट के परिणामस्वरूप जिससे न केवल भारतीय निगम क्षेत्र अपितु भारतीय निगम में शासन प्रणाली पर भी गंभीर रूप से दुष्प्रभाव पड़े हैं, गंभीर रूप से चिंतित आईसीएआई की परिषद् ने साधारण जनता में लेखांकन और लेखा परीक्षा वृत्ति के प्रति विश्वास पुनःस्थापित करने की आवश्यकता को महसूस किया और इसलिए उसने सत्यम कांड के संदर्भ से वित्तीय रिपोर्टिंग, लेखांकन और संपरीक्षा पहलुओं की संपूर्ण रूप रेखा की जांच करने का विनिश्चय किया, जिसके अंतर्गत विभिन्न अभिकरणों द्वारा किए जा रहे अन्वेषणों में सहायता/सहयोग करना, समस्या की जड़ तक जाना, विद्यमान प्रणाली की प्रभाविकता, प्रणाली संबंधी मुद्दे, इसमें संलिप्त/सहबद्ध व्यक्तियों सहित मूल कारणों की पहचान करना और जहां कहीं अपेक्षित हो केन्द्रीय सरकार, सेबी और अन्य विनियामकों को उपयुक्त सिफारिशें करने के प्रयोजन के लिए परिवर्तनों का सुझाव देना है ।

अपने इस कार्य के दौरान इस उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों ने विभिन्न अभिकरणों/ प्राधिकारियों से बैठकें की थी । 27 फरवरी, 2009 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ हुई ऐसी एक बैठक के दौरान, मंत्रालय ने यह सुझाव दिया था कि वे संपरीक्षकों की भूमिका के संबंध में लोक छवि, उस रीति, जिसमें प्रतिनिधि फर्मों को जनता द्वारा प्रतिधारित कराया जाता है, अंतरराष्ट्रीय ब्रांड नाम के उपयोग से संबंधित मुद्दों और अनेकों अन्य संबद्ध मुद्दों पर विचार करें ।

आईसीएआई ने सीबीआई के बहुविषयक अन्वेषण दल की सहायता करने के लिए हैदराबाद में स्थानीय चार्टर्ड एकाउंटेंटों के एक समूह का गठन किया था । इस समूह को कंपनी के संपरीक्षकों द्वारा आईसीएआई द्वारा नकद तथा बैंक अतिशेषों, विक्रय, प्राप्ति, प्रोदभूत ब्याज तथा सावधि निक्षेपों से संबंधित स्रोत पर कर की कटौति और वित्तीय रिपोर्टिंग तथा उस पर संपरीक्षक की रिपोर्ट पर उसके प्रभाव के संबंध में जारी विभिन्न संपरीक्षा और आश्वासन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणों के अनुपालनों या अन्यथा के सत्यापन का कार्य सौंपा गया था । समूह ने 5 अप्रैल, 2009 को अपनी रिपोर्ट सीबीआई को प्रस्तुत की थी, जो सीबीआई द्वारा फाइल किए गए आरोपपत्र का भाग बनी थी । इस समूह की रिपोर्ट को उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट (भाग 1) में सम्मिलित किया गया है । 5 अप्रैल, 2009 को समिति के सदस्यों ने आईसीएआई के 3 सदस्यों के साथ कारागार में बंद व्यक्तियों के संबंध में जांच की थी और अभिलेख पर उनके बयान दिए थे । यह कार्य सीबीआई न्यायालय हैदराबाद द्वारा दी गई अनुमति के अनुसरण में किया गया था ।

तत्पश्चात्, उच्च स्तरीय समिति ने “सत्यम कांड” को अंतर्विष्ट करने वाली एक रिपोर्ट तैयार की थी । परिषद् ने उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, दो भागों में अपनी रिपोर्ट सरकार (कारपोरेट कार्य मंत्रालय) को प्रस्तुत की थी - रिपोर्ट (भाग 1) 17 जुलाई, 2009 को और रिपोर्ट (भाग 2) 24 मई, 2010 को । इन दोनों रिपोर्टों में केवल “सत्यम कांड” से संबंधित विषय सम्मिलित थे ।

प्रारूप रिपोर्ट (भाग 2) पर विचार करते समय परिषद् ने 13 मार्च, 2010 को हुई अपनी एक विशेष बैठक में एक समूह का गठन किया था, जो रिपोर्ट पर हुए परामर्शों के दौरान सदस्यों द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों को एकीकृत करते हुए उक्त रिपोर्ट को उपांतरित करने का कार्य करेगा। उक्त समूह इस समय निम्नलिखित के संबंध में कार्य कर रहा है :

- वह रीति, जिसमें प्रतिनिधि फर्मों को जनता द्वारा प्रतिधारित कराया जाता है, अंतरराष्ट्रीय ब्रांड नाम के उपयोग से संबंधित मुद्दों और अनेकों अन्य संबद्ध मुद्दों पर विचार करना।
- चार्टर्ड एकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 190 में, जो बहुलक व्यापार/फर्म नामों, एक समान और और एक जैसे व्यापार/फर्म नामों, नामों के अनुमोदन और अनुपालन से संबंधित है, अंतर्विष्ट उपबंधों की समीक्षा करना।

8.6.1 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 में संशोधन - अनुशासन तंत्र को और मजबूत करने तथा सीए फर्मों को दंड देने के विस्तार क्षेत्र में विस्तार करने संबंधी एक पहल

पिछले वर्ष हुई कतिपय घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, परिषद् ने ऐसे पूर्ण मामलों, जिनके अंतर्गत उनके संबंध में संपरीक्षकों की भूमिका भी है, की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर परिषद् द्वारा साधारण रूप से और विशिष्ट रूप से निम्नलिखित सिफारिशों पर विचार किया गया था और इस विषय पर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, विनियम और नियम के विद्यमान उपबंधों के आलोक में पूर्णरूपेण समीक्षा करने के लिए मई, 2010 में परिषद् सदस्यों के एक समूह का गठन किया गया था जो चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम और तदधीन बनाए गए विनियम और नियम में उचित संशोधनों का प्रस्ताव देगा :-

“जहां किसी संपरीक्षा दल के भागीदार और सदस्य लापरवाही/कपटपूर्ण क्रियाकलापों के दोषी पाए जाते हैं वहां फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही करने, जिसके अंतर्गत प्रतिबंध अधिशेषित करना भी है, के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, विनियम और नियम में संशोधन करना।”

इस समूह ने इस मामले को महत्व को ध्यान में रखते हुए इस मामले में किए गए गहन विचार-विमर्श के पश्चात् जून, 2010 में परिषद् को अपनी प्रारंभिक सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। परिषद् ने उन सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, समूह को यह अनुरोध किया था कि वे परिषद् के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न मतों/टीका-टिप्पणों/सुझावों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशों को, यदि कोई हो, पुनरीक्षित करें। तदनुसार समूह ने उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर पुनः विचार किया था और समिति को अपनी पुनरीक्षित सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। यह विषय इस समय और प्राप्त हुई सुझावों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुती हेतु अपेक्षित संशोधनों को अंतिम रूप दिए जाने के लिए समूह के विचारधीन है।

9. सदस्य

9.1 सदस्यता

31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान आईसीएआई द्वारा 10853 नए सदस्यों को दर्ज किया गया था जिससे 1 अप्रैल, 2010 को आईसीएआई की कुल सदस्यता संख्या 161516 हो गई है।

पूर्व वर्ष में 3101 की संख्या की तुलना में 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 3211 सहयोजित सदस्य अध्येता के रूप में प्रविष्ट किए गए।

1.4.2010 को सदस्यों की कुल संख्या

सदस्यों का प्रवर्ग	अध्येता (1)	सहयोजित (2)	स्तंभों का योग (1) और (2)
पूर्णकालिक व्यवसाय में	53141	20321	73462
अंशकालिक व्यवसाय में	3140	5041	8181
जो व्यवसाय में नहीं हैं	10244	69629	79873
	66525	94991	161516

9.2 दीक्षांत समारोह

संस्थान, नवम्बर, 2008 से अपने नए नामांकित सदस्यों को सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन कर रहा है। दीक्षांत समारोह का आयोजन पाँचों प्रादेशिक मुख्यालयों में प्रत्येक वर्ष में दो बार आयोजित किया जाता है जिससे कि मार्च से अगस्त और सितम्बर से फरवरी तक की अवधि का लगभग सम्मिलित किया जा सके, इन समारोहों में उक्त अवधि के दौरान सदस्यता में लिए गए सदस्यों को सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं। इस संबंध में मार्च, 2009 और अगस्त, 2009 के बीच सम्मिलित किए गए सदस्यों के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन संस्थान के प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालय में जनवरी, 2010 के दौरान किया गया था। सितम्बर, 2009 और फरवरी, 2010 के बीच सम्मिलित किए गए सदस्यों के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन शीघ्र ही किया जाएगा।

9.3 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स कल्याण निधि

दिसम्बर, 1962 में स्थापित चार्टर्ड एकाउंटेंट कल्याण निधि ऐसे जरूरतमंद लोगों, जो संस्थान के सदस्य हैं या रहे हैं और उनके आश्रितों को, उनके भरण-पोषण तथा शिक्षा और चिकित्सा आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। निधि की वित्तीय विशिष्टियाँ निम्नानुसार हैं :-

सदस्यता के ब्यौरे

1.	31 मार्च, 2009 को कुल आजीवन सदस्य	= 94,480
2.	31 मार्च, 2010 को कुल आजीवन सदस्य	= 97564
3.	नए आजीवन सदस्यों में कुल वृद्धि (31 मार्च, 2010 तक)	= 3084
4.	31.03.2010 तक दी गई कुल वित्तीय सहायता	= रु. 22,975,500

वित्तीय विशिष्टियों के ब्यौरे

	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के दौरान (रु.)	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान (रु.)
1.	दी गई कुल वित्तीय सहायता	57,00,000
2.	प्रशासनिक खर्च	14,438
3.	निधि में अधिशेष (कमी)	32,17,810
4.	निधि का अतिशेष	1,99,08,990
5.	कोरपस का अतिशेष	8,06,82,800
		22,975,500

9.4 एस. वैद्यनाथ अय्यर स्मारक निधि

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान, 500 रुपए प्रतिमास के मूल्य की 60 छात्रवृत्तियाँ, चार्टर्ड एकाउंटेंटसी पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को दी जा रही थी। निधि की आजीवन सदस्यता 31 मार्च, 2009 को 1775 के मुकाबले 31 मार्च, 2010 को बढ़कर 2129 हो गई थी। निधि के पास जमा शेष 31 मार्च, 2009 को 9,57,181/- रुपए के मुकाबले 31 मार्च, 2010 को 15,99,441/- रुपए हो गया है।

9.5 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स छात्र कल्याण निधि (सीएएसबीएफ)

आईसीआई के साथ रजिस्ट्रीकृत छात्रों को वित्तीय और अन्य अनुषंगी प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लक्ष्य और उद्देश्यों से अगस्त, 2008 में इस निधि की स्थापना की गई थी। 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान चार्टर्ड एकाउंटेंटसी पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में एक वर्ष के लिए 1000 रुपए प्रति मास मूल्य की 100 छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध कराई गई थी। 31 मार्च, 2009 को 21,44,658 रुपए की तुलना में 31 मार्च, 2010 को साधारण निधि में 78,02,562 रुपए का अतिशेष जमा था।

10. छात्र

समिति ने कई वर्ष पूर्व, 1954 में चार्टर्ड एकाउंटेंसी पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत छात्रों को सैद्धांतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 'कोचिंग बोर्ड' की स्थापना की थी। ऐसे किसी अभिकरण की स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि इसे निजी संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने की प्रणाली पर निर्भर रहने की बजाय छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने का एक अधिक प्रभावी उपाय समझा गया था।

प्रारंभ में, सैद्धांतिक प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रीकरण वैच्छिक था। तथापि, वर्ष 1956 से इसे अनिवार्य बना दिया गया था। उस समय से, किसी आर्टिकल या संपरीक्षा सहायक (पूर्व में आर्टिकल या संपरीक्षा लिपिक) के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने वाले किसी छात्र से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह स्वयं को कोचिंग बोर्ड के छात्र के रूप में रजिस्ट्रीकृत करे। चूंकि पाठ्यक्रम को करने वाले छात्र पूरे देश में बिखरे हुए थे, इसलिए कोचिंग बोर्ड द्वारा संचालित पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से एकसमानता को सुनिश्चित किया गया था। तत्पश्चात् वर्ष 1973 में कोचिंग बोर्ड के नाम में परिवर्तन करके उसे "अध्ययन बोर्ड" नाम दिया गया था। वर्तमान में, यह बोर्ड चार्टर्ड एकाउंटेंसी पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को सैद्धांतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंसी पाठ्यचर्या के प्रशासन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

वर्ष 1955 से आईसीएआई द्वारा दूरस्थ-शिक्षा पद्धति अपनाए जाने के साथ ही और वर्ष से अधिक दशकों से उसके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन को देखते हुए, आईसीएआई इस क्षेत्र में अग्रणी के रूप में उभरा है। इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करके उसने समय-समय पर अत्यधिक सस्ती कीमतों पर शिक्षा सामग्री और अन्य शैक्षिक अंतःनिवेशों को उपलब्ध कराके सर्वोत्तम क्वालिटी और संगतता को सुनिश्चित किया है। सैद्धांतिक शिक्षा और व्यावहारिक प्रशिक्षण को एकीकृत करने वाले मॉडल को अपनाकर, यह न केवल अधिकांश संख्या में छात्रों के बीच वृत्तिक ज्ञान, अपितु कौशल के विकास को भी सुकर बनाने में समर्थ रहा है, साथ ही यह उनमें वृत्तिक मूल्यों, आचार और सही व्यवहारों को भी उत्पन्न करने में सफल रहा है। अध्ययन बोर्ड छात्रों को परीक्षाओं के लिए पर्याप्त रूप से तैयारी करने में समर्थ बनाने के लिए शैक्षणिक अंतःनिवेशों का एक व्यापक पैकेज उपलब्ध कराता है। देशभर और साथ ही विदेशों में बिखरे बड़ी संख्या में छात्रों को ध्यान में रखते हुए, यह छात्रों के फायदे के लिए प्रौद्योगिकी और वर्चुअल पद्धति के माध्यम से सैद्धांतिक शिक्षा को एकीकृत करने का उद्देश्य रखता है। इसने देश भर में कंप्यूटर प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं, जिनमें सीए के छात्र सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। छात्रों को प्रस्तुतीकरण संबंधी कौशल से लैस करने और उनके सकल व्यक्तित्व के विकास हेतु, उन्हें वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से स्वरूप कराने के लिए बोर्ड अनुकूलन कार्यक्रमों और साधारण प्रबंध और संचार कौशल (जीएमसीएस) संबंधी पाठ्यक्रम का आयोजन करता है।

चार्टर्ड एकाउंटेंट सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हैं जिसका संचालन संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा समूह 'क' समूह 'ख' केन्द्रीय सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए किया जाता है।

अध्ययन बोर्ड ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ परस्पर समझ ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो सीए के छात्रों को बीबीए, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए डिग्रियां प्राप्त करने में समर्थ बनाते हैं। बोर्ड, छात्रों के विभिन्न वृत्तिक विषयों में नवीनतम ज्ञान को अद्यतन बनाने के लिए बड़ी संख्या में राष्ट्रीय सभाओं, संगोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन भी करता है।

वर्ष के दौरान बोर्ड की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

10.1 प्रत्यायन स्कीम

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान सीपीटी मौखिक कोचिंग कक्षाएं संचालित करने के लिए प्रत्यायित संस्थाओं की सूची में 6 और संस्थाओं के नामों को सम्मिलित किया गया था। इस प्रकार उनकी कुल संख्या 137 हो गई है। इसी प्रकार 5 और संस्थाओं को पीसीसी/आईपीसीसी मौखिक कोचिंग कक्षाओं के संचालन के लिए प्रत्यायित किया गया था, इस प्रकार उनकी कुल संख्या 79 हो गई है। वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम - 2) के लिए प्रत्यायित संस्थाओं की कुल संख्या वही बनी रही, जो कि 96 है और साथ ही फाइनल पाठ्यक्रम के लिए विद्यमान 10 संस्थाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

10.2 आईपीसीसी के लिए हिन्दी में अध्ययन सामग्री

दिसम्बर, 2008 में प्रारम्भ किए गए एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (आईपीसीसी) और लेखांकन तकनीशियन पाठ्यक्रम (एटीसी) के लिए जून, 2009 में हिन्दी अध्ययन सामग्री जारी की गई थी।

10.3 सुझाए गए उत्तर

छात्रों के लिए परीक्षाओं की बेहतर तैयारी को सुकर बनाने और उनके मार्गदर्शन के लिए वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा - 2) (पीई -2), वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (पीसीसी), एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (आईपीसीसी), लेखांकन तकनीशियन पाठ्यक्रम (एटीसी), फाइनल (पुराना) पाठ्यक्रम और फाइनल (नया) पाठ्यक्रम की जून, 2009 और नवंबर, 2008 में कराई गई परीक्षाओं के लिए सुझाए गए उत्तरों को मुद्रित किया गया था और उन्हें काफी समय पहले ही छात्रों को उपलब्ध करा दिया गया था। इन सुझाए गए उत्तरों को आईसीएआई की वेबसाइट पर रखा गया था जिसमें उन्हें निःशुल्क डाउनलोड करने का विकल्प उपलब्ध था।

10.4 पुनरीक्षण परीक्षा पत्र

पीई-2, पीसीसी, आईपीसीसी/एटीसी और फाइनल परीक्षाओं के लिए पुनरीक्षण परीक्षा पत्रों (आरटीपी) को समय से प्रकाशित किया गया था जिससे कि छात्रों को परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

उपरोक्त को आईसीएआई की वेबसाइट पर रखा गया था जिसमें उन्हें निःशुल्क डाउनलोड करने का विकल्प उपलब्ध था।

10.5 अध्ययन सामग्री का पुनरीक्षण

छात्रों की जानकारी को अद्यतन करने की सतत प्रक्रिया के भागरूप में विभिन्न अध्ययन सामग्रियों की अंतर्वस्तु को अद्यतन किया गया है और समुचित परिवर्तनों को भी सम्मिलित किया गया है। आईपीसीसी की अध्ययन सामग्री को भी, उसमें अग्रिम लेखांकन, लागत लेखांकन, वित्तीय प्रबंध और आईपीसीसी के अध्ययन मॉड्यूल में लेखांकन को सम्मिलित करके पुनरीक्षित किया गया था। फाइनल (नए) पाठ्यक्रम के लिए प्रैक्टिस मॉड्यूल प्रक्रियाधीन है।

10.6 चयनित मामलों का संकलन

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में चयनित मामलों का संकलन, 2009, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर विधियों से संबंधित चयनित मामले अंतर्विष्ट हैं, प्रकाशित किया गया है।

10.7 कराधान विषयों में अनुपूरक अध्ययन सामग्री

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में अनुपूरक अध्ययन सामग्री एक वार्षिक प्रकाशन है जिसमें प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों में नवीनतम परिपत्रों के साथ वार्षिक वित्त अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन अंतर्विष्ट हैं। वर्ष के दौरान, वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 द्वारा किए गए संशोधनों और 1 मई, 2008 और 30 अप्रैल, 2009 के बीच जारी महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं/परिपत्रों को अंतर्विष्ट करने वाले अनुपूरक अध्ययन पत्र - 2009 को छात्रों के फायदे के लिए निकाला गया था।

10.8 अध्ययन बोर्ड के प्रकाशनों की सूची

अध्ययन बोर्ड द्वारा निकाले गए प्रकाशनों में सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी), वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम 2), वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (पीसीसी), एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (आईपीसीसी), लेखांकन तकनीशियन पाठ्यक्रम (एटीसी) और फाइनल परीक्षाओं के संबंध में अध्ययन सामग्री सम्मिलित थी। बोर्ड ने सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के संबंध में पाठ्यक्रम सामग्री, वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम 2), वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (पीसीसी) और फाइनल परीक्षाओं के लिए सुझाए गए उत्तर और साथ ही वृत्तिक परीक्षा (पाठ्यक्रम 2) और फाइनल परीक्षाओं के संबंध में सुझाए गए उत्तरों का संकलन निकाला था। पीसीसी, आईपीसीसी, एटीसी, फाइनल पाठ्यक्रम से संबंधित अध्ययन सामग्री की सीडी और साथ ही स्वनिर्धारण (सीपीटी) को जारी किया था।

10.9 100 घंटे का सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण

वर्तमान में आईसीआई द्वारा स्थापित 143 सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र पूर्णतया कार्यरत हैं और अन्य 5 ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिए कार्यवाही की जा रही है। वर्ष के दौरान इन केन्द्रों में प्रतिष्ठापित कंप्यूटरों और प्रशिक्षित किए गए छात्रों की संख्या के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

पूर्णतया कार्यरत कंप्यूटर प्रयोगशालाएं	149
ऐसी प्रयोगशालाएं जिनकी स्थापना के लिए कार्यवाही की जा रही है	5
प्रतिष्ठापित कंप्यूटरों की संख्या	4,940
अप्रैल, 2009 से मार्च, 2010 तक प्रशिक्षित किए गए छात्रों की संख्या	66,243
आईसीआई प्रयोगशालाओं में छात्रों को प्रशिक्षित करने की वार्षिक क्षमता	1,77,840

100 घंटे की सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संबंधी अध्ययन सामग्री को पूर्णतः पुनरीक्षित और अध्ययन किया गया है।

10.10 साधारण प्रबंध और संसूचना कौशल पाठ्यक्रम

वर्ष के दौरान, प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं द्वारा देश भर में (दुबई केन्द्र सहित) 57 केन्द्रों पर साधारण प्रबंध और संचार कौशल पर 15 दिवसीय पाठ्यक्रमों के 317 बैचों का आयोजन किया गया था और इन कार्यक्रमों में, वर्ष 2008-2009 के दौरान 10,870 छात्रों की तुलना में 13168 छात्रों ने भाग लिया था।

10.11 एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (आईपीसीसी) और लेखांकन तकनीशियन पाठ्यक्रम (एटीसी) के लिए अनुकूलन कार्यक्रम

ऐसे छात्रों को, जिन्होंने एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (आईपीसीसी) और लेखाकरण तकनीशियन पाठ्यक्रम (एटीसी) के लिए रजिस्ट्रीकरण किया है, अनिवार्य रूप से 35 घंटे का 7 दिवसीय अनिवार्य अनुकूलन कार्यक्रम में भाग लेना होता है। इस अनुकूलन कार्यक्रम का उद्देश्य नए अर्हित सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) के छात्रों को संसूचना कौशल, प्रस्तुती कौशल, कार्यलय प्रक्रियाएं और साधारण वाणिज्यिक ज्ञान जैसे क्षेत्रों की सामान्य जानकारी प्रदान करना है। अनुकूलन कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम अंतर्वस्तु को समाविष्ट करने वाली व्यापक अध्ययन सामग्री तैयार की गई है और ऐसे पाठ्यक्रम के संचालन के लिए प्रदेशों और शाखाओं को वितरित की गई है। वर्ष के दौरान 86 केन्द्रों पर अनुकूलन कार्यक्रम के 957 बैचों का आयोजन किया गया था और कुल 52,606 छात्रों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया था।

10.12 छात्रों को प्रदान की गई छात्रवृत्तियां

बोर्ड ने इस वर्ष के दौरान छात्रों को गुणता, गुणता एवं आवश्यकता आधृत और आवश्यकता आधृत तथा कमजोर वर्गों के अधीन कुल 220 छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं।

10.13 छात्रों का संवादपत्र (स्टूडेंट्स न्यूजलेटर)

मासिक सीए छात्र संवादपत्र - 'दि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स्टूडेंट' को जनवरी, 2010 में एक पूर्णरूपेण जर्नल के रूप में संवर्धित किया गया था। इस जर्नल में सीए छात्रों से सुसंगत विषयों पर उपयोगी लेख, शैक्षणिक अध्ययन और अन्य सुसंगत उद्घोषणाएं अंतर्विष्ट होती हैं। यह जर्नल छात्रों और साथ ही संस्थान के सदस्यों में लोकप्रिय और उनके लिए उपयोगी बना हुआ है।

10.14 सर्वश्रेष्ठ लेख के लिए पुरस्कार

सर्वोत्तम लेख के लिए प्रथम पुरस्कार श्री अशीष प्रभाकर हरकारे को अप्रैल, 2009 के छात्र संवाद पत्र के अंक में प्रकाशित उनके लेख "फ्रॉडस - ए चैलेंज बीफोर सीए" के लिए दिया गया था तथा द्वितीय पुरस्कार श्री मिहिर झावेरी को नवम्बर, 2008 के छात्र संवाद पत्र - दि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स्टूडेंट के अंक में प्रकाशित उनके लेख "फोरेसिक एकाउंटिंग : ए ग्लिपस" के लिए दिया गया था।

10.15 छात्र आदान-प्रदान स्कीम

श्रीलंका चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएएसएल) के 12 छात्रों और नेपाल चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएएन) के 6 छात्रों ने भारत का दौरा किया और 21 तथा 22 अगस्त, 2009 को एर्नाकुलम में आयोजित एसएएफए छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रम में भाग लिया।

10.16 सीए पाठ्यक्रम को पीएच.डी कार्यक्रम के लिए मान्यता

विभिन्न विश्वविद्यालयों से निरंतर संपर्क करने के बाद अध्ययन बोर्ड शिक्षा बोर्ड पीएचडी/फैलो कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए 4 भारतीय प्रबंध संस्थानों और भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अलावा 80 विश्वविद्यालयों से सीए पाठ्यक्रम के लिए मान्यता प्राप्त करने में सफल रहा है।

10.17 एकदिवसीय संगोष्ठियां

वर्ष के दौरान, 14 शाखाओं द्वारा 48 एकदिवसीय संगोष्ठियों का आयोजन किया गया था।

10.18 वक्तृता प्रतियोगिता

5 प्रादेशिक परिषदों, जिन्होंने शाखा स्तरीय वक्तृता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था, सहित 41 शाखाओं द्वारा शाखा स्तरीय वक्तृता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इसके अलावा 5 प्रादेशिक स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। अखिल भारतीय वक्तृता प्रतियोगिता का आयोजन पूणे में 28 जनवरी, 2010 को किया गया था।

10.19 क्विज प्रतियोगिताएं

5 प्रादेशिक परिषदों, जिन्होंने शाखा स्तरीय क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था, सहित 43 शाखाओं द्वारा शाखा स्तरीय क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इसके अलावा 5 प्रादेशिक स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। अखिल भारतीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन पूणे में 28 जनवरी, 2010 को किया गया था।

10.20 अखिल भारतीय सीए छात्र सम्मेलन

22वें अखिल भारतीय सीए छात्र सम्मेलन का आयोजन 21 और 22 अगस्त, 2009 को एर्नाकुलम, केरल में किया गया था।

10.21 सीए छात्रों के राष्ट्रीय अभिसमय

वर्ष के दौरान 8 राष्ट्रीय अभिसमयों का आयोजन किया गया था अर्थात् दसवें राष्ट्रीय अभिसमय का आयोजन 10 और 11 जुलाई, 2009 को बड़ौदा में, 11वें राष्ट्रीय अभिसमय का आयोजन 15 और 16 जुलाई, 2009 को इंदौर में, 12वें राष्ट्रीय अभिसमय का आयोजन 25 और 26 जुलाई, 2009 को नागपुर में, 13वें राष्ट्रीय अभिसमय का आयोजन 3 और 4 अगस्त, 2009 को कानपुर में, 14वें राष्ट्रीय अभिसमय का आयोजन 29 और 30 अगस्त, 2009 को कोलकाता में, 15वें राष्ट्रीय अभिसमय का आयोजन 31 अगस्त और 1 सितम्बर, 2009 को गाजियाबाद में, 16वें राष्ट्रीय अभिसमय का आयोजन 26 और 27 दिसम्बर, 2009 को सिलीगुड़ी में और 17वें राष्ट्रीय अभिसमय का आयोजन 9 और 10 जनवरी, 2010 को पूणे में किया गया था।

10.22 प्रादेशिक/उप प्रादेशिक/राज्य स्तरीय सम्मेलन

राज्य स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन 1 और 2 अगस्त, 2009 को शिवकाशी सीपीई अध्ययन सर्कल (एसआईआरसी) में, 28 और 29 जुलाई, 2009 को भीलवाड़ा में, 5 सितम्बर, 2008 को गुंदूर में, 29 और 30 अगस्त, 2009 को कोयम्बटूर में किया गया था। प्रादेशिक स्तरीय सभा का आयोजन 1 और 2 फरवरी, 2010 को हैदराबाद में एसआईसीएएसए द्वारा किया गया था।

10.23 विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त संगोष्ठियां

वर्ष के दौरान, अनेक विश्वविद्यालयों के समन्वयन से शाखाओं द्वारा 3 संयुक्त संगोष्ठियां आयोजित की गईं

थी, अर्थात् 6 और 7 सितम्बर, 2009 को वाराणसी शाखा द्वारा फेकल्टी ऑफ मेनेजमेंट स्टडीज, बीएचयू के साथ, 26 नवम्बर, 2009 को बड़ौदा शाखा द्वारा एम.एस.विश्वविद्यालय बड़ौदा के साथ और 27 जुलाई, 2009 को टूटीकोरिन शाखा द्वारा एम.एस.विश्वविद्यालय, तिरुनलवेली के साथ ।

10.24 कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम

पाठ्यविवरणों के बहुत से विषयों में अनेक विद्या संबंधी शंकाओं को स्पष्ट करने के लिए छात्रों की सहायता हेतु और सीए पाठ्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रादेशिक मुख्यालयों और शाखाओं में कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है । 1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 की अवधि के दौरान देश भर में विभिन्न अवस्थानों पर 54 कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था ।

10.25 वृत्तिक कौशल विकास संबंधी त्रैमासिक (12 सप्ताह) आवासी कार्यक्रम

सीए के छात्रों और नए अर्हता प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंटों के फायदे के लिए वृत्तिक कौशल विकास (साधारण प्रबंध, व्यक्तित्व का विकास और संसूचना कौशल) संबंधी त्रैमासिक (12 सप्ताह) आवासी कार्यक्रम आरंभ किया गया है । यह कार्यक्रम सीए के छात्रों और नए अर्हता प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंटों की, कारबार संगठनों और वृत्ति में प्रभावी कार्यक्रम के लिए अपेक्षित वृत्तिक कौशल प्राप्त करने में सहायता कर रहा है । इस कार्यक्रम के आयोजित विभिन्न बैच निम्नानुसार हैं :

बैच	स्थान	तारीख	भाग लेने वाले छात्रों की संख्या
छठा	भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर	13 अप्रैल, 2009 से 14 जुलाई, 2009	60
सातवां	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान, फरीदाबाद	6 जुलाई, 2009 से 25 सितम्बर, 2009	60
आठवां	भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर	15 जनवरी, 2010 से 16 अप्रैल, 2010	60

10.26 सीपीटी, पीसीसी और फाइनल के छात्रों के लिए ज्ञान दर्शन कार्यक्रम

सामान्य प्रवीणता परीक्षा, वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले और फाइनल के छात्रों के फायदे के लिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सहयोग से ज्ञान दर्शन चैनल के माध्यम से वर्ष के दौरान विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान परिदत्त किए गए थे । देश के विभिन्न भागों के छात्रों ने आईएसआरओ द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रणाली के माध्यम से संकाय के साथ परस्पर संवाद किया था । सीपीटी और पीसीसी के लिए क्रमशः 178 और 90 ऐसे व्याख्यानों का आयोजन किया गया था ।

10.27 भरथिआर विश्वविद्यालय के साथ परस्पर समझ ज्ञापन

भरथिआर विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर और आईसीएआई के बीच एक परस्पर समझ के ज्ञापन पर 4 दिसम्बर 2008 को कोयम्बटूर में हस्ताक्षर किए गए हैं । एमओयू के अनुसार, सीए छात्र और साथ ही अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंटों को भरथिआर विश्वविद्यालय से बी.काम, एम.काम, बीबीए और एमबीए उपाधियां प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होंगे । उन्हें सीए पाठ्यचर्या के अंतर्गत आने वाले प्रश्न पत्रों के संबंध में छूट प्रदान की जाएगी और उन्हें ये उपाधियां प्राप्त करने के लिए केवल कुछ प्रश्न पत्रों की परीक्षा देनी होगी और उन्हें उत्तीर्ण करना होगा ।

10.28 छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निःशुल्क फोन नम्बर

छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नोएडा में एक निःशुल्क टेलीफोन नम्बर 1800-200-2501 प्रतिष्ठापित किया गया है । उक्त समर्पित फोन लाइन अध्ययन बोर्ड द्वारा चलाई जा रही है और शिक्षा संबंधी प्रश्नों का उत्तर संबद्ध संकाय सदस्यों द्वारा दिया जा रहा है ।

10.29 छात्र परामर्शी

दिल्ली, चैन्नई, कोलकाता, मुंबई और जयपुर स्थित संस्थान के कार्यालयों में छात्र परामर्शियों को नियुक्त

किया गया है। वे चार्टर्ड एकाउंटेंसी पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सीए छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं।

10.30 आईटी छात्रों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण

सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षकों के लिए “प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दें” एफडीपी के प्रथम चरण को नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार सफलतापूर्वक पूरा किया गया था :

स्थान	तारीख	भाग लेने वालों की संख्या
चेन्नई	22 जून, 2009 से 26 जून, 2009	23
नोएडा	29 जून, 2009 से 3 जुलाई, 2009	22
मुंबई	6 जुलाई, 2009 से 10 जुलाई, 2009	26
कानपुर	13 जुलाई, 2009 से 17 जुलाई, 2009	27
कोलकाता	24 अगस्त, 2009 से 28 अगस्त, 2009	18

सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षकों के लिए टैली और सीएएटी उपकरणों संबंधी एफडीपी के दूसरे चरण को नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार सफलतापूर्वक पूरा किया गया था :

स्थान	तारीख	भाग लेने वालों की संख्या
गोवा	5 अक्टूबर, 2009 से 9 अक्टूबर, 2009	24
हैदराबाद	11 जनवरी, 2010 से 15 जनवरी, 2010	35
दिल्ली	18 जनवरी, 2010 से 22 जनवरी, 2010	49
कानपुर	25 जनवरी, 2010 से 29 जनवरी, 2010	40
कोलकाता	1 फरवरी, 2010 से 5 फरवरी, 2010	24

10.31 अध्यापक दिवस समारोह

4 सितम्बर, 2009 को अध्ययन बोर्ड, नोएडा में अध्यापक दिवस समारोह का विशाल उत्सव किया गया था जिसमें संकाय सदस्यों को आईसीएआई के अध्यक्ष द्वारा मूर्तों प्रदान किया गया था।

10.32 छात्रों के आंकड़े

2005-2006 से 2009-2010 तक के पिछले पांच वर्षों के दौरान रजिस्ट्रीकृत छात्रों के संबंध में ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

वर्ष	फाइनल	सीपीटी	पीसीसी	आईपीसीसी	एटीसी (अनन्य रूप से रजिस्ट्रीकृत)
2005-2006	13,010	-	-	-	-
2006-2007	11,838	1,29,110*	24,041*	-	-
2007-2008	19,558	1,42,612	61,186	-	-
2008-2009	11,562	1,39,140	33,764	18,318**	8 **
2009-2010	24,109	1,63,397	1,204	81,833	4
योग	80,077	5,74,259	1,20,195	1,00,151	12

* 13 सितम्बर, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक ** 10 दिसम्बर, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक

11. प्रादेशिक परिषदें और उनकी शाखाएं

संस्थान की पांच प्रादेशिक परिषदें हैं अर्थात् पश्चिम भारत प्रादेशिक परिषद्, दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद्,

पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद्, मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् और उत्तर भारत प्रादेशिक परिषद् जिनके मुख्यालय क्रमशः मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता, कानपुर और नई दिल्ली में हैं।

प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं की कुल संख्या 126 हैं। इस समय, संस्थान के विदेश स्थित 21 चैप्टर विद्यमान हैं और देश भर में 27 संदर्भ पुस्तकालय हैं।

11.1 शाखाओं के लिए भवन

रिपोर्टीधीन अवधि के दौरान प्रादेशिक परिषदों की अनेक शाखाएं अपने निजी परिसर बनाने में रूचि दिखाती रही हैं। कुल मिलाकर 63 शाखाओं के अपने भवन हैं।

11.2 चल शील्ड

संस्थान सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक परिषद् को हर वर्ष चल शील्ड प्रदान करता है। पुरस्कार सम्पूर्ण कार्यों को देखकर दिया जाता है। इसी प्रकार हर वर्ष सर्वश्रेष्ठ शाखा को एक पृथक चल शील्ड प्रदान की जाती है। पुरस्कार स्थापित सिद्धांतों के आधार पर दिया जाता है। अखिल भारतीय आधार पर सर्वश्रेष्ठ सीए छात्र संघ को और प्रादेशिक आधार पर छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा को चल शील्ड प्रदान करने की योजना वर्ष 1999 से चलाई गई है। वर्ष 2009 के लिए ये शील्डें 11 फरवरी, 2010 को आयोजित वार्षिक समारोह में निम्नलिखित विजेताओं को दी गई थी :-

- सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक परिषद् पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद्।
- प्रादेशिक परिषद् की सर्वश्रेष्ठ शाखा
 - लघु आकार शाखा प्रवर्ग सीआईआरसी की मिलाई शाखा
 - मध्यम आकार शाखा प्रवर्ग एसआईआरसी की सलेम शाखा
 - बड़ी शाखा प्रवर्ग एनआईआरसी की लुधियाना शाखा और सीआईआरसी की इंदौर शाखा (संयुक्त रूप से)
- छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा :
 - पश्चिमी क्षेत्र डब्ल्यूआईसीएसए की बड़ौदा
 - दक्षिण क्षेत्र एसआईसीएसए की एर्नाकुलम
 - पूर्वी क्षेत्र ईआईसीएसए की गुवाहाटी शाखा
 - मध्य क्षेत्र सीआईसीएसए की इंदौर शाखा

- उत्तम कार्य प्रदर्शन को देखते हुए निम्नलिखित शाखाओं को अलग से प्रशंसनीय कार्य के लिए शील्ड प्रदान की गई :-

लघु आकार शाखा प्रवर्ग :

- एसआईआरसी की हुबली शाखा
- ईआईआरसी की सिलीगुड़ी शाखा

मध्यम आकार शाखा प्रवर्ग :

- ईआईआरसी की गुवाहाटी शाखा
- डब्ल्यूआईआरसी की औरंगाबाद शाखा

बड़ी शाखा प्रवर्ग :

- डब्ल्यूआईआरसी की बड़ौदा शाखा
- डब्ल्यूआईआरसी की नागपुर शाखा
- एसआईआरसी की एर्नाकुलम शाखा

11.3 विकेन्द्रीकृत कार्यालय

तुरंत तथा व्यक्तिपरक सेवा के महत्व को मानते हुए, जो विकेन्द्रीकरण के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं, संस्थान की परिषद् मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता, कानपुर और नई दिल्ली में पहले से कार्यरत विकेन्द्रीकृत कार्यालयों के अलावा, दक्षिणी क्षेत्र में बंगलौर और हैदराबाद में, पश्चिमी क्षेत्र में अहमदाबाद और पुणे में और मध्य क्षेत्र में जयपुर में पांच और विकेन्द्रीकृत कार्यालय पहले ही स्थापित कर चुकी है। प्रादेशिक स्तर पर कार्य/गतिविधियों की मात्रा में वृद्धि पर विचार करते हुए, नागपुर, सूरत, वदोदरा और ठाणे (पश्चिमी क्षेत्र), एर्नाकुलम और कोयम्बटूर (दक्षिणी क्षेत्र), इन्दौर (मध्य क्षेत्र) और चंडीगढ़ (उत्तरी क्षेत्र) में आठ और विकेन्द्रीकृत कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

12. वित्त और लेखा

31 मार्च, 2010 को यथाविद्यमान तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय-व्यय का लेखा जो परिषद् द्वारा अनुमोदित है, संलग्न है।

13. अनुशंसा

13.1 परिषद् व्यवसाय के उन सदस्यों की आभारी है, जो चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन गठित संस्थान के बोर्डों/समितियों में सहयोजित सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए थे और उस रूप में कार्य किया था और उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती है, जो व्यवसाय के सदस्य नहीं हैं लेकिन जिन्होंने परिषद् के शैक्षिक, तकनीकी, अन्य विकास क्रियाकलापों में और उसकी परीक्षाओं के संचालन में वर्ष 2009-2010 के दौरान परिषद् की सहायता की।

13.2 परिषद् की हार्दिक कामना है कि वर्ष 2009-2010 में केन्द्रीय सरकार और परिषद् में उनके मनोनीत सदस्यों द्वारा दी गई निरंतर सहायता और समर्थन की प्रशंसा अभिलेख पर अंकित की जाए।

13.3 परिषद् सीए के. रहमान खान, राज्यसभा के माननीय उपसभापति, श्री सलमान खुशीद, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, प्रो० सुगाता रे, माननीय राज्य मंत्री, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, श्री श्रीप्रकाश जयसवाल, माननीय संघ राज्यमंत्री, कोयला, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, श्री राजकुमार धूत, माननीय संसद् सदस्य (राज्य सभा), डा० ए. के. वालिया, वित्तमंत्री, दिल्ली सरकार, श्री महाबल मिश्रा, माननीय संसद् सदस्य, श्री अशोक चावला, वित्त सचिव, श्री एस.एस.एन मूर्ति, अध्यक्ष, सीबीडीटी, श्री आर. बंधोपाध्याय, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, श्री अनुसंग गोयल, सदस्य, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का, जिन्होंने आईसीएआई द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर उन्हें गौरवान्वित किया, दिल से आभार व्यक्त करती है। परिषद् राज्य स्तर पर विभिन्न कृत्यकारियों की भी, जिन्होंने जिन्होंने आईसीएआई के विभिन्न अंगों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर उन्हें गौरवान्वित किया, सराहना करती है।

13.4 परिषद् आईसीएआई द्वारा की गई अनेक गतिविधियों में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिखाई गई गहन रुचि और की गई पहल के अनुसरण में उनके द्वारा पहले ही उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा करती है।

13.5 संस्थान के सभी अधिकारी और कर्मचारी वर्ष 2009-2010 के दौरान अपने निष्ठापूर्ण और अनथक प्रयासों के लिए परिषद् द्वारा प्रशंसनीय है।

सदस्य
(1 अप्रैल, 2000 से)
सारणी - 1

वर्ष (को यथाविद्यमान)		पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र	योग
1 अप्रैल, 2000	सहयुक्त अध्येता योग	17771 12200 29971	13023 10369 23392	5807 4941 10748	5057 5617 10674	8411 9784 18195	50069 42911 92980
1 अप्रैल, 2001	सहयुक्त अध्येता योग	19243 12868 32111	12915 10749 23664	5732 5077 10809	5215 5995 11210	8498 10100 18598	51603 44789 96392
1 अप्रैल, 2002	सहयुक्त अध्येता योग	20771 13540 34311	13456 11248 24704	5872 5296 11168	5493 6400 11893	9074 10580 19654	54666 47064 101730
1 अप्रैल, 2003	सहयुक्त अध्येता योग	23194 14279 37473	14446 11742 26188	6374 5572 11946	6318 6909 13227	10287 11135 21422	60619 49637 110256
1 अप्रैल, 2004	सहयुक्त अध्येता योग	24515 15091 39606	14943 12377 27320	6515 5836 12351	6714 7557 14271	10697 11846 22543	63384 52707 116091
1 अप्रैल, 2005	सहयुक्त अध्येता योग	26351 15834 42185	15724 12969 28693	6785 6146 12931	7552 8207 15759	11640 12338 23978	68052 55494 123546
1 अप्रैल, 2006	सहयुक्त अध्येता योग	28528 16385 44913	16,700 13358 30058	7172 6313 13485	8480 8539 17019	12898 12573 25471	73778 57168 130946
1 अप्रैल, 2007	सहयुक्त अध्येता योग	31159 16896 48055	18237 13646 31883	7829 6488 14317	9642 8882 18524	14182 12880 27062	81049 58792 139841
1 अप्रैल, 2008	सहयुक्त अध्येता योग	32364 17646 50010	19203 14034 33237	7939 6738 14677	10045 9472 19517	14642 13398 28040	84193 61288 145481
1 अप्रैल, 2009	सहयुक्त अध्येता योग	34294 18442 52736	20666 14516 35182	8193 7002 15195	10578 10007 20585	15951 13951 29902	89682 63918 153600
1 अप्रैल, 2010	सहयुक्त अध्येता योग	36390 19181 55571	21733 15076 36809	8512 7192 15704	11252 10615 21867	17104 14461 31565	94991 66525 161516

सदस्य
(1 अप्रैल, 1950 से)
सारणी 2

	सहयुक्त	अध्येता	योग
1 अप्रैल, 1950 को	1,120	569	1,689
1 अप्रैल, 1951 को	1,285	672	1,957
1 अप्रैल, 1961 को	4,059	1,590	5,649
1 अप्रैल, 1971 को	7,901	3,326	11,227
1 अप्रैल, 1981 को	16,796	8,642	25,438
1 अप्रैल, 1991 को	36,862	22,136	58,998
1 अप्रैल, 2001 को	51,603	44,789	96,392
1 अप्रैल, 2002 को	54,666	47,064	1,01,730
1 अप्रैल, 2003 को	60,619	49,637	1,10,256
1 अप्रैल, 2004 को	63,384	52,707	1,16,091
1 अप्रैल, 2005 को	68,052	55,494	1,23,546
1 अप्रैल, 2006 को	73,778	57,168	1,30,946
1 अप्रैल, 2007 को	81,049	58,792	1,39,841
1 अप्रैल, 2008 को	84,193	61,288	1,45,481
1 अप्रैल, 2009 को	89,682	63,918	1,53,600
1 अप्रैल, 2010 को	94,991	66,525	1,61,516

छात्र रजिस्ट्रीकरण प्रगति चार्ट
(31 मार्च, 1997 से)

पाठ्यक्रम वर्ष के दौरान	फाउंडेशन/ पीई (पाठ्यक्रम-I)	इंटरमीडिएट/ पीई (पाठ्यक्रम-II)	फाइनल	सीपीटी	पीसीसी	आईपीसीसी	एटीसी	योग
1996-97	28,209	21,354	9,275	-	-	-	-	58,838
1997-98	37,052	24,652	9,394	-	-	-	-	71,098
1998-99	43,809	28,253	12,227	-	-	-	-	84,289
1999-00	44,180	27,508	10,787	-	-	-	-	82,475
2000-01	35,999	23,405	9,026	-	-	-	-	68,430
2001-02	34,215*	29,403**	11,524	-	-	-	-	75,142
2002-03	35,524	33,283	11,102	-	-	-	-	79,909
2003-04	38,188	34,232	11,390	-	-	-	-	83,810
2004-05	39,000	34,190	11,061	-	-	-	-	84,251
2005-06	38,901	39,467	13,010	-	-	-	-	91,378
2006-07	45,617	32,339	11,838	1,29,110***	24,041***	-	-	2,42,945
2007-08	-	-	19,558	1,42,612	61,186	-	-	2,23,356
2008-09	-	-	11,562	1,39,140	33,764	18,318****	8****	2,02,792
2009-10			24,109	1,63,397	1,204	81,833	4	2,70,547

* इसमें 1.10.2001 से 31.3.2002 तक पीई (पाठ्यक्रम-I) में रजिस्ट्रीकृत छात्र सम्मिलित हैं : 5006

** इसमें 1.10.2001 से 31.3.2002 तक पीई (पाठ्यक्रम-II) में रजिस्ट्रीकृत छात्र सम्मिलित हैं : 11848

*** 13 सितम्बर, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक

**** 10 दिसम्बर, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक

परिषद् (2009-10) की संरचना

	परिषद् (2009-10) के सदस्य	
अध्यक्ष	निर्वाचित सदस्य	
सीए उत्तम प्रकाश अग्रवाल	सीए अभिजीत बंधोपाध्याय	कोलकाता
	सीए अक्षय कुमार गुप्ता	कानपुर
	सीए अमरजीत चोपड़ा	नई दिल्ली
	सीए अनुज गोयल	गाजियाबाद
उपाध्यक्ष	सीए अतुल चुन्नीलाल भेंस	मुम्बई
सीए अमरजीत चोपड़ा	सीए भावना दोशी	मुम्बई
	सीए चरणजोत सिंह नन्दा	नई दिल्ली
	सीए जी रामास्वामी	कोयम्बटूर
	सीए हरिन्दरजीत सिंह	नई दिल्ली
अवधि	सीए जे. वेंकटेश्वरलू	हैदराबाद
5 फरवरी, 2009 - 11 फरवरी, 2010	सीए जयंत गोखले	मुम्बई
	सीए जयदीप नरेन्द्र शाह	नागपुर
	सीए के. रघु	बंगलोर
	सीए के.पी. खण्डेलवाल	कोलकाता
सचिव	सीए महेश पी. शारदा	जामनगर
श्री टी. कार्तिकेयन	सीए मनोज फड़नीस	इन्दौर
	सीए पंकज इन्द्रचंद जैन	मुम्बई
	सीए प्रीति प्रदीप महात्मे	गोवा
	सीए राजकुमार एस. अडुकिया	मुम्बई
	सीए एस. गोपालाकृष्णन्	हैदराबाद
	सीए एस. संथानाकृष्णन्	चेन्नई
	सीए संजीव महेश्वरी	मुम्बई
	सीए शांति लाल डागा	हैदराबाद
लेखा परीक्षक	सीए सुबोध कुमार अग्रवाल	कोलकाता
सीए प्रमोद जैन	सीए सुनील एच. तलाटी	अहमदाबाद
सीए पुष्पेन्द्र सरना	सीए उत्तम प्रकाश अग्रवाल	मुम्बई
	सीए वी. मुरली	चेन्नई
	सीए वी. सी. जेम्स	कोच्ची
	सीए वेद जैन	नई दिल्ली
	सीए विजय गर्ग	जयपुर
	सीए विजय कुमार गुप्ता	फरीदाबाद
	सीए विनोद जैन	नई दिल्ली
	नामनिर्दिष्ट सदस्य	
	श्री अनिल कुमार अग्रवाल	नई दिल्ली
	श्री जीतेश खोसला	नई दिल्ली
	श्री के.पी. शशिचरन	नई दिल्ली
	श्री के.आर. महेश्वरी	जयपुर
संयुक्त आंतरिक लेखा परीक्षक	सीए कृष्णा कान्त (अप्रैल, 2009 से)	नई दिल्ली
पी.आर.मेहरा एंड कंपनी	सीए मनोज के. सरकार	कोलकाता
भसीन राघवन एंड कंपनी	श्री ओ.पी.वैश	नई दिल्ली
	डा० प्रीतम सिंह (अप्रैल, 2009 तक)	गुडगांव
	श्री आर. शेखर	नई दिल्ली
	श्रीमती रेणुका कुमार (मई, 2009 से)	नई दिल्ली

परिषद् (2010-11) की संरचना

अध्यक्ष	परिषद् (2010-11) के सदस्य निर्वाचित सदस्य	
सीए अमरजीत चोपड़ा	सीए अभिजीत बंधोपाध्याय	कोलकाता
	सीए अमरजीत चोपड़ा	नई दिल्ली
	सीए अनुज गोयल	गाजियाबाद
उपाध्यक्ष	सीए अतुल चुन्नीलाल भेड़ा	मुम्बई
सीए जी. रामास्वामी	सीए भावना दोशी	मुम्बई
	सीए चरणजोत सिंह नन्दा	नई दिल्ली
	सीए देवराज रेड्डी एम.	हैदराबाद
	सीए धीनल अश्विनभाई शाह	नागपुर
	सीए जी. रामास्वामी	कोयम्बटूर
अवधि	सीए जे. वेंकटेश्वरलू	हैदराबाद
12 फरवरी, 2010 से आगे	सीए जयंत गोखले	मुम्बई
	सीए जयदीप नरेन्द्र शाह	नागपुर
	सीए के रघु	बंगलोर
	सीए मधुकर नारायण हीरगंगे	बंगलोर
सचिव	सीए महेश पी. शारदा	जामनगर
श्री टी. कार्तिकेयन	सीए मनोज फड़नीस	इन्दौर
	सीए नवीन एन. डी. गुप्ता	नई दिल्ली
	सीए पंकज इन्द्रवंद जैन	मुम्बई
	सीए पंकज त्यागी	नई दिल्ली
	सीए राजेन्द्र कुमार पी.	चेन्नई
	सीए राजकुमार एस. अदुकिया	मुम्बई
	सीए रविन्द्र होलानी	ग्वालियर
	सीए एस. संधानाकृष्णन्	चेन्नई
	सीए संजय कुमार अग्रवाल	नई दिल्ली
	सीए संजीव महेश्वरी	मुम्बई
	सीए शिवाजी भीकाजी जवारे	पूणे
लेखा परीक्षक	सीए सुबोध कुमार अग्रवाल	कोलकाता
सीए पुष्पेन्द्र सरना	सीए सुमंत्र गुहा	कोलकाता
सीए अशोक कुमार जैन	सीए वी. मुरली	चेन्नई
	सीए विजय कुमार गर्ग	जयपुर
	सीए विनोद जैन	नई दिल्ली
	नामनिर्दिष्ट सदस्य	
	श्री अनिल के. अग्रवाल	नई दिल्ली
	श्री आशुतोष दीक्षित	नई दिल्ली
	श्री दीपक नारायण	नई दिल्ली
	श्री के.पी. शशिधरन	नई दिल्ली
	श्री पृथ्वी हल्दिया	नई दिल्ली
संयुक्त आंतरिक लेखा परीक्षक	श्रीमती रेणुका कुमार (31 अगस्त, 2010 तक)	नई दिल्ली
पी.आर.मेहरा एंड कंपनी	श्री सिद्धार्थ कुमार बिड़ला	नई दिल्ली
भसीन राघवन एंड कंपनी	डा० टी.वी. सोमनाथन (1 सितम्बर, 2010 से)	नई दिल्ली
	श्रीमती ऊषा नारायणन	मुम्बई

संपरीक्षक की परिषद् को रिपोर्ट

1. हमने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के 31 मार्च, 2010 को यथा विद्यमान संलग्न तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए संलग्न आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण की संपरीक्षा की है। इसमें अन्य संपरीक्षकों द्वारा संपरीक्षित संस्थान के विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, कंप्यूटर केन्द्रों, क्षेत्रीय परिषदों और उनकी शाखाओं के लेखाओं को सम्मिलित किया गया है एवं हमारी रिपोर्ट तैयार करते समय उनकी रिपोर्टों पर सम्यक्तः विचार किया गया है। ये वित्तीय विवरण, संस्थान के प्रबंध मंडल का दायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व अपनी संपरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. हमने भारत में साधारणतया स्वीकृत संपरीक्षा मानकों के अनुसार संपरीक्षा की है। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षित है कि हम इस बाबत युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए संपरीक्षा की योजना बनाएं और उसके अनुसार संपरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण किसी तात्त्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं। किसी संपरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में रकमों और प्रकटनों का समर्थन करने वाले साक्ष्य की परीक्षण आधारित जांच करना सम्मिलित है। संपरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का निर्धारण और प्रबंध मंडल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलन तथा संपूर्ण वित्तीय विवरण प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हमारा यह विश्वास है कि हमारी संपरीक्षा हमारी राय के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

3. हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि :-

(क) हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में हमारी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे ;

(ख) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और नकद प्रवाह विवरण, लेखा बहियों के अनुसार हैं ;

(ग) हमारी राय में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की अपेक्षाओं के अनुपालन में समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं ;

(घ) हमारी राय में तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण सुसंगत लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं ;

(ङ) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखाकरण सिद्धांतों के साथ पठित संलग्न अनुसूचियां और साथ ही लेखाओं का भाग बनने वाले टिप्पण भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुपालन में, निम्नलिखित के संबंध में एक सत्य और उचित मत प्रदान करते हैं :

(i) तुलन पत्र की दशा में, 31 मार्च, 2010 को संस्थान के मामलों की स्थिति ;

(ii) आय और व्यय लेखा की दशा में, उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अधिशेष ; और

(iii) नकद प्रवाह विवरण की दशा में उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण।

ह/-

सीए पुष्पेन्द्र सुराना

चार्टर्ड एकाउंटेंट

सदस्यता सं.-504087

ह/-

सीए प्रमोद जैन

चार्टर्ड एकाउंटेंट

सदस्यता सं.-90358

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 25.9.10

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
31 मार्च, 2010 को यथाविद्यमान तुलन पत्र

	अनुसूची	31.3.2010 को रकम	(लाख रु. में) 31.3.2009 को रकम
निधियों के स्रोत :			
आस्थितियाँ और अधिशेष	I	35602.89	24896.60
उद्दिष्ट निधियाँ	II	11369.16	9152.98
योग		46972.05	34049.58
निधियों का उपयोग :			
नियत आस्तियाँ :			
सकल ब्लॉक	III	21162.34	15747.23
घटाएँ : अवक्षयण और परिशोधन		6550.88	5275.28
शुद्ध ब्लॉक		14611.46	10471.95
चालू पूंजी संकर्म (पूँजी अग्रिमों सहित)		8698.73	4324.02
निवेश :			
उद्दिष्ट निधि निवेश	IV	11369.16	9152.98
कर्मचारी फायदाप्रद निवेश		2283.48	2206.13
अन्य निवेश		16979.60	10290.74
चालू आस्तियाँ, ऋण और अग्रिम :			
वस्तु-सूचियाँ	V	701.72	679.84
नकद और बैंक अधिशेष	VI	6149.25	4072.47
ऋण और अग्रिम	VII	2147.08	2507.16
निवेशों पर प्रोदभूत ब्याज		2463.36	2719.41
सकल योग		11461.41	9978.88
घटाएँ : चालू दायित्व और प्रावधान :			
चालू दायित्व	VIII	16252.24	10102.19
कर्मचारियों के फायदों के लिए प्रावधान		2179.55	2272.93
सकल योग		18431.79	12375.12
शुद्ध चालू आस्तियाँ (दायित्व)		(6970.38)	(2396.24)
योग		46972.05	34049.58
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण			
लेखाओं का भाग बनने वाले टिप्पण	XII		
उत्तर निर्दिष्ट अनुसूचियाँ तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं ।	XIII		

ह/-
सीए एच. घोष
वरि. उप निदेशक

ह/-
श्री टी. कार्तिकेयन
सचिव

ह/-
सीए जी. रामास्वामी
उपाध्यक्ष

ह/-
सीए अमरजीत चौपड़ा
अध्यक्ष

हमारी संलग्न सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

ह/-
सीए प्रमोद जैन
चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता सं.-90358

ह/-
सीए पुष्पेन्द्र सुराना
चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता सं.-504087

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 25.9.10

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
आय और व्यय लेखा
31.3.2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

	अनुसूची	रकम 31.3.2010 को समाप्त वर्ष	रकम (लाख रु. में) 31.3.2009 को समाप्त वर्ष
आय :			
फीस	IX	31643.56	20770.19
संगोष्ठियां		3821.95	2454.68
अन्य आय	X	2526.24	2324.97
पूर्व अवधि की आय		53.67	25.16
	योग	38045.42	25575.00
व्यय :			
वेतन और भत्ते		6258.58	3490.27
मुद्रण और लेखन सामग्री		4332.60	3033.06
संगोष्ठी संबंधी व्यय		3382.87	2528.17
अन्य प्रचालन व्यय	XI	10443.21	7350.67
अवक्षयण और परिशोधन		1322.61	1057.91
पूर्व अवधि के व्यय		71.80	59.87
	योग	25811.67	17519.95
शुद्ध आधिक्य		12233.75	8055.05
निधियों/आरक्षितियों को विनियोग :			
शिक्षा निधि [पॉलिसी सं.3 (ग)]	XII	4077.76	2711.67
कर्मचारी कल्याण निधि [पॉलिसी सं.3(घ)]	XII	22.86	21.69
साधारण आरक्षिती		8133.13	5321.69
	योग	12233.75	8055.05
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण	XII		
लेखाओं का भाग बनने वाले टिप्पण	XIII		
ऊपर निर्दिष्ट अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं।			

ह/-
सीए एच. घोष
वरि, उप निदेशक

ह/-
श्री टी. कार्तिकेयन
सचिव

ह/-
सीए जी. रामास्वामी
उपाध्यक्ष

ह/-
सीए अमरजीत चोपड़ा
अध्यक्ष

हमारी संलग्न सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

ह/-
सीए प्रमोद जैन
चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता सं.-90358

ह/-
सीए पुष्पेन्द्र सुराना
चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता सं.-504087

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 25.9.10

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
नकद प्रवाह विवरण
31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

	(रकम लाख रुपए में)	
	2009-2010	2008-2009
क. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
शुद्ध अधिशेष	12233.75	8055.04
निम्न के लिए समायोजन :		
अवकाश और परिशोधन	1322.61	1057.91
निवेशों पर ब्याज	(1203.80)	(1216.82)
	118.81	(158.91)
कार्य पूंजी के परिवर्तन के पूर्व प्रचालन अधिशेष	12352.56	7896.13
वस्तु सूची में (वृद्धि)/कमी	(21.68)	38.68
ऋण और अधिमो में (वृद्धि)/कमी	360.08	(859.58)
चालू दायित्वों में वृद्धि/(कमी)	6150.06	2680.17
कर्मचारी फायदों संबंधी उपबंध में वृद्धि/(कमी)	(93.38)	557.82
	6694.88	2417.09
प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद	18747.44	10313.22
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
चालू पूंजी संकर्म सहित नियत आस्तियों का अर्जन (शुद्ध)	(9836.84)	(5887.70)
निवेशों का अर्जन (शुद्ध)	(8982.40)	(3727.02)
निवेशों पर ब्याज	1513.53	1159.21
पूंजी प्राप्ति	241.77	224.16
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद	(17063.94)	(8031.39)
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह		
नए सदस्यों के लिए प्रवेश शुल्क	117.14	103.49
सदस्यों से अभिदाय	276.14	299.98
	393.28	403.47
नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/कमी	2076.78	2685.34
वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य	4072.47	1387.13
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य - अनुसूची सं. VI का संदर्भ ले	6149.25	4072.47

टिप्पण :

- उपरोक्त नकद प्रवाह विवरण को आईसीएआई द्वारा जारी एएस-3 में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए तैयार किया गया है।
- संलग्न अनुसूची I से XIII नकद प्रवाह विवरण का अभिन्न भाग है।

ह/-
सीए एच. घोष
वरि. उप निदेशक

ह/-
टी. कार्तिकेयन
सचिव

ह/-
सीए जी. रामास्वामी
उपाध्यक्ष

ह/-
सीए अमरजीत चौपड़ा
अध्यक्ष

हमारी संलग्न सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

ह/-
सीए प्रमोद जैन
चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता सं.-90358

ह/-
सीए पुष्पेन्द्र सुराना
चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता सं.-504087

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 25.9.2010

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

**अनुसूची I
आरक्षितियाँ और अधिशेष**

	शिक्षा		अवसंरचना		साधारण		अन्य *		योग	
	निम्नलिखित तारीख को रकम		निम्नलिखित तारीख को रकम		निम्नलिखित तारीख को रकम		निम्नलिखित तारीख को रकम		निम्नलिखित तारीख को रकम	
	31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009
प्रारंभिक अधिशेष	8,064.49	6,353.52	2,161.11	1,663.84	14,416.91	9,435.47	254.09	197.79	24,896.60	17,650.62
अय और व्यय लेखा से विनियोग	-	-	-	-	8,133.13	5,321.68	-	-	8,133.13	5,321.68
साधारण आरक्षितियों, अवसंरचना आरक्षितियों और अन्य आरक्षितियों से/(को) अंतरण	-	-	50.00	83.91	(108.03)	(147.37)	58.03	63.46	-	-
उद्धिष्ट निधियों से/(को) अंतरण	2,707.56	1,710.97	-	9.89	(507.86)	(192.87)	27.02	(13.92)	2,226.72	1,514.07
दाखिला फीस और आबंटित प्रवेश फीस	-	-	117.14	103.49	-	-	-	-	117.14	103.49
भवनों के लिए प्राप्त संदान	-	-	276.14	299.98	-	-	-	-	276.14	299.98
शुद्ध (कमी)/परिवृद्धियाँ	-	-	41.36	-	(144.40)	-	56.20	6.76	(46.84)	6.76
योग	10,772.05	8,064.49	2,645.75	2,161.11	21,789.75	14,416.91	395.34	254.09	35,502.89	24,896.60

*टिप्पण : अन्य आरक्षितियाँ ऐसी आरक्षितियाँ हैं जैसे कि पुस्तकालय आरक्षितियाँ और शिक्षण कक्ष आरक्षितियाँ, जैसी कि वे प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं की बहियों में विद्यमान हैं।

लाख रुपए में

	प्रारंभिक अतिशेष	आय और व्यय लेखा से		आकृतियों और अतिशेष से/(से)		वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान/परिशुद्धि		वर्ष के दौरान आय		वर्ष के दौरान संदाय		योग	
		निम्नलिखित तारीख को		अंतरण		निम्नलिखित तारीख को		रकम		निम्नलिखित तारीख को			
		2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09		
	01.04.2009	01.04.2008										31.03.2009	
अनुसंधान निधियाँ	1,140.44	981.31	-	-	-	-	-	61.23	93.29	97.90	-	1,233.73	1,140.44
लेखांकन अनुसंधान भवन निधि	394.77	358.26	-	-	-	-	-	-	32.88	36.51	-	427.85	394.77
शिक्षा निधि	6,145.05	4,658.62	4,077.78	2,711.67	(2,707.56)	(1,710.97)	-	-	511.88	475.73	-	8,027.13	6,145.05
सेटल और पुरस्कार निधि	151.10	137.07	-	-	-	-	0.10	8.13	9.05	9.64	(4.01)	156.24	151.10
छात्रों की छात्रवृत्ति निधि	73.28	41.91	-	-	-	-	1.45	27.95	6.10	4.27	(2.12)	78.71	73.28
कर्मचारी कल्याण निधि	153.12	120.45	22.96	21.69	-	-	-	-	12.76	12.27	(1.16)	187.56	153.12
अन्य निधियाँ (प्रदेशिक परिषदें और शाखाएँ)	1,095.22	660.77	-	-	480.84	196.90	287.06	320.11	46.38	40.31	(651.36)	1,258.14	1,095.22
योग	9,152.98	6,968.39	4,100.82	2,733.36	(2,226.72)	(1,514.07)	288.61	417.42	712.34	676.63	(658.67)	11,309.16	9,152.98

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची III नियत आस्तियां

लाख रुपए में

आस्तियां	सकल स्वीकृत			अवकाश और परिसोधन			शुद्ध स्वीकृत	
	1.4.2009 को लागत	वर्ष के दौरान परिवर्धन	31.3.2010 को लागत	वर्ष के लिए	समावोजन/अंतरण/विक्रय	31.3.2010 तक	31.3.2010 को शुद्ध स्वीकृत	31.3.2009 को शुद्ध स्वीकृत
क. पूंजी आस्तियां								
1. पूंजी - पूर्ण स्थापित	1,318.38	1,449.48	2,767.86	-	-	-	2,767.86	1,318.38
2. श्रुति - पट्टाभूत स्थापित	3,252.31	7.44	3,259.75	40.23	-	219.26	3,040.49	3,073.28
3. बचन	3,883.02	1,256.71	5,139.73	169.21	(7.39)	953.17	4,165.90	3,091.67
4. विद्युतीय संस्थापन और फिटिंग	516.46	533.67	1,050.13	179.35	(1.43)	236.92	807.03	337.11
5. कम्प्यूटर्स	2,760.05	523.71	3,283.76	2,001.51	(25.48)	2,565.14	657.59	758.54
6. वातावरण	843.05	217.90	1,060.95	609.11	(0.35)	318.86	437.85	287.36
7. फर्नीचर और फिक्स्चर्स	1,404.94	631.99	2,036.93	465.07	(4.23)	578.64	1,446.27	939.87
8. सिस्टम्स	113.42	121.85	235.27	12.45	0.24	68.36	166.91	57.75
9. कार्यालय उपकरण	848.89	702.37	1,551.26	328.56	(2.18)	452.98	1,038.85	520.33
10. वाहन	66.89	0.28	67.17	32.30	0.06	39.33	27.84	34.59
11. पुस्तकालय पुस्तकें	501.54	69.04	570.58	72.43	(6.25)	567.72	-	-
ख. अमूर्त आस्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-
साफ़देयर	538.28	46.09	584.37	44.29	-	529.50	54.87	53.07
योग	15,747.23	5,560.53	21,307.76	1,322.61	(47.01)	6,550.88	14,611.46	10,471.95
पूर्व वर्ष के आकड़े	12,325.29	3,497.69	15,822.98	1,057.91	(29.80)	5,275.28	10,471.95	8,079.12

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान**अनुसूची IV****निवेश**

लाख रुपए में

		रकम	रकम
		31-03-2010 को	31-03-2009 को
क. दीर्घकालीन निवेश (लागत पर)			
बंधपत्र			
(i) भारत सरकार - 8% (कराधेय) बॉण्ड - 2003		3650.00	4750.00
अन्य			
(ii) अनुसूचित बैंकों में सावधि निक्षेप		5400.00	3800.00
ख. अन्य निवेश			
अनुसूचित बैंकों में लघु अवधि निक्षेप (जिनकी अवधि एक वर्ष तक है)		21582.24	13099.85
	कुल निवेश	30632.24	21649.85
निम्नलिखित को आबंटित :			
उद्दिष्ट निधि निवेश		11369.16	9152.98
कर्मचारी कल्याण निवेश		2283.48	2206.13
अन्य निवेश		16979.60	10290.74
	योग	30632.24	21649.85

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान**अनुसूची V****वस्तु सूचियां**

लाख रुपए में

		रकम	रकम
		31.03.2010 को	31.03.2009 को
प्रकाशन और अध्ययन सामग्री		645.04	647.99
उपभोज्य भंडार		56.68	31.85
	योग	701.72	679.84

अनुसूची VI**नकद और बैंक अतिशेष**

लाख रुपए में

		रकम	रकम
		31.03.2010 को	31.03.2009 को
हाथ में नकदी		13.13	25.38
बैंक में नकदी		6136.12	4047.09
	योग	6149.25	4072.47

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान**अनुसूची VII**

ऋण और अग्रिम (जिन्हें सुरक्षित माना गया है)

लाख रुपए में

		रकम	रकम
		31.03.2010 को	31.03.2009 को
ऋण और अग्रिम - कर्मचारिवृंद		377.30	612.76
कर्मचारिवृंद ऋण से वसूलनीय ब्याज		116.83	111.25
प्रतिभूति जमा		110.26	340.65
प्राप्य लेखे		1133.22	605.27
अन्य - अग्रिम और पूर्व भुगतान		409.47	837.23
	योग	2147.08	2507.16

अनुसूची VIII

चालू दायित्व

लाख रुपए में

		रकम	रकम
		31.03.2010 को	31.03.2009 को
अग्रिम में प्राप्त फीसें			
परीक्षा फीसें	2044.98	701.81	
पत्रिका अभिदाय	29.24	50.39	
सदस्यता फीस	669.49	513.78	
शिक्षा फीस	6338.36	5013.33	
अर्हतापश्च पाठ्यक्रम (पीक्यूसी)	114.50	110.15	
प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	11.75	17.50	
संगोष्ठी फीसें और अन्य संग्रहण	956.18	10164.50	730.02
			7136.98
खर्चों के लिए क्रेडिटर्स		5,097.37	2,180.97
अन्य दायित्व		990.37	784.24
योग		16252.24	10102.19

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान**अनुसूची IX**

लाख रुपए में

फीस	रकम	रकम
	31/3/2010 को समाप्त वर्ष	31/3/2009 को समाप्त वर्ष
शिक्षा	20933.31	13747.17
परीक्षा	6269.88	2942.93
सदस्यता	3126.23	3001.48
छात्र पंजीकरण	181.23	270.88
प्रवेश	34.59	28.52
छात्र संघ	126.74	250.89
अर्हतापश्च पाठ्यक्रम (पीक्यूसी)	219.24	176.11
प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	752.34	352.21
योग	31643.56	20770.19

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची X
अन्य आय

लाख रुपए में

	रकम	रकम
	31/3/2010 को समाप्त वर्ष	31/3/2009 को समाप्त वर्ष
प्रकाशन	750.99	533.14
निवेशों पर ब्याज	1,203.80	1,216.82
छात्र-न्यूजलेटर	1.59	10.51
पत्रिका-अभिदाय	143.43	151.30
न्यूजलेटर्स (प्रादेशिक परिषदें और शाखाएं)	51.20	68.32
कैम्पस साक्षात्कार (प्रत्यक्ष व्ययों का शुद्ध)	160.82	147.19
विशेषज्ञ सलाहकार फीस	11.99	12.65
कर्मचारिवृत्त ऋण पर ब्याज	15.75	15.84
अनापेक्षित प्रावधान प्रतिलिखित	0.90	2.23
अन्य	185.77	166.97
योग	2526.24	2324.97

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची XI
अन्य प्रचालन व्यय

लाख रुपए में

	रकम	रकम
	31/3/2010 को समाप्त वर्ष	31/3/2009 को समाप्त वर्ष
डाक, टेलीफोन और तार	1,221.43	955.34
किराया दर और कर	864.25	643.24
यात्रा और वाहन - अंतर्देशीय	1,069.43	958.77
विदेशी संबंध		
- यात्रा	129.19	104.20
- विदेशी वृत्तिक निकायों की सदस्यता फीस	60.14	57.36
- अन्य व्यय	23.66	4.72
मरम्मत और अनुस्क्षण	651.96	547.61
प्रकाशन	342.48	243.80
परीक्षकों, परामर्शियों और अन्यो को फीस और व्यय	3169.80	1816.69
कक्षा प्रशिक्षण व्यय	1792.96	1185.35
विज्ञापन और प्रचार	275.66	364.57
कार्यालय बैठक व्यय	76.91	90.57
योग्यता छात्रवृत्ति	37.98	21.42
संपरीक्षा फीस		
- प्रधान कार्यालय	4.14	3.31
- अन्य कार्यालय	11.76	10.98
अन्य व्यय	711.46	342.74
योग	10443.21	7350.67

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची XII

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों पर विवरण

I. लेखाकरण प्रथा

ये लेखा ऐतिहासिक लागत आधार पर बनाए गए हैं और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा लागू लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं तथा जब तक अन्यथा कथित न हो प्रोद्भवन आधार पर हैं।

II. राजस्व मान्यता

क. सदस्यता फीस :-

(i) प्रवेश फीस, किसी व्यक्ति के सदस्य के रूप में प्रवेश के समय प्राप्त की जाती है और उसके एक तिहाई को आय के रूप में इस वर्ष मान्यता दी गई है।

(ii) वार्षिक सदस्यता तथा व्यवसाय प्रमाणपत्र फीस को, जब वे देय हो जाएं, उसी वर्ष में मान्यता दी जाती है।

ख. दूरस्थ-शिक्षा और अर्हतातर पाठ्यक्रम फीस को पाठ्यक्रम की अवधि में मान्यता दी जाती है।

ग. परीक्षा फीस को परीक्षा संचालन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

घ. जर्नल के लिए अभिदाय को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है, जब वह देय हो जाए।

ङ. प्रकाशन के विक्रय से राजस्व को, विक्रय बिल तैयार किए जाने के समय मान्यता दी जाती है, अर्थात् जब संपत्ति माल के रूप में और साथ ही महत्वपूर्ण जोखिम और संपत्ति के फायदे क्रेता को अंतरित होते हैं।

च. ब्याज धारित प्रतिभूतियों और सावधि जमा में ब्याज से आय को समय अनुपात आधार पर बकाया रकम और लागू दर को ध्यान में रखते हुए मान्यता दी जाती है।

III. आरक्षिती और अधिशेष तथा उद्दिष्ट निधि को आबंटन से अंतरण

क. अध्येता सदस्यों से दाखिला फीस और सदस्यों के रूप में प्रविष्ट व्यक्तियों से प्रवेश शुल्क का 2/3 भाग सीधे अवसंरचना आरक्षिती में चला जाता है।

ख. भवनों और अनुसंधान प्रयोजनों के लिए वर्ष के दौरान प्राप्त संदान सीधे अपने-अपने आरक्षिती लेखा में संगणित किए जाते हैं।

ग. दूरस्थ-शिक्षा फीस का 25%, जो वर्ष के शुद्ध अधिशेष के 50% से अधिक न हो, शिक्षा निधि में अंतरित किया जाता है।

घ. वर्ष के दौरान सदस्यों से प्राप्त सदस्यता फीस का 0.75% (वार्षिक तथा व्यवसाय प्रमाणपत्र फीस) कर्मचारी कल्याणकारी निधि को आबंटित किया जाता है।

ङ. निम्नलिखित उद्दिष्ट निधियों से शिक्षा आरक्षिती को अंतरण

- | | | |
|-----|---------------------------|---|
| i. | लेखांकन अनुसंधान भवन निधि | लेखांकन अनुसंधान भवन से संबंधित भवन में परिवर्धन की लागत (शुद्ध कटौतियों) का 100% |
| ii. | शिक्षा निधि से | अन्य नियत आस्तियों की परिवृद्धि (कटौतियों के शुद्ध) का 50%। |

च. उद्दिष्ट निधियों के निवेशों से आय, भारत औसत पद्धति के आधार पर उद्दिष्ट निधियों को संबंधित उद्दिष्ट निधियों के आरंभिक अतिशेष पर आबंटित की जाती है।

IV. स्थिर आस्तियां/अवक्षयण और परिशोधन

- क. भूमि को छोड़कर नियत आस्तियां, अवक्षयण तालाकर ऐतिह्यसिद्धता पर वर्णित की जाती हैं ;
- ख. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि लागत पर वर्णित की जाती है । पर्यटन भूमि, पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए संदत्त प्रीमियम की रकम पर कथित होती है । इस प्रकार संदत्त प्रीमियम का परिशोधन पट्टे की अवधि में किया जाता है ।
- ग. अवक्षयण, संबंधित आस्तियों के उपयोग जीवन के आधार पर परिषद द्वारा यथा अनुमोदित निम्नलिखित दरों से अवलिखित मूल्य पर प्रदान किया जाता है :-

भवन	5%
वातानुकूलक और कार्यालय उपस्कर	15%
लिफ्ट, विद्युतीय संस्थापन, फर्नीचर और फिक्सचर	10%
वाहन	20%
कंप्यूटर	60%

- घ. अभिवृद्धियों पर अवक्षयण मासिक यथानुपात आधार पर दिया जाता है ।
- ङ. पुस्तकालय पुस्तकों पर क्रय वर्ष में अवक्षयण 100% की दर पर होता है ।
- च. अमूर्त आस्तियां (साफ्टवेयर) तीन वर्षों में समान रूप से परिशोधित की जाती हैं ।

V. निवेश

- क. दीर्घकालिक निवेश, लागत पर अवधारित किए जाते हैं और अस्थाई से भिन्न मूल्यों में कमी का प्रावधान किया जाता है ।
- ख. चालू निवेश लागत या उचित मूल्य के निम्नतर पर वहन होते हैं ।

VI. वस्तु-सूचियां

- कागज, उपभोज्य सामग्री, प्रकाशन और अध्ययन सामग्री की वस्तु-सूचियां लागत या शुद्ध वसूलनीय मूल्य के निम्नतर पर मूल्यांकित होती हैं । लागत का अवधारण फीफो रीति से होता है ।

VII. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

- क. विदेशी मुद्रा संव्यवहार, संव्यवहार की तारीख को प्रचलित विनिमय दर की रकम पर विदेशी मुद्रा उपयोजित करके रिपोर्टिंग मुद्रा में आरंभिक मान्यता पर अभिलिखित किए जाते हैं ।
- ख. सभी आय और व्यय औसत दर पर निष्पादित होते हैं । सभी धनीय आस्तियां वर्षांत दरों पर निष्पादित होती हैं जबकि गैर-धनीय आस्तियां संव्यवहार की तारीख वाली दर पर निष्पादित होती हैं ।
- ग. विनिमय दर अंतर के कारण किसी आय या व्यय को आय और व्यय लेखा में मान्यता दी जाती है ।

VIII. कर्मचारियों को फायदे

- क. अल्पकालिक कर्मचारी फायदों को उस वर्ष में प्रभारित किया जाता है, जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं ।
- ख. नियोजन पञ्च और दीर्घकालिक कर्मचारी फायदों को उस वर्ष में प्रभारित किया जाता है, जिसमें कर्मचारी ने अपनी सेवा प्रदान की है । प्रभारित रकम को, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अवधारित संदेय रकमों के वर्तमान मूल्य पर मान्यता दी जाती है । बीमांकिक मूल्यांकन प्रक्षेपित यूनिट प्रत्यय पद्धति के अनुसार किया जाता है । नियोजन पञ्च और अन्य दीर्घकालिक फायदों के संबंध में बीमांकिक अभिलाभ और हानियों को आय और व्यय लेखा में प्रभारित किया जाता है और उन्हें आस्थगित नहीं किया जाता है ।
- ग. भविष्य निधि के रूप में सेवानिवृत्ति फायदे एक परिभाषित अभिदाय स्कीम है और भविष्य निधि न्यास को किए गए अभिदाय को, उस अवधि के लिए जब संबंधित निधि में अभिदाय शोध्य हो जाता है, आय और

व्यय लेखा में प्रभासित किया जाता है।

IX. आस्तियों का हानिकरण

क. यदि आंतरिक/ बाह्य कारकों के आधार पर किसी हानिकरण का कोई संकेत प्राप्त होता है तो आस्तियों की अग्रणीत रकमों को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को पुनर्विलोकित किया जाता है। किसी हानिकरण हानि को वहां मान्यता दी जाती है, जहां किसी आस्ति की अग्रणीत रकम उसकी वसूलनीय रकम से अधिक हो जाती है। आस्ति की वसूलनीय रकम उसकी शुद्ध विक्रय कीमत और उपयोग में मूल्य से अधिक है। उपयोग में मूल्य का निर्धारण करते समय, प्राक्कलित भावी नकद प्रवाह को पूंजी की भासित लागत पर उसके वर्तमान मूल्य में पट्टा प्रदान किया जाता है।

ख. हानिकरण के पश्चात्, आस्तियों को, उसके शेष बचे उपयोगी जीवन के लिए, पुनरीक्षित अग्रणीत रकम पर अवक्षयण प्रदान किया जाता है।

X. प्रावधान

किसी प्रावधान को उस समय मान्यता दी जाती है जब किसी पूर्व घटना के कारण उद्यम के पास कोई विद्यमान बाध्यता है; यह संभावना है कि उस बाध्यता के समाधान के लिए संसाधनों का बहिर्प्रवाह अपेक्षित होगा, जिसके संबंध में कोई विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है। प्रावधानों को, उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टा नहीं दिया जाता है और उनके संबंध में तुलनपत्र की तारीख को बाध्यताओं के समाधान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम प्राक्कलनों के आधार पर अवधारण किया जाता है। इनको प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को पुनर्विलोकन किया जाता है और वर्तमान सर्वोत्तम प्राक्कलनों को उपदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची XIII

लेखाओं का भाग बनने वाले टिप्पण

1. आकस्मिक दायित्व

1.1 संस्थान के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:

	(राशि लाख रुपए में)	
	2009-10	2008-09
i) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 156 के अधीन मांग		
- निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए	1497/-	1497/-
- निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए	1578/-	-
ii) लीविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड द्वारा फाइल किया गया वाद जो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित बना रहा।	287/-	287/-

2. अन्य टिप्पण

2.1 निर्धारण वर्ष 2006-07 और 2007-08 के संबंध में 3074.95 लाख रुपए की आयकर मांग को उठाया गया है, जिसे संस्थान ने आय-कर आयुक्त (अपील) के समक्ष विवादित ठहराया है। संस्थान ने 300.54 लाख रुपए जमा किए हैं (जिनमें उक्त मांग के संबंध में प्रतिदाय के समायोजन के रूप में 26.54 लाख रुपए सम्मिलित हैं)। शेष मांग को आयकर निदेशक (छूट) द्वारा आस्थगित कर दिया गया है। संस्थान ने निर्धारण वर्ष 2006-07 और 2007-08 के संबंध में निर्धारण आदेशों को रद्द करने के लिए और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग)(त्थ) के अधीन छूट को पुनःप्रदान करने के लिए, जिसे डीजीआईटी (छूट) द्वारा नामंजूर कर दिया गया है, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट फाइल की है। संस्थान अधिनियम की धारा 12क के अधीन एक पूर्त न्यास के रूप में रजिस्ट्रीकृत है और इसकी आय को अन्यथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार भी छूट प्राप्त है। संस्थान यह आशा करता है कि अपील प्राधिकारी उसे समुचित अनुतोष प्रदान करेंगे और इस प्रकार विवादित दायित्व के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है।

2.2 संस्थान के कर्मचारियों के एक वर्ग के साथ समझौता लंबित रहने के दौरान 2262 लाख रुपए (जो कि 31 मार्च, 2009 तक का बकाया है) की राशि को वेतन पुनरीक्षणों के रूप में उपलब्ध कराया गया है और इस प्रभाव के पहले संदत्त 507 लाख रुपए की अग्रिम राशि को वेतन और भत्ते शीर्ष के अंतर्गत दर्शित किया गया है।

2.3 1 अप्रैल, 2009 से रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक छात्र के लिए 250 रुपए प्रति छात्र की एक राशि को, जो छात्र की सहबद्धता फीस का एक भाग है, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स कल्याण निधि में जमा किया जा रहा है।

2.4 पूंजी वचनबद्धता (अग्रिमों का शुद्ध) की प्राक्कलित रकम 3943.50 लाख रुपए है। (पूर्व वर्ष - 7136.32 लाख रुपए)।

2.5 पट्टाघृत भूमि में 6.17 लाख रुपए सम्मिलित है जो भूमि और विकास प्राधिकरण से आई.पी.स्टेट, दिल्ली में विद्यमान कार्यालय के प्लॉट के साथ लगी भूमि से संबंधित है, जिसके लिए करार और पट्टाभिलेख के ज्ञापन के निष्पादन संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

2.6 भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी “ कर्मचारियों के फायदे संबंधी लेखांकन मानक - 15 (पुनरीक्षित) के अधीन अपेक्षित प्रकटन नीचे दिए गए हैं :-

परिभाषित अभिदाय योजना

मान्यताप्राप्त परिभाषित अभिदाय योजना में किया गया अभिदाय अर्थात् भविष्य निधि में कर्मचारी के अभिदाय को वर्ष के लिए प्रभारित किया जाता है।

परिभाषित कल्याण योजना

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित कर्मचारी उपदान निधि एक परिभाषित फायदा योजना है। बाध्यता के वर्तमान मूल्य को, अंतिम बाध्यता संगणित करने के लिए प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन पर अवधारित किया जाता है। छुट्टी नकदीकरण और पेंशन की बाध्यता को भी उसी आधार पर मान्यता दी जाती है, जो आधार उपदान के लिए है।

परिभाषित कल्याण योजना की प्रास्थिति

पुनरीक्षित लेखांकन मानक-15 द्वारा अपेक्षा किए गए अनुसार परिभाषित फायदा योजना की स्थिति निम्नानुसार है :

	उपदान (निधि पोषित)		छुट्टी - नकदीकरण (गैर निधि पोषित)		पेंशन (गैर निधि पोषित)	
	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
परिभाषित फायदा बाध्यता के आरंभिक और अंतिम अतिशेषों का समाधान						
वर्ष के आरंभ में परिभाषित फायदा बाध्यता	742.15	643.03	936.14	704.13	1224.76	851.81
चालू सेवा लागत	75.89	70.45	162.23	165.07		
ब्याज लागत	59.89	47.07	75.12	50.64	100.94	63.83
बीमांकिक (अभिलाभ/हानि)	(73.52)	12.19	(82.91)	74.28	(159.44)	310.54
संदत्त फायदे	(32.48)	(30.6)	(51.31)	(57.98)	(2.60)	(1.42)
वर्ष के अंत में परिभाषित फायदे बाध्यता	771.82	742.15	1039.26	936.14	1163.65	1224.76

योजना आस्तियों के उचित मूल्य के आरंभिक और अंतिम अतिशेषों का समाधान						
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	675.35	559.49	-	-	-	-
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	68.87	54.93	-	-	-	-
दीर्घकालिक अभिलाभ/ (हानि)	1.22	(1.39)	-	-	-	-
नियोजक का अंशदान	160.99	95.25	-	-	-	-
सदस्य फायदा	(30.70)	(32.93)	-	(57.98)	-	-
वर्ष के अंत पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	875.73	675.35	-	-	-	-
आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य का समाधान						
31 मार्च, 2010 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	875.73	675.35	-	-	-	-
31 मार्च, 2010 को बाध्यताओं का विद्यमान मूल्य- दीर्घकालिक	771.82	742.15	1039.26	936.14	1163.65	1224.76
31 मार्च, 2010 को बाध्यताओं का विद्यमान मूल्य- अल्पकालिक	-	-	80.57	45.23	-	-
31 मार्च, 2009 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई रकम	(103.90)	66.8	1119.83	981.37	1163.65	1224.76

वर्ष के दौरान माने गए व्यय						
चालू सेवा लागत	75.79	70.45	162.22	165.07	-	-
ब्याज लागत	59.89	47.08	75.12	50.63	100.94	63.83
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	(68.87)	(54.93)	-	-		
बीमांकिक	(74.74)	13.59	(82.91)	74.28	(159.44)	310.54
(अभिलाभ)/हानि						
अल्पकालिक दायित्व	-	-	80.57	45.22	-	-
शुद्ध लागत	(7.93)	76.19	235.00	335.21	(58.50)	374.37
बीमांकिक पूर्वानुमान						
नश्वरता सारणी	एलआईसी 1994-96 अंतोगत्वा	एलआईसी 1994-96 अंतोगत्वा	एलआईसी 1994-96 अंतोगत्वा	एलआईसी 1994-96 अंतोगत्वा	एलआईसी 1994-96 अंतोगत्वा	एलआईसी 1994-96 अंतोगत्वा
संनिघर्षण दर	05.00% वार्षिक	05.00% वार्षिक	05.00% वार्षिक	05.00% वार्षिक	05.00% वार्षिक	05.00% वार्षिक
अधिरोपित ब्याज की दर	08.25% वार्षिक	07.50% वार्षिक	08.25% वार्षिक	07.50% वार्षिक	08.25% वार्षिक	07.50% वार्षिक
वेतन में वृद्धि	मूल:03.00% वार्षिक और म.भ.:06.00% वार्षिक	मूल:03.00% वार्षिक और म.भ.:06.00% वार्षिक	मूल:03.00% वार्षिक और म.भ.:06.00% वार्षिक	मूल:03.00% वार्षिक और म.भ.:06.00% वार्षिक	मूल:03.00% वार्षिक और म.भ.:06.00% वार्षिक	मूल:03.00% वार्षिक और म.भ.:06.00% वार्षिक
योजना आस्तियों से आय	09.30% वार्षिक	09.30% वार्षिक				
शेष बची औसत कार्यावधि	17.94 वर्ष	18.23 वर्ष	17.94 वर्ष	18.23 वर्ष	17.94 वर्ष	18.23 वर्ष
निवेश के ब्यौरे	100% निवेश एलआईसी में	100% निवेश एलआईसी में	1119.83 *	981.37 *	1163.65 *	1224.76*

* निवेश संस्थान द्वारा किए जाते हैं।

2.7 कैंपस साक्षात्कार आय को शुद्ध प्रत्यक्ष रूप से होने वाले व्ययों के रूप में दर्शित किया गया है और सामान्य व्ययों को व्ययों के संबंधित शीर्षों में विकलित किया गया है।

2.8 प्रकाशन और संगोष्ठी की गतिविधियों के केवल प्रत्यक्ष रूप से लक्षणीय खर्चों को क्रमशः इन व्यय शीर्षों पर प्रभारित किया गया है और इन गतिविधियों पर अप्रत्यक्ष व्यय, व्यय के कृत्यकारी शीर्षों पर प्रभारित किए गए हैं।

2.9 पूर्व अवधि आय में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

	2009-10 लाख रुपयों में	2008-09 लाख रुपयों में
संगोष्ठी आय	22.78	-----
अन्य	30.89	25.16
योग	53.67	25.16

पूर्व अवधि खर्चों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

मुद्रण और लेखन सामग्री	0.82	0.40
लेखा परीक्षा फीस	—	0.25
परीक्षा फीस	7.04	0.96
मरम्मत और अनुरक्षण	2.05	0.63
यात्रा और वाहन	12.06	6.21
वेतन और भत्ते	0.51	2.45
वृत्तिक फीस	6.80	0.17
अन्य	42.52	48.80
योग	71.80	59.87

2.10 संस्थान मुख्यतः भारत में और एक खंड में प्रचालन करता है, अर्थात् चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की वृत्ति को बढ़ावा देने ।

2.11 जहां कहीं, पूर्व वर्ष के आंकड़ों की तुलना चालू वर्ष के प्रस्तुतिकरण से करना आवश्यक समझा गया, इन्हें पुनः समूहबद्ध और पुनः वर्गीकृत किया गया है ।

टी. कार्तिकेयन, सचिव

[विज्ञापन III/4/104/10/असा.]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2010

(Chartered Accountants)

No.1-CA(5)/61/2010 – In pursuance of sub-section (5B) of Section 18 of the Chartered Accountants Act, 1949, a copy of the Audited Accounts and Report of the Council of the Institute of Chartered Accountants of India for the year ended 31st March, 2010 is hereby published for general information.

61st Annual Report

The Council of the Institute of Chartered Accountants of India (hereinafter referred to as the "Council") has immense pleasure in presenting its 61st Annual Report for the year ended 31st March, 2010.

The Council, at the outset, commends the members and students for the respect which the Chartered Accountancy Profession commands today in the Society, who have kept the lamp burning by way of their *excellence, independence* and *integrity* all along.

While highlighting through this Report, the important activities of the Council and its various Committees for the year 2009-2010, besides the accounts of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) for the year 2009-2010, the Council also takes this opportunity to cover in this Report major initiatives, important events, statistical profile relating to

members, students, details of seminars, conferences, workshops and training programmes organised during the period upto the first week of July, 2010. The entry into its 62nd year of existence by the ICAI on 1st July, 2010 marks another step forward in its long and historic journey spanning six decades serving the nation and other stakeholders. Throughout the year under report the ICAI has strived to undertake various initiatives/programmes which has enhanced the glory of the profession and the ICAI continues to serve our Nation and other Stakeholders with the same spirit of excellence and integrity which have been the guiding principles of this profession over the past decades.

Since 1st July, 1949, when the Institute was set up by an Act of Parliament, the accountancy profession has grown by leaps and bounds in terms of membership and students' base. Founded with just about 1,700 members, the Institute has grown to cross the mark of 1,64,000 members and 6,90,000 students as of now. During its glorious journey, the accountancy profession in India has successfully passed through many crucial phases of restructuring, upgradation, value addition, diversification and global integration. Over the years, the Institute has made considerable progress in its core mission as custodian of transparency and integrity in financial reporting and evolvement of highest accounting and auditing standards as it always engaged in change, coupled with a need to adapting consistently to changing economic environment. Today the Indian Chartered Accountant has transformed himself from a mere professional engaged in day-to-day accounting matters to a versatile and complete business solution provider. The ICAI as the leader of the Accountancy Profession in India has always been focused and watchful in ensuring the acceptability, stature and brand image of its members and whereby their quality of services provided to the society at large is at par with global standards.

The rapid changes in the economic environment of our country fuelled by the global recession that threatened to shatter the very foundation of financial self-sufficiency attained over the years, provided a distinctive challenge and welcome opportunity to this noble profession. Seizing the opportunity, the ICAI strove towards displaying the distinctive techniques of the accounting profession as the sole solution in rebuilding the financial infrastructure of the nation as a whole. The globalization of the Indian Chartered Accountancy profession through the inking of various MoUs/MRAs with the Accountancy Institutes of the world has opened up new vistas of professional opportunities to the members of the profession and also strengthening the economic bonds among the countries concerned. There has been renewed initiatives undertaken in revamping the Chartered Accountancy curriculum as a whole to make it attractive and popular amongst the vibrant student community taking up the Chartered Accountancy Course as their mainstream of education.

As the Institute marches along its 62nd year of existence, it is a matter of great pride that the Institute continues to be recognized as one of the prominent accounting bodies all over the world. In the 62nd year of its existence, it is a matter of both fulfillment and encouragement in the journey ahead to note that the leaders of our nation have consistently acknowledged all along the ICAI's initiatives and contributions towards the cause of nation-building.

The services of the Indian Chartered Accountant are being sought over from every nook and corner of the world and in recognition of the need to provide more and more opportunities to its members in the international arena, the Institute has signed MOUs with some of the renowned Accountancy Institutes of the world and has also opened Chapters of the Institute in some more countries across the globe.

The Institute has also taken many pro-active step in keeping pace with the technological advancement sweeping across the world including initiatives in the field of IT through conduct of Online examination in CPT and holding of seminars/programmes through web-cast/ video conferencing.

The Council has been constantly striving to maintain and heighten the image of the profession which is held in high esteem by both the stakeholders and the public in general as a continuous process. To this end, the ICAI is currently on course to bring in necessary amendments in the Parent Act, i.e., The Chartered Accountants, 1949, to provide for stringent and faster mechanism to deal with cases of professional misconduct by any errant members of the profession in keeping with the public sentiments. This step would go a long

way in keeping the strong and robust profession with its own in-built mechanism of checks and balances acting as a catalyst in preserving the economic wealth and financial health of the nation in high esteem in the eyes of stakeholders and regulators in particular and the society in general.

In keeping with its commitment for convergence with International Accounting Standards, the ICAI has been constantly working in re-writing the existing plethora of Accounting Standards and incorporating the best international practices prevalent in various accounting bodies of the globe thereby making the Accounting Standards, Auditing and Assurance Standards issued by the ICAI comparable with the best in the world.

The Council firmly believes that the knowledge and skills displayed by the Indian Chartered Accountants during the recent global recession period has once again brought into focus the adaptability of the Indian Chartered Accountancy profession towards tackling the financial crisis that swept across the world. Through the development and adoption of the Indian Accounting Standards which incorporates the best of international practices prevalent across the world, the ICAI today stands high amongst the various accounting bodies of the globe.

1. THE COUNCIL

The Twentieth Council composed of 32 elected members and 8 members nominated by the Central Government, was constituted on 5th February, 2007 for a period of three years. The composition of the Council for the year 2008-2009 and the same for the year 2009-2010 are shown separately. The election to the Twenty-first Council was held in December, 2009. On successfully contesting some of the election petitions filed in the Courts of Law, the Council was constituted on 12th February, 2010 involving a gap of about a week.

2. COMMITTEES OF THE COUNCIL

The Council, in terms of Section 17 of the Chartered Accountants Act, 1949, constituted on 12th February, 2010 three Standing, and various Non-Standing Committees/Boards to deal with matters concerning the profession. The Council also constituted a Board of Discipline and a Disciplinary Committee in pursuance to the provisions of Sections 21A and 21B of the Chartered Accountants Act, 1949 respectively. Further, a Disciplinary Committee, a Standing Committee, was also constituted under Section 21D of the said Act to deal with disciplinary cases falling under the erstwhile disciplinary mechanism. While constituting the various Non-Standing Committees for the year 2010-2011, some of the Committees constituted for the year 2009-2010 were combined together and re-christened for harmonised functioning. During the year ended 31st March, 2010, 194 meetings were held of various Committees of the Council as compared to 214 meetings held during the year ended 31st March, 2009.

3. AUDITORS

CA. Pramod Jain, FCA and CA. Pushpendra Surana, FCA were the joint auditors of the Institute for the financial year 2009-10. The Council wishes to place on record its appreciation of the services rendered by them.

4. STANDING COMMITTEES

4.1 Executive Committee

This Committee is responsible for all regulatory functions, e.g., maintenance of various registers pertaining to students/members/firms, admission, removal and restoration of members, matters relating to members including issue of certificate of practice, matters relating to students including according permission, wherever required, condonation of delay on the part of students/members/firms, matters connected with Branches including setting up of new Branches, opening of new Chapters, Students Associations at the Branch level and overseas offices and those connected with employees etc. The functions of the Committee also include developing infrastructural facilities at all levels all across the country, proposals for amendments in the Chartered Accountants Act, 1949 and the Regulations/Rules made thereunder, and any other matter touching upon the realm of policy of the Institute.

Some of the important decisions taken/recommendations made by the Committee during the period under Report related to matters on :

- Steps to increase in Life Membership Subscription to the Chartered Accountants Benevolent Fund
- Augmenting corpus of the Chartered Accountants Students Benevolent Fund
- Issue of study material to students by at the branch level
- Encouraging branches to conduct more and more education programmes – seminars, elocution/quiz contest, and other activities - for the benefit of students and, for the purpose, increase in related grants
- Fixing fee payable by members for undertaking Ph.D. Programme in accordance with the terms of MoU with Bharathiar University
- Increase in grant for Joint Seminars with Universities
- Financial support for establishing additional ITT Centres at the Branches
- Setting up of ITT Centres at the level of CPE Chapters
- Exemption of fees and other concessions to handicapped/physically disabled students for Orientation Programme
- Proposal for National Young CA in Industry Award
- Setting up of a branches of WIRC at Bhavnagar, Gandhidham, Latur and Vapi, of SIRC at Tirupati, and of CIRC at Pali, Ratlam, and Sriganganagar
- Guidelines for training of articled assistants abroad
- Hosting of agenda/minutes of the Non-Standing Committees/Boards on the website
- Uniformity of letter-heads of the Regional Councils and their Branches as also Newsletter published by them
- Modification in the Directions of the Central Council regarding Functions of the Branches of Regional Councils to provide for
 - Extension of Election Code of Conduct applicable for election to the Council and the Regional Councils to Managing Committees of Branches
 - Voting through single transferable system at the election to Managing Committees of Branches
 - Imposing conditions for re-election to the Managing Committee after having held the office of Chairperson
 - Nomination of members of Council/Regional Council only as Ex-Officio member on the Managing Committee of Branches
- Revision in the criteria for selection of Best Branch
- Revision in the norms for setting up of branches
- Setting up of a branch of Students' Association at Pimpri Chinchwad in the Western Region and Nellore in the Southern Region
- Renaming of certain chapters and setting up new chapters abroad
- Enlarging the jurisdiction of Durgapur Branch of EIRC
- Creation of Information Technology Directorate
- Determining fee payable by members of the professional bodies in U.K. and Australia for registration to specified ICAI examinations under Memorandum of Understanding signed with the respective bodies
- Simplification of format of letter of good standing
- Initiation of entering into Mutual Recognition Agreements/Memoranda of Understanding with Certified General Accountants, Canada, Institute of Chartered Accountants in New Zealand, Institute of Certificate Public Accountants in Ireland, Institute of Chartered Accountants of Nepal and Malaysian Institute of Accountants
- Invitation to ISA Qualified members for reviewing the functioning of IT Centres
- Enhancement in grant to Regional Councils for organising orientation programmes for Managing Committee Members of their branches
- Enhancement in the honorarium to Technical Reviewers and members of Financial Reporting Review Groups [other than Members of Central/Regional Councils and Branch Managing Committee members]
- Exemption of fee to members joining Post Qualification Courses of the Institute on the ground of physical disability
- Acknowledging contribution made/services rendered by individuals/ organisations in preparation/development of publications
- Proposal for imposing certain restrictions on Restoration of Membership as also on entertaining delayed applications for admission to the membership
- Review of Policy and Procedure for permission to reproduce from the publications of the Institute and hosting of publications on the website

4.2 Finance Committee

The Finance Committee – one of the Standing Committees of the Council – came into existence consequent to the amendments to the Chartered Accountants Act, 1949 by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006. The said Committee controls, implements and supervises the activities related with and incidental, inter alia, to maintenance of true and correct accounts, formulation of annual budget, investment of the funds, and disbursements from the funds for expenditure – both revenue and capital.

4.3 Examination Committee

Due to the then impending elections to the Lok Sabha and the Legislative Assemblies of some of the States in May, 2009, the Chartered Accountants Examinations were postponed to be held in the month of June, 2009 instead of May, 2009. Accordingly, Chartered Accountants Professional Education-II (PE-II), Professional Competence Examination (PCE) and Final (Old and New Courses) Examinations were smoothly conducted all over the country and abroad in 146, 202 and 185 centres respectively from 1st to 15th June, 2009. The total number of candidates who appeared in the PE-II, PCE and Final (Old and New Courses) examinations held in June, 2009 were 18507, 59329 and 35350 respectively.

The next Chartered Accountants Professional Education-II (PE-II), Professional Competence Examination (PCE), Integrated Professional Competence Examination (IPCE) and Final (Old and New Courses) examinations, during the year, were smoothly conducted from 5th to 19th November, 2009 all over the country and abroad in 173, 245, 178 and 198 centres respectively. The total number of candidates who appeared in the PE-II, PCE, IPCE and Final (Old and New Course) examinations held in November, 2009 were 12,809, 67,474, 25,723 and 38,636 respectively.

For the November, 2009 CA examinations, new examination centres had been opened at Bhavnagar, Bhuj, Nanded, Panvel, Satara, Sambalpur and Tinsukia.

Further, the Common Proficiency Tests – Paper-Pencil Mode and Online continued to be successfully conducted. The Common Proficiency Test [CPT] in Paper-Pencil mode was held on 28th June, 2009 across the country and abroad at 252 examination centres located in 119 cities and 1,12,788 candidates appeared in the said Test. Another CPT in Paper-Pencil mode was conducted on 13th December, 2009 at 269 examinations centres in 123 cities spread across the country and abroad, and 1,17,001 candidates appeared in that Test. For the CPT held on 13th December, 2009, 8 new examination centres were set up, viz., Bhavnagar, Bhuj, Nanded, Panvel, Ratlam, Sambalpur, Satara, and Tinsukia. The Online Common Proficiency Tests [Online CPT] were conducted at the examination centres located at various Information Technology Training Centres of the Institute as per details below :

Sr. No.	Date(s) of Online CPT	Number of / Cities in which examination centres were set up	Candidates Appeared
1	25 th April, 2009	15 — Ahmedabad, Bangalore, Chandiragh, Chennai, Coimbatore, Delhi, Guntur, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Mumbai, Nagpur, Pune, Surat & Visakhapatnam	183
2	23 rd May, 2009	19 — Ahmedabad, Bangalore, Chandigarh, Chennai, Delhi, Guntur, Hyderabad, Indore, Jaipur, Kanpur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Pune, Raipur, Surat, Udaipur and Visakhapatnam	271
3	22 nd -23 rd August, 2009	20 — Ahmedabad, Bangalore, Chennai, New Delhi, Kanpur, Kolkata, Mumbai, Jaipur, Hyderabad, Pune, Chandigarh, Coimbatore, Ernakulam, Guntur, Indore, Lucknow, Surat, Thiruvananthapuram, Udaipur and	818

		Vishakapatnam	
4	26 th -27 th September, 2009	18 — Ahmedabad, Bangalore, Chennai, New Delhi, Kanpur, Kolkata, Mumbai, Jaipur, Hyderabad, Pune, Chandigarh, Coimbatore, Guntur, Indore, Lucknow, Surat, Udaipur and Vishakapatnam	717
5	24 th -25 th October, 2009	20 — Ahmedabad, Bangalore, Chennai, New Delhi, Kanpur, Kolkata, Mumbai, Jaipur, Hyderabad, Pune, Chandigarh, Coimbatore, Ernakulam, Guntur, Indore, Lucknow, Surat, Thiruvananthapuram, Udaipur and Vishakapatnam	787
6	21 st -22 nd November, 2009	20 — Ahmedabad, Bangalore, Chennai, New Delhi, Kanpur, Kolkata, Mumbai, Jaipur, Hyderabad, Pune, Chandigarh, Coimbatore, Ernakulam, Guntur, Indore, Lucknow, Surat, Thiruvananthapuram, Udaipur and Vishakapatnam	1186

Besides the aforesaid students' examinations, the Post-Qualification Examinations were also conducted. In that, the Information Systems Audit – Assessment Test [ISA-AT] was held on 20th June, 2009 at 36 examinations centres in 34 cities all over the country. Another ISA-AT was conducted on 19th December, 2009 at 42 examination centres in 40 cities across the country. Further, Management Accountancy Course [MAC (Part I)], Corporate Management Course [CMC (Part I)], Tax Management Course [TMC (Part I)], Insurance and Risk Management [IRM] and International Trade Laws and World Trade Organisation [ITL&WTO] Examinations were also held in November, 2009 whereas only MAC (Part-I), IRM and ITL & WTO examinations were held in June, 2009.

During the year for the convenience of candidates, the facilities continued to be provided included : Examination Application Forms in the OMR; availability of examination applications forms at all the Regional Offices of the Institute and Branches of the Regional Councils, as also at different locations in the metropolis of Delhi, Kolkata and Mumbai; downloading of admit cards by the candidates, and availability of results as well as marks on the website with the facility of downloading.

4.4 Disciplinary Committee

This Committee assists the Council in the maintenance of the status and standards of professional qualification awarded by the Institute. In discharging its avowed responsibility of conducting disciplinary inquiries against members, under the erstwhile disciplinary mechanism, whose cases have been referred to it by the Council upon *prima facie* opinion, during the year 1st April, 2009 to 31st March, 2010, this Committee held sittings on 14 occasions for a period spanning 18 days and at venues covering the various regions of the country. During the year under Report, the Committee concluded its inquiries in 52 cases, which included cases, referred to it in previous years.

In addition, under the new disciplinary mechanism in 138 and 165 cases of complaint and "information" respectively the *prima facie* opinion of the Director (Discipline) was considered by the Board of Discipline (under Section 21A). Further, in 64 and 24 cases of Complaints and "information" respectively, the *prima facie* opinion of the Director (Discipline) was considered by the Disciplinary Committee (under Section 21B).

5. TECHNICAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

5.1 Accounting Standards Board

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), an apex premier accounting body in the country set up under an Act of Parliament, has been continuously working to provide a sound, reliable and high-quality accounting and financial reporting system in the country. For harmonising the diverse accounting policies and practices in India, the ICAI had set up the Accounting Standards Board (ASB) in 1977 for formulating the Accounting Standards. Since its inception, ASB has been working in this direction by formulating new Accounting Standards as well as revising the existing Accounting Standards from time to time with the objective to bring the Indian Standards in line with the International Accounting Standards (IAS)/ International Financial Reporting Standards (IFRS), as issued by the International Accounting Standards Board (IASB). The ASB also issues various announcements from time to time to provide guidance on matters pertaining to uniform application of the Accounting Standards and their implementation.

The legal recognition to the Accounting Standards formulated by the ICAI was granted in October 1998 with insertion of Section 211(3A), (3B), and (3C) in the Companies Act, 1956. As per Section 211(3C) of the Act, Accounting Standards issued by the ICAI may be prescribed by the Central Government in consultation with the National Advisory Committee on Accounting Standards (NACAS). As per the proviso in the section, till the notification of the Accounting Standards by the Government, the Accounting Standards issued by the ICAI are required to be followed by companies. In the year 2006, Accounting Standards 1 to 7 and 9 to 29 were prescribed by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, under the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 vide its notification dated December 7, 2006 in the Gazette of India. These are to be effective in respect of accounting periods commencing on or after the publication of these Accounting Standards (i.e., December 7, 2006). Further, Limited Revision to Accounting Standard (AS) 15 was notified under Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2008 vide its notification dated March 27, 2008. Whereas, amendment to the Accounting Standard (AS) 11 has been notified under Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2009 vide notification dated March 31, 2009, by the Central Government in consultation with NACAS.

With globalisation and liberalisation, world economies have gone global. Firms seeking to tap foreign capital markets often have to prepare two sets of accounts; one to adhere to the home requirements and the other to conform to the foreign market in which capital is raised. Multiple standards constrain the volume and efficiency of capital allocation since the investors cannot easily compare financial information of companies in different jurisdictions. Thus, a need for a single set of globally accepted and high-quality Accounting Standards has often been felt. The International Financial Reporting Standards being issued by the IASB are increasingly being recognised as the global financial reporting standards. Many countries have either adopted or have permitted adoption of IFRS for preparing financial statements of various entities. Though the Accounting Standards issued by ICAI are primarily based on IAS/IFRS, in certain cases, the Accounting Standards have departed from IASs/IFRSs in view of legal and regulatory requirements apart from the economic conditions prevailing in the country.

Convergence with International Financial Reporting Standards has gained worldwide momentum in recent years. About 117 countries currently require or permit the use of or have a policy of convergence with IFRS. Certain other countries have announced their intention to adopt IFRS, for example, Brazil and Canada from the year 2010 and 2011 respectively. Financial Accounting Standards Board (FASB) of USA and IASB are also working towards convergence of US GAAP and IFRS. The Securities and Exchange Commission (SEC) of USA has decided to permit filing of IFRS-compliant financial statements without requiring presentation of a reconciliation statement between the US GAAP and IFRS. In this scenario, with India being an important emerging global economy, the Institute of Chartered

Accountants of India (ICAI) has decided to converge with IFRS from 1st April 2011 for certain class of companies. The Ministry of Corporate Affairs has also agreed to do so. Convergence, among other things, would help Indian entities raise capital from abroad at a low cost. It will also benefit the chartered accountants with opening of increased opportunities abroad for the Indian professionals.

To consider convergence with IFRS and making India IFRS-compliant, ASB had constituted a Task Force in the year 2006 with a mandate to explore the approach for convergence with IFRS and lay down a road map for achieving such convergence. The Task Force prepared a Concept Paper, which was accepted by the ASB and the Council of the ICAI. The principal recommendation in the Concept Paper was convergence with IFRS by large-sized companies and public interest organisations such as listed entities, banks and insurance entities from accounting periods beginning on or after 1st April 2011. However, keeping in view the changed circumstances and to address issues being faced in implementation of the decision of convergence, the road map is being reconsidered for suitable modifications.

For implementation of the decision on convergence with IFRS, the ASB constituted a Group to carry out various functions for a smooth transition to IFRS from 2011. This Group further constituted four Sub-Groups for (a) preparing the work plan of ASB and liaising with the IASB; (b) approaching the government and regulatory authorities; (c) liaising with the industry associations; and (d) providing education and training on IFRS so that the accountants are ready for convergence.

The Sub-Group for Approaching the Government and Regulatory Authorities was constituted with the objective of identifying the conflicting legal and regulatory requirements arising out of convergence with IFRS and approaching the relevant authorities to change various laws and regulations, where appropriate. This Sub-Group further constituted Core Groups for identifying the issues relating to adoption of IFRS for Companies Act, SEBI Rules and Regulations; apart from the issues concerning insurance entities, banks and other financial institutions. In this regard changes required in the Companies Act have already been identified and sent to the Ministry of Corporate Affairs, Government of India. The Government is expected to amend the Act shortly. Changes required in other laws, such as, Banking laws regulations, Insurance laws and regularities, SEBI Rules and Regulations are being finalised.

The Sub-Group for Liaising with Industry Associations was constituted with the objective of seeking their co-operation in making the industry ready for adoption of IFRS after obtaining industry-specific views on implementation of IFRS. In this regard, the Sub-Group has held meetings with representatives of various industries associations in association with the ASB. All associations are supporting the convergence with IFRS.

The Sub-Group on Education and Training was constituted with the objective of looking into the requirements for providing training to preparers, auditors and other accounting professionals. In this regard, a Certificate Course on IFRS has been launched. In terms of this initiative Chain-Workshops on Indian Accounting Standards converged with IFRSs was inaugurated by Shri R. Bandyopadhyay, Secretary, Ministry of Corporate Affairs at New Delhi on 29th April, 2010, under which two types of Training Workshops are being planned to be conducted at the 58 locations i.e. Two Days Training Workshops and One Day Training Workshops.

Despite of the aforesaid, total of 26 batches were conducted on the Certification Course on IFRS during the period starting from April 1, 2009 to March 31, 2010 across the various locations viz: Delhi(6), Mumbai(6), Bangalore(3); Pune (1); Hyderabad(2); Kolkata(2); Chennai(2); Dehradun (1); PFC(1) at Delhi; Jaipur(1); Ahmedabad(1). During the said period the examination for the certification Course on IFRS was conducted four times, in which out of 620 candidates who appeared 510 were declared pass.

The ICAI is having the target of finalising the Indian-equivalent standards that correspond to all the IAS/IFRS issued by the IASB by the end of August, 2010. As of May 31, 2010 the Accounting Standards Board of the Institute had placed Exposure Drafts of all Accounting Standards converged with IFRS on its web-site for public comments. To achieve this onerous task, the Accounting Standards Board held 9 meetings upto June 20, 2010 since middle of February 2010, at which the Drafts received from various Study Groups set up by the Board were considered and finalized as Exposure Drafts. During this period, the Board finalised 31 Exposure Drafts, while the remaining drafts were finalized before February 2010.

A brief overview of other activities of the Accounting Standards Board during the period under report is as follows:

5.1.1 Contribution to the Activities of the International Accounting Standards Board (IASB) and Participation in Other International Developments

The Board interacts with the IASB at various levels, such as:

- Active participation in the meetings of the World Standard-Setters with IASB, other National Standard Setters and Regional Standard-Setters with the IASB.
- The Board circulated and hosted on the website, various Exposure Drafts/Discussion Papers issued by the IASB for comments by various stakeholders.
- To play a more influential role pending convergence with the IFRS, the Board constitutes from time to time Study Groups to analyse Discussion Papers or Exposure Drafts issued by the IASB. After analysis, the Groups send their comments listing the India-specific concerns, which are reviewed by the ASB prior to its submission to the IASB.

5.1.2 Interaction with Regulatory Bodies

Being the premier accounting body, the ICAI, through ASB, interacts with various regulatory bodies from time to time and expresses its views on various accounting matters.

In addition to the above, regular meetings are held with MCA on various accounting issues.

5.1.3 Other Projects

Comments on the following IASB Exposure Drafts/Discussion Papers were sent to the IASB:

- Exposure Draft on Financial Instruments: Classification and Measurement
- Request for Information ('Expected Loss Model') Impairment of Financial Assets: Expected Cash Flow Approach
- Discussion paper on Credit Risk in Liability Measurement
- Exposure Draft on Classification of Rights Issues

Given below is the resume of the important activities of the Accounting Standards Board:

5.1.4 Standards cleared by Council

36 Standards, which included AS 1 corresponding to IAS 1, *Presentation of Financial Statements*, AS 12 corresponding to IAS 20, *Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance*, AS 18 corresponding to IAS 24, *Related Party Disclosures*, AS 24 corresponding to IFRS 15, *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*, AS 30 corresponding to IAS 39, *Financial Instruments: Recognition*

and Measurement, AS 36 corresponding to IAS 26, *Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans*, have been cleared by the Council.

5.1.5 Exposure Drafts issued

- AS 39 corresponding to IFRS 4, *Insurance Contracts*
- AS 41 corresponding to IFRS 1, *First Time Adoption of International Financial Reporting Standards*

As per the roadmap to Convergence laid down by the Ministry of Corporate Affairs, Small and Medium Companies (SMCs) will not require to follow the notified Accounting Standards which are converged with the IFRS (through they may voluntarily opt to do so) but need to follow only the notified Accounting Standards which are not converged with the IFRS.

5.2 Committee on Accounting Standards for Local Bodies

The Institute of Chartered Accountants of India constituted a Committee on Accounting Standards for Local Bodies in the year 2005 to formulate the Accounting Standards for Local Bodies. The Committee has been established with the primary responsibility to conceive and suggest areas in which Accounting Standards for Local Bodies (ASLBs) need to be developed, formulate ASLBs, integrate the ASLBs to the extent possible, with the International Public Sector Accounting Standards issued by the International Public Sector Accounting Standards Board, provide implementation guidance on ASLBs, review and revise the ASLBs, assist Local Bodies in adoption of accrual system of accounting, and propagate the ASLBs among the stakeholders in preparation and presentation of financial statements.

The ASLBs formulated by the CSALB are sent to the Technical Committees on Budget and Accounting Standards for Local Bodies for ULBs and PRIs constituted by the Ministry of Urban Development and Ministry of Panchayati Raj respectively, for recommending the same for implementation by the State Governments concerned.

Since its inception, the Committee has issued four Accounting Standards for Local Bodies (ASLBs) viz. Accounting Standard for Local Bodies (ASLB) 3, *'Revenue from Exchange Transactions'*, Accounting Standard for Local Bodies (ASLB) 4, *'Borrowing Cost'*, Accounting Standard for Local Bodies (ASLB) 5, *'Property, Plant & Equipment'*, Accounting Standard for Local Bodies (ASLB) 6, *'Event After the Reporting Date'*. Other publications of the Committee include *'Preface to the Accounting Standards for Local Bodies'*, English and Hindi version of booklet on *'Accrual Accounting for Local Bodies: Elected Representatives and Stakeholders'* and Status Paper on *'Accounting Reforms in Local Bodies in India and Role of Chartered Accountants'*.

'Preface to the Accounting Standards for Local Bodies' sets out the objectives and operating procedures of the Committee on Accounting Standards for Local Bodies and explains the scope and authority of the Accounting Standards for Local Bodies.

The booklet titled *'Accrual Accounting for Local Bodies: Elected Representatives & Stakeholders'* seeks to provide introductory information to the elected representatives and stakeholders about the accrual accounting benefits for the Local Bodies. It brings out the distinguishing features of the two systems of accounting: the traditional cash accounting system and modern accrual accounting system, and the manner in which they impact income, expenses, assets and liabilities of a local body. Some misconceptions about accrual accounting have also been clarified, to reduce the perceived information gap about the system and its use. The Committee has brought out the Hindi version of this booklet during the period to enhance the usefulness of the same for the elected representatives.

The Committee has brought out the Status Paper on *'Accounting Reforms in Local Bodies in India and Role of Chartered Accountants'* during the period which incorporates the status of

adoption of accounting reforms in the Local Bodies in India. This status paper also chalks out the role that Chartered Accountants can play in implementation of the accounting reforms in Local Bodies.

Apart from above, various projects undertaken by the CASLB during the last and previous years for preparation of Accounting Standards for Local Bodies (ASLBs) corresponding to International Public Sector Accounting Standards are in progress.

The ICAI is a member of the Government Accounting Standards Advisory Board (GASAB) and is also represented on its various Sub-Committees constituted from time to time by GASAB. The representatives of the ICAI participate in the meetings of GASAB and contribute to the technical activities of the Board. During the period, the CASLB jointly with the Committee on Government Accounting (which has been merged with and a rechristened Committee, viz Committee on Public Finance and Government Accounting, constituted for the year 2010-2011), submitted comments on GASAB's Exposure drafts of the IGFRS on '*Property Plant & Equipment*', for the consideration of the GASAB.

The important activities under taken by the Committee during the period are as under

5.2.1 Accounting Standards for Local Bodies (ASLB)s issued during the period:

- Accounting Standard for Local Bodies (ASLB) 5, '*Property Plant & Equipment*'.
- Accounting Standard for Local Bodies (ASLB) 6, '*Events after the Reporting Date*'.

5.2.2 Other publications issued during the period:

- Hindi version of the Booklet on '*Accrual Accounting for Local Bodies: Elected Representatives & Stakeholders*'.
- Status Paper on '*Accounting Reforms in Local Bodies and Role of Chartered Accountants*'.

5.2.3 Drafts of proposed ASLBs being finalised by the Committee for circulation among the Institute's Council Members and Specified Outside Bodies for comments:

- Proposed Accounting Standard for Local Bodies (ASLB) on '*Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*'
- Proposed Accounting Standard for Local Bodies on '*Presentation of Financial Statements*'
- Proposed Accounting Standard for Local Bodies on '*Revenue from Non-Exchange Transactions*'
- Proposed Accounting Standard for Local Bodies on '*Construction Contracts*'
- Proposed Accounting Standard for local Bodies (ASLB) on '*Segment Reporting*'

5.2.4 Drafts of proposed ASLBs which are under preparation by various Study Groups:

- Cash Flow Statements
- Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
- Inventories
- The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

5.2.5 Other Projects:

- Translation of the Booklet Highlighting the Benefits of Accrual Accounting into various regional languages.
- Formulation of Comments on the Exposure Draft of proposed IPSAS on '*Service Concession Arrangements: Grantor*'.

5.3 Audit Committee

In the year 2001, the ICAI had constituted Central Audit Committee for the first time as a non-standing Committee to overview the Institute's reporting process and disclosure of its financial information as also the adequacy of internal control systems, as well as to ensure the independence and integrity of auditors at the Decentralized Offices and Head Office of the Institute.

Since its inception, the Committee is continuously striving to further improve the reporting process of the Institute and to bring in greater transparency in the working of the Institute, as also to making the internal controls more stringent. The Committee is also striving to bring about more transparency in the appointment of auditors and providing them with a more comprehensive scope of audit while at the same time giving them more independence in their work. The Committee holds regular interaction with the auditors as well as with the auditee Departments / Committees / Regional Councils / Decentralized Offices / Branches / Overseas Offices so that the lacunae / weaknesses, if any, pointed out by the auditors can be mitigated. During the year 2009-2010, the initiatives taken by the Committee included the following :

- Appointment of Internal Auditors of Branches having membership strength of more than 1000 members
- Appointment of Internal Auditors at all newly formed DCOs
- Strengthening of the Internal Control mechanism
- Implementation of System audit of all Information Technology Training centres

5.4 Auditing and Assurance Standards Board

Audit serves a vital economic purpose and plays an important role in serving and protecting the public interest by strengthening accountability and reinforcing trust and confidence in financial reporting. Audit helps enhancing the economic prosperity, expanding the variety, number and value of transactions that people enter into. However, in the recent years, due to the growing complexity of the business environment and business models and their geographical spread the auditing profession witnessing a quantum leap in the expectations from the profession.

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) too recognizes the pressing need to respond to these expectations proactively. The Institute through its dedicated Board (Auditing and Assurance Standards Board) formulates high quality standards on auditing, review, other assurance, quality control and related services. It also develops Guidance Notes on generic as well as industry specific issues in auditing. These documents, after a rigorous due process, are issued under the authority of the Council of the Institute. The Standards issued by the Institute are harmonized with the International Standards on Auditing. The latter are recognized for their high quality and have a global acceptance. Further, the Board also formulates Technical Guides, Practice Manuals, Studies and Other Papers under its own authority for the guidance of the members. To provide guidance in implementation of Standards on Auditing (SAs), the Board is also bringing out Implementation Guide to the Standards issued under the Clarity Project. Since 2007, the Board has been closely following the developments in the ISAs arising out of the IAASB's Clarity Project. In fact in January, 2010, ICAI completed substantial convergence with ISAs. The following is a comprehensive overview of the important achievements of the Board till date:

Engagement & Quality Control Standards

Quality Control Standards

- ♦ Standard on Quality Control (SQC) 1, "Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements".

Engagement Standards

- ♦ 37 Standards on Auditing, including 35 Standards under the Clarity Project, Glossary of Terms and 1 General Clarifications issued. The Standards issued related to General Principles and Responsibilities, Risk Assessment and Response to Assessed Risks, Audit Evidence, Using work of others, Audit Conclusions and Reporting and Specialized Areas. The General Clarifications issued are on Review Engagements, Assurance Engagements and Related Services.

Statements on Auditing and Guidance Notes

2 Statements on Reporting under Section 227(1A) of the Companies Act, 1956 and on Companies (Auditor's Report) Order 2003 (Revised 2005 Edition); and 28 Guidance Notes on matters including Proposed Dividend, Accounts of Liquidators, Independence of Auditors (Revised), Duty Cast on the Auditors under Section 45 MA of the Reserve Bank of India Act, 1934, and on Audit of Fixed Assets, Inventories, Investment, Liability, Revenue and of Capital and Reserves, were issued.

Industry Specific Guidance Notes

- ♦ Audit of Banks (Revised 2009 edition)
- ♦ Audit of Accounts of Members of Stock Exchanges
- ♦ Audit of Companies Carrying on General Insurance Business
- ♦ Audit of Companies Carrying on Life Insurance Business

Other Publications (Non – authoritative)

Implementation Guides

- ♦ Implementation Guide to SQC 1
- ♦ Implementation Guide to Risk-based Audit of Financial Statements

Technical Guides

- ♦ Technical Guide on Audit in Telecom Industry – Revenue, Fixed Assets and Related Operating Costs
- ♦ Technical Guide on E-Commerce- Considerations for Audit of Financial Statements

Studies

- ♦ A Study on Money Laundering: An Accountant's Perspective
- ♦ A Study on Basel II and Risk-based Supervision

Other Important Publications (Non – authoritative)

- ♦ Training Manual on Engagement and Quality Control Standards
- ♦ Practitioner's Guide to Audit of Small Entities
- ♦ Revised version - What is an Audit – Understanding an Audit of Financial Statements.
- ♦ Issues on the Companies (Auditor's Report) Order, 2003

5.4.1 The Year 2009-10

During the year 2009-10, six meetings of the Auditing and Assurance Standards Board totaling 9 days of full Board deliberations were held. During this year, the main focus of the Board was to complete Convergence with the International Standards on Auditing (ISAs)

issued by IAASB under the Clarity Project, as the Board had, at the beginning of the year, committed April 1, 2010 for the completion of the convergence process. The Board began its year with 16 new/revised Standards on Auditing under the Clarity Project in hand. During the year, the Board issued 19 new/revised Standards on Auditing, taking the tally of the new/revised Standards to 35 as against the 36 new/revised ISAs issued by IAASB. With this, the Board almost completed its convergence with ISAs except SA 600 in March, 2010. The brief description of the new/Revised SAs issued during the year is as follow:

Revised SA 200, "Overall Objectives of the Independent Auditor, and the Conduct of an Audit in Accordance with Standards on Auditing"

SA 200 (Revised) is a mother standard for all other Standards on Auditing issued by the Institute. The concepts covered by erstwhile SA 200 (AAS 1), "*Basic Principles Governing an Audit*", issued in April, 1985 and SA 200A (AAS 2), "*Objective and Scope of the audit of Financial Statements*" issued in 1985 have been merged into one Standard, i.e., SA 200 (Revised). The revised Standard establishes the independent auditor's overall responsibilities when conducting an audit of financial statements in accordance with SAs. Specifically, it sets out the overall objectives of the independent auditor, and explains the nature and scope of an audit designed to enable the independent auditor to meet those objectives. It also explains the scope, authority and structure of the SAs, and includes requirements establishing the general responsibilities of the independent auditor applicable in all audits, including the obligation to comply with the SAs. Revised SA 200 also provides the essential requirements to be kept in mind by the auditor while doing an audit of an entity, such as, compliance with the ethical requirements relating to an audit of financial statements, professional skepticism, professional judgment, sufficient appropriate audit evidence and audit risk, and conduct of an audit in accordance with SAs. This SA is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2010.

Revised SA 210, "Agreeing the Terms of Audit Engagements"

SA 210 is a revised version of the erstwhile Auditing and Assurance Standard (AAS) 26, *Terms of Audit Engagements*, issued by the Institute in 2003. The new Standard deals with the auditor's responsibilities in agreeing the terms of the audit engagement with management and, where appropriate, those charged with governance that includes establishing that certain preconditions for an audit, responsibility for which rests with management and, where appropriate, those charged with governance, are present. The Standards further elaborates on the aspects such as acceptability of the financial reporting framework, auditor's responsibilities in case auditor's report format is prescribed by laws or regulations, etc. Revised SA 210 also provides the illustrative format of the audit engagement letter. This SA is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2010.

Revised SA 220, "Quality Control for an Audit of Financial Statements"

SA 220 is a revised version of the erstwhile SA 220 (AAS 17), "*Quality Control for Audit Work*", issued by the Institute in 1999. Whereas SQC 1 issued by Institute in March, 2008 is to be applied at the firm level, this SA is to be applied at an engagement level. This SA also presumes that the firm is applying SQC 1. This Standard deals with the specific responsibilities of the auditor regarding quality control procedures for an audit of financial statements. It also addresses, where applicable, the responsibilities of the engagement

quality control reviewer. It also provides the guidance on the aspects, such as, leadership responsibilities for quality on audits, relevant ethical requirements, acceptance and continuance of client relationships and audit engagement, assignment of engagement teams, engagement performance, monitoring and documentation requirements. This SA is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2010.

SA 265, "Communicating Deficiencies in Internal Control to Those Charged with Governance and Management"

Auditor's objective under this SA is to communicate appropriately to those charged with governance and management deficiencies in internal control that the auditor has identified during an audit and in the auditor's professional judgment, needs attention of the those charged with governance and the management. Though the aspects relating to communication of audit matters have been covered by Revised Standard on Auditing (SA) 260, Communication with Those Charged with Governance, this Standard specifically deals with the auditor's responsibility to communicate appropriately to those charged with governance and management deficiencies in internal control that the auditor has identified in an audit of financial statements. This Standard is effective for audits of all financial statements for periods beginning on or after April 1, 2010.

Revised SA 450, "Evaluation of Misstatements Identified during the Audit"

Although there is no separate Standard on Auditing corresponding to SA 450, "Evaluation of Misstatement Identified During the Audit", the some concepts of SA 450 has been covered by the erstwhile AAS 13, *Audit Materiality* issued in January, 1997. This SA deals with the auditor's responsibilities to evaluate the effect of misstatements identified during the audit or uncorrected misstatements, if any, on the financial statements and its link with SA 320, which deals with the auditor's responsibilities to apply the concept of materiality in planning and performing an audit of financial statements. This Standard is effective for audits of all financial statements for periods beginning on or after April 1, 2010.

Revised SA 501, "Audit Evidence – Specific Considerations for Selected Items"

SA 501 is a revised version of the erstwhile SA 501 (AAS 34), "Audit Evidence – Additional Considerations for Specific Items", issued by the Institute in 2005. The revised Standard deals with specific considerations by the auditor in obtaining sufficient appropriate audit evidence in accordance with SA 330, SA 500 (Revised) and other relevant SAs, with respect to certain aspects of inventory, litigation and claims involving the entity, and segment information in an audit of financial statements. Revised SA 501 also provides the detailed procedures for obtaining audit evidence in the case of inventory, litigation and claims, and segment information. This SA is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2010.

Revised SA 505, "External Confirmations"

SA 505 is a revised version of the erstwhile SA 505 (AAS 30), "External Confirmations", issued by the Institute in August 2003. The revised Standard deals with the auditor's use of external confirmation procedures to obtain audit evidence in accordance with the requirements of SA 330 and SA 500 (Revised). It also provides the procedures for obtaining the audit evidence through external confirmations. It also provides the procedures to be followed by an auditor in certain cases, such as, management's refuses to allow the auditor

to send a confirmation request, non-responses to the external confirmations, results of the external confirmation procedures, negative confirmations. This SA is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2010.

Revised SA 520, "Analytical Procedures"

SA 520 is a revised version of the erstwhile SA 520 (AAS 14), "Analytical Procedures", issued by the Institute in December, 1997. It deals with the auditor's use of analytical procedures as substantive procedures ("substantive analytical procedures"), and as procedures near the end of the audit that assist the auditor when forming an overall conclusion on the financial statements. It also provides the detailed requirements relating to suitability, reliability of the substantive analytical procedures, analytical procedures to be followed in assisting forming an overall conclusion, and investigating the results of analytical procedures. This SA is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2010.

Revised SA 620, "Using the Work of an Auditor's Expert"

SA 620 is a revised version of the erstwhile SA 620 (AAS 9), "Using the Work of An Expert", issued by the Institute in December, 1991. The revised Standard deals with the auditor's responsibilities regarding the use of an individual or organisation's work in a field of expertise other than accounting or auditing, when that work is used to assist the auditor in obtaining sufficient appropriate audit evidence. It also provides the procedures to be followed by an auditor when decided to use the work of an external expert. It also provides the illustrative matters to be included in the agreement between the auditor and the external expert. This SA is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2010.

Revised SA 700, "Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements"

SA 700 is a revised version of the erstwhile SA 700 (AAS 28), "The Auditor's Report on Financial Statements", issued by the Institute in March, 2003. Whereas erstwhile SA 700 (AAS 28) deals with unmodified, modified and Emphasis of Matter paragraph, revised SA 700 deals only with the unmodified opinion on the general purpose financial statements. It deals with the auditor's responsibilities to form an opinion on the financial statements and the form and content of the auditor's report issued as a result of an audit of financial statements. It also provides the procedures to be followed by an auditor in forming an opinion on the financial statements. It also provides the form and essential contents of the auditor's report required to be given in any kind of auditor's report on the general purposes financial statements. It also provides the illustrative formats of the auditors' reports on financial statements. This SA is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2011.

SA 705, "Modifications to the Opinion in the Independent Auditor's Report"

Although there is no separate Standard on Auditing corresponding to SA 705, the aspects relating to modified opinion on the general purpose financial statements have been covered by the erstwhile SA 700 (AAS 28), "The Auditor's Report on Financial Statements", issued by the Institute in March, 2003. SA 705 deals with the auditor's responsibility to issue an appropriate report in circumstances when, in forming an opinion in accordance with SA 700 (Revised), the auditor concludes that a modification to the auditor's opinion on the financial

statements is necessary. It also provides the circumstances when a modification to the auditor's opinion is required, the type of modification to the auditor's opinion to be given by an auditor, form and content of the auditor's report when the opinion is modified. It also contains the illustrative formats of auditors' reports with modifications to the opinion. This SA is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2011.

SA 706, "Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the Independent Auditor's Report"

Although there is no separate Standard on Auditing corresponding to SA 705, the aspects relating to emphasis of matter paragraph on the general purpose financial statements have been covered by the erstwhile SA 700 (AAS 28), "The Auditor's Report on Financial Statements", issued by the Institute in March, 2003. SA 706 which deals with additional communication in the auditor's report when the auditor considers it necessary to provide emphasis of matter paragraph or other matter paragraph in the auditor's report. It also contains the illustrative formats of an auditor's report that includes an emphasis of matter paragraph/other matter paragraph. This SA is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2011.

Revised SA 710, "Comparative Information - Corresponding Figures and Comparative Financial Statements"

SA 710 is a revised version of the erstwhile SA 710 (AAS 25), "Comparatives", issued by the Institute in September, 2002. The revised Standard deals with the auditor's responsibilities regarding comparative information in an audit of financial statements. In accordance with this SA, there are two approaches for the comparative information, first, Corresponding Figures, and second, Comparative Information. It also provides the detailed procedures to be followed an auditor regarding these two approaches. It also contains the examples of the auditor's Report. This SA is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2011.

SA 800, "Special Considerations - Audits of Financial Statements Prepared in Accordance with Special Purpose Frameworks"

SA 800 is a new Standard on Auditing which deals with special considerations in the application of those SAs to an audit of financial statements prepared in accordance with a special purpose framework. Whereas 700 series is to be applied in case of reporting under the general purpose financial statements, 800 series to be applied in case of reporting under special purpose financial statements. It also provides the considerations to be kept in mind by an auditor, such as relating to, acceptability of financial reporting framework, planning and performing the audit, forming an opinion and reporting, applicability of financial reporting framework. It also contains the illustrative formats of the auditors' Reports on special purpose financial statements. This SA is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2011.

SA 805, "Special Considerations – Audits of Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or Items of a Financial Statement"

SA 805 is a new Standard on Auditing which deals with special considerations in the application of those SAs to an audit of a single financial statement or of a specific element, account or item of a financial statement. It also provides the considerations to be kept in

mind by an auditor, such as relating to, acceptance of the engagement, planning and performing the audit, forming an opinion and reporting. It also provides the examples of specific elements, accounts or items of a financial statement. It also contains the illustrative formats of the auditors' reports on a single financial statement and on a specific element of a financial statement. This SA is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2011.

SA 810, "Engagements to Report on Summary Financial Statements"

SA 810 is a new Standard on Auditing which deals with the auditor's responsibilities when undertaking an engagement to report on summary financial statements derived from financial statements audited in accordance with SAs. It covers aspects, such as, engagement acceptance, nature of procedures, form of opinion, timing of work and events subsequent to the date of the auditor's report on the audited financial statements, auditor's report on summary financial statements, restriction on distribution or use or alerting readers to the basis of accounting, comparatives, unaudited supplementary information presented with summary financial statements, other information in documents containing summary financial statement and auditor association. It also contains the illustrative formats of reports on summary financial statements. This SA is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2011.

In addition to the above, the Board has also issued the following new/Revised Standards on Review Engagements (SREs):

SRE 2400 (Revised), "Engagements to Review Financial Statements"

SRE 2400 is a revised version of the erstwhile SRE 2400 (AAS 33), "Engagements to Review Financial Statements", issued by the Institute in January, 2005. The purpose of this revised Standard is to establish standards and provide guidance on the practitioner's professional responsibilities when a practitioner, who is not the auditor of an entity, undertakes an engagement to review financial statements and on the form and content of the report that the practitioner issues in connection with such a review. A practitioner, who is the auditor of the entity, engaged to perform a review of interim financial information performs such a review in accordance with SRE 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity". It covers the aspects, such as, general principles of a review engagement, scope of a review, moderate assurance, terms of engagement, planning, work performed by others, documentation, procedures and evidence, and Conclusions and Reporting. It also contains the specimen of an engagement letter for a review of financial statements, illustrative detailed procedures that may be performed in an engagement to review financial statements, form of unqualified review report, and examples of review reports other than unqualified. This SRE is effective for reviews of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2010.

SRE 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity"

SRE 2410 is a new Standard the purpose of which is to establish standards and provide guidance on the auditor's professional responsibilities when the auditor undertakes an engagement to review interim financial information of an audit client, and on the form and content of the report. Unlike an audit, a review engagement is based mainly on analytical procedures and inquiries conducted by the auditor. The quarterly un-audited financial results of companies listed on stock exchanges in India are subject to limited review by the

chartered accountants. The SRE on Engagements to Review Financial Statements provides extensive guidance on the types of such procedures and enquiries to be employed by the auditors. It also covers the aspects, such as, general principles of a review of interim financial information, objective of an engagement to review interim financial information, agreeing the terms of the engagement, procedures for a review of interim financial information, evaluation of misstatements, management representations, auditor's responsibility for accompanying information, communication, reporting the nature, extent and results of the review of interim financial information and documentation. It also contains the example of an engagement letter for a review of interim financial information, analytical procedures the auditor may consider when performing a review of interim financial information, example of a management representation letter, illustrative formats of the review reports on interim financial information to be given in different circumstances. This SRE is effective for reviews of interim financial information for periods beginning on or after April 1, 2010.

5.4.2 Exposure Drafts

The Board also issued the Exposure Drafts of the Standard on Assurance Engagements (SAE) 3000, "*Assurance Engagements Other than Audits and Reviews of Historical Financial Information*" for public comments. The proposed SAE 3000 and the issues related thereto are under consideration of the Board.

5.4.3 Other Technical Literature

The Board issued the following other technical literature during the year:

Handbook of Auditing Pronouncements (2009 Edition)

- Authoritative text of auditing pronouncements as on July 1, 2009.
- Availability of technical literature on auditing at one place.
- One stop reference for members as well as all professionals and academicians.
- Two distinct volumes one, for Standards and Statements and another for Guidance Notes.
- Contents of both volumes given in each volume for cross reference.
- Accompanied with CD.

Volume I—Compendium of Standards and Statements

- ♦ Compendium of Statements on Auditing and containing the text of all the Engagement and Quality Control Standards.
- ♦ Contents of each Standard and Statement given at the beginning for quick reference and overview.
- ♦ Contains the text of the nine (9) revised/ new Standards on Auditing (SAs) issued under the Clarity Project, which are effective for audits of financial statements for period: beginning on or after April 1, 2009. The text of the corresponding SAs has also been kept for the ease of reference.
- ♦ Also contains the text of nine (9) revised/ new Standards on Auditing (SAs) issued under the Clarity Project, which are effective for audits of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2010. The text of the corresponding SAs has also been kept for the ease of reference.
- ♦ Status of AASB's Standards *vis-à-vis* IAASB's Standards issued under the Clarity Project - As on July 1, 2009.

Volume II—Compendium of Guidance Notes

- ◆ Contains the text of 31 Guidance Notes on auditing aspects.
- ◆ Contents of each Guidance Note given at the beginning for quick reference and overview.

Training Manual on Engagement and Quality Control Standards (2009 Edition)

- Prime objective of the training manual is to serve as a background material for training programmes on auditing standards.
- Gives extensive but simple reading material on auditing standards.
- Re-numbering and Re-classification of all the auditing standards as per the revised Preface.
- Includes presentation on the revised/new issued SAs under the Clarity Project and effective from April 1, 2008 or April 1, 2009.
- Divided into five parts:
 - ◆ *Introduction* - gives a brief insight to the readers in to the history and nature of auditing, importance of auditing standards, framework for assurance engagements, etc.
 - ◆ *Presentations* - contain snap shots of the fundamental principles contained in the auditing standards along with some notes.
 - ◆ Documentation Requirements in the SAs.
 - ◆ Case Studies and Technical Posers.
 - ◆ Text of the revised/ newly issued Standards on Auditing under the Clarity Project, effective for audits of financial statements for periods beginning on or after April 1, 2010.
- Accompanied with CD.

5.4.4 Projects under progress

In addition to these, the Board, during the year also undertook several other projects relating, among others, to Engagement and Quality Control Standards, Implementation Guides, and Technical Guides – including Industry Specific ones.

5.4.5 Other Initiatives and Development**➤ Interaction with Regulatory Bodies**

The Board, from time to time, interacts with the regulators and other Government institutions such as, Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), Ministry of Corporate Affairs (MCA), Insurance Regulatory Development Authority (IRDA) Comptroller and Auditor General of India (C&AG), etc., to discuss the critical issues relating to auditing standards and other aspects relating to auditing.

➤ Contribution to the IAASB Activities and Responding to International Developments

The Institute is actively involved in the developments made at international level. Being the founder member of the International Federation of Accountants (IFAC), the Board, through the Chairman, remained in touch with the National Standards Setters Committee of the International Auditing and Assurance Standards Board and provided its inputs to that Committee at its meeting. At the IAASB NSS meeting held on June 3-4 at Dublin, the Institute was represented by the Chairman, AASB and Secretary, AASB.

➤ ***Creating Awareness and Capacity Building***

Creating awareness amongst the members on auditing standards is one of the main agenda for the Board during the year 2009-10. In this process, to facilitate one to one interaction with the members on issues faced by them in auditing and also to impart knowledge on the latest auditing standards being issued by the Institute, the Board also organised five seminars/training program/conferences on auditing standards and other aspects relating to auditing at Indore, Hyderabad, Visakhapatnam, Chennai and New Delhi. Further, the Board is also planning to revise its existing two publications, "What is an Audit-Understanding an Audit of Financial Statements" and "Training manual on Engagement and Quality Control Standards".

➤ **Future Strategy and Work Program**

As the Auditing and Assurance Standards Board (AASB) has completed its Clarity Project in March, 2010, the Board will focus on to create awareness about the new/revised Standards on Auditing (SAs) issued under the Clarity Project. For this purpose, the Board will adopt two prong strategies. It will organise seminars/conferences/training programs for members and regulators, and will issue implementation guides to new/revised SAs so as to help the members to better understand and implement the Standards. The Board will also bring out other auditing literature to guide the members on the contemporary issues relating to auditing, generally as well as in specific industry sectors.

5.5 Committee on Banking, Insurance & Pension

The Committee on Insurance & Pension has been rechristened as Committee on Banking, Insurance and Pension. The terms of reference of the Committee, inter alia, include Research, Dialogue, Inputs in policy formulation, Knowledge dissemination and alike to ultimately provide for competency building in areas of Banking, Insurance & Pension. The Committee also conducts a Post Qualification Course in Insurance and Risk Management.

5.5.1 Developing Professional Opportunities for CAs with DIRM Qualification

- The IRDA, vide its Circular dated 4th August 2009, has mandated insurers to have their Investment Systems and Process audited by Chartered Accountant firms once in three years and their Investment transactions audited through Internal Audit on a Quarterly basis or for Insurers with Assets Under Management over ` 1,000 Crores, through Concurrent Audit by Chartered Accountant firms. The Committee in consultation with the IRDA has brought out the 'Technical Guide on Internal/ Concurrent Audit of Investment Functions of Insurance Companies' for providing necessary technical guidance to the members of the Institute and others concerned.
- DIRM marketing letters were sent to the CMD of various insurance companies with a request to utilize the services of DIRM qualified Chartered Accountants.

5.5.2 Training and equipping members in insurance and pension sectors by way of a Post Qualification Course i.e. Diploma in Insurance and Risk Management (DIRM)

- The Committee conducts Orientation Programmes for the DIRM Technical Examination passed members of the Institute to enable them to complete the last phase of the DIRM Course to be eligible for award of the Diploma in Insurance and Risk Management, at the various parts of the country.
- Suggested Answers to the DIRM Technical Examination held in June, 2009 and November, 2009 were prepared and hosted on the website www.icai.org for the benefit of the DIRM Course pursuing members. With this, suggested Answers to DIRM Technical Examinations held upto November, 2009 have been hosted at the hyperlink http://www.icai.org/post.html?post_id=2432.
- To popularize the DIRM course amongst the members, the Committee is consistently making efforts and taking up appropriate measures. As a result, the numbers of registrations have reached upto 3707 till March 31, 2010. The region-wise break up is as under:

Region	Registrations	Percentage
Central	774	21
Eastern	410	11
Northern	543	15
Southern	1175	31
Western	805	22

- Online facility for the payment of Registration Fee to the Post Qualification Course on Diploma in Insurance and Risk Management (DIRM) has been activated at the website www.icai.org.

5.5.3 Updates on Banking, Insurance and Pension Sectors

Daily news updates on Banking, insurance and pension sectors are hosted at our website www.icai.org on daily basis (except Saturday, Sunday and Gazetted Holidays) for dissemination of knowledge and awareness of the sectors amongst the members of the Institute.

5.5.4 Capacity Building for the Members of the Institute in the Banking, Insurance, Risk Management and Pension Sectors by way of various modes:

Publications

The Committee brings out publications on the contemporary topics in insurance, pension and risk management to develop and maintain the core competencies of the members in these areas. The following publications were released by the Committee during the period under report :

- Technical Guide on Internal/Concurrent Audit of Investment Functions of Insurance Companies
- Micro Insurance
- Motor Third Party Claim Management

Programmes on Insurance and Pension Sectors conducted by the Committee

- Recognizing the need of conducting interactive and intensive programmes for members of the Institute and others concerned on the Technical Guide on Review and Certification of Investment Risk Management Systems and Processes of Insurance Companies and Technical Guide on Internal/ Concurrent Audit of Investment Functions of Insurance Companies, the Committee had conducted three Workshops on Internal/Concurrent Audit of Investment Functions of Insurance Companies, jointly with IRDA, at Mumbai, Kolkata and Chennai on 12th October, 2009, 28th November, 2009 and 14th December, 2009 respectively which were well attended by the senior officials of IRDA and insurance companies besides the members of the Institute.
- **A National CPE workshop on 'Emerging Professional Opportunities for Chartered Accountants in Insurance Sector'** was organized on 27th August, 2009 at Chennai and the same was attended by 280 members of the Institute.
- A Meeting of the Senior Officials (CFOs/CMDs/CEOs) of insurance companies was organised on 12th October, 2009 at Mumbai to discuss and deliberate on the emerging issues in the industry comprising concerns of the industry on GST, challenges in implementation of IFRS in the insurance industry and impact of Direct Taxes Code on the insurance industry.
- The Committee had been providing financial, technical support to the Regional Councils and selected Branches of each Regional Council towards conducting programmes on insurance and pension sectors for developing and maintaining domain knowledge by the members and others concerned in these sectors. During the year, the following programmes were organised:

S. No.	Name of the organizing unit	Date & Venue	Topics covered
1.	Gurgaon Branch of SIRC of ICAI	16th May, 2009 at Gurgaon	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Insurance Arbitration ▪ Development in Pension Sector ▪ Insurance Survey and Loss Assessment (Loss of Profit policy) ▪ Emerging insurance market and opportunity for CAs
2.	Jaipur Branch of CIRC of ICAI	18 th July, 2009 at Jaipur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Insurance Survey and Loss Assessment of Insurance claims ▪ Risk Management
3.	Bareilly Branch of CIRC of ICAI	2 nd August, 2009 at Barielly	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Role of CAs in Insurance sector ▪ Insurance Survey & Loss Assessment ▪ Third Party Insurance & Claims Management ▪ Audit of General Insurance

			Companies
4.	Saharanpur Branch of CIRC of ICAI	11 th August, 2009 at Saharanpur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Insurance Survey & Loss Assessment ▪ Recent Developments in Insurance sector and Opportunities for CAs ▪ Recent Developments in Income Tax visa-a-vis insurance sector
5.	Mathura Branch of CIRC of ICAI	13 th August, 2009 at Mathura	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CA's Role in Insurance Sector and Professional Opportunities available for the members ▪ Survey and Loss Assessment of insurance claims with special reference to loss of Profit Policies ▪ Insurance Broking ▪ Anti Money Laundering in Insurance Sector
6.	Ranchi Branch of CIRC of ICAI	23 rd August, 2009 at Ranchi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accounting and Auditing issues of General Insurance Business ▪ Recent Developments in Insurance sector and opportunities for CAs ▪ Insurance Survey & Loss Assessment

5.5.5 Research activities in the areas of Insurance and Pension

- The queries received from the Insurance Companies on Direct Taxation issues are being replied with the technical support of the Committee on Direct Taxes of the Institute.

5.5.6 Technical Support for the Endeavors of the PFRDA

- The Committee has been providing technical support to the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) with the help of an ICAI Technical Group for PFRDA, in the following areas:
 - i. Drafting of accounting norms for Pension Fund Managers.
 - ii. Designing Reporting formats for receiving and evaluating information being collected from Pension Fund Managers.
 - iii. Audit of activities of the fund managers and report on compliance with guidelines and directions issued by the PFRDA/NPS Trust from time to time.
- The Reporting Formats for receiving and evaluating information being collected from Pension Fund Managers were submitted to the PFRDA, in due consultation with Technical Director of ICAI. The PFRDA has accepted the reporting formats and the same have been put on use for collecting information from the Pension Fund Managers.

- The Committee has submitted the Accounting Norms for the Pension Fund Managers to the PFRDA after modification as suggested by the ICAI Technical Group for PFRDA. The PFRDA has conveyed its acceptance and implementation of the accounting norms for Pension Fund Managers.
- The Committee is coordinating with the Auditing and Assurance Standard Board of ICAI for the preparation of the Audit Norms for audit of activities of the fund managers and report on compliance with guidelines and directions issued by the PFRDA/NPS Trust from time to time.
- On considering the proposal of the Committee, the Executive Committee has decided to grant fee exemption to the members of the Institute on the ground of the physical disability to the extent of fifty percent of the registration fee payable to the various Post Qualification Courses of the Institute to facilitate and motivate the members having physical disability to pursue the Course(s) of their choice to acquire industry specific qualification and develop expertise in the relevant field.
- An article on Internal/Concurrent Audit of Investment Functions of Insurance Companies was published in the June, 2010 issue of the CA Journal for the awareness and dissemination of information on the manner of carrying out audit of the investment functions of the insurance companies either internally or concurrently.
- With the support of a Technical Group and in due consultation with Technical Director, ICAI, the Accounting Norms for Pension Fund Managers were prepared and submitted to the PFRDA for its consideration and use.
- The Secretariat of the Committee has compiled opinions of the Expert Advisory Committee (EAC) of the Institute relating to Banking, Insurance and Pension sectors to showcase the peculiarities in accounting and auditing in these sectors. The opinion would be hosted on the website in consultation with the EAC.
- Mandatory attendance in an Orientation Programme of six days duration is marked as completion of the Diploma in Insurance and Risk Management Course whereby the technical examination passed members get an opportunity to interact with the experts of the industry to reinforce their theoretical knowledge with the real life experience. During the year, the Committee conducted four batches of the DIRM Orientation Programmes for the DIRM Technical Examination passed members to enable them to complete the last phase of the DIRM Course to be eligible for award of the Diploma in Insurance and Risk Management as detailed below:

S.No.	Date	Venue
1	May 18-23, 2009	Hotel Broadway, New Delhi
2	October 5-10, 2009	Sir Sorabji Pochkhanawala Bankers' Training College (SPBT), Mumbai
3	May 3-8, 2010	ICAI Information Technology Training Cum Classroom Training Centre, Mumbai
4	May 17-22, 2010	Indian Medical Association (IMA), New Delhi

5.6 Committee for Capacity Building of CA Firms & Small and Medium Practitioners

5.6.1 Overview

The Committee for Capacity Building of CA Firms, reconstituted in February 2010 and known as Committee for Capacity Building of CA Firms and Small & Medium Practitioners is a non-standing Committee of the Institute formed under regulatory provisions of CA Act, 1949. This Committee is established with the objective of facilitating consolidation and capacity building of CA firms in order to address various problems faced by CA firms and to conceptualize and implement various means for strengthening their capacity as well as providing comprehensive guidelines for consolidation of CA firms. Thus the Committee aims at strengthening CA firms as well as Small & Medium Practitioners to rejuvenate their practice portfolio.

The Committee has organized several programmes for making awareness on consolidation of firms through Networking, Merger and setting up corporate form of Practice (MCS Company).

5.6.2 Major activities:

- The Committee reviewed the position of the 35 Networks registered with ICAI by sending Feedback Forms to the 112 firms constituting it and thereby, identified the challenges/bottlenecks being faced by them in the functioning of their Networks.
- The Committee facilitated the identification & interaction amongst interested practicing members for Networking, Mergers etc. through CA Networking Portal www.caconnect.co.in
- The Committee ensured availability of updated comprehensive data of the Networks registered in India, on the website of the Institute for easy accessibility by the end users.
- The Committee constituted a Study Group for Revision of Guidelines on Network, Merger-Demerger and Corporate Form of Practice in order to identify and eliminate the impediments in the existing Guidelines.
- The Committee has brought out a 'Questionnaire' on Capacity Building in the CA Journal, and hosted the same on ICAI website. Feedback is being received from the members and analysis of inputs is being considered.
- The programmes conducted by the Committee included a series of Workshops on Capacity Building of CA Firms.

5.6.3 Other Initiatives of the Committee:

- The Committee jointly with Professional Development Committee of the Institute released e-book on Bank Branch Audit 2009-10 and circulated amongst all CA firms empanelled for bank audit. The book contains complete information and Accounting Standard templates, document for bank branch audit. The book is well appreciated by the members.

- The Committee has launched in an audit tool kit containing software – KDOC and eSecretary circulated to all the members and CA firms free of cost. The software facilitates easy and handy preparation of audit reports with the help of inbuilt readymade Accounting Standard templates enhancing productivity and reducing time in service delivery. This software also helps in managing documents and secretarial practices at CA Firms.
- The Committee has also arranged for Capitaline TP Corporate Database (online version) at a very reasonable cost for all the members helping them to access Company's database in 24x7 mode at their convenience. Use of this database will make transfer pricing easy and comparable. The members have found the same useful in many respect.
- To redress the grievances of SMPs and for removal of their practical difficulties the Committee proposes to organize interactive sessions with partners of CA Firms and to have Brainstorming exercise for exploring new professional avenues. In the series of such programme, next meeting is scheduled to be held in Chennai on 12th July 2010 and at Delhi in August 2010.
- The Committee has come out with FAQs on Networking and Corporate form of practice to facilitate members the benefits of consolidation of CA firms. The FAQs is being made available at the web portal of the Committee.
- To address the professional issues for SMPs, Committee has initiated the process to review limitation on minimum audit fee in terms of undercutting, Guidance Note on Independence restricting a statutory auditor to be internal auditor and regulatory measures covering non-attestation areas of audit profession.
- The Committee is working for the arrangement of financial assistance for SMPs and CA firms through the Nationalized Banks providing special loan scheme at the considerate rate of interest without collateral security for setting up and expansion of their office infrastructure.
- The Committee has also initiated steps for providing group Insurance & Pension benefits for the partners of CA firms taking care of their social security concern. This will motivate continued association of partners with the firm.
- The Committee is endeavouring to regulate SMPs and middle sized CA Firms in reference to the provisions on Networking prescribed by IFAC and other international bodies and to promote them in the direction of LLP, and for mapping of competencies to facilitate them grow bigger making multi-locational presence with brand equity.

5.7 Continuing Professional Education Committee

During the year, the Continuing Professional Education Committee (CPEC) has taken a number of initiatives and significant decisions for effectively organizing the CPE Programmes and also to extend the reach of the CPE Programmes to a larger section of members.

5.7.1 Steps to streamline the CPE Programmes:

The following decisions have been taken to streamline the organization of the CPE Programmes throughout the country:-

- a) As per past practice (if an event is organized jointly by two POU's, that is uploaded by the POU organizing the programme on the CPE Portal), the status quo should be continued and only one of the Study Circles should be permitted to upload the details on the CPE Portal in respect of the programmes organized jointly.
- b) The POU's should maintain the attendance of members in a systematic manner and should upload the attendance data on CPE Portal within 48 hours of the completion of the concerned programme.
- c) Strict monitoring should be done for maintaining an accurate and truthful attendance record.
- d) The POU's should send their valuable suggestions for improving the recording of the attendance and the procedure for conducting the meetings:
- e) The programmes should be conducted in such a way as to cut down the travel time of the members
- f) Study Circles should preferably conduct the programmes within a radius of 2 kilometers of their jurisdiction
- g) Study Circles should conduct only short duration programmes namely half day or maximum one day.
- h) The advisability of introducing biometric attendance may be considered.
- i) The CPE Committee has taken an important decision regarding the tenure of office of Convenor/Deputy Convenor of Study Circles. Accordingly it has been decided that after serving for three years term as a Convenor/Deputy Convenor, a person cannot continue to be the Convenor/Deputy Convenor of the same Study Circle. Further, the procedure for electing Convenor/Deputy Convenor should be on similar lines as followed for electing the office-bearers for the Regional Council/Branches.

5.7.2 Mandatory CPE Requirements for Members:

CPE credit requirements for members of the ICAI for the block of three years (1.1.2008 to 31.12.2010) stood as follows:

- **All the members who are holding Certificate of Practice (except those members who are residing abroad), unless exempted, are required to:**
- (a) Complete at least 90 CPE credit hours in each rolling three-year period of which 60 CPE credit hours should be of structured learning.
 - (b) Complete minimum 20 CPE credit hours of structured learning in each year.

- **All the members who are not holding Certificate of Practice or are residing abroad (whether holding Certificate of Practice or not), unless exempted, are required to:**
 - (a) Complete at least 45 CPE credit hours of structured/unstructured learning in each rolling three-year period
 - (b) Complete minimum 10 CPE credit hours of structured/unstructured learning in each year.
- **All the members (above 60 years of age) who are holding Certificate of Practice, unless exempted, are required to:**
 - (a) Complete at least 70 CPE credit hours (structured/unstructured) in each rolling three-year period.
 - (b) Complete minimum 10 CPE credit hours of structured/ unstructured learning in the first year i.e. 2008
 - (c) Complete minimum 20 CPE credit hours of structured/ unstructured learning in the second and third year i.e. 2009 & 2010.
- **All the members (above 60 years of age) who are not holding Certificate of Practice, unless exempted, are required to:**
 - (a) Complete at least 35 CPE credit hours (structured/unstructured) learning in each rolling three-year period.
 - (b) Complete minimum 5 CPE credit hours of structured/ unstructured learning in the first year i.e. 2008
 - (c) Complete minimum 10 CPE credit hours of structured/ unstructured learning in the second and third year i.e. 2009 & 2010.

An Advisory on Unstructured CPE Learning Activities has also been issued. The said advisory has been hosted on the Institute website (www.icaai.org) and on the CPE Portal (www.cpeicaai.org). This Advisory serves as a guidance and direction to the members and includes the details about the unstructured learning activities and the ways in which these can be undertaken.

5.7.3 In-house Executive Development Programmes (IHEDP) organized

The Committee is committed to impart quality education with a view to hone the skills of officials of and cater to the needs of the business houses on areas of their interest at affordable cost. The Committee conducts about 4 to 5 such events every month at various organizations across the country on topics of contemporary relevance and on IFRS in particular. More than 2000 officials took benefit of such courses to upgrade their knowledge, during the year.

5.7.4 Teleconferencing Programmes Organised

Since long, teleconferencing remained one of the cost effective modes to disseminate knowledge. The Committee holds one or two such events on topics related and relevant to the Profession in collaboration with the Indira Gandhi National Open University (IGNOU), Delhi. The topics so far covered are: Computation of Capital Gains and Survey, Search & Seizure; Set off and Carry Forward of losses under the Income Tax Act – Practical Issues & Appeal Procedure before CIT (Appeals) and ITAT; Legal Compliance aspects relating to Non-

Profit Organizations with Special Reference to Income Tax Act and Foreign Contribution Regulation Act & Art of Preparation of Project Reports with Reference to availing term loan and Working Capital. Opportunities, Challenges and Ethical Requirements for the CA Profession and The Finance (No.2) Bill, 2009 – A clause-by-clause Analysis; Practical Approach to Compliance of Accounting Standards and Professional Opportunities for Chartered Accountants in Capital and Financial Markets; Direct Taxes Code Bill, 2009 – An In-Depth Analysis and its Impact on Tax Practice; Furnishing of Return of Income and Assessment Procedure- Practical Issues; Convergence with IFRS; Provisions of Finance Bill 2010 - A Clause by Clause Analysis; Role of CAs in Corporate Governance; Statutory Audit of Branches of Bank; Wealth Creation in Capital Markets.

Taking into consideration the overwhelming responses that have continually been received from the members, the CPE Committee has started making DVDs of the Teleconferencing Programmes. The members could get these CDs on payment of ` 50 per unit and by viewing these CDs, members could also claim 2 hours (unstructured) CPE Credit.

5.7.5 Awareness Programmes Organised

- Nine awareness programmes on Accounting/Auditing Standards and Code of Ethics were organized in all the five Regions hosted by different Branches.
- Mega 'Professional Excellence' CPE Programme on "Corporate Governance, Capital Markets and Investors' Protection" was organized on 17th April, 2010 at Chennai, jointly by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, New Delhi.

5.7.6 CPE Calendar

The Committee issues every year a Calendar of topics for CPE Programmes having regard to fast paced developments with a view to facilitating POU's maintaining uniformity while conducting CPE Programmes. The said Calendar issued for the year 2010-2011 included variety of obligatory topics under the broad heading (a) Accounting and Auditing, (b) Cost and Financial Management, (c) Information Technology, (d) Taxation, (e) Business Management, (f) Corporate Laws & Corporate Governance, (g) Code of Conduct, (h) Financial and Capital Markets, (i) Insurance & Risk Management, (j) Public Finance, (k) Soft Skills, and other topics, amongst others, on Consultancy and Advisory Services and Right to Information Act. The aforesaid Calendar, containing also the optional topics of professional and contemporary interest, is hosted on the website of the Institute.

5.8 Corporate Laws and Corporate Governance Committee

The Corporate Laws Committee and the Committee on Corporate Governance constituted for the year 2009-2010 have been merged and a rechristened Committee, viz., Corporate Laws and Corporate Governance Committee has been constituted for the year 2010-2011. The initiatives taken by the said respective Committees included the following :

5.8.1 Corporate Laws Committee

• Suggestions/Representation

Submission of suggestions/representations to Ministry of Corporate Affairs in respect of the following:

- Suggestions on Proposed Norms on Managerial Remuneration.
- Suggestions on the Company (Court) Rules, 1959 for streamlining the winding up of the companies in a time bound manner.
- Suggestions on Companies Bill 2009.

• **Training for the Officers of the Official Liquidator of Delhi**

The Committee has organized a training programme for the Officers of the Official Liquidator of Delhi from 20th April 2009 to 1st May 2009. A background material has been prepared and distributed to the participants. Hon'ble Justice Gita Mittal inaugurated the Training Programme. Services of the eminent Chartered Accountants and Study Group Members of the Committee were utilized as faculty for the same. On the last day of the training programme, Certificate of participations was awarded to the officials.

• **Workshop on Limited Liability Partnership**

With the view to impart knowledge, dissemination of policy issues, e-portal issues and other operational aspects of LLP, the Committee organised One Day Workshop on Limited Liability Partnership for the members of the Institute at Kolkata & Coimbatore. For the purpose of workshops, background material was prepared. The aim of the Workshop is to inform the end users about the practical issues related to LLP Act and Rules framed thereunder.

• **Corporate Affairs Standards**

While appreciating the need of the members for appropriate guidance, the Committee has initiated steps to formulate the Corporate Affairs Standards. The three Corporate Affairs Standards on Business Valuation, on Auditors' Appointment, Retirement and Removal and on MCA-21 Certification have been released.

• **Certificate Course on Valuation**

The Certificate Course on Valuation was launched by the Committee in November 2008 for the members of ICAI and CA final examination passed students. 9 batches at Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata were conducted during the year. 429 members have successfully completed the Course.

• **Study Groups**

The Committee constituted the following Study Groups in relation to various aspects of corporate laws:

- Study Group to give suggestions on the proposed norms of the Managerial Remuneration
- Study Group on Companies Bill 2009
- Study Group on Company (Court) Rules 1959

5.8.2 Committee on Corporate Governance

The very purpose of the Committee on Corporate Governance is to encourage appropriate level of corporate governance, provide assistance in laying down benchmarks and proactively conduct research about the difficulties/ problems being faced by the corporations in view of globalization.

The Committee has been organizing several training programmes/ seminars with an aim to provide knowledge in various components of corporate governance. One of the thrust areas of the Committee is to organize training programmes on "Independent Directors", across the country. Some of the topics on which the Committee organized conferences/ seminars/ symposiums are Benchmarking Corporate Governance, Corporate Governance-At Centre stage, Corporate Governance-Raising standards, Corporate Governance-Key to Sustainable Development, Corporate Governance through Audit Committee and Role of CAs in Corporate Governance.

The Committee is also associated with the National Foundation for Corporate Governance (NFCG), set up by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India and NFCG often sponsors the programmes of the Committee. As part of another major initiative, the Committee has brought out the publication entitled "Code of Governance for NGOs" to help NGOs ensure greater transparency and better internal control.

• ***Programmes organized***

During the year, the Committee organized the following programmes:

- A National Seminar on Corporate Governance held at Coimbatore in November, 2009 in partnership with NFCG and hosted by Coimbatore Branch of SIRC of ICAI.
- A National Seminar on Corporate Governance held at Bhubaneswar in December, 2009 (during 'India Corporate Week') in partnership with NFCG and hosted by Bhubaneswar Branch of EIRC of ICAI.
- As part of "India Corporate Week" during December 14-21, 2009, observed by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), ICAI organized jointly with MCA half day National Conclave, hosted by the respective branches of ICAI, at the places and on the themes as mentioned below:

Place	Theme
Jaipur	Corporate Governance for Social Empowerment
Baroda	Corporate Governance - Key to Sustainable Development
Ernakulam	Corporate Governance for Social Empowerment
Chandigarh	Corporate Governance - Key to Sustainable Development
Nagpur	Corporate Governance - Creating and Managing Shareholders Value

- A Conclave on Benchmarking Corporate Governance held at Mumbai in January, 2010 jointly with the Committee for Members in Industry (CMII) of ICAI
- A National Seminar on Corporate Governance held at Indore in February, 2010 in partnership with NFCG and hosted by Indore Branch of CIRC of ICAI

➤ ***Initiatives/Projects include :***

- Interaction with regulators on various issues relating to corporate governance.
- Launch of Certificate Course on Corporate Governance
- Constitution of ICAI Expert Advisory Group in the preparation of ICAI Code on Corporate Governance comprising of renowned experts
- Research – Case Studies on success/failure of Corporate Governance in Indian Corporate World

- Bringing out publication on Role and Responsibilities of Independent Directors and Audit Committee
- Organizing Public Awareness Programme on Corporate Social Responsibility
- Organizing Programmes on the emerging areas of interest like Climate Change/ Global Warming, Carbon Credit, Millennium Development Goals (MDGs) etc.
- Organizing Workshops on Independent Directors
- Holding National Seminars in partnership with NFCG

5.8.3 Activities/Initiatives undertaken by the rechristened Corporate Laws and Corporate Governance Committee include :

The Committee discussed the matter on the Companies Bill, 2009 in its first meeting held on 11th March, 2010 in detail and finalised the suggestions on the same. The suggestions as finalised have been forwarded by the Institute to the Ministry of Corporate Affairs and to the Parliamentary Standing Committee on Finance. The Parliamentary Standing Committee has also given the Institute an opportunity of oral hearing.

1. Suggestions/Representation

a) Companies Bill 2009

An oral hearing of the representatives of ICAI on its suggestions on Companies Bill 2009 was held before the Parliamentary Standing Committee on Finance in May, 2010.

b) Corporate Governance Voluntary Guidelines 2009

The Committee deliberated on various aspects of the document in detail and also compared the same with Clause 49 of Listing Agreement, Companies Bill, 2009, Recommendations by CII Task Force headed by Mr. Naresh Chandra & ICSI Recommendations to strengthen Corporate Governance Framework. Based on the Committee's comments/ suggestions, a formal feedback on the document on behalf of ICAI would be submitted to MCA.

c) Draft International Standard ISO 26000 (Guidance on social responsibility)

The Committee is preparing its comments/ suggestions on the above document for submission to the MCA.

2. Renewed Scheme for Certified Filing Centre (CFC) under MCA 21 e-governance Programme

The Ministry of Corporate Affairs has identified ICAI for collecting, processing and verification of applications submitted by the applicants for fresh registration of CFC and for re-activation/renewal of existing CFC.

Initiatives/Projects in progress

- Work Plan for the year 2010-2011 for conducting joint programmes with NFCG :
The Committee has prepared the Work Plan for the year 2010-2011 for conducting Joint programmes and Research projects with the National Foundation for Corporate Governance (NFCG).

- Interaction with regulators on various issues relating to Corporate Laws and Corporate governance.
- Publication on Corporate Governance Practices for Public Sector Enterprises.
- Organizing workshops on Limited Liability Partnership in Eastern Region
- Organizing training programmes on Actuarial Valuation
- Organizing training programmes on Corporate Governance and Role of Independent Directors and other related topics.
- Organizing training programmes on Easy Exit Scheme and Company Law Settlement Scheme.

5.9 Direct Taxes Committee

5.9.1. Representations to the Central Board of Direct Taxes

The Committee submitted the following representations to the CBDT :

- (i) The Committee had sought clarification on the issue whether remittances relating to TDS can be made using the old challan 281 as the new form No.17 was not uploaded in the payment gateway on Ministry's website.
- (ii) The Committee had requested CBDT to take appropriate steps at the earliest for timely completion of scrutiny assessment in refund cases also, preferably by setting a cut-off date for completion of such assessments. In the alternative, it was suggested that the condition that refund should be granted only after completion of such assessment may be removed.
- (iii) Circular No.03/2009 dated 21.5.2009, issued by CBDT caused some hardship and practical difficulties to the assesseees and accordingly it was requested to issue appropriate instruction regarding the following:
 - (a) Form ITR-V may be allowed to be submitted by the assessee to the respective Assessing Officers having jurisdiction over the assessee as before. The Income-tax Department may be required to collect these forms and send the same to the Bangalore office.
 - (b) The assessee may be allowed to file the ITR V within 30 days from the end of the month in which the return has been electronically furnished.
- (iv) The CBDT was requested to consider genuine hardships and practical difficulties faced by the assesseees in getting a Certificate for lower deduction or non-deduction of tax at source.
- (v) A representation was submitted to the CBDT requesting them to consider extension of the due date of filing return of income suitably in appropriate cases.
- (vi) As it was noticed that a large number of cases have been fixed up by the Assessing Officers nearer to the last date for filing of return of income which becomes burdensome for the assesseees. The CBDT was suggested to request the Assessing Officers not to fix the cases near to the last date of filing return of income and where the cases are already fixed up the same may be adjourned to some later date.
- (vii) A representation was submitted to the CBDT to verify the fact that the tax audit has been done by a Chartered Accountant. It was suggested that the ITR should contain a column requiring the tax auditor to certify that the tax audit has been conducted by him on the date specified therein or alternatively it was suggested that the tax audit report digitally signed by a Chartered Accountant should be filed along with the return of income.

5.9.2 Inputs to the Ministry of Corporate Affairs

The Committee submitted to the Ministry of Corporate Affairs a detailed reply relating to the measures taken by ICAI to check malpractices in the field of tax audit.

5.9.3 Submission of Pre-Budget Memorandum – 2009 (May, 2009)

The Committee submitted the Pre-Budget Memorandum – 2009 containing suggestions relating to direct taxes to the Hon'ble Finance Minister and Officials of the Central Board of Direct Taxes.

5.9.4 Budget Viewing Sessions

The Year 2009-10 witnessed the presentation of two Union Budgets namely Union Budget 2009 & Union Budget 2010 on 6th July, 2009 and 26th February, 2010 respectively.

The Committee organised a Budget Viewing Session on both these occasions jointly with the Indirect Taxes Committee and the Committee on International Taxation. These Sessions were attended by the members of the Direct Taxes Committee, the Indirect Taxes Committee, the Committee on International taxation and other Council Members and eminent members of the profession. The members and other invitees deliberated on the various clauses of the respective Finance Bills and a Press release was issued detailing the Institute's views on these Budgets.

5.9.5 Budget 2009 & 2010 - Articles for the Journal

The Committee invited articles on Budget proposals – 2009 & 2010 relating to direct taxes from eminent members of the profession. The related articles published in the Journal of the Institute – The Chartered Accountant – included the following :

- New Provisions for Taxation of Gifts
- Salient features of the Finance (No.2) Bill, 2009 -Direct Taxes
- Salient features of the Finance Bill, 2010 – Direct Taxes
- Finance Bill, 2010 – Proposals for change in conversion to LLP and MAT
- Issues on Amendments in deductions by the Finance Bill, 2010
- User friendly proposals in the Union Budget

5.9.6 Workshops on Union Budget 2009

- ***Union Budget 2009 presented on 6th July, 2009***

The Committee together with the Indirect Taxes Committee and the Committee on International Taxation organized a Workshop on Union Budget 2009-10 on 17th July, 2009. The Workshop was graced among others, by Shri S.S.N. Moorthy, Chairman, CBDT, Shri Ashutosh Dikshit, Joint Secretary (TPL-II), CBDT, and Shri Anand Kedia, Director (TPL-III & IV), CBDT. Senior professionals from the industry also joined the Workshop. A Press release on the Workshop was also issued.

- ***Union Budget 2010 presented on 26th February, 2010***

The Committee organized a Workshop on direct tax proposals of the Union Budget 2010-11 on 23rd March, 2010. The Workshop was graced among others, by Shri Ashutosh Dikshit, Joint Secretary (TPL-I), CBDT, Shri Sunil Gupta, Joint Secretary

(TPL-II), CBDT, Shri Munesh Kumar, Director (TPL-II), CBDT and Shri Rajesh Kumar Bhoot, Director (TPL- III), CBDT. Senior professionals from the industry also joined the Workshop.

5.9.7 Live Web-cast and Commentary on Union Budget 2010

The Committee organised a live web-cast on 26th February, 2010 which was addressed by the members of the Direct and the Indirect Taxes Committees. The web-cast and a commentary on the proposed changes in the areas of direct taxes were hosted on the website of the Institute.

5.9.8 Submission of Post Budget Memorandum

The Committee submitted the Post Budget Memorandum – 2009 & 2010 containing the suggestions of the Institute on Budget 2009 & 2010 respectively to the Finance Minister and the Officials of the CBDT. The Post Budget Memorandum 2009 & 2010 were also hosted on the website of the Institute.

5.9.9 Guidance in respect of Clause 17A of the Form No.3CD

The Central Board of Direct Taxes through Income-tax (Tenth Amendment) Rule, 2009 introduced a new clause 17A in Form No.3CD. The Committee finalized the guidance in respect of the newly inserted clause 17A and the same was hosted on the website on 25th August, 2009.

5.9.10. Guidance on Tax queries by ICAI at the Special Camp hosted by the Income-tax Department at Pragati Maidan, New Delhi.

A desk was provided by the Institute at the special camps hosted by the Income-tax Department at Pragati Maidan, New Delhi during 28th to 31st July, 2009 in pursuance of a request received from the office of the Additional Commissioner of Income-tax to provide cost free services of direct tax experts to give expert advice on the queries raised by the assesseees at these special camps.

5.9.11 Activities pursuant to the release of the Direct Taxes Code Bill, 2009

The Ministry of Finance released the Direct Taxes Code Bill, 2009 on 12th August, 2009. The suggestions of the ICAI in this regard have been submitted to the Ministry.

• Organization of Lecture Series on Direct Taxes Code Bill, 2009

The Committee organized a series of lectures on Direct Taxes Code Bill, 2009 in co-ordination with the Ministry of Finance to generate discussions and bring about awareness about the proposed law as under:

- Mumbai on 29th August, 2009
- Bangalore on 31st August, 2009
- Kolkata on 31st August, 2009

Various CBDT officials deliberated upon the rationale behind introduction of this new Direct Taxes Code Bill, 2009.

• ***Formation of Study Groups on Direct Taxes Code Bill, 2009***

The Committee formed Study Groups and sub-groups at various places to identify the issues arising from the Direct Taxes Code Bill, 2009 for making suitable recommendations to the Government. These Groups held meetings in their respective regions to discuss the issue on the chapters of the Direct Taxes Code Bill, 2009 allocated to them. The inputs received from the Convenor of these sub-groups were compiled by the office and placed for the consideration of the Committee.

5.9.12 Constitution of Group for identifying direct tax issues arising from convergence of Indian Accounting Standards (ASs) with International Financial Reporting Standards (IFRS)

A Group has been constituted for identifying direct tax issues arising from convergence of Indian Accounting Standards with International Financial Reporting Standards. The Group comprises of Council members and members nominated by the Central Board of Direct Taxes.

5.9.13 Seminars and Conferences

- A Workshop on Direct Taxes was organised at Indore on 25th April, 2009
- A Residential Workshop on Direct Taxes & IFRS was organised at Trichur on 17th and 18th May, 2009
- A National Tax Seminar on Direct Taxes on 30th May, 2009 at Kanpur
- A National Seminar on Direct Taxes on 27th June, 2009 at Raipur
- A full day Workshop on Direct Taxes on 27th June, 2009 at Salem.
- An All India Conference on Direct Taxes on 10th and 11th July, 2009 at Kolkata
- A National Tax Convention on 1st and 2nd August, 2009 at Ahmedabad
- A One day Workshop on Capacity Building on 18th August, 2009 at Madurai
- A Seminar on Infrastructure and Works Contract Industry organised on 21st August, 2009 at Hyderabad
- A Residential Refresher Course organised at Mumbai and Singapore from 22nd to 26th November, 2009
- All India Conference on 19th and 20th December, 2009 at Guwahati
- Two Days' National Seminar on Direct Taxes on 13th and 14th February, 2010 at Indore
- Workshops on Union Budget 2010 were organised on 5th March, 2010, 6th March, 2010 and 10th March, 2010 at Mumbai, Hyderabad and Kolkata respectively.

5.10 Committee on Economic & Commercial Laws and Trade Laws & WTO

In February, 2010, a rechristened Committee on Economic, Commercial Laws & WTO came into existence with the merger of two former Committees, viz., Committee on Economic & Commercial Laws, and Committee on Trade Laws & WTO.

The objective of the Committee is to create a knowledge base on various matters concerning National and International Trade Laws and Protocols, and their implications and ramifications by examining various Economic, Commercial Laws, Rules/ Regulations/ Notifications issued thereunder, vis-à-vis International Legal scenario/best practices and those arising from WTO era and to make representations to the concerned authorities suggesting suitable amendments/modifications, wherever deemed fit, inter alia, covering the following :

- To strive for capacity building of members in the rapidly changing world trade scenario in order to technically equip the members of the Institute to face the challenges and derive advantages to broaden the scope of their expertise in the new world trading regime and to contribute towards the economic development of India.
- To make representations to the concerned authorities suggesting suitable amendments/modifications, wherever deemed fit.
- To develop and publish Technical Guidance, Background Materials/Reports, Guides, Commentaries, References, Publications etc. on Economic, Commercial Laws and WTO agreement.
- To serve the multifunctional task of analysis, knowledge dissemination, inputs to policy formulation, references in areas of professional interest to ICAI Membership and bolster the element of potential professional opportunities.
- To develop a base of expertise amongst the members of the Institute on Economic, Commercial Laws, Intellectual Property Rights, TRIPS, Anti-dumping laws, Foreign Trade Policy matters etc., through Seminars, training programs and such other methods as may be considered effective.

The significant achievements and exercises undertaken by the Committee are as follows:-

5.10.1 Post-Qualification Course in International Trade Laws & WTO/Certificate Course on Arbitration

- The Post Qualification Course in International Trade Laws and World Trade Organisation is to orient Chartered Accountants towards developing the necessary and desirable capabilities to adapt to and respond to the dynamic and challenging international economic environment. This Course has also been receiving good response from the members. More than 330 members have been registered in the Course from across the Country. The Committee is in the process and also in contact with the Ministry of Corporate Affairs for restructuring of the said Course.
- The First and Second Phase of the Personal Contact Programme (PCP) classes have been organised by the Committee from 1st to 15th July, 2010 and from 29th July, 2010 to 12th August, 2010 respectively at New Delhi for the members registered for the Post-Qualification Course in International Trade Laws & WTO.
- The Committee has been taking efforts to popularize the Course amongst members throughout the country and also to promote the Course in the industry, Government and other potential user-groups to create professional avenues for members so equipped in International Trade Laws and WTO field.
- The Certificate Course on Arbitration was started with a view to sensitize its members on the Alternative Dispute Redressal Mechanism. 7 batches of the Course have already been conducted and more are being planned in the current year. The Committee has also decided to organize Two Days Advance Level Workshop on Arbitration to train its members in the field across the country.
- There are at present 314 members on the ICAI Panel of Arbitrators and efforts are being made to apprise the user bodies of the availability of Chartered Accountants for appointment as Arbitrators within the country and globally. The World Intellectual Property Organisation (WIPO) has also been requested to consider enrolling the members of the ICAI Panel of Arbitrators on their list of experts. A few International bodies like International Court of Arbitration in Europe (ICAE) and Chartered Institute of Arbitrators, UK (CI Arb) have also been approached for academic cooperation.

5.10.2 E- Newsletter

E-Newsletter covering the emerging issues related to the Economic, Commercial, Trade Laws & WTO is also being released by the Committee.

5.10.3 Views on the WTO Document No. S/C/W/316 on Accountancy Services prepared by the WTO Secretariat.

The Committee made a lot of analysis and research with regard to the commitments to the accountancy sector by different member-states under various Modes. The Committee submitted its response to the Ministry of Commerce & Industry and Ministry of Corporate Affairs outlining the possible liberalization in Mode 3 Commitments and a modified draft to the ICAI's response to the WTO Document No. S/C/W/316.

5.10.4 Publications

- The Committee is in the process of revising its earlier publications titled "Referencer on FEMA" (Foreign Exchange Management Act, 1999), "A Handbook on Special Economic Zones" and its publication on Arbitration.
- Efforts are being made to revise its other earlier publications and to bring out a few more new publications titled "Study on Benefits of Preferential Trade Agreements with ASEAN countries in Agriculture and Commerce Sector", "Study on Cross- Border Mergers and Acquisitions" and on the other subjects related to Economic, Commercial, Trade Laws & WTO.

5.10.5 Workshops/Seminars/Conference

The Committee organised the following Workshops/Conference:

- Workshop on Professional Opportunities in Competition/Consumer Laws on 28th May 2010 at Mumbai
- Workshop on Non-Banking Financial Companies on 5th June 2010 at Kolkata
- Workshop on FEMA - Inbound and Outbound Investments on 25th and 26th June 2010 at Mumbai
- Two Day National Conference on 17th and 18th July 2010 at Chennai

5.10.6 Interaction with the various Government Departments/Ministries

- There has been interaction with the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Department of Economic Affairs, SIDBI, CCI and Foreign Investment Promotion Board and National Consumer Disputes Redressal Commission to explore more professional opportunities for members. The Committee intends to continue its dialogue with some more Government Departments/Ministries in this regard.
- A representation has been made to the Government of Maharashtra regarding Introduction of Amnesty Scheme and on-line system for compliances/registration of documents with the office of the Registrar of Firms, Maharashtra.
- The Ministry of Corporate Affairs has been apprised about the issues that arose from the new FDI Policy with the request to take up the matter appropriately with the Ministry of Commerce & Industry in this regard.

5.10.7 Erstwhile Committee on Economic and Commercial Laws

The Committee on Economic and Commercial Laws (CECL) was constituted in February 2008 with the specific objective of focusing more clearly on the emerging professional opportunities in the area of economic and commercial laws and to facilitate legislative process in the area of making/amending economic and commercial laws.

The significant achievements and exercises undertaken by the said Committee are as follows:-

- The Committee submitted its Comments/Suggestions on the Indian Trust (Amendment) Bill, 2009 to the Parliamentary Standing Committee. The delegation headed by the then President had a personal hearing before the Standing Committee.
- The Committee organised Seminar on Prevention of Money Laundering Act, 2002 on 18th May, 2009 at Pune and a National CA Conference 2009 - Enriching Potentials Delivering Excellence on 28th and 29th November 2009 at Cuttack.
- The Revised Second Edition of the book titled "A Study on Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976" has been printed. The Committee took initiatives to finalise the its new publications, viz., 'A Study on Prevention of Money Laundering Act, 2002', 'Handbook on Professional Opportunities in Economic and Commercial Laws', and 'A Study on Drafting, Conveyance, Stamping and Registration of Commercial and other Documents'.
- Steps are being taken to prepare the suitable Background Material on Advance Level Workshops and SEZ Laws for circulation amongst the participants in the Workshops. The Background Material meant for Certificate Course on Arbitration is also being revised and updated.

5.10.8 Erstwhile Committee on Trade Laws and WTO

The Committee on Trade Laws and WTO was constituted with the mission to establish and assure the expertise and authority of the Institute of Chartered Accountants of India in all matters concerning Laws of Trade including Trade in Goods and Services in particular, and the implementation of international trade regimes including the WTO regime in general, both nationally and internationally and to create and expand a base of expertise in these matters among the membership of the Institute through such ways and means as are considered to be most effective so as to fulfill national stated and unstated aspirations, concerns, and needs in all these regards.

The significant achievements and exercises undertaken by the said Committee are as follows:-

- The Committee launched the Post Qualification Course in International Trade Laws & WTO (ITL & WTO) in November 2004. Since the launch of the Course, the applications for registration in the course have been coming from all parts of the country. More than 330 members have been registered in the Course from across the country. The syllabus, course structure, study material and the framework of the Post Qualification Course in International Trade Laws and WTO are proposed to be realigned with a view to give a focused outlook to the overall structure of the Course.
- With a view to create awareness amongst the members on WTO at the grassroots level and thereby expanding the number of candidates for the Post Qualification Course in International Trade Laws and WTO, co-operation of all the Regional Councils/Branches had been sought in the following areas: -

- To popularize the Post Qualification Course in International Trade Laws and WTO of ICAI by providing information about the Course to members.
- To create awareness on WTO amongst the members by organizing programmes.
- An Interaction was held with the Trade officials of various Embassies in India at ICAI, New Delhi on 15th May, 2009 which was attended by the representatives from the various embassies, viz., Belarus, Germany, Iceland, Malawi, Maldives, Paraguay, Pakistan, Tunisia & Sri Lanka. Further, an Interaction was also held with British High Commission on 26th May, 2009 at ICAI New Delhi.
- The Committee has published a Study on Benefits of Preferential Trade Agreements. A Standard Background Material has also been brought out for the various programmes.
- The following Awareness Programmes/ Workshops/ Seminars/ International Study Tour were organized by the Committee:
 - Diamond Jubilee National Symposium on Professional Excellence & Enrichment jointly with the Professional Development Committee and hosted by Bhilai Branch of CIRC of the ICAI on 15th February, 2009 at Bhilai.
 - International Study Tour to Thailand during 4th-8th May, 2009 jointly with Bhilai Branch of CIRC of the ICAI.
 - Interactive workshop for members on GATS – Issues for Accounting on 26th May, 2009 at New Delhi, which was also relayed through Video-conferencing at the Offices of the Institute at Mumbai, Chennai, Kolkata and Kanpur.
 - National Conference on "Emerging Paradigm for Accounting Professionals" hosted by NIRC of the ICAI and Ghaziabad Branch of CIRC of the ICAI during 15th-16th August, 2009 at Sahibabad (Ghaziabad).
 - National Conference on "Emerging Paradigm for Accountants", hosted by Kolhapur Branch of WIRC of ICAI during 20th-22nd August, 2009 at Kolhapur.
 - First Batch of 30 days Personal Contact Programme (PCPs) in two phases of 15 days each during 1st July, 2009 to 15th July, 2009 and from 29th July, 2009 to 12th August, 2009 at New Delhi for the members registered in the Post Qualification Course in ITL & WTO.
 - Second Batch of 30 days Personal Contact Programme (PCPs) in two phases of 15 days each during 5th November, 2009 to 19th November, 2009 and from 5th January, 2010 to 19th January, 2010 at New Delhi for the members registered in the Post Qualification Course in ITL & WTO.
 - Interactive Workshop on "Anti Dumping Subsidies & Safeguard - Law & Procedure Opportunities & Challenges for Chartered Accountants" on 5th February, 2010 at New Delhi.

The Committee released the April, 2009 & July, 2009 issues of E-newsletter titled Gateway to International Trade – E-Communiqué of the Committee on Trade Laws and WTO.

5.11 Ethical Standards Board

At times, it is felt as to what is the requirement of professional ethics when law and the consequences of its non-compliance are already in place. The objective of law and ethics is same. But ethics is required to encourage people to maintain rightful professional conduct. Jurists Hart and Fuller, in the famous Hart-Fuller debate published in Harvard Law Review in 1958 agree at a point that a system devoid of ethics cannot command the allegiance of people and must depend upon repression. When the repression regime falls, the system falls with it. The law therefore must be guided and informed by morality. Any law which is not so guided and informed will be unjust, and would fail to achieve its objective.

Today, Ethics is required as an indispensable part of profession and business. As a part of Sarbanes Oxley law, directors have to sign an ethics declaration. In India, all directors annually sign affirmation for compliance of Code of Business Conduct and Ethics as per the requirement of Clause 49 of the Listing Agreement.

The Ethical Standards Board of the ICAI takes notice of the above relationship between profession and ethics and is working towards dissemination of professional ethics, to the highest standards, among the members of the ICAI. It formulates ethical principles for members and creates awareness of ethics among them through various ways. The Code of Ethics for members, a publication of the Board, has two parts : Part-A, being principle based and Part-B being rule based are complementary components of each other and represent one of the best Code for a profession. The mission of the Board is *"To work towards evolving a dynamic and contemporary Code of Ethics and ethical behaviour for members while retaining the long cherished ideals of 'excellence, independence, integrity' as also to 'protect the dignity and interests of the members'.* Besides, the Board also examines and renders advice on ethical issues referred to it. It reviews and revises its publications '*Code of Ethics*', '*FAQ on Ethical Issues*', '*Guidance Note on Independence of Auditors*' and '*Guidance Note on Revision of the Audit Report*' from time to time. The Board promotes public awareness and confidence in the fundamental principles, viz., integrity, objectivity, competence and professionalism for members. It also examines and deals with the complaints of members against their unjustified removal as auditors of an entity, as per procedure evolved, and takes necessary steps to protect the interest of its members.

5.11.1 Important Decisions on various issues :

- In its endeavour to bring awareness of ethical issues among members, the Board has started a full page titled as '*Know your Ethics*' in the CA journal which is being published regularly since September, 2009.
- Necessary amendments required to be made in the Chartered Accountants Act, 1949 and Companies Act, 1956 due to enactment of Limited Liability Partnership Act, 2008 were proposed by the Board. The recommendations of the Board, as approved by the Council, were sent to Ministry of Corporate Affairs in August, 2009 for the amendments in the Act.
- Modalities on Multi-Disciplinary Partnerships (MDPs) were framed by the Board on direction of the Council. The said modalities were approved by the Council.
- The Board decided that :-
 - Tax Audit and Sox Certification can be done only by Statutory Auditor.
 - Designing of system and day to day support to outsourced business processes can be done only by Internal Auditor.
 - Tax Representation, Consultancy Advisory, IFRS Conversion and resource raising can be done by both.
- In line with the principle of strict independence as adopted in the earlier decisions, it is not permissible to accept concurrent audit of one of the branches of a nationalized bank who has conducted statutory audit of 3 different branches of the same bank.
- An internal auditor of an entity may be appointed as Tax Consultant of the same entity for a particular year.
- The ICAI cannot interfere in the Quotations/Bids invited from Chartered Accountants regarding empanelment for Audit work by Govt. Companies/ Organizations/ PSUs/ Corporation as the CA (Amendment) Act, 2006, specifically allowed Chartered Accountants in practice to respond to the tenders vide proviso (ii) to Clause (6) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949.

5.12 Expert Advisory Committee

Expert Opinions

With the constant economic growth and development leading to complex business transactions across enterprises, the accounting professionals, while discharging their duties are often posed with difficulties, especially in the application and implementation of the accounting and auditing principles to various unique and complex business situations. To provide guidance and assistance to the Chartered Accountants in such a scenario, the Expert Advisory Committee of the Institute answers the various queries raised by them in matters dealing with the interpretation and application of various accounting and auditing standards, guidance notes and other pronouncements of the Institute in accordance with the Advisory Service Rules framed for this purpose. The Committee deals with the queries relating to accounting and/or auditing principles and allied matters and as a general rule, does not answer queries which involve only legal interpretation of various enactments and matters involving professional misconduct. It also does not answer queries which concern a matter which is pending before the Board of Discipline or the Disciplinary Committee of the Institute, any court of law, the Income-tax authorities or any other appropriate department of the government. The Advisory Service Rules can be accessed from the website of the Institute or can be obtained from the Institute's Head Office at New Delhi.

The opinions of the Expert Advisory Committee are the opinions or views of the members of the Committee on the given facts and circumstances of the query, arrived at on the basis of the applicable accounting/auditing standards, guidance notes, and other pronouncements of the Institute as well as the relevant laws and regulatory environment applicable under the circumstances of the query, as on the date of finalisation of the opinion. Every opinion, therefore, must be read and applied after taking into account any amendments and/or other developments subsequent to the date of finalisation of the opinion by the Committee which is mentioned thereagainst.

Although the opinion given or a view expressed by the Committee represents the opinion or view of the members of the Committee and not the official opinion of the Council of the ICAI, it carries an authoritative guidance which is well recognised by various government/regulatory bodies, such as, the Comptroller and Auditor General of India (C&AG), Ministry of Corporate Affairs, etc.

During the period from 01.04.2009 to 30.06.2010, the Committee finalised 43 opinions received from the members of the Institute and 4 opinions on different accounting issues received from the Regulators/ Government authorities. Various issues on which the Committee opined during the period were accounting for foreign exchange rate variation, depreciation, revenue recognition, segment reporting, treatment of goodwill arising on consolidation, deferred taxes, treatment of expenditure during construction period, etc.

The opinions issued by the Committee are also published in the Compendium of Opinions. Till now, twenty-six volumes of the Compendium have been released for sale. The next volumes of the Compendium in the series are under compilation and are likely to be released for sale shortly. A CD containing more than 1000 opinions contained in the twenty-five volumes of Compendium of Opinions with user-friendly features for easy referencing is also being upgraded to include opinions contained in the later volumes.

Some of the opinions finalised by the Committee are published in every issue of the Institute's Journal 'The Chartered Accountant'. Recent opinions of the Committee are also hosted on the website of the Institute.

5.13 Committee on Financial Markets and Investors' Protection

To educate investors about their rights and responsibilities, informing them about grievance redressal mechanism and importance of fundamental analysis based on balance sheets and other financial statements specially notes and other disclosures is one of the focus area of the Committee. The Ministry of Corporate Affairs has entrusted this Committee to educate the investors in relation to the Capital Market under the aegis of Investor Education and Protection Fund (IEPF) of Govt. of India. The Committee has been organizing several programmes/ workshops across the country with an aim to provide knowledge in various components of Capital Market.

In addition to above, the Committee also plays a pro-active role in conducting various other programmes such as Seminars on Capital Markets, Investor Summit, Private Equity Workshops and Career Counseling Programmes etc. The Committee has also published various publications such as Booklets and Pamphlets on Investors Awareness, Hand Book on Capital Market Regulations, Background Material on Private Equity and Guidance Note on Certification of Corporate Governance (Revised).

5.13.1 Projects

- **Interface with Regulatory Authorities – RBI, SEBI & MCA – Submissions/ Suggestions on Policy/Discussion Papers**

The Committee represented the Institute at the three meetings of Investor Education and Protection Fund Committee of the Ministry of Corporate Affairs on programmes relating to investor awareness and protection. The Committee had also made representation to the BSE/NSE/SEBI on the issue relating to reduction in the number of trading holidays for stock exchanges in tune with the international practices.

- **Certification Courses - Forex and Treasury Management**

The Committee conducted the second batch/third batch of Certificate Course on Forex and Treasury Management at New Delhi and Mumbai respectively. The Committee is now further proposing to extend these courses to other metros.

5.13.2 Programmes Organized

- Conference on Emerging Trends in the field of Financial Markets on 24th & 25th April, 2009 at Amritsar hosted by the Amritsar Branch of NIRC.
- Two days Workshop on Capital Markets on 11th & 12th July, 2009 jointly with Ludhiana Branch of the ICAI at Ludhiana.
- Diamond Jubilee Conference on Capital Market on 17th & 18th July, 2009 at New Delhi.
- Two day Seminar on the Private Equity on 1st & 2nd August, 2009 at Bangalore.
- During the year 2009-10, the Institute under the aegis of the Investor Education and Protection Fund of the Ministry of Corporate Affairs of the Government of India had organized 76 Investor Awareness programmes.

5.13.3 Publications

- **Revision of the existing Guidance Note on Certification of Corporate Governance (As stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement)**

The revised Guidance note 2009 was published.

5.14 Financial Reporting Review Board

The ICAI, continuing with its endeavours to improve the financial reporting practices in the country, had constituted the Financial Reporting Review Board (FRRB). The FRRB reviews the General Purpose Financial Statements of various enterprises and the auditors' report thereon either *suo motto* or on a reference made to it by any regulatory body(ies) or where serious accounting irregularities have been highlighted by the media reports with a view to determine, to the extent possible:

- a) Compliance with the generally accepted accounting principles in the preparation and presentation of the financial statements;
- b) Compliance with the disclosure requirements prescribed by the regulatory bodies, statutes and rules and regulations relevant to the enterprise; and
- c) Compliance with the reporting obligation of the enterprise as well as the auditors.

As per the Operating Procedures of the FRRB, the Board is assisted by Technical Reviewers and Financial Reporting Review Groups in review of the General Purpose Financial Statements and the auditors' report thereon. The preliminary review of the General Purpose Financial Statements and the auditors' report thereon selected for review is conducted by the Technical Reviewers selected from the panel maintained by the Board. Preliminary review reports of Technical Reviewers on review of the General Purpose Financial Statements and the auditors' report thereon are considered and finalised by Financial Reporting Review Groups before the same are finally examined by the Board.

5.14.1 Review of General Purpose financial statements and auditors' report thereon

During the year 2009-10, the Board has completed the review of 76 cases including special cases.

5.14.2 Constitution of Financial Reporting Review Groups

The Board constituted thirteen (13) Financial Reporting Review Groups for the Council Year 2009-10 for consideration and finalisation of the preliminary review reports submitted by the Technical Reviewers on General Purpose Financial Statements and the auditors' report thereon.

5.14.3 Publications

- In order to enhance the knowledge of preparers of the financial statements and auditors, the Board had released the publication '**A Study on Compliance of Financial Reporting Requirements**' during this period. The Publication contains pertinent observations of the Board on compliance aspects of various Financial Reporting Requirements in context of the applicable Accounting / Auditing Standards and Guidance Notes as well as relevant Laws and Statutes. It includes the observations of the Board

made during the review of the general purpose financial statements relating to the financial years from 2002-03 to 2006-07.

- With a view to apprise the members of the Institute and others concerned about the non-compliances observed during the review, note on non-compliances was published in the Institute's Journal, 'The Chartered Accountant', in the issues of June, July, December, 2009 and January 2010.

5.14.4 Conduct of Training Programmes/Workshops

In order to cope up increasing volume of work, the Board felt the need to enhance the number of technical reviewers empanelled with it. Accordingly, the Board conducted various training programmes at various regional branches to impart training to the members of the Institute for review of the general purpose financial statements of the enterprises and finally to empanel them with the Board. During the period, the Board conducted 4 training programmes, the details of which are outlined as below:

- At Chennai on June 13, 2009, which was inaugurated by the Hon'ble CA. K. Rahman Khan, FCA, Deputy Chairman, Rajya Sabha and well attended by 273 participants from various fields of the Profession and from various firms.
- At Kolkata on August 14, 2009, which was attended by 67 participants.
- At Indore on January 19, 2010 which was attended by 78 participants.
- At Mumbai on January 23, 2010 which was attended by 47 participants.

Thus, the Board was able to empanel 90 more technical reviewers. At present, 214 technical reviewers are empanelled with the Board.

5.15 Indirect Taxes Committee

5.15.1 Activities relating to Budget

• Budget Viewing Session on Budget 2009

The Indirect Taxes Committee along with Direct Taxes Committee and Committee on International Taxation organized a Budget viewing session on Union Budget – 2009 on 6th July, 2009. The members and other invitees held deliberations on the Finance Bill, 2009 and a Press Release was issued detailing the Institute's view on the Budget – 2009.

• Budget Viewing Session on Budget 2010

The Indirect Taxes Committee organised a Budget Viewing Session jointly with Direct Taxes Committee and Committee on International Taxation on 26th February, 2010 to analyse the Budget proposals of 2010-11. After the Budget was presented, the proposals were discussed in detail by the members and were summarised in the form of Highlights, which were then hosted on the website. Further, the Committee prepared a detailed note on issues arising out of budget proposals and the same were also hosted on the website. The Committee also organised on the same day a live webcast jointly with Direct Taxes Committee.

- **Workshop on Union Budget – 2009**

The Committee along with Direct Taxes Committee organised a Workshop on Union Budget – 2009 on 17th July, 2009. Shri B. Shridhar, the then Member (Budget), Shri Vivek Johari, Joint Secretary (TRU) and Shri Gautam Bhattacharya, Joint Secretary (TRU) from Central Board of Excise and Customs (CBEC) addressed the Workshop.

- **Workshop on Indirect Tax Proposals of the Budget - 2010**

The Committee organised a Workshop on Union Budget – 2010 on 16th March, 2010 to discuss the Indirect Tax proposals with the Officials of the CBEC. Shri Gautam Bhattacharya, Joint Secretary (TRU) and CA. Sushil Solanki, Commissioner, CBEC, addressed the Workshop. The members brought to the notice of the dignitaries of the CBEC, the possible issues arising out of the Budget proposals. The Workshop was received very well.

5.15.2 Seminar/Convention/Workshop/Training Courses

- A Workshop on Indirect Taxes jointly with Continuing Professional Education Committee at Dombivali on 4th August, 2009 which was hosted by the Thane Branch of WIRC of the ICAI.
- A National Tax Convention jointly with Direct Taxes Committee at Ahmedabad on 1st and 2nd August, 2009.
- A National Seminar on Indirect Taxes on 16th August, 2009 at Allahabad, Uttar Pradesh.
- A National Seminar on Taxes on 26th August, 2009 at Trivandrum jointly with Committee on International Taxation.
- A National Seminar on VAT, CENVAT, Service Tax and GST at Kolkata on 28th August, 2009.

- **Three Days Basic Level Course on Service Tax**

The basic idea for organising three days basic level course was started by the Committee during the year 2008 when separate Committees – one on Indirect Taxes and another on Direct Taxes - were formed in place of Fiscal Laws Committee at the relevant time. As the area of Indirect Taxes was expanding very fast, the Indirect Taxes Committee thought it fit to continue this activity of organising the Three Days Basic Level Course on Service Tax across the country and facilitate members to take up practice in the field of service tax. The Committee organised two programmes of "Three Days Basic Level Course on Service Tax" during the year 2009 – 10 one at Dhanbad which was hosted by Dhanbad Branch of the CIRC, and another at Palghat Branch of the SIRC.

- **Training Programmes for Government Officials**

The Committee organised a two weeks' Training Course "Use of Financial and Accounting Tools in the area of Indirect Taxes" for the Indian Revenue Service (Customs & Central Excise) Group "A" Probationers of 60th batch. The Training Course was conducted from 1st June to 12th June, 2009 at National Academy of Central Excise & Narcotics, NACEN Complex, Faridabad. The Course was attended by 130 IRS probationers and was well appreciated by them.

5.15.3 Publications

- **Post Budget Memorandum - 2009**

The Committee submitted the Post Budget Memorandum – 2009 to the Chairman, and other Senior Officials of the Central Board of Excise and Customs on 20th July, 2009. Further, the Post Budget Memorandum was also hosted on the website of the ICAI.

- **Pre-Budget Memorandum - 2010**

On the basis of suggestions received from Regions and Branches, the Committee prepared the Pre-Budget Memorandum – 2010 containing the suggestions of the Institute and the same was submitted to the Government.

- **Post Budget Memorandum – 2010**

The Committee submitted to the Government the Post Budget Memorandum - 2010 containing the suggestions of the Institute relating to the indirect taxes on the Budget – 2010 proposals. The same was also hosted on the website of the ICAI.

- **Guide to Goa VAT Audit – New Publication**

It was decided to bring out Guides on State VAT Audit as members also handled matters relating to State VAT. In this regard, the Workgroup on Goa VAT Audit constituted by the Committee for bringing out the "Guide to Goa VAT Audit" provided the basic draft of the "Guide to Goa VAT Audit", which was finalised and published by the Committee.

- **Guide to Karnataka VAT Audit – New publication**

Similarly, the Committee also constituted the Workgroup on Karnataka VAT Audit for bringing out publication "Guide to Karnataka VAT Audit" and the said Workgroup provided the basic draft of the publication, which was finalised and published by the Committee.

- **Recommendation on the Goods and Services Tax (GST) in India**

Taking into consideration the developments taking place in the Government for introducing the Goods and Services Tax in the country and the First Discussion Paper on Goods and Services Tax in India issued by the Government on 10th November, 2009, the Committee submitted the Recommendations on Goods and Services Tax in India to the Government in January, 2010.

5.15.4 Others

- **Articles on Budget - 2009 published in CA Journal**

The Committee invited articles on Budget proposals – 2009 relating to indirect taxes from members of the profession practising in the field of the indirect taxes. The related articles published in the Journal of the Institute – The Chartered Accountant – included : 'Budget 2009 – Service Tax Perspective' and 'Budget 2009 – Indirect Taxation – Devil in Fine Print?.'

- **Articles on Budget 2010 published in CA Journal**

After the Budget was presented on 26th February, 2010, as a general practice, the Committee invited members to contribute articles on the provisions of the Finance Bill, 2010 relating to indirect taxes. The related articles published in the Journal of the Institute – The Chartered Accountant – included : 'Amendments in CENVAT Credit Rules, 2004', 'Service Tax proposals under the Finance Bill, 2010', and 'Construction Services'.

5.16 Committee on Information Technology

5.16.1 Overview

Information Technology has today emerged as the business driver of choice, from a humble role of business enabler. Information Technology has brought about revolutionary changes in the way business is being transacted today as enterprises and governments are adopting IT in a big way to better manage their operations and offer value added services to their clients/ citizens through e-services/ e-governance initiatives - e-Banking/ e-Service/ e-Payments/ e-Governance/ e-Reservations/ e-Procurement/ e-Tender!

IT Enabled Services (ITeS) like Enterprise Resource Planning (ERP)/ Business Process Outsourcing (BPO)/ Knowledge Process Outsourcing (KPO) are fast becoming the order of the day with the new WTO and the World fast transforming into a global village.

The Council of the Institute had constituted the Committee on Information Technology in the year 2000 to regularly map IT challenges and convert them into gainful professional opportunities for the profession through suitable education and development programmes like Post Qualification Courses/ Conferences/ Seminars/ Practical Workshops; apart from coming out with study guides, resources, e-learning/ computer based training modules.

The first initiative of the Committee was to equip CAs to offer IS Audit/ Systems & Process Audit Assurance (SPA) value added services, which are in increasing demand today, through the Post Qualification Course (PQC) on Information Systems Audit. CAs are increasingly offering these services to their clients, particularly Banks/ Financial Institutions/ Stock Brokers, where there is a statutory requirement.

Considering the demand from members in general and ISA members in particular, the Committee has started offering Practical Workshops on use of Information Technology to enhance the efficiency and effectiveness of operations, such that CAs can offer better value added services to their clients by use of IT as a tool. The Committee also offers CPE Course on CAAT to provide hands-on practical training on computer assisted audit techniques/ general audit software and has also released CAAT Resources CD.

The Committee has identified ERP Consulting as the next area for the development of the profession considering increasing emerging professional opportunities in this sector and has started offering courses on SAP FA & SAP MA, and Microsoft Dynamics NAV.

The Committee has launched e-Learning/ Computer Based Learning module on "Bank Branch Audit – An Overview" with Continuing Professional Education Committee (CPEC) of the Institute, "Using CAAT/ GAS", "Using MS-Excel 2007 as an Audit Tool", "Information Systems Security, Cyber Threats and Review - An Intro" and "Windows, Network & Wi-Fi Security - An Intro". The Committee also launched e-Learning courses on Service Tax, Transfer Pricing and IFRS. The Committee is actively endeavoring to develop competencies to facilitate increased professional opportunities for CAs in the IT area.

The Committee has also started offering Computer Appreciation Course for senior members in association with the CPEC as a part of the Institute's initiative to ensure that the profession is increasingly IT equipped. The batches of this Course are organized across the ITT Centres established by the Institute.

The Committee has started "Certificate Course on Forensic Accounting and Fraud Detection in IT Environment". The Course aims to develop investigative skills required to uncover corporate/ business fraud, measure resultant damage, provide litigation support/ outside counsel by applying accounting, auditing principles for the detection of frauds. The first batch of this Certification Course was conducted in January, 2009 at Mumbai.

5.16.2 Initiatives

5.16.2.1 Project Parivartan (Improving e-governance in ICAI): The Project 'Parivartan' was conceived with an idea of taking ICAI to a new way of working that would bring Chartered Accountants and CA students in the country as a CA Pariwar. The goal is to create a single and tightly integrated IT system for catering to the entire community of Chartered Accountants and students irrespective of their geographical locations through the Internet. Under this project, Workshops were organised earlier at New Delhi, Kolkata, Chennai, Kanpur, Mumbai, Bangalore, Ernakulam and Jaipur to get feedback from members and students. Infosys Technologies Ltd., a world leader in IT, is putting its strength to help the ICAI become a world class tech-savvy accounting body in the world.

5.16.2.2 Publications: The Committee has launched five new publications, viz., "Technical Guide on Systems Audit of Stock Brokers", "Technical Guide on Information Systems Audit", "Data Analysis for Auditors - Practical Case Studies on Using CAATs", "Technical Guide on IT Migration Audit" and "XBRL - A Primer" to help members develop expertise in these new areas.

5.16.2.3 International Initiatives: The Committee facilitated conducting ISA Course for members of the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka (ICASL) as per the MoU between the ICAI and the ICASL.

5.16.2.4 Revamped Committee Portal: The Committee has launched its new CIT Portal which is more user friendly and efficient with added features. The portal is developed in Visual Studio 2008 and is equipped with RSS Facility by which users are able to get the latest updates hosted on the site. The new portal has online e-Learning module on IS Security, Cyber Threats & Review. Members can access the Portal from <http://cit.ica.org>.

5.16.2.5 Forensic Accounting Course for Banks and RBI Officials: The Committee has agreed to facilitate in providing necessary assistance to College of Agricultural Banking (CAB), Pune for Forensic Accounting Courses for RBI Officials as a matter of Institute's Social Responsibility, and accordingly the Course was organized.

5.16.2.6 New Syllabus and Background Materials for on Information Systems Audit (ISA) PQC: The IT Committee launched the revised ISA Background Materials and that the same are used in ISA Professional Training (PT) Batches from 1st April, 2010 and will facilitate Eligibility Test with the revised syllabus in November, 2010 and ISA Assessment Test (AT) in December, 2010.

5.16.2.7 Post Qualification Course on Information Systems Audit: The Post Qualification Course on Information Systems Audit (ISA) continues to be very popular amongst the members. This Course has been a unique rallying point for members to develop and grow all over the country. The Committee organized 60 batches of ISA Professional Training at 60 centres and the ISA Eligibility Test was organized at about 61 centres, during the period under report. The following table provides the numerical data :

Particulars	Registration	ET Pass
As on April 1, 2009	28,935	19,760
During the Year	1,989	1,225
As on March 31, 2010	30,579	20,985

5.16.2.8 Registration Statistics of the Various Courses offered by IT

Committee: The details of registrations for CAAT, SAP ERP Course, Microsoft NAV Dynamics and Certificate Course on Forensic Accounting & Fraud Detection using IT & CAATs as on 31st March, 2010 is as follows :

Sr. No.	Course	Registrations as on 31 st March 2010
1.	CAAT	3,205
2.	SAP ERP Course	355
3.	Microsoft NAV Dynamics	74
4.	FAFD	33

5.17 Internal Audit Standards Board

A strong, skillful and independent internal audit function is fundamental to achieve effective corporate governance. Internal auditing is considered one of the four cornerstones of corporate governance - along with the board, management, and external auditors. Charged with assessing and monitoring risks and with providing assurance as to the effectiveness of the controls that are in place within an organization, internal auditors are on the front lines of corporate accountability. Thus, internal auditors increasingly are recognized by stakeholders as key to ensuring organizational success.

Internal audit related activities have also been in prime focus for the Institute of Chartered Accountants of India which was formalised by constitution of a non-standing Committee, Committee on the Internal Audit on 5th February 2004. The prime objective of the Committee is to reinforce the primacy of the Institute of Chartered Accountants of India as a promoter, source and purveyor of the knowledge of internal audit in the country. The basic idea was to enable the members of the Institute to provide more effective and efficient value added services related to the field of internal audit so as to enable the clients to systematise and strengthen their governance process by systematising and strengthening their control and risk management process.

Considering the crucial role being played by the Committee on Internal Audit in growth and development of the internal audit in India, the Committee had been converted into "*Internal Audit Standards Board*" in November 2008. This transformation from Committee to Board is a step forward by the Institute in building a new vision for internal audit which is able to meet the challenges thrown up by the dynamic business environment. The Board is working relentlessly to bring out high quality technical literature in the form of Standards on Internal Audit and Technical Guides/ Studies/ Manuals, which constitute an important tool in helping the internal auditors to provide effective and efficient internal audit services to the clients and/ or employers.

5.17.1. Standards on Internal Audit

The Institute has been bringing out Standards on Internal Audit as these Standards will go a long way in strengthening the position and building up the performance benchmarks for

internal auditors. The Standards represent a codification of the best practices for internal auditors. The Institute has issued sixteen Standards on Internal Audit till March 31, 2009, which, include those on Basic Principles Governing Internal Audit, Documentation, Analytical Procedures, Internal Audit Evidence, Reporting, Enterprise Risk Management, etc.

During the period, the Internal Audit Standards Board has issued the following SIA:

Standard on Internal Audit (SIA) 17, *Consideration of Laws and Regulations in an Internal Audit.*

This Standard on Internal Audit (SIA) deals with the internal auditor's responsibility to consider laws and regulations when performing an internal audit. This SIA also applies to other engagements in which the internal auditor is specifically engaged to test and report separately on compliance with specific laws or regulations

5.17.2 Technical Guides:

In addition to bringing out Standards, the Board is also working aggressively on formulating industry specific guidelines on internal audit. The Board has issued Technical Guide on Internal Audit of Oil & Gas Industry, Aluminium Industry, Telecommunications Industry, Stock Brokers, Intangible Assets, etc. The basic objective of these Technical Guides is to help the members as well as other readers in understanding the basic operations undertaken in the relevant industry. These Technical Guides also comprehensively cover detailed procedures to be undertaken by the internal auditor in respect of the specified areas.

During the period, the Internal Audit Standards Board has issued the following Technical Guides:

1. ***Technical Guide on Internal Audit of Treasury Functions in Bank.***

The purpose of this Technical Guide is to serve as a useful tool for the readers in understanding and appreciating the role and responsibility of the treasury function in banks as well as in determining the nature of internal audit procedures to be undertaken. The Guide also deals with the fundamental controls and the internal audit procedures with specific reference to treasury/market risk.

2. ***Technical Guide on Internal Audit of Educational Institutions.***

This Guide provides comprehensive reference material on operational as well as internal audit aspects relevant for various types of educational institutions.

3. ***Technical Guide on Internal Audit of Construction Industry.***

This Guide provides overall approach of internal audit with reference to Standards on Internal Audit and the procedures to be undertaken with regard to peculiar aspects of construction industry.

In addition, the Board has also undertaken the projects relating to formulation of Technical Guides on Internal Audit of certain industries/segments, including those in Sugar Industry, BPO Industry, Non-Profit Organisations, Infrastructure, Power, Entertainment, Electricity Distribution Companies, Hotel & Tourism, Aviation, Newspaper, Software Development etc.

Other ongoing projects of the Board are as follows:

- Diligence Report for Banks
- Study on Internal Audit Charter

- Study on Fraud Investigations
- Study on Co-ordination of Internal Auditors with Functional Heads
- Implementation Guides
 - SIA 4, Reporting
 - SIA 7, Quality Assurance in Internal Audit

5.17.3 Conferences and Other Programmes

With a view to create awareness about the latest developments in the field of internal audit, the Board has organised following programmes in association with the concerned Regional Councils and their branches:

- (a) Seminar on Internal Audit at Hyderabad
- (b) National Seminar on Internal Audit at Patna
- (c) Seminar on Internal Audit at Dehradun
- (d) Seminar on Internal Audit at Visakhapatnam
- (e) Seminar on Internal Audit – Tool for Management at Mumbai
- (f) Seminar on Internal Audit and ERM at New Delhi

5.17.4 Courses

The Board has successfully completed two batches of the ***Certificate Course on Enterprise Risk Management*** one each at Mumbai and New Delhi. The prime objectives of this Course is to impart the necessary technical knowledge and expertise and build upon the skill sets of the members of the Institute, thereby assisting them to play a leading role in various aspects of Enterprise Risk Management and develop it as an area of core competence.

Having regard to the professional and personal preoccupations of the participants, the Course is designed as a balanced mix of class room teaching, e-learning as well as self study. The class room teaching comprises of a 6 week class room time framework with classes being held on six Saturdays.

5.17.5 Others

The Board had also issued Brochure "***What is an Internal Audit***" highlighting the evolving needs of modern organisations and the changing role of internal audit function.

5.18 Committee on International Taxation

With the advent of globalization and liberalization, the globe is reduced to a small village with unimaginable growth in movement of men, capital and goods across the borders of the sovereign countries. The cross border transactions had tax implications different from the domestic transactions. A Chartered Accountant is required to be fully equipped with the knowledge of such tax implications. It was also realized that the need was across length and breadth of the country and not necessarily limited to metro cities.

Considering the need for better understanding of tax implications of increasing number of cross border transactions, a separate Committee on International Taxation was constituted in the Institute for the first time in the year 2009 with the principal objective of spreading the knowledge of International Taxation among the members so as to strengthen their capacity to be a good advisor to the users/receivers of their services. The aim is to empower

the members to have better understanding of International taxation and capacity to apply the knowledge to practical situations.

5.18.1 Activities

- With a view to have structured approach in its efforts, the Committee introduced and successfully completed three batches of Post-qualification Certificate Course on International Taxation in Mumbai, Hyderabad and New Delhi. In order to add value to the Course an Assessment Test was conducted for the participants who had attended the Course and certificates awarded to the successful participants. It is also heartening to note that the participants derived excellent value addition from the valuable contribution made by the eminent members of the profession having practical exposure in the subject and also senior departmental officers dealing with the subject. These certificate courses have been very well received by the members and there is ever increasing demand from many parts of the country for organizing these courses. Further, in response to demand from the members abroad, efforts are being made to launch this Course in select centers abroad.
- The Committee's suggestions in relation to International Taxation in the context of Direct Taxes Code Bill, 2009 were appropriately included in the Memorandum submitted by the ICAI to the Government.
- In order to broad base its activities, the Committee has become a member of the International Fiscal Association.
- In order to facilitate availability of the Course to the members located in remote and smaller places, the Committee has taken steps to popularize e-learning mode of imparting education in International Taxation. Accordingly, in collaboration with the Committee on Information Technology, an e-learning module in transfer pricing has been launched.

Apart from the above activities, the Committee brought out following publications 'International Taxation - Background material' and on 'ABC on Double Tax Avoidance Agreements'.

5.19 Committee for Members in Industry

5.19.1 Overview

The Committee for Members in Industry is involved in encouraging and enhancing close links between ICAI and the Chartered Accountants working in industries in various capacities so as to provide them, a base of reference in terms of knowledge, expertise, skills and assistance in individual career growth through the development of extensive and intensive relationship with organizations and agencies of the Government, so as to provide the maximum possible exposure to the world of trade, commerce, industry and governance, while simultaneously pursuing the goal of providing the maximum of employment opportunities.

The Committee also provides assistance to members of the Institute in finding appropriate career opportunities in the industry. In this regard, the Committee is engaged in providing placement services to the following categories of members and students of the Institute:

- (i) Newly qualified Chartered Accountants through the campus placement programme.
- (ii) Experienced Chartered Accountants – who are presently serving in industry.
- (iii) Semi Qualified Accounting Professionals.

All the above services are being administered through the Placement Portal www.cmii.icaai.org and <http://Jobs4CAs.icaai.org>. The ICAI placement portal provides an opportunity to both qualified as well as semi qualified and the industry to interact with the objective of building capacity for international best practice oriented finance and accounting culture in the Indian industry.

5.19.2 Career Assistance Programmes organised for the benefit of the Members of the Institute

- Campus Placement Programmes for the members continued to be held during the year – one in August-September, 2009 and another in February-March, 2010 - at a number of centres/places. The highest salary offered at the above programmes was `70 lakhs and the minimum salary offered was `3 lakhs. A total of 2,436 candidates were got job offers.
- Special Campus Placement Programmes for those who had undergone three months residential programme on Professional Skills Development (General Skills) were also organized in May, 2009, October, 2009 and January, 2010. 7, 13 and 6 organisations participated in the above Special Campus Placement Programmes and offered jobs to 28, 45 and 16 candidates respectively.
- Campus Placement Programme exclusively structured for Small & Medium sized Enterprises (SMEs) and Small & Medium Chartered Accountants firms
- The Campus Placement Programme for qualified Chartered Accountants for Small and Medium sized Enterprises (SMEs) and Small and Medium Chartered Accountants firms were held during June, 2010 at thirteen centres across the country to further improve the penetration of the Campus Placement Programme amongst each and every possible employers of CAs. In all 133 candidates got job offers from 69 organizations.

5.19.3 HR Meets

As a relationship building endeavour with the Industry, the Committee has organised a series of HR Meets at (1) Bangalore, (2) Chennai, (3) Kolkata, (4) Mumbai, and (5) New Delhi.

5.19.4 ICAI Job Portal <http://Jobs4CAs.icaai.org>

The Committee has launched ICAI Job portal on 21st August, 2009. The said Job Portal has been designed and developed to provide a platform for industry to fill their vacancies and for chartered accountants to get jobs.

5.19.5 Redesign of Placement Portal www.cmii.icaai.org

The Committee for Members in Industry has re-designed the Placement Portal www.cmii.icaai.org to make it more user friendly and convenient for companies and Chartered Accountants to interact with the Institute.

5.19.6 Formation of CPE Study Circle for Members in Industry

As a proactive measure to meet the CPE requirements of the Members in industry, the Committee was instrumental in formulation of the Norms for the CPE Study Circles for Members in Industry. The Committee has already registered 30 CPE Study Circles for Members in industry, across various regions. These are spread in different parts of the country, viz., Bangalore (5), Chennai (2), Delhi (1), Gurgaon (2), Hooghly (1), Kolkata (1), Mumbai (6), New Delhi (3), Noida (2), Nungambakkam (1), Pune (2), Surat (Hazira) (1), Tamil Nadu (1), Trichy (1), Visakhapatnam (1)

5.19.7 Developing Competencies amongst the Members of Institute in Industry

• Publications

- The Committee has brought out two editions of 'Handbook for Newly Qualified Chartered Accountants' for the benefit of newly qualified Chartered Accountants to enable them to face the interviewing team and at the same time enlighten themselves with matters relating to general knowledge and topics relevant to them.
- The Committee has released three issues of eNewsletters of the Committee - 'Corporate Communique'.
- Invitation for Expression of interest for Authoring Publications relevant to the members serving in Industry was also released by the Committee.
- The Committee contributes articles in the Chartered Accountant Journal under the heading Career Watch after the completion of its each Campus Placement Programme.

• Webcasting with eminent leader in profession

The Committee has organized on 14th December, 2009 a webcasting programme on issues concerning the latest trends in Indian economy and the role of Chartered Accountants with CA. Keki Mistry, CEO, HDFC Group and CA. Uttam Prakash Agarwal, President-in-Office at the relevant time.

• Programmes Organised

In its endeavour to provide tailor made technical training to the members in Industry, Committee successfully organized 24 Programmes across the regions of the Institute on variety of topics, including those on Personality Development and Goal Setting for Professionals, Information Technology, Private Equity, Developing competencies to promote excellence, International Taxation, IFRSs, and XBRL.

5.19.8 CPE Requirements for members In Industry

CPE requirements have been made mandatory for all the members who are not in practice w.e.f. 01.01.2008, according to which '.....All the members who are not holding Certificate of Practice or are residing abroad (whether holding Certificate of Practice or not), unless exempted, are required to:

- Complete at least 45 CPE credit hours of structured/unstructured learning in each rolling three-year period

- (b) Complete minimum 10 CPE credit hours of structured/unstructured learning in each year.'

5.19.9 Statistics of the Members Working in Industry

The total number of members in industry, vis-à-vis, membership of the Institute are as follows :

As on	Members in Industry <i>[Total of not in practice and part time practice]</i>	Total Membership
1 st April, 2005	56677	123546
1 st April, 2006	62920	130946
1 st April, 2007	70897	139841
1 st April, 2008	76502	145481
1 st April, 2009	83238	153600
1st April, 2010	88054	161516

5.19.10 CFO Guild and Members in industry Guild

CFO Guild: This Guild comprises of members occupying high positions (CEO/CFO/Treasury Head/Head of Analyst, GM or above) in Industry. The Primary objective of setting up such a guild is to develop a platform where highly intellectual & talented pool of people from various organizations can discuss various issues. They can plan, formulate and strategize policies for improving the image of the Chartered Accountants in the eyes of the Industry. 3510 members are registered in this Guild till now.

Members in Industry Guild: The Primary objective of setting up such a Guild is to develop and maintain an industry wise database of the members of our Institute serving in industries. The Guild acts as a forum where various issues concerning the profession in general and for Members in Industry in particular are discussed. 536 members are registered in this Guild till now.

5.19.11 Significant Initiatives

• Satisfaction Survey

The Committee has hosted online the questionnaire for conducting the satisfaction survey amongst the employer and candidates which are given below.

- Pre Selection Questionnaire - For Candidate
- Post Selection feed back form - For Candidate
- Company Feedback form

This survey was aimed at analyzing the reasons behind the rising attrition.

• Results of Survey:

The maximum number of respondents ranked Growth and Development as the No.1 factor and Job Profile as the No.2 factor. Organization Brand Value stood as the No. 3 factor which was followed by location of posting, compensation and work timing respectively at No 4, 5, and 6 positions.

Growth and Development was found to be the driving force for joining an organization followed by the Profile, Organization Brand Value, location of posting, Compensation and work timing respectively.

• **Recognition of Members in industry working in Non Conventional area:**

The Committee took an unprecedented initiative to highlight the members in industry working in the areas that are not conventional to the profession of chartered accountancy. Select experiences of the chartered accountants in the non-conventional areas such as marketing, software development, risk management, legal, socio-economic and management consulting were included in the Brochure for the Campus Placement Programme, website of the ICAI and the CA Journal.

• **Recognition of the Corporate Entrepreneurs of CA Profession**

The Committee has invited quotes from the leading industrialists about the importance of Chartered Accountants in Industry for publication in the Institute's Journal.

5.19.12 Third Annual Corporate Forum

The Committee organized the unique Annual Corporate Forum at Goregoan Sports Club, Mumbai from 29th January to 31st January, 2010.

The ICAI forum comprised of high-profile concurrent events including:-

- Career Ascent – Mid Career Campus
- Special Campus Placement Programme
- Accounting Thrust – Career Fair for ICAI Certified Accounting Technicians
- Corporate Conclave - In Pursuit of Excellence (Four Programmes)
- Capital Advantage - Invest & Buy Mart
- ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting
- ICAI Awards 2009 – Corporate CA Achiever's Acclaim
- ICAI CA Career Counselling Programme for aspiring students of CA Course

Results of Placement Event (29th – 30th) January, 2010			
S. No.	Name of the Event	No. of Candidates Selected	CTC Offered (per annum)
1	CAREER ASCENT	32	` 6 lacs – ` 13 lacs
2	ACCOUNTING THRUST	1	\$24000 - \$30000 for International posting

Registrations of the Corporate Conclave

Name of the Programme	No. of Participants
Conclave on Cyber Threats & Information Systems Security and XBRL organised jointly with the Committee on Information Technology, ICWAI and ICAN	190
Conclave on Inspiring Today, for Tomorrow (All India Mega Women Conference) organised jointly with the Women	53

Steering Group of the ICAI	
Conclave on Benchmarking Corporate Governance organised jointly with the Committee on Corporate Governance	110
Conclave on Challenges & Roadmap to IFRS organised jointly with the Accounting Standards Board	234

Capital Advantage

An exhibition to showcase financial and investment products and services to Chartered Accountants, which was participated in by corporate leaders and decision makers was conducted during 29th – 31st January, 2010, which was participated in by Bharti AXA Life Insurance/ BSE/ Fidelity MF/ HDFC/ Ideal e-live/ KDK software/ LG/ MCX-FTKMC/ United Stock Exchange.

ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting were conducted 30th January 2010.

ICAI's Award 2009 - Corporate CA Achievers Acclaim: The ICAI Awards 2009 function was conducted on 31st January, 2010 to acknowledge Chartered Accountants in industry who have demonstrated their excellence. The distinguished jury included the following:-

S. No.	Name	Designation	Company Name
1	Shri Adesh Gupta	Executive Director/CEO	Liberty Shoes Ltd.
2	Shri Akshaya Moondra	Chief Financial Officer	Idea Cellular Ltd.
3	Ms. Aruna Sharma	Director General	Doordarshan
4	Shri Arvind Khicha	Jt. Vice President (Coml.)	Shree Cement Limited
5	Shri Bharat Banka	MD & CEO	Aditya Birla Private Equity
6	Shri Gautam Vora	Managing Partner	ULJK Group
7	Shri K. Ullas Kamath	Dy. Managing Director	Jyothy Laboratories Limited
8	Shri Kamal K. Singh	Chairman & CEO	Rolta India Ltd
9	Shri M. M. Miyajiwal	Chief Financial Officer & Executive Vice President (Finance)	Voltas Ltd.
10	Shri Mahesh S. Gupta	Group Managing Director	Ashok Piramal Group
11	Shri Motilal Oswal	Chairman & Managing Director	Motilal Oswal Financial Services Ltd.
12	Shri P. R. Dhariwal	Managing Director & CEO	Essar Steel Caribbean Ltd.
13	Shri Ramesh D. Chandak	Managing Director & CEO	KEC International Ltd
14	CA. Uttam Prakash Agarwal	The President-in-office at the relevant time	ICAI
15	CA. V. C. Darak	Past Central Council Member	ICAI
16	Shri Venugopal Nandlal Dhoot	Chairman	Videocon Industries Ltd.
17	Shri Vijay Shah	Managing Director	Piramal Glass Ltd.
18	Shri Yogesh Agarwal	Chairman & Managing Director	IDBI Bank

Award Winners

Sl. No	Category of Award and Name of the Awardee	Current Designation	Name of the Organisation where serving
I	Business Achiever - Corporate		
	CA. Arun Kumar Nanda	Executive Director & President	Mahindra & Mahindra Ltd.
II	Business Achiever - SME		
	CA. Paresh Jamnadas Rajde	Chief Managing Director	Suvidhaa Infoserve Pvt. Ltd.
III	CFO - MANUFACTURING		
	CA. Tarun Jain	CFO	Vedanta Resources PLC
IV	CFO - ENGG & CAPITAL GOODS SECTOR		
	CA. Ajay Seth	ED (Finance) & CFO	Maruti Suzuki India Limited
V	CFO - PUBLIC SECTOR		
	CA. G .N. Nair	Director-Finance	Central Warehousing Corporation
VI	CFO - SERVICE SECTOR		
	CA. Mukul Gupta	CFO	Om Logistics Ltd.
VII	CFO - FMCG / HEALTH CARE / RETAIL SECTOR		
	CA. R. Sankaraiah	CFO	Jubilant Organosys Limited
VIII	CFO - IT / MEDIA COMMUNICATION ENTERTAINMENT SECTOR		
	CA. Yunus Zulfikar Bookwala	Finance Head	Capgemini India Pvt. Ltd.
IX	CFO - FINANCIAL SECTOR		
	CA. Rakesh Jain	Director & CFO	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.
X	CFO - INFRA & CONSTRUCTION		
	CA. Vardhan Dharkar	CFO	KEC International Ltd.
XI	Professional Achiever - MANUFACTURING		
	CA. Mukesh Babu Agarwal	Finance Head	Ultratech Cement Limited
XII	Professional Achiever - ENGG & CAPITAL GOODS SECTOR		
	CA. D. D. Goyal	Chief General Manager - Finance	Maruti Suzuki India Limited
XIII	Professional Achiever - SERVICE SECTOR		
	CA. Vikas Khemani	Executive President Institutional Equity	Edelweiss Securities Ltd.
XIV	Professional Achiever - PUBLIC SECTOR		
	CA. Srinivas Gurazada	Director	O/o The Comptroller & Auditor General of India

XV	Professional Achiever - WOMAN		
	CA. Rupshikha Saikia Borah	General Manager - Treasury	Oil India Limited

5.19.13 New Initiatives

The new initiatives of the Committee include the following :

- National Young CA in Industry Award 2010
- Study tours for Members in Industry
- Constitution of Industry Specific Groups on certain Industries to address specific issues concerning them
- Organizing programmes in collaboration with apex trade and industry associations for the benefit of members in industry
- Increasing Interface between the Committee and the members in industry who are residing abroad to provide them better services and take their inputs for external reach of the Indian Accountancy Profession
- Involving Members in Industry in responding to Exposure Draft issued by the ICAI
- Meeting Top industrialist/CEO/CFO
- Creating Jobs for Chartered Accountants in mofussil towns
- To bring new publications for the members in industry
- Organising placement for members of ICAI through video conferencing for the corporates based in gulf countries

5.20 Peer Review Board

The Peer Review Board was established by the Council in the year 2002 with the objective of putting in place a mechanism to proactively pursue, upgrade, maintain and enhance the quality of attestation services. The Board, comprising of members of the Council and representatives from Government and other bodies like the Ministry of Corporate Affairs, C&AG, SEBI & CII, is moving forward in ensuring that the reviews are carried out as per the best global practices.

The Securities & Exchange Board of India (SEBI), vide its circular no. CIR/CFD/DIL/1/2010 dated April 5, 2010, has made mandatory with effect from April 1, 2010 for the listed entities, that limited review/statutory audit reports submitted to the concerned stock exchanges shall be given only by those auditors who have subjected themselves to peer review process and who hold a valid certificate issued by the 'Peer Review Board' of the Institute.

The Comptroller & Auditor General of India (C&AG) has also recognised Peer Review Board's work as it seeks additional details from the Chartered Accountants firms about their Peer Review Status in the application form for allotment of audit for Public Sector Undertakings. Furthermore from last few years the C&AG annually seeks details from the Institute of those firms which have been issued certificate by the Peer Review Board.

In order that there is consistency and uniformity in carrying out reviews by the Reviewers, the Board imparts training to the Reviewers, before assigning them the practice units for review. The training modules specially developed for the purpose "Training Modules for Peer Reviewers" is provided as training curriculum for Reviewers and also guidance for the training facilitators on how to conduct reviewer's training.

The Peer Review Process aims to cover all firms of Chartered Accountants (PUs) in a phased manner in three stages. PUs covered under Stage I have been selected in 5 phases and those under Stage II have so far been selected for 4 phases. Selection of PUs under Stage III has also been made under phase I thereof. The number of PUs thus selected aggregate to 10293.

5.20.1 Initiatives of the Board

In order to provide the latest and updated information to members, the Board brought out an updated and improved version of the FAQs for the benefit of members.

The Sub-Committee of the Board for consideration of the Final Clean, qualified and the follow up reports met during the year and in total 4441 Practice Units have been issued Peer Review Certificates by the Peer Review Board till June 2010.

The Board has constituted its Sub Group to revise the Statement on Peer Review.

The Board decided to revise the Questionnaire which is given to the Practice Units by the Board mentioning the details of their firms and submitted to the reviewer for further conducting the peer review of the Practice Unit keeping in view Standard on Quality Control (SQC)¹.

5.21 Professional Development Committee

The Professional Development Committee was set up in the year 1962 as a non-standing Committee by the Institute of Chartered Accountants of India. The Professional Development Committee is one of the most vibrant Committees of the Institute which has always been making vigorous efforts towards exploring, and making available ample opportunities for the members of the Institute in different sectors of the economy. It determines the professional development needs and identifies issues and other areas, which can impact the profession. In order to achieve this, Committee has been striving to generate more professional opportunities for the members of the Institute by exploring/pursuing new/existing areas where the professional skills of the members could be utilized in a productive and fruitful manner. The Committee has also made considerable efforts to ensure that equitable opportunities are available to all members of the profession. Apart from exploring uncharted territories in the professional development, the Committee strives to strengthen the communication process with multitude of users across the different sections of the society and educate them about the role of Chartered Accountants. With a view to enhance skill sets of Chartered Accountants in the existing and new areas, it also organizes seminars, workshops on contemporary areas of interest.

The Committee took many initiatives during the year, like holding meetings with different officials of Ministry of Finance, in different government departments, regulatory bodies etc. Besides meetings, Committee organized seminars and workshops with the objective of improving the skills of the members, keeping them abreast of the new rules & regulations and bringing members and regulators closer to each other.

The major achievements/endeavors of the Committee in this reporting period are given below:

- Meeting with the Minister of State of Finance and officials of the Ministry of Finance, Reserve Bank of India on issue relating to managerial autonomy in the appointment of statutory auditors.
- SEBI revised the fees for inspection audit of Mutual Funds, applicable from the year 2008-09, with fees ranging from `70,000 to `8,50,000 based on size of assets under management.
- Meeting with the officials of the Reserve Bank of India on various matters of professional interest including revision of remuneration for Concurrent Audit of Banks, issues relating to bank branch audit/allocation & allotment, issues related to NBFCs, etc.
- Meetings held with the officials of NABARD to discuss various issues of professional interest such as revision of audit fee for Statutory Auditors, appointment and remuneration of auditors of District Central Co-operative Banks and audit manual for the auditors of RRBs.
- Meeting with the officials of Office of Comptroller and Auditor General of India on various issues of professional interest.

To explore more professional avenues, representation were sent to the :

- Hon'ble Minister of Rural Development, Government of India requesting to avail the panel of Chartered Accountants from Institute of Chartered Accountants of India for conducting various kinds of audits/assignments.
- Hon'ble Chief Minister of Gujarat requesting to avail the panel of Chartered Accountants from Institute of Chartered Accountants of India for conducting various assignments.
- Secretary, Department of Finance, Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 regarding appointment of only Chartered Accountants as auditor to conduct VAT audit.
- Chairman, State Bank of India in respect of appointment of tax auditor with reference to circulars issued in July, 2007 and December, 2009 allowing all Public Sector Banks to appoint at the Branch/Head office level, any chartered accountant firm as their tax auditor at a reasonable fee with the approval of their Board /ACB. The matter was taken up with the senior officials of SBI and convinced them to get the tax audit done from the existing branch auditors. However, in the process, SBI brought down the tax audit fee to 7.5% from the existing rate of 15% of the branch audit fee.
- Chairman & Managing Director, Bharat Sanchar Nigam Ltd. regarding usage of derogatory expression in the tender.
- Chairman, Securities and Exchange Board of India for revision of circular SEBI/IMD/CIR No. 8/176988/2009 dated September 16, 2009 to include DISA qualification as recognized qualification to conduct system audit of Mutual funds and Assets Management Companies.
- Director, Maharashtra State Agricultural Marketing Board regarding appointment of chartered accountants as auditor of Agriculture Produce Market Committee in Maharashtra.
- Hon'ble Governor, Madhya Pradesh regarding Section 39(2) of Madhya Pradesh VAT Act for furnishing of audit report prepared by a Chartered Accountant and a meeting was held.

- Chairman, Forward Markets Commission regarding Performance Audit/ Inspection of books of accounts of members of Commodity Exchanges and subsequently a meeting was held with the Member, Forward Markets Commission.
 - Chairman & Managing Director, Central Bank of India requesting to reconsider the restrictive criteria mentioned in the advertisement RFP CBI/CAD/BS/RFP-CONS/I/2009-10 hosted by Central Bank of India on its website for proposal for appointment of Consultant for Convergence with International Financial Reporting Standards (IFRS).
 - Commissioner and Registrar, Co-operative Societies, Maharashtra State regarding Revision of Audit Fee Scale for Statutory Audit of various types of Societies.
- Besides the above, meetings were held with the following authorities with the objective to explore more professional avenues and to focus on the untouched areas in the existing avenues:
 - Principal Director, Railways and Executive Director (Accounting Reforms) Railways
 - Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance
 - Executive Director, Securities and Exchange Board of India
 - Deputy Governor, RBI and Executive Director, DBS, RBI
 - Comptroller & Auditor General, O/o of Comptroller & Auditor General of India
 - As a result of great stride for ensuring equitable professional opportunities and to provide more and more tasks, following authorities/organisations were provided the panels of Chartered Accountants/ firms :
 - The Oriental Insurance Co. Ltd
 - The Financial Commissioner & Principal Secretary, Chandigarh
 - Office of the Commissioner of Income Tax, Kanpur
 - Central Bureau of Investigation (Chennai)
 - Central Bureau of Investigation (Bangalore)
 - Central Bureau of Investigation (New Delhi)
 - Joint Commissioner, Office of the Chief Commissioner, Central Excise, Customs & Service Tax, Lucknow
 - The Chief Commissioner of Income Tax, Kanpur
 - The General Manager (Finance), Tehri Hydro Development Corporation Ltd.
 - 18 RoCs for empanelment of the professionals by RoC for technical scrutiny of balance sheet
 - The President, Sarvhit Residents Welfare Association, Delhi
 - The Joint Commissioner of Income Tax, Gorakhpur
 - UP Power Corporation Limited, Lucknow
 - Axis Bank Ltd.
 - Dena Bank, Mumbai
 - Hamdard Wakf Laboratory, New Delhi
 - Centre for Good Governance, Hyderabad
 - M/s Financial Transaction House, Saudi Arabia
 - Additional Registrar of Cooperative Societies, Chennai
 - The Regional Officer, All India Council for Technical Education, Kanpur
 - In its endeavour to consider ways and means to provide specific assistance in improvement of skill and talent of our members, the Committee organized the following Conferences/Seminars/Workshop/training programmes during the period:

- An Interactive Meet of Chartered Accountant Directors on the board of Public Sector Banks at New Delhi.
- Workshops for Auditors of Non Banking Financial Companies at Bangalore and Meerut.
- National Conference on Professional Development & Enrichment at Goa.
- National Conference on "CA – Core of Global Economy - Practice & Innovations" at Chandigarh.
- The tripartite Workshops involving ICAI, O/o C&AG and CMDs/ Director (Finance) of State PSUs for Auditors of State PSUs at Varanasi, Jaipur, Ranchi, Raipur, Patna and Bhopal.

5.22 Committee on Public Finance & Government Accounting

The Committee on Public Finance and Committee on Government Accounting constituted earlier have been merged and a rechristened Committee, viz., Committee on Public Finance & Government Accounting constituted for the year 2010-2011. The activities/initiatives of the said two Committees are as follows.

5.22.1 Committee on Public Finance

Committee on Public Finance is a stepping stone in Institute's mission of partnering with the Government in Nation's building to meet its social obligation by providing professional services of Chartered Accountants beyond corporate sector and to the public at large.

Accordingly, the Committee focuses on study, research and report on fiscal policy, financial planning, revenue and expenditure, public debt management, developmental schemes, welfare schemes, industrial and agriculture sector growth, financial resources and distribution of income & wealth at Centre, State and Local Level.

The Committee also undertakes and organizes training programmes, courses, seminars, and workshops for Government officials, bureaucrats and persons involved in machinery of public delivery system.

Making its approach more effective and result oriented, the Committee holds regular dialogues with the Governor, Chief Minister and Finance Minister of States and also interacts with CEOs of PSUs, Commissioner of Municipal Bodies and head of National & International Financiaries funding developmental programmes in India.

The major initiative of the Committee during the year are as under :-

- On 14th April 2009, the Committee invited Hon'ble Prof. Atul Sarma, Member, Thirteenth Finance Commission as the Chief Guest in its sixth meeting and he deliberated upon Federal Finance Structure in India and progress of Indian Economy.
- Conducted Workshop on Outcome Budget and Accrual Based Accounting System for Orientation to the officials of Agartala Municipal Council on 15th & 16th May, 2009 at Agartala, Tripura.
- On 26th May, 2009, seventh meeting of the Committee was held in which Hon'ble Finance Minister of Delhi, Dr. A.K. Walia was invited as Chief Guest. Dr. Walia

discussed with the members on various issues related to infrastructure development in metros and sub-urban areas, highlighting his major contributions in Delhi.

- On 18th June, 2009 at a meeting conducted at Mumbai with Shri Ashok Chavan, Hon'ble Chief Minister of Maharashtra, the Vice-President, ICAI and the Chairman and Vice-Chairman of the Committee met the Chief Minister and discussed the issues related to Public Finance in the State.
- Conducted Workshop on Municipal Administration and Accrual Accounting for officials of Kohima and Dimapur Municipal Council on 20th & 21st August, 2009 at Kohima, Nagaland.
- Conducted Training Programme on Accounts, Municipal and PRIs Administration for officials of Finance & Accounts Department, Secretaries of PRIs and other officials of Andaman & Nicobar Administration from 14th to 18th September, 2009 at Port Blair, Andaman & Nicobar.
- Conducted Training Programme on Accrual Accounting, Treasury Management and Urban Local Bodies for the officials of Finance Department, Govt. of Mizoram from 17th to 20th November, 2009 at Aizawl, Mizoram.
- On 11th January, 2010, the Committee conducted its eighth meeting and invited Shri Mahabal Mishra, Member of Parliament as the Chief Guest. He shared his experiences in social work and up-liftment done for the lower class in Delhi and sought help of Chartered Accountants in better implementation of NREGA and other Government Schemes.

5.22.2 Committee on Government Accounting

The Committee on Government Accounting was constituted in the year 2008 with the following objectives:

- To review and on that basis suggest improvements to the existing Government Accounting System.
- Providing awareness of Government Accounting to the society at large and specifically to the stakeholders including, inter alia, to employees of the government, C&AG, members of the profession, media, NGOs and to citizens generally.
- To provide training within the Government bodies at Central, State, and District level, including Local bodies and Gram Panchayats.
- To facilitate suitable interface with present day Information Technology and to evolve methods which would enable increased use of technology in assisting the accounting reform process.
- Collaboration and coordination with Comptroller & Auditor General of India (CAG), Controller General of Accounts (CGA) and various other Ministries for development of and improvements in the framework of Government Accounting System.
- To assist Central Government and the State Governments in enhancing accountability and transparency in Public service delivery mechanism.

- To suggest to the Central and State Government accounting reforms which would assist in widening the tax base and in better administration of the revenue collection and deployment machinery, as also to assist the process of outcome measurement and improved MIS, reporting and budgetary control mechanisms.
- To encourage the study of and create awareness in regard to government accounting within the profession and to undertake capacity building measures for the profession to enable the profession to assist the government in the process of implementation of government accounting reforms and for this purpose undertake studies, conduct training and awareness programmes, publish background material etc.

5.22.3 Activities undertaken

- A draft status paper covering the current state of Government Accounting, benefits of accrual accounting for the Government, experience of other countries, strategies and preconditions for implementation of accrual accounting in the Government etc. has been prepared by the office. The same would be finalized shortly.
- The Committee had received a proposal from office of C&AG for conducting module on IPSAS for the Sr. Officers of the CAG. The Committee successfully conducted the said training programme on IPSAS for the Sr. Officers of CAG on August 24-25, 2009 at ICISA, Noida which was very well appreciated by the participants.
- With reference to one of the relevant action point covered under the Action plan 2009-10 of the Committee on Government Accounting, i.e., *'to assist the Central and the State Governments in implementation of the accounting reforms'* - a letter was sent to all the State Governments introducing them to the Committee on Government Accounting of ICAI and inviting their queries relating to accrual accounting implementation. Replies from the State Governments are also being received.
- The Committee has given the detailed and exhaustive Comments on the GASAB's Accrual Exposure Draft (AED) 2 on *"Property, Plant and Equipment"* for consideration by the Government Accounting Standards Advisory Board (GASAB). The Committee has also drafted the Comments on the GASAB's Accrual Exposure Draft (AED) on *'Inventories'* for consideration of the GASAB.
- In accordance with the decision taken by the Committee to publish a booklet on government accounting running into 15-20 pages consisting of the current system of government accounting, drawbacks of the current system, how the accrual accounting would benefit the government if implemented etc., the basic draft of the booklet is under development. The target audience would be the Ministers at the State and the Central level.
- A Study on *"Accounting for food, fertilizers and oil bonds"* is also proposed by the Committee. The proposed study may cover the study on current methodology, drawbacks and deficiencies in the current system and recommendations for the improvement in the current practices. The study may cover all the aspects from the perspective of the Government as well as from the perspective of the Companies which issues food, fertilizers and oil bonds. The study may be undertaken by a Group to be formed for this purpose. The group may comprise of members from the Committee and some experienced people from the food, fertilizer and oil industry.

5.23 Research

Research is the foundation on which a profession grows and prospers. Realising the importance of research for the profession, the Council at its 17th meeting held in 1955 constituted Research Committee as a Non-Standing Committee. Since its inception, the Research Committee has been working relentlessly to provide guidance to the members of the Institute in various areas of professional interest. The Committee publishes Guidance Notes, Technical Guides, Studies, Monographs, etc., on generally accepted accounting principles and practices designed to enhance the value of the services rendered by the profession. It undertakes research projects concurrently in various areas to provide guidance to members and others concerned. The Committee also conducts a competition for the 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' annually. These awards recognise and encourage excellence in the preparation and presentation of financial information and are devoted to the cause of greater accountability and well informed decision-making.

5.23.1 Achievements of the Committee

During this period, the Committee released the following publications:

Technical Guide on *Estimation of Future Cash Flows and Discount Rates for the purposes of AS 28, Impairment of Assets*

Accounting Standard (AS) 28, 'Impairment of Assets', prescribes the principles that an enterprise has to apply to ensure that its assets are carried at no more than their recoverable amount. For this purpose AS 28 lays down the principles for the measurement of 'value in use' which in turn requires estimation of cash flows and the appropriate discount rates. However, a need was felt for providing guidance on many related aspects as regards the measurement of 'value in use'. Therefore, the Research Committee formulated this Technical Guide on '*Estimation of Future Cash Flows and Discount Rates for the purposes of AS 28, Impairment of Assets*' to deal with such aspects. This Technical Guide provides invaluable guidance in implementing the principles enunciated in AS 28 by taking examples from practical situations.

Technical Guide on *Accounting for Not-for-Profit Organisations (NPOs)*

With a view to incorporate the Accounting Standards issued/revised by the Institute since the issuance of the previous edition of this publication in the year 2006, the Research Committee brought out this Technical Guide. This Technical Guide is an attempt towards suggesting the accounting and financial reporting framework for NPOs. The purpose is to ensure accountability and transparency of NPOs in their operations. The Technical Guide explains the accounting of key elements of the financial statements – income, expenses, assets and liabilities, in the context of NPOs, in accordance with the Accounting Standards relevant to NPOs.

Technical Guide on *Accounting for Special Economic Zones (SEZs) Development Activities*

Keeping in view the peculiar and complex nature of activities involved in the development of Special Economic Zones (SEZs), the Research Committee has issued this Technical Guide that provides explicit guidance on accounting for SEZ Development Activities. The Technical Guide has been prepared with a view to explain, inter alia, the application of relevant

Accounting Standards in respect of transactions entered into by the SEZ Developers. It explains the accounting treatment for expenses incurred prior to and after the SEZ notification as well as those on rehabilitation and resettlement besides providing guidance on expenses incurred on land taken on lease for notification of SEZ.

5.23.2 Important Projects in Progress

Apart from the projects completed during the year, certain other projects of the Committee are in progress which are as follows:-

- (i) The Committee has undertaken the project of revision of the Guidance Note on Accounting for Oil & Gas Producing Activities. This initiative was undertaken to keep pace with the developments in Oil and Gas Industry and various amendments in laws.
- (ii) The Committee has also taken up the task of providing guidance on specific issues involved in the recognition of revenue for telecom operators through its Technical Guide on Revenue Recognition for Telecom operators.

It is also in the process of compiling list of the common discrepancies found by it in the evaluation of the Annual Reports at the time of assessing reports for awards for best presented accounts and is developing a publication to provide guidance on best practices.

5.23.3 ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting

Towards promoting better standards in financial reporting and preparation and presentation of annual reports, the Institute, through its Research Committee, started the **ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting** as early as 1958 albeit they were known as 'Best Presented Accounts Competition' then and has been holding it annually thereafter.

The objective of this competition is to recognise and encourage excellence in the preparation and presentation of financial information. These awards are instituted to encourage the effective compliance of the Accounting Standards and other pronouncements issued by the Institute as well as the legal and statutory requirements. The Competition for the year 2008-09 was held under seven categories based on the functional classification of various industries.

Shield Panel, a sub Committee of the Research Committee, meticulously Judges the financial and other information contained in the Annual Reports and Accounts of these enterprises. As per the scheme of awards, one Gold Shield and one Silver Shield are awarded in each category for the best entry and the next best entry, respectively. Plaques are awarded for commendable entries in each category. Apart from these, Hall of Fame is awarded to the entity that has been winning the Gold Shield under the same category continuously in the last five years, if any.

A total of sixteen awards - five Gold Shields, six Silver Shields and five Plaques were given away for the year 2008-09 as detailed hereunder:

5.23.4 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting'**Awardees for the year 2008-09**

Category		Award	Name of the Entity	Annual Report and Accounts for the year ended
I	Manufacturing and Trading enterprises (including Processing, Mining, Plantations, Oil Gas and enterprises)	Gold Shield	ACC Limited	December 31, 2008
		Silver Shield	Dr. Reddy's Laboratories Limited	March 31, 2009
		Plaque for Commended Annual Report	Hero Honda Motors Limited	March 31, 2009
II	Banking and Financial Institutions (including NBFCs, Mutual Funds, Unit Trust of India, Investment Bankers, HFCs, etc.)	Gold Shield	Axis Bank Limited	March 31, 2009
		Silver Shield	ICICI Bank Limited	March 31, 2009
		Plaque for Commended Annual Report	Capital Local Area Bank Limited	March 31, 2009
III	Service Sector (including Hotels, Consultancy, Transport, Stock Exchanges, R&D, Private Hospitals)	Gold Shield	Decided not to give the award	
		Silver Shield	Bombay Stock Exchange Limited	March 31, 2009
		Plaque for Commended Annual Report	Decided not to give the award	
IV	Insurance Sector	Gold Shield	ICICI Prudential Life Insurance Co. Limited	March 31, 2009
		Silver Shield	Birla Sun Life Insurance Company Limited	March 31, 2009
		Plaque for Commended Annual Report	IFFCO-TOKIO General Insurance Co. Limited	March 31, 2009
V	Information Technology, Communication and Entertainment enterprises	Gold Shield	Nucleus Software Export Limited	March 31, 2009
		Silver Shield	Decided not to give the award	
		Plaque for Commended Annual Report	Persistent Systems Ltd.	March 31, 2009
VI	Infrastructure & Construction Sector (including Power Generation and	Gold Shield	Decided not to give the award	
		Silver Shield	Nagarjuna Construction Company Limited	March 31, 2009

	Supply, Port Trusts, Metro, Roads)	Plaque for Commended Annual Report	Larsen & Toubro Limited	March 31, 2009
VII	Others (Section 25 companies, Educational Institutions, NGOs, Charitable hospitals and other organisations)	Gold Shield	The Akshaya Patra Foundation	March 31, 2009
		Silver Shield	Vidya Dairy	March 31, 2009
		Plaque for Commended Annual Report	Decided not to give the award	

The awardees of the Competition 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' for the year 2008-09 were felicitated at the function 'ICAI Awards' organised at Goregaon Sports Club, Mumbai in January, 2010. The function was attended by senior government officials, celebrities, industrialists, chief executives of large public and private enterprises.

5.23.5 Invitation for Research Proposals

With the view to increase participation in the research activities of the Institute, as well as to give a platform to genuine research talent, Research Committee invited applications for Research Projects from members and others, like management institutes, etc., for carrying out research in the field of accounting and other affiliated fields, e.g., accounting for chain departmental stores, accounting in health care industry, accounting for electricity generation and distribution companies, accounting in aviation industry, accounting for shipping companies, management control systems, approaches to social cost-benefits analysis in the Indian context, etc. Some of the research proposals received are under active consideration of the Committee.

5.24 Vision & Perspective Committee

The Vision Committee and the Perspective Planning Committee constituted earlier have been merged and a rechristened Committee, viz., Vision & Perspective Committee constituted for the year 2010-2011. The activities/initiatives of the said two Committees are as follows.

5.24.1 Vision Committee

The Vision Committee was entrusted with the task of developing Vision Statement with 2021 as the target year, presented ICAI Vision and Mission Pilot Document, 2021 in the Council Year 2008-09. The Council agreed with the Vision set out in the Pilot Document. The Committee, during the Council Year 2009-10 was tasked to further refine the same and draw up a concrete action plan to achieve the Vision so set out and to identify specific actions to be taken during term of the present, i.e., Twenty First, Council.

Significant Achievements and Initiatives : 2009-10

The Committee held interactive workshops with various stakeholders to validate its findings, to identify need, if any, to refine the Vision set out in the Pilot Document in light of the current developments and to assess actions required to achieve the refined Vision.

The Committee organized Workshops with participation of past presidents, past and present members of the Council and of the Regional Councils, senior professional from industry

segments and others at the national as well as the international level. The Workshops were held at Haridwar, Chennai, Kanpur, Pune and New Delhi.

5.24.2 Perspective Planning Committee

The Perspective Planning Committee considers all the emerging developments nationally and internationally which may have possible bearing on regulated area carved out for the profession and supplement further by suggesting ways and means to promote the role of Chartered Accountancy profession in other areas by flagging issues requiring attention. The activities/initiatives undertaken by the Committee during the year 2009-2010 included the following :

- **Reports on Financial Sector Reforms:** A detailed study of the following reports released during the last quarter of 2009 was made and submitted its recommendation to the Council -

- a) Raghuram G Rajan Committee Report on Financial Sector, Planning Commission
- b) Dr. Rakesh Mohan Committee Report on Financial Sector Assessment, RBI & GOI

The Committee developed a white paper highlighting the contribution of accounting profession in overall economic development in particular the role of ICAI in this regard.

- **European Commission Decision concerning transitional period for audit activities of third country auditors:** The Committee also considered the European Commission Decision of 29th July, 2008 concerning A Transitional Period for Audit Activities of Certain Third Country Auditors and Audit Entities including India. The matter is being deliberated at Council level since this European Commission provision would be contrary to the domestic regulatory structure of accountancy profession within India as well as have far-reaching ramifications for the Indian Inc.
- **Requirement of dealing international cases through separate cell:** Further, the Committee proposed of setting up a separate cell to deal with the complaint cases pertaining to international jurisdiction or received from international accounting bodies /regulators to the Council for its discussion in view of the increasing MRAs and globalization.

Significant Achievements

- **Interaction with FATF team:** The Committee had also presented the position of Indian accountancy profession to the visiting Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering team as a part of mutual evaluation exercise for granting India the membership of FATF as undertaken by Financial Intelligent Unit of Ministry of Finance and highlighted various initiatives undertaken by the ICAI in preventing the act of Money Laundering and combating the terrorism financing.

In order to keep the accountancy profession in tune with the developments taking place around the world and to provide an interactive platform for Accountants, the Committee organized two conferences — one, Diamond Jubilee National Conference on "Emerging Paradigm of Accountancy Profession : Issues and Perspectives" at Vijayawada on 26th-27th June 2009; and the other, All India Diamond Jubilee Conference on "Exploring New Horizons" at Hyderabad on 17th-18th July 2009.

5.24.3 Vision and Perspective Planning Committee

The rechristened Vision & Perspective Planning Committee, which is a fusion of two erstwhile Committees, viz., Vision Committee and Perspective Planning Committee, reviews emerging developments nationally and internationally to improvise the strategic work plan to achieve the long-term vision for building further up the profession's credibility and create a niche in emerging areas as well as to expand reach so as to be of greater value to society.

Significant Achievements and Initiatives : 2009-10

With a view to involve every stakeholder in the vision exercise, the Vision and Perspective Planning Committee is organizing vision workshops in 25 major cities with an objective to incorporate views from different geographies and different levels of development and perspectives considering the diversity of India. These workshop have already been held at Ahmedabad, Baroda, Nagpur, Nasik, Hyderabad, Mangalore, Chennai, Ernakulam, Lucknow, Bhopal, Jaipur, Jalandhar, Chandigarh, Faridabad, Gurgaon, Bhubaneswar, Kolkata and Guwahati. These workshops seek participation from members of the profession at the top echelon, regulators, eminent personalities along with the past and current council members seeking their inputs on the vision development process.

The Financial Action Task Force (FATF), an international group constituted by G-20 for assessing and enabling countries on money laundering aspects, after its interaction with the ICAI in December 2009, has completed its evaluative exercise in March 2010 and has submitted mutual evaluation report on anti money laundering and combating the financing of terrorism in India which includes evaluation of the DNFBP Professionals including Chartered Accountants. It is heartening to note that India has been given membership to the elite club of FATF which will enable India gain access to real-time data on terrorism funding which will further strengthen the national security.

5.25 Public Relation Activities

The Public Relations Activities in the year 2009-2010 took a leap forward as the Institute celebrated its Diamond Jubilee with the focus on enhanced brand building of the profession domestically and globally. This historic year saw an increased interaction with media, within the Institute - its members, branches and regional offices. The PR activities undertaken included the following:

- The Institute launched **"Planet Alert"**, a mega initiative in India to spread awareness and solutions, both at individual and government policy level to tackle climate change. The ICAI's President-in-office at the relevant time and Mr. Rahul Bose, Alert Ambassador, Planet Alert kick-started this mega movement to raise awareness on a planet in peril. The media covered this green initiative at wide level.
- An International Conference titled **"Winds of Challenges-Global Strategies for Accounting Profession"** was organized in Agra from 3rd to 5th July, 2009 where in 3 MoUs/Joint Declarations were signed. The Conference was attended by 2100 delegates and over 200 foreign delegates from over 25 countries. The whole event was given wide coverage in the media.
- With the advent of **"India Corporate Week"**, a sibling of Ministry of Corporate Affairs, the Institute co-partnered the Ministry in its initiative to disseminate knowledge amongst the public at large to enlighten them about the processes, structures and practices in

place to protect the interest of the stakeholder in the current market, while simultaneously encouraging the shareholders to join the governance process for unleashing the latent advantages of corporate governance. During the India Corporate Week, Her Excellency Smt. Pratibha Devisingh Patil, Hon'ble President of India, awarded the Institute with **"Recognition of Excellence Award"** for its valuable contribution in upholding the Corporate Governance norms of India Inc. The event was duly covered in the media.

- The ICAI organized the annual **ICAI Corporate Forum, Ascent to Pinnacle** in Mumbai from 29th to 31st January, 2010 which witnessed the presence of Shri Shriprakash Jaiswal, Hon'ble Union Minister for State for Coal, Statistics and Programme Implementation, CA. Kumar Manglam Birla, Group Chairman, Aditya Birla Group, and many more dignitaries. The whole event was given good coverage in the media.
- The **Campus Placement Programme** organized by the Committee for Members in Industry of the Institute in March, 2010 was a grand success and the media highlighted the top salary packages offered to the new Chartered Accountants all over India.
- The Institute organized a **special address** for its members on 12th March, 2010 at New Delhi wherein **Shri Salman Khurshid, Hon'ble Minister of State (Independent Charge), Ministry of Corporate Affairs**, addressed the members of the profession. The media covered the event at a large scale.
- The Institute signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the CBEC on 31st March, 2010. The media highlighted the importance of this MoU as it opens new professional avenue for the Chartered Accountants. CAs can now provide services to the assesseees of Central Excise and Service Tax in filing their returns and other documents electronically under ACES.
- A curtain raiser ceremony was organized by the Institute regarding the Chain-Workshops on Indian Accounting Standards converged with IFRSs at New Delhi on 29th April, 2010. The function was inaugurated by Shri R. Bandyopadhyay, Secretary, Ministry of Corporate Affairs. The event was given wide coverage by the media.
- The Media interactions increased through one to one interviews, constantly apprising the media of the latest developments on IFRS front, regarding the curriculum, profession, introduction of new courses, new guidelines for CAs, visit of foreign delegations, other activities and events etc.
- Promoted the potential and scope of Chartered Accountancy Profession in today's dynamic context by way of articles as well as through interactive meetings/releases issued to the press at national/regional level and through various TV Channels.
- Providing logistic support to various departments within the Institute and to the regional Offices and Branches with a view to develop communication link between the Institute and its offices/related organizations.
- As a part of the PR exercise, organized appropriate coverage in Print and Electronic Media to different Seminars/Programmes/Events/book launches of the Institute, organized by different Committees.

- The Press and Media continues to be apprised of the emerging developments in the profession through constant interactions and in particular after each of the Council meetings.
- The ICAI website continues to be a versatile medium for coverage relating to ICAI events wherein all press coverage about the various initiatives taken by the Institute for its members and students is duly highlighted.

6. INTERNATIONAL AFFAIRS COMMITTEE

6.1 Recognition of Indian Qualification by other Accounting Bodies

The process of dialogue for evaluation of the Institute's qualification by selected overseas accounting bodies, being a long drawn process, inter alia, involving the evaluation of qualification, training, continuing professional education, disciplinary requirements and involving domestic sensitivities, the results of the process are slow. Yet, at the same time, the Institute is continuing its efforts for early culmination of the process. The Institute had signed Memorandum of Understanding (MoU) with The Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW) and the University of Djibouti. Mutual Recognition Agreement (MRA) has been signed with CPA Australia and the ICAA. The process of qualification recognition is at various stages of discussion with accounting bodies in Canada, Singapore, Bahrain, Ireland etc.

6.2 Institute's Representation at International Forums

The prominent role played by the Institute is evidenced in the form of nomination it enjoys in the governing boards of international accounting bodies, namely, the International Federation of Accountants (IFAC), Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA) and South Asian Federation of Accountants (SAFA) in addition to their various functional Committees. The Institute is, through its nominees, currently represented on the following:

Committees of IFAC

- As Board Member
- Small and Medium Practices Committee
- Developing Nations Committee
- IFAC Compliance Advisory Panel
- International Public Sector Accounting Standards Board

CAPA

- As Board Member

SAFA

- As Board Member
- Committee on Education, Training & CPD
- Committee on Accounting and Auditing Standards
- Committee on Professional Ethics and Independence
- Committee for Improvement in Transparency, Accountability and Governance
- Committee on Professional Accountants in Business

- Committee on Quality Control
- Small and Medium Practitioners Committee
- Committee on Harmonization of Fiscal and Tariff Regime
- Task Force to review Constitution of SAFA
- President, ICAI as Board Member
- Secretary, ICAI as Permanent Secretary

6.3 MOUs/MRAs

The Institute of Chartered Accountants of India ICAI signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the *University of Djibouti*, Republic of Djibouti on 18th May, 2009 coinciding with the Africa Day Celebrations on 18th-19th May, 2009 at Mumbai. The MoU was signed for imparting training to Djibouti nationals in sphere of accountancy and working collaboratively for institutionalization of Accountancy Body in Djibouti.

The ICAI signed a MoU with *The Institute of Chartered Accountants in Australia* (ICAA), on 3rd July, 2009 at the occasion of the Inauguration of the International Conference "Winds of Challenges - Global Strategies for Accounting Profession" at Agra. The Conference was inaugurated by Sir David Tweedie, Chairman, IASB. At the said occasion, Ernest Almonde, President, AICPA and Professor Schilder, Chairman, IAASB were also present. The two Institutes have decided together to work out a Memorandum of Understanding to recognize the qualification, training of each other and admit the members in good standing by prescribing a bridging mechanism.

The ICAI signed a joint declaration with the *Certified General Accountants Association of Canada* on 4th July, 2009 coinciding with the ICAI's Diamond Jubilee International Conference "Winds of Challenges - Global Strategies for Accounting Profession" at Agra from 3rd to 5th July, 2009. The two bodies wish to work together to develop a mutually beneficial relationship in the best interest of members, students and their organizations.

The ICAI signed a Joint Declaration with the *Bahrain Institute of Banking and Finance* on 5th July, 2009 on the concluding day of the International Conference "Winds of Challenges - Global Strategies for Accounting Profession" at Agra, organized by the ICAI from 3rd to 5th July, 2009. The Declaration would establish closer working linkages between ICAI and *Bahrain Institute of Banking and Finance* as it will enable the two to draw synergies from the professional expertise available with each other in areas of accounting, financial engineering, corporate governance and alike.

Steps for undertaking further rounds of bilateral talks with the Institute of Certified Public Accountants, Singapore have been initiated to crystallize the MoU between two countries and also support the initiatives being undertaken by Government in this regard. Steps are also being taken to finalize the MoU with CICA and CPA Ireland also.

6.4 Opening up of Chapters Abroad

The 21st Chapter of ICAI at Singapore has been operationalized in January 2010.

Talks are on and the opening up of ICAI Chapter in Ireland, Thailand and Ras Al Khaimah are on the anvil.

The Institute is initiating dialogues and taking proactive steps in the opening up of ICAI Chapters in Switzerland, New Zealand, and South Africa. The foreign chapters of the

Institute have a pivotal role to play in furthering the Mission of the Indian Chartered Accountancy profession and this would be a stride forward in our aim to position our self as the Valued Trustees of World Class Financial Competencies, Good Governance and Competitiveness.

6.5 Inbound Delegation

• Visit of Delegation from Canada

Mr. Lyle Handfield, Vice-President, International and Corporate Affairs and Mr. Baldev Gill, Vice-president, Finance and Administration, Certified General Accountants Association (CGA) of Canada Visited the ICAI on 15th April 2009 to discuss the bilateral talks between the ICAI and CGA Canada for entering into a Mutual Recognition Agreement. The meeting aimed to discuss the comparative analysis of CGA Canada and ICAI and to carry forward the dialogue of MRA.

• Visit of Delegation from Bahrain

Dr. George Joseph, Ambassador of India to the Kingdom of Bahrain, visited the ICAI on 17th & 18th April, 2009 and had interactions with the ICAI representatives on the various issues concerning the development of the accounting profession in Bahrain and the significant role which the Institute can play in institutionalization the accounting profession. Steps have been taken at an active stage to open up the ICAI office at Bahrain.

• Visit of Delegation from the Canadian Institute of Chartered Accountants

A delegation from the Canadian Institute of Chartered Accountants led by CA Jylan Khalil, Director of CA Qualification along with CA Paule Massicotte, Principal of CA Qualification had visited the ICAI from 8th to 10th June, 2009 to discuss, in detail, the possibilities of reciprocal recognition agreement of professional qualification between both the Institutes.

• Visit of delegation from the American Institute of CPAs

Mr. Emile Almonte, Chairman, AICPA visited India from 30th June, 2009 to 4th July, 2009 to deliver a Keynote Address at the ICAI Diamond Jubilee International Conference in Agra. Coinciding with the visit, meetings with C&AG, CGA, Ministry of Finance and Ministry of Corporate Affairs also took place.

• Visit of delegation from ICAA

A delegation comprising Mr. Graham Meyer, CEO, The Institute of Chartered Accountants in Australia and Mr. Bill Palmer, Director Asia, ICAA visited ICAI on 12th and 13th April, 2010 to further strengthen the association formed after the ICAI and ICAA signed an MoU in 2009. During their visit to India, they had meetings with Deputy Comptroller and Auditor General of India and Secretary, Ministry of Corporate Affairs in addition to the ICAI functionaries. During the course of meeting, the delegation had the opportunity to discuss the way ahead for joint collaboration between the two Institutes and to explore the possibilities to work together more closely in future for the mutual benefit and to also discuss the challenges each body face in their respective jurisdiction.

- **Visit of delegation from Japan**

Further, delegation from Japan led by Mr. Noriaki Shimazaki, Chairman, Internal Affairs Committee IFRS Council of Japan visited the ICAI on 22nd April 2010 for formulating coordination between the two countries for the effective implementation of IFRS. The ICAI will play a key role to implement the understanding reached between these two countries along with The Japanese Institute of Certified Public Accountants. The deliberations have taken place in the presence of Shri Salman Khurshid, Hon'ble Minister of State for Corporate Affairs (Independent Charge), Shri R. Bandyopadhyay, Secretary, Ministry of Corporate Affairs, the Japanese Delegates and the officials of the ICAI led by the Vice-President, ICAI. The ICAI will address critical issues involved in convergence to IFRS and evolve consensus through process of consultation mutually agreed to.

- **Visit of delegation from IFAC**

A delegation from IFAC comprising Mr. Robert Bunting, President, IFAC, Mr Ian Ball, Chief Executive Officer, IFAC and Mr Matthew Bohun, Technical Manager, Governance and Operations visited India on 10th-12th May, 2010 for the proposed 19th World Congress of Accountants due in 2014 in Hyderabad, India. The delegation also met with the Hon'ble Chief Minister of Delhi, State Government Functionaries and also Secretary, Ministry of Corporate Affairs, in Delhi.

- **Visit of delegation from Xiamen National Accounting Institute**

A delegation from the Xiamen National Accounting Institute headed by Mr. Zhang Jun Professor, PHD in Economics, Xiamen National Accounting Institute; Zhang Meng Deputy General Director, Personnel & Education Department of Ministry of Finance; Shen Yi, Director, General Office, Xiamen National Accounting Institute; Zhang Jialin, Professor, Xiamen National Accounting Institute; CAO Yanjie, Associate Professor, Xiamen National Accounting Institute and Ye Hui, Deputy Senior Staff, Information Management Department, Xiamen National Accounting Institute visited ICAI on June 11, 2010 to interact with the ICAI functionaries and to have an insight about the Institute.

6.6 Africa Day Celebrations

The ICAI and Indo-African Chambers of Commerce and Industry celebrated Africa Day on 18th-19th May, 2009 at Mumbai. Diplomats from various countries from African Continent congregated to formalize strategy for working towards the growth of the Africa. The diplomats applauded the endeavors of India for development of African continent and expressed confidence for taking forward the productive relationship between India and Africa to new heights.

To mark the augmentation of relationship, a Memorandum of Understanding between the ICAI and University of Djibouti was signed for imparting training to Djibouti nationals in sphere of accountancy and working collaboratively for institutionalization of Accountancy Body in Djibouti. Hon'ble Shri S C Jamir Governor, Maharashtra, Hon'ble Shri Musalia Mudavadi, Deputy Prime Minister of Kenya and Shri Jayant Rao Patil, Minister of Home Affairs, Maharashtra Government graced the occasion.

6.7 Setting up of an International Federation of Accounting Technicians

The ICAI is considering the proposal for setting up International Federation of Accounting Technicians (IFAT) in line with International Federation of Accountants (IFAC) to promote the profession of Accounting Technician worldwide. The mission of the IFAT is to provide a framework to develop and strengthen the accounting technician profession as a semi-skilled certification through quality accounting education, training, ethical requirements, CPD, disciplinary requirements and professional outreach activities that meet the needs of all the stakeholders worldwide.

6.8 Contribution to Special Groups constituted by the Government of India

The ICAI is actively participating and contributing to Special Task Forces, namely, Indo UK Accountancy Task Force and Indo UK Task Force on Corporate Affairs constituted under the aegis of the Ministry of Commerce & Industry and the Ministry of Corporate Affairs respectively.

6.9 Conferences

An International Conference on the theme "Accountancy Profession - Beyond Regulatory Compliance" was organized from 3rd to 5th July, 2009 at Agra, Uttar Pradesh. The International Conference was attended by over 2100 delegates all across from the country and about 200 foreign delegates from over 25 other countries. The three day conference dwelt upon issues of emerging and contemporary significance, namely, harmonization of International Standards, Technology in Financial Sector, Bridging expectation gap, financial markets and beyond.

7. OTHER ACTIVITIES

7.1 Human Resource Development

To propel the organization into the next orbit of growth, it is essential for an organization to have sincere, dedicated and competent human resources at its command. Towards this, the Council not only continued to focus on retaining its high performance work force, but also initiated steps to attract the best and the brightest talent. Recognizing also the fact that training is the backbone for enhancement in the level of competence and personality development, continued emphasis was laid on participation in training programmes, courses organized within and outside the premises of the ICAI. Perhaps for the first time, more and more technical/academic hands in the Institute are deputed for the meetings of Committees of IFAC with a view to further enhance the academic excellence of individuals.

Aiming at future sharpening the skills and knowledge and also bringing attitudinal changes for providing quality services to members, students and others concerned, various structured training programmes on different topics were organized, as under, in the headquarters in Delhi as well as in regional offices.

TRAINING PROGRAMMES APRIL 2009 ONWARDS

S. No.	Date of Programme	Duration (Days / Hours)	Title	No. Of Participants	No. of manhours
Delhi Office					
01.	29 th April, 2010	One hour	Curtain raiser ceremony of the chain-workshops on Indian Accounting Standards converged with IFRSs	All chartered accountants 69	69 x 1 = 69 hrs
02.	7 th June, 2010 to 8 th June, 2010	8 hours	Orientation Course on International Financial Reporting Standards	All chartered accountants 69	69 x 8 = 552 hrs
Chennai Office					
01.	2 nd May, 2009	Half day	Fundamentals of Tally	20	20x4 = 80 hrs
02.	15 th June, 2010 to 18 th June, 2010	Four days	13 th National Convention for Librarians	01	1x4x8 = 32 hrs

The aforesaid is in addition to the areas/topics/specific programmes separately attended by individual officers of various committees/departments.

Besides, a family get-together-cum-Holi Milan of all employees and their families was organized on 27th February, 2010 at the headquarters of the Institute which was also participated in by the President, Vice President, and other members of the Council.

In its quest to attract the best and the brightest talent, time-scheduled recruitment drives with focus on faculty /academics were successfully undertaken during the period under report. Special initiatives have been undertaken in recruiting 26 more human resources meant for technical/academics and administrative positions in the different areas of the ICAI. Further, 62 management trainees have been absorbed at suitable levels.

Further HR Initiatives aimed at grievance redressal, timely counselling, enhanced facility management etc. taken during the period under report include, better and quality work environment, weekly departmental meetings, periodic employee counselling, together with grievance seeking and hardship mitigating steps.

During the period under report, various initiatives have been taken through Committee and Groups, viz., HR & Admin Committee, HR Group on revision of pay structure and HR Group on Review of Organisation strength at various levels/locations and determination of staff strength through identification of required strength vis-à-vis surplus etc. not only for harmonising the committee/department requirements and availability of staff but also to ensure attractive compensation to human resources. The initiatives so taken are expected to yield the desired results soon.

7.1.2 Procurement of DG Set for ITT labs/ branches

In line with the approval of the competent authority of the Institute, till date orders for 77 nos. of DG Sets of various capacities as per the requirement have been placed for different ITT labs set up through branches for uninterrupted back up power. Further, as per the approval of the competent authority, the facility of provision of DG Set has been extended to ITT Labs established/to be established under CPE chapters of the Institute. In most of the locations, installation and commissioning work has been completed and DG sets have been put to use. In the remaining locations DG Sets are expected to be operational by end of September 2010.

7.1.3 Accountancy Museum

The Accountancy Museum having rare & historic images like oldest balance sheet and documentary evidence of the evolution of accountancy was inaugurated at Institute's premises at C-1, Sector-1, Noida. Recognition/ permission has been given by the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Govt. of India for use the name of the museum as **Accountancy Museum of India** vide their letter dated 30th April, 2009.

7.1.4 Revamping of Administrative procedures

For effecting purchases and procurements, a review of the purchase policy was undertaken during the year, and a recast purchase policy put in place. Further, a Weeding out/Disposal policy having regard to the necessity to retain all records of historical/archival importance and for retaining the other records with reference to legal and other requirement has been put in place. Besides, review of continuation or otherwise of service providers was also undertaken.

7.1.5 Face-lifting of the main building of the Head Office

Renovation of Reception at the ground floor at the main building of the Head office of the Institute along with renovation of the front lawn of the Head office. Structural strengthening and repairing of the main building at the Head office of the Institute.

7.1.6 Representations made to different Government authorities/departments

A number of representations have been made through a Representation Committee constituted during the year 2009-2010 and the representations made during the year are as follows :

- Reserve Bank of India, Mumbai opposing autonomy given to banks to appoint auditors.
- Insurance Institute of India, Mumbai seeking exemption in their Licentiate, Associateship and Fellowship papers for members of the ICAI.
- The Department of Commercial Tax, Government of Uttar Pradesh seeking clarifications under Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 and VAT audit provision under the Act and also seeking general extension to obtain and submit the Audit Report till 30th June, 2009.
- The Charity Commissioner (Maharashtra State), Mumbai requesting for allowing Chartered Accountants to appear in matters pertaining to registration of societies and registration of trusts.

- The Chief Minister of Goa for introduction of Double Entry and Accrual Based Accounting System for Goa Government.
- The Controller of Certifying Authorities, Department of Information Technology, Government of India for empanelment of Auditors for auditing infrastructure of Certifying Authorities.
- The Central Board of Direct Taxes seeking clarification regarding new Form No. 17.
- The Central Board of Direct Taxes on undue hardship faced by assesses on account of delay of refund in scrutiny cases in respect of A.Y. 2007-08.
- Andaman & Nicobar Islands, Khadi & Village Industries Board asking them to amend their quotation notice for preparation, re-casting and auditing of the Budgetary Resources Account and Consortium Bank Credit Account, and bring the same in line with the Code of Ethics.
- Ministry of Finance, Government of Maharashtra and the Commissioner of Sales Tax (Maharashtra State), Mumbai regarding violation in the matter of VAT & CST Registration Certificate of Dealers in Maharashtra.
- Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India for empowerment of visually challenged Chartered Accountants by mandating their employment in government sector in finance and accounts areas.
- All Chief Ministers suggesting introduction of Double Entry Accrual Based Accounting system.
- Reserve Bank of India requesting them to provide updated list of districts to ICAI for Bank Branch Auditors Panel.
- The Law & Judiciary Department, Government of Maharashtra, Mumbai suggesting introduction of Amnesty Scheme and on-line system for compliances/registration of documents with the office of the Registrar of Firms, Maharashtra, Mumbai.
- Central Board of Excise & Customs proposing nomination of Chartered Accountants u/s 14A and 14AA of the Central Excise Act, 1944 for special audit.
- Comptroller & Auditor General of India regarding differential audit fee of Public sector and Private sector.
- The Ministry of Information Technology & Communications, Government of India seeking extension of time to submit the Annual Performance Report (APR) to the STPI.
- Chief Finance & Accounts Officer regarding Audit of schemes under Madhyan Bhojan Pradhikaran.
- The Central Board of Direct Taxes on genuine hardships and practical difficulties faced in getting a Certificate for lower deduction or non-deduction of tax at source.
- The Central Board of Direct Taxes on hardships and practical difficulties likely to arise in the filing of Income tax Returns for A.Y. 2009-10 with respect to the directions given in the CBDT Circular No. 03/2009 dated 21-05-2009.
- Reserve Bank of India regarding Remuneration for Concurrent Audit of Banks.
- The Deputy Comptroller & Auditor General of India requesting them to avoid turnover criteria while forwarding the panel to other Government authorities.
- The Comptroller & Auditor General of India regarding rationalisation of audit fees of public sector undertakings.
- The Principal Secretary, Panchayati Raj, Government of Uttar Pradesh requesting him to cancel the tender floated for appointment of auditors of Gram Panchayat - DPRO Faizabad.
- The Commissioner of Sales-tax, State of Maharashtra requesting him not to issue the Ordinance for formation of Institute of Sales Tax Practitioners.
- The Minister of State for Finance, Government of India, requesting reconsideration of autonomy given to banks to appoint auditors.
- Ministry of Rural Development, Government of India requesting them to avail the panel of Chartered Accountants from ICAI for conducting various kinds of audits/assignments.

- The Reserve Bank of India on procedure for allocation of Central Statutory Audits of Public Sector Banks.
- Ministry of Finance, Government of India, regarding expanding the scope of audit of Private Sector Banks & other related issues.
- Minister of Finance and Commercial tax, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal regarding memorandum on problems and hardships faced pursuant to implementation of VAT Act in Madhya Pradesh.
- Securities and Exchange Board of India (SEBI) for recognition of D.I.S.A. Qualification for Systems Audit of Mutual Funds.
- Reserve Bank of India, Mumbai to reconsider the present system of allotment of Statutory Bank branch audits.
- Finance Minister, Ministry of Finance, Government of India, suggesting to add a column in the Income Tax return to enable verification of the fact that the tax audit has been done by a chartered accountant.
- Executive Director, Reserve Bank of India requesting for increase in audit remuneration for Statutory Audits of Banks.
- Chief General Manager, Department of Supervision, National Bank for Agricultural and Rural Development requesting for revision in the fees of auditors of Regional Rural Banks.
- Deputy General Manager, SEBI (Market Intermediaries Regulation and Supervision Department) requesting that internal Audit for Credit Rating Agencies (CRAs) be conducted only by Chartered Accountants.
- Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce & Industry seeking nomination of representative of the ICAI on Board of Trade.
- Central Board of Excise & Customs seeking nomination of representative of ICAI on Customs and Central Excise Advisory Council and on the Regional Advisory Committees of the Commissionerates.

7.1.7 Outcome of efforts made

- The Insurance Institute of India has simplified the procedure for availing exemption in a few papers of Licentiate, Associate and Fellowship Courses.
- The Central Board of Direct Taxes issued clarification on the new Form No. 17.
- The Union Government included in its budget proposal 2009-10, an amendment to the Section 14A and 14AA empowering the Chief Commissioner of Central Excise to nominate a Chartered Accountant for conducting special audit.
- The suggestions given vide representation made to Minister of Finance and Commercial tax, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal regarding memorandum on problems and hardships faced pursuant to implementation of VAT Act in Madhya Pradesh received favourable consideration.
- Pursuant to the communication issued by Commissioner of Service Tax, President, ICAI nominated on the Regional Advisory Committee, Commissionerate of Service Tax, New Delhi.
- Pursuant to requests received from various Commissionerates, nominations have been made on the Dibrugarh, Cochin, Shillong, Kanpur, Jaipur and Chandigarh Commissionerates.

7.2 Infrastructure Initiatives

During the year 2009-2010, initiatives on Institute's Infrastructure and infrastructural related tasks were looked after by the Infrastructure Committee constituting during that year.

These tasks have now been assigned to the Infrastructure Acceleration Group constituted for the year 2010-2011.

7.2.1 Inauguration of ICAI Complex at plot no A-29, Sector- 62, Noida

The Administrative block of ICAI Complex at Plot no A-29, Sector-62, Noida was inaugurated by the President-in-office, ICAI, on 1st July, 2009 in presence of Mr. Ernest A. Almonte, President, American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) and the Vice-President-in-office, ICAI. Later, the entire complex was inaugurated by the President-in-office, ICAI on 17th January, 2010 in presence of the Vice-President, ICAI, and Shri R. Bandyopadhyay, Secretary, Ministry of Corporate Affairs.

7.2.2 Foundation stone laying ceremony of ICAI's building at Hatisur, Kolkata

The Foundation stone of the Institute's building at Hatisur, Kolkata was laid by the President-in-office, ICAI on 12th December, 2009. The proposed campus will be spread over a land of 15 cottahs.

7.2.3 Commencement of construction of Bandra Kurla Complex (BKC), Mumbai

The matter related to award of work, which was earlier subjudice, has since been settled, and the work has been awarded and the construction has commenced in full swing.

7.2.4 Inauguration of Residential block of Centre of Excellence at Hyderabad

The Residential Block of Centre of Excellence of the Institute at Hyderabad has been inaugurated by the President-in-office, ICAI on 2nd July, 2009 in the presence of CA. Shantilal Daga, Central Council Member at the relevant time.

7.2.5 Foundation stone laying ceremony of CA. Rameshwar Thakur Centre of Excellence at Bangalore

The Foundation stone of the Institute's Centre of Excellence at Bangalore was laid by the President-in-office, ICAI on 15th August, 2009. The proposed campus will be of residential type and will be spread over a plot of land of 10 acres. The selection of architect has been finalized and the construction of boundary wall is in progress.

7.2.6 Foundation stone laying ceremony of Centre of Excellence at Jaipur

Foundation stone of the Institute's Centre of Excellence at Jaipur was laid by the then Union Minister of Corporate Affairs in presence of the Chief Guest, the then Chief Minister of Rajasthan on 11th September, 2009. The proposed campus will be of residential type and will be spread over a land of 25 acres. The selection of architect has been finalized and selection of contractor is under process.

7.2.7 Foundation stone laying ceremony of proposed Centre of Excellence at Abu Road

The Foundation stone of the Institute's Centre of Excellence at Abu Road was laid by the President-in-office, ICAI on 21st January, 2010. The proposed campus will be of residential type and will be spread over a plot of land of 10 acres.

7.2.8 Purchase of land for Centre of Excellence at Rajkot

Land of area 7985 sq. mts. has been purchased from local Municipal Corporation for setting up a centre of Excellence of the Institute.

7.4 Diamond Jubilee Committee

The Diamond Jubilee Committee was constituted as a Special Purpose Committee to manage the Diamond Jubilee Celebrations of the Institute. Concomitantly proliferating the message "Celebrating 60th year of Excellence" amongst the masses through Conferences, Seminars, and Media to involve all the stakeholders associated with the profession, prominently highlighting the ICAI's Partnership in Nation Building at all the forums nationally and internationally, were the essential tasks of the Committee.

Significant Achievements

7.4.1 The three day ICAI Diamond Jubilee International Conference on the theme "Winds of Challenges – Global Strategies for Accounting Profession" from 3rd to 5th July, 2009 at Agra dwelled upon issues of emerging and contemporary significance, viz, harmonization of international standards, technology in financial sector, bridging expectation gap, financial markets and beyond. The Conference had brought the entire ICAI membership to Agra as against a member base of nearly 500, more than ninety percent of conference participation was from all other parts of country and south East Asia and majority of developed countries with over 200 foreign delegates from over 25 countries. 5th July, 2009 i.e. last day of the International Conference had witnessed the Agra Go Green Run, a mega initiative to integrate Chartered Accountants and students with people from all walks of life, having concerns of protecting the environment. Celebrities namely Rahul Bose, amongst others, had participated thereat. The run was participated by over 3000 students and members and their families.

7.4.2 Celebrating Sixty Years of historic existence and the year under report as the ICAI's Diamond Jubilee Year, the ICAI organized a two hours Diamond Jubilee Conference for its members with a theme "**Professionalism as a Tool to Economic Growth**" at New Delhi on July 11, 2009. The Conference was inaugurated by CA. K. Rahman Khan, Hon'ble Deputy Chairman of Rajya Sabha.

7.4.3 The ICAI, through Diamond Jubilee Committee and Corporate Governance Committee, Co-partnered with Ministry of Corporate Affairs to organize India Corporate Week from 14th to 21st December, 2009 to acknowledge the significant contribution of Indian Corporates and associates like ICAI/ICSI/ICWAI/CII /FICCI/ASSOCHAM/PSUs in the socio-economic development of the country.

The Week finally culminated with Grand Finale at Vigyan Bhavan, New Delhi on 21st December, 2009 whereat Her Excellency Smt. Pratibha Devisingh Patil, Hon'ble President of India awarded the ICAI and other institutions in recognition of their pursuit for excellence and contribution to the growth of the country. The ICAI Branches, namely, Nagpur, Baroda, Ernakulam, Jaipur, Chandigarh and Bhubaneswar covered India Corporate Week through seminars during Corporate Week.

7.4.4 While each year, the ICAI has been celebrating 1st July as the CA Day, given the stature of the current year being a landmark year of the Diamond Jubilee, the ICAI's role was positioned in various contemporary and emerging areas by associating/organizing

events commemorating the ICAI's contribution. The period from July, 2009 to December, 2009 was dedicated month-wise for different activities as under :

Activity	Month
Go Green	July, 2009
Educational Initiative and IT Training	August, 2009
Career Counseling	September, 2009
Empowerment	October, 2009
Agriculture	November, 2009
Public Awareness	December, 2009

7.5 Committee on Management Accounting

The Committee on Management Accounting organised classes of Master in Business Finance Certificate Course during the year 2009-10.

Eminent faculty member from IIMs, IITs, NIBM, XLRI, Sr. Chartered Accountants from Industry and Profession and Sr. Professor from Universities etc. deliberated upon various topics of course curriculum.

The participants of the course were assigned various topics to prepare Project Reports and they were asked to present the Project Reports before the experts.

Brain storming sessions and group discussions were also conducted.

The Committee is getting overwhelming response from prospective candidates, who are more eager to join this Course.

8. OTHER MATTERS

8.1 Annual Function of the ICAI

The 60th Annual Function of the ICAI was held on 11th February, 2010 at Vigyan Bhawan, New Delhi. Prof. Saugata Roy, Hon'ble Union Minister of State, Ministry of Urban Development, was the Chief Guest and Shri Rajkumar Dhoot, Hon'ble Member of Parliament (Rajya Sabha) and Shri S.S.N. Moorthy, Chairman, Central Board of Direct Taxes were the Guests of Honour. The 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' for the year 2008-09, Prizes and Medals to the meritorious students in the examinations conducted by the ICAI, Shields and Certificates of appreciation to the outstanding Regional Council and Branches of the ICAI, were given away at the said Function. The Function was attended by a record number of invitees which included, among others, Senior Government Officers, Members, Students, Officers and Staff of the ICAI. The Chief Guest showered flowers of appreciation on the profession of Chartered Accountants.

8.2 Celebrations of Chartered Accountants Day – 1st July, 2010

The Chartered Accountants' Day Celebrations began with the hosting of the Institute's flag and garlanding the statue of Late G.P. Kapadia, the first President of the Institute, in the morning of 1st July, 2010 at the Headquarters of the Institute. A function befitting the occasion was thereafter held in the evening at Vigyan Bhawan, New Delhi. CA. K. Rahman Khan, Hon'ble Deputy Chairman, Rajya Sabha and Shri Salman Khurshid, Hon'ble Minister of State (Independent Charge), Ministry of Corporate Affairs, graced the function as Guests of Honour and addressed the members, students and other dignitaries/invitees present. Shri

R. Bandyopadhyay, Secretary, Ministry of Corporate Affairs, also graced the occasion and gave a special address. The function was truly special as CA. Ajeet Singh S. Bhandari, the topper in the first CA Final Examination held in November, 1949 was specially invited, a first in the history, to and was felicitated befittingly at the said function. An unprecedented number of members and students as acknowledged by the dignitaries participated in the Function. The function was followed by a Special Address on Future of Accounting Profession in India by CA. T.V. Mohandas Pai, Member of the Board, Infosys Technologies Limited, and a Panel Discussion on Revised Discussion Paper on Direct Taxes Code wherein the distinguished panelists led the discussion.

8.3 Central Council Library

The Central Council Library is globally connected through Internet, fully computerized & operational. Library material including database of Books, Journals & Articles can be searched through Subject, Author, Title, Topic, Keyword, & Publisher wise. This record is available on Internet Online Services www.icaai.org under "Know your Institute – Central Council Library"- online search OPAC-Liberty for the books, Journals, articles etc. in the library. Reference service is also provided to the Researchers & Scholars from different Universities & CPT Course Students as a special case. Noida Office of the Institute & Vishwas Nagar Students library has also been provided with library facilities by the Central Council Library, along with nucleus Libraries provided to each Directorates of the Institute and various committees.

The Central Council Library provides Links for various Library-Web services through www.icaai.org under "know your Institute – Central Council Library". The services are self-explanatory. Some of these links such as list of online Journals, E-books, Articles from Chartered Accountants Journals and online database of Books, Journals and Articles in the Library, provide further search in the above online databases. One can even suggest new Books/Journals under "Suggest Books/Journal columns" for addition in the Library. The "Accountants Browser" is an index of important/Professional Articles with archives for the last 10 years.

Besides the above, the Library has installed a number of the Institute's databases in the Central Council Library premises and at various Departments to facilitate the search for required material by the students, Members, Faculties and the Research Scholars. A New Software – Liberty is acquired connecting the database of Central Council Library with all Regional libraries database. The Library is also procuring necessary publications/Books for all the Committees as also for various Course offered by the ICAI, such as, Certificate Course on Enterprise Risk Management, International Taxation and IFRS.

Web services:

The Web Services available on www.icaai.org- Central Council Library are as follows:-

- List of Online Journals
- e-Books Links
- Articles from the Chartered Accountant Journal (1951 - 2000)
- Articles from the Chartered Accountant Journal (2001 - 2007)
- A complete Online Search for Books, Journals & Articles in the Central Council Library
- List of Books on WTO available in the Central Council Library
- Accountant's Browser, an Archive of Professional Articles for last 12 years
- Central Council Library - New Delhi - Conference / Seminar

- CDs available in the Library
- The Chartered Accountant Index July 1995 - June 2007
- List of Recommended Books
- Library Security Deposit Rules
- Library News and Views
- List of Journals Subscribed by Central Council Library
- Library Services - Membership Form for Members
- Library Services - Membership Form for Students
- Photographs Available in the Library
- Recent Additions - Books added in Central Council Library
- SAFA Books/ Publications Available in the library
- Suggest Books/ Journals

The Online database installed in the Library are as follows:

Library Software – Liberty	CTR Online	ITR Online	Excus Online	E- Jurix
Indlaw.com	Delnet	Indiastat.com	Taxmari	

8.4 Editorial Board

Surging ahead with its mission to keep the ICAI members and other readers of *The Chartered Accountant* journal up-to-date on various subjects, emerging areas, aspects and challenges of the profession in today's age of fast-paced globalisation, the Editorial Board has established many a landmark during 2009-2010.

A 'Brand Ambassador' of ICAI and the most visible indicator of the Institute's profile for the members, students and external audiences, *The Chartered Accountant* today matches the global standards of professional Journals, be it content quality, in-depth topical coverage, interactive features, international standard layout/design, paper quality, overall look and feel or greater reach. It is increasingly being recognised as one of the most reliable and reader-friendly tools of professional knowledge update, not only for the members but also for allied professionals, institutions and a cross-section of the economic world in India and abroad, if the feedback received from the is any indication.

With ever-widening reach and readership base, the total circulation the Journal stands at more than **191000** today.

Contents and e-Journal:

- During **1st April 2009 and 31st March 2010, a total of 163 articles** on various topics were printed.
- Some new features like 'Know Your Ethics', 'International Taxation', 'Insurance', 'Outsourcing', 'Career/Professional Avenue', 'Foreign Trade', 'World Trade Organisation', etc. were introduced in the journal. Existing features like 'From the President', 'Legal Update', 'National Update' and 'International Update' were further upgraded to keep the members better informed. It was decided to cover about 20 areas of professional interest in every quarter in the journal to make its coverage more comprehensive.

A unique 180-page July 2009 issue was brought out celebrating the completion of 60 years of the ICAI's glorious existence. It elaborately covered the rare glorious moments of ICAI history and the inspiring status and shape of the Institute.

Another rare issue was brought out in January 2010 on the theme 'Women Empowerment and Profession' wherein highly knowledgeable women and profession oriented articles were all contributed by women.

Special issues were also published on themes 'Bank Audit', 'Limited Liability Partnership/Union Budget' and 'XBRL' in March, August and September 2009 respectively and on Union Budget 2010-11 in March 2010.

- The online journal, which has been hosted on the ICAI website with a unique URL www.ejournal.icai.org, was further upgraded and improvised to make it more dynamic and user-friendly with faster and easier browsing with search facility without any requirement of any specific software. The new system provided feel of the print version while being online. Every issue of the Journal was made available online well in advance. The Editorial Board page on the ICAI website were also comprehensively upgraded and updated.

Layout and Design:

- The layout-design and font type face of the entire journal were further upgraded to match international standards.
- The Masthead and basic template of the Cover and inside pages were further improved.

Other Initiatives:

- For added convenience of reading the journal, members were given option to get the copy of their journal at their residential addresses if they so desired.
- The panel of professional editors was expanded to expedite release of the ICAI publications after professional language editing.

8.5 High Powered Committee

Consequent to the corporate fraud of huge magnitude coming to light in Satyam Computer Services Ltd., the Council of the ICAI, deeply concerned with the financial scandal having serious ramifications for not only India's corporate sector, but also on the governance system in Indian corporates, felt the need to reinforce the confidence of the public in the accounting and auditing profession, and hence constituted a High Powered Committee at its 284th meeting held on 12th & 13th January, 2009 at New Delhi to look into the entire gamut of financial reporting, accounting and auditing aspects with regard to Satyam fiasco, including helping/co-ordination with the investigation being carried out by various agencies, going into the roots of the problem, effectiveness of the system in place, systemic issues; to identify the root causes including persons involved/associated; and to suggest change(s), wherever required, for the purpose of making appropriate recommendation(s) to the Central Government, SEBI and other Regulators.

During the course of their task, the members of the High Powered Committee met various agencies/authorities. During one such meeting with the Ministry of Corporate Affairs held on 27th February, 2009, the Ministry suggested to look into issues relating to public image about auditor's role, manner in which surrogate firms hold out to the public, use of international brand name and host of other related issues.

The ICAI constituted a group of local chartered accountants at Hyderabad to assist the CBI's Multi-disciplinary Investigation Team. The group was entrusted with the task of verification of compliances or otherwise by the auditors of the Company, with various auditing and

assurances standards and guidance notes issued by the ICAI, in respect of cash and bank balances, sales, receivables, interest accrued and tax deducted at source relating to fixed deposits and its impact on financial reporting and auditor's report thereon. The Group submitted its report to the CBI on 5th April, 2009 which formed part of the charge sheet filed by CBI. The group's report has been incorporated in the Report (Part-I) of the High Powered Committee. On 5th April, 2009, the members of the Committee conducted inquiry with three members of ICAI lodged in prison and took their statements on record. This was done pursuant to permission granted by the CBI Court, Hyderabad.

Thereafter, the High Powered Committee prepared a report covering "Satyam fiasco". The Council, on consideration of the same, submitted its recommendations to the Government (Ministry of Corporate Affairs) in two parts – Report (Part-I) on 17th July, 2009 and Report (Part-II) on 24th May, 2010. Both these reports cover matters relating to "Satyam fiasco" only.

While consideration of the draft Report (Part-II), the Council, at its special meeting held on 13th March, 2010 constituted a Group to modify the said Report integrating the various suggestions made by members across the table during the discussions on the Report. The said Group is now seized of the following:

- to look into issues relating to the manner in which surrogate firms hold out to the public, use of international brand name and host of other related issues.
- examining the provisions contained in Regulation 190 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 relating to multiple trade/firm names, identical and similar trade/firm names, approval of names, and the compliance.

8.6.1 Amendment in the Chartered Accountants Act, 1949 – An initiative towards further strengthening the disciplinary mechanism and enlarging the scope of award of punishment to the CA firms as well.

In the wake of certain developments taken place last year, the Council constituted a High Powered Committee to look into the entire spectrum of the matter including the role of auditors therein. The recommendations made by the said Committee was considered by the Council in general, and the following recommendation in particular, and a Group of Council members was constituted in May, 2010 to examine the matter, in entirety, in the light of the existing provisions of the Chartered Accountants Act, Regulations and Rules and, thereafter, propose suitable amendments in the Chartered Accountants Act/Regulations and Rules framed thereunder:-

"Seek amendment in the Chartered Accountants Act, Regulations and Rules to proceed against the firm, including imposition of ban, where the partners and the members of an audit team are found to be guilty of gross negligence/fraudulent activities."

The Group, after deliberating on the matter extensively, having regard to the significance involved, submitted its initial recommendations to the Council in June, 2010. The Council, on consideration of the same, requested the Group to revise its recommendations, if necessary, in the light of the various views/comments/ suggestions made by the members of the Council. Accordingly, the Group reconsidered the matter, in the light of the above and re-submitted its revised recommendations to the Council. The matter is presently under consideration of the Group for finalising the required amendments, in the light of further suggestions, for submission to the Central Government.

9. MEMBERS

9.1 Membership

During the year ended 31st March, 2010, 10853 new members were enrolled by the ICAI bringing the total membership to 161516 as on 1st April, 2010.

During the year ended 31st March 2010, 3211 associates were admitted as fellows, in comparison to the figure of 3101 in the previous year.

Total Members as on 1.4.2010

Category of Members	Fellow (1)	Associate (2)	Total of Columns (1) and (2)
In Full Time Practice	53141	20321	73462
In Part-time Practice	3140	5041	8181
Not in Practice	10244	69629	79873
	66525	94991	161516

9.2 Convocation

Since November 2008, the Institute has been organising Convocation to confer membership certificates on newly enrolled members. The Convocation is organized at each of five Regional Headquarters twice a year covering the period from March to August and September to February whereat membership Certificates are conferred to members admitted to the membership during the said period. In this regard, for members admitted between March, 2009 and August 2009, the Convocation was organized in January, 2010 at each of the Regional head quarters of the Institute. For the members admitted between September, 2009 and February, 2010, the Convocation(s) will be organized shortly.

9.3 Chartered Accountants' Benevolent Fund

Established in December, 1962, the Chartered Accountants Benevolent Fund continues to provide financial assistance to needy persons who are or have been members of the Institute and their dependents, for maintenance of the dependents, their educational and medical needs etc. The financial and other particulars of the Fund are as follows:

Details of Membership

1. Total Life Members as on 31 st March, 2009	=	94,480
2. Total Life Members as on 31 st March, 2010	=	97,564
3. Total Additions of New Life Members (as on 31 st March, 2010)	=	3,084
4. Total Financial Assistance given upto 31.03.2010	=	22,975,500

Details of Financial Particulars

	During the year ended 31 st March, 2009	During the year ended 31 st March, 2010
1. Total Assistance provided	57,00,000	22,975,500
2. Administrative Expenses	14,438	17,142
3. Surplus (Deficit) of the Fund	32,17,810	(10,480,363)
4. Balance of the Fund	1,99,08,990	9,428,627
5. Balance of Corpus	8,06,82,800	88,107,800

9.4 S. Vaidyanath Aiyar Memorial Fund

During the year ended 31st March, 2010, 60 scholarships of the value of ` 500 each per month are given to the students undergoing the Chartered Accountancy course. The number of life membership of the Fund increased from 1,775 as on 31st March, 2009 to 2,129 as on 31st March, 2010. The balance in the credit of the Fund was ` 15,99,441 as on 31st March, 2010 as against ` 9,57,181 as on 31st March, 2009.

9.5 Chartered Accountants Student's Benevolent Fund (CASBF)

The Fund was established in August, 2008 with the aim and objective to provide financial assistance, scholarships etc. to the students registered with ICAI. During the year ended 31st March, 2010, 100 scholarships of the value of ` 1,000 each per month for one year in the form of financial assistance have been given to the students undergoing the Chartered Accountancy course. The balance in the credit of the general fund was ` 78,02,562 as on 31st March, 2010 as against ` 21,44,658 as on 31st March, 2009.

10. STUDENTS

As far back as in September, 1954, the Council established a 'Coaching Board' to impart theoretical education to students registered for the Chartered Accountancy course. Such an agency was established as it was considered more effective way of catering to the needs of the students rather than relying on the system of recognizing private institutions.

To start with, registration for the theoretical training was voluntary. However, from 1956, it was made compulsory. Since then, any student registering as an articled or audit assistant (earlier, articled or audit clerk) was required to register himself as a student of the Coaching Board. Since the students for the course are scattered all over the country, uniformity was ensured through correspondence course conducted by the Coaching Board. Later on in 1977, the name of Coaching Board was changed to "Board of Studies". Today, the Board is solely responsible for the administration of the Chartered Accountancy curriculum imparting theoretical education to students undergoing Chartered Accountancy course.

With the adoption of distance-education mode by the ICAI since 1955 and successful implementation of the same for over five decades, the ICAI has emerged as a pioneer in this field. By undertaking this responsibility, it has ensured the highest quality and consistency by providing education material and other academic inputs from time to time at the most affordable prices. Through the adoption of model of integrating theoretical education and practical training, it has been able to facilitate the development of not only professional

knowledge and skills amongst large number of students but also inculcate professional values, ethics and attitudes. The Board of Studies provides a comprehensive package of educational inputs to enable the students to prepare adequately for the examinations. In view of the large number of students scattered throughout the country as well as abroad, it aims to leverage technology and theoretical education through virtual mode for the benefit of students. It has established computer labs all over the country in which CA students are getting training in Information Technology. In order to equip students with the presentation skill and real life environment and to enhance their overall personality, the Board organizes Orientation Programme and Course on General Management and Communication Skills (GMCS).

Chartered Accountants are eligible for admission to the Civil Services Examination, which is conducted by the Union Public Service Commission (UPSC) for recruitment to Group 'A'/Group 'B' Central Services / Posts.

The Board of Studies has also entered into Memorandum of Understanding with various universities enabling CA students to acquire BBA, B.Com, M.Com, MBA degrees. The Board also organizes a large number of National Conventions, Seminars and Conferences to update the students with the latest knowledge in different professional subjects.

Some of the significant achievements during the year are as follows.

10.1 Accreditation Scheme

During the year ended 31st March, 2010, 6 more institutions were accredited for conducting CPT oral coaching classes. The number of such institutions thus aggregated to 137. Similarly, 5 more institutions were accredited for conducting PCC/IPCC Oral coaching classes, taking the number of such institutions to 79. The number of accredited institutions for Professional Education (Course - II), remains the same, as 96 and also there is no change in the number of existing 10 institutions for Final Course.

10.2 Release of Study Material in Hindi for the IPCC

The study materials in Hindi for Integrated Professional Competence Course (IPCC) and Accounting Technician Course (ATC) launched in December, 2008 were released in June, 2009.

10.3 Suggested Answers

In order to facilitate and guide the students for better preparedness to face the examinations, suggested answers for the Professional Education (Examination-II) [PE-II], Professional Competence Course (PCC), Integrated Professional Competence Course (IPCC), Accounting Technician Course (ATC), Final (Old) Course, and Final (New) Course Examinations held in June, 2009 and November, 2009 were printed well in advance and made available to them. These Suggested Answers were also hosted on the website of the ICAI with download option free of cost.

10.4 Revision Test Papers

The Revision Test Papers (RTPs) for PE-II, PCC, IPCC/ATC and Final examinations were published well in time to enable the students to prepare for their examinations.

The above were also hosted on the website of the ICAI with download option free of cost.

10.5 Revision of Study Materials

As a part of continuous process of updating/revising knowledge of students, the contents of various study materials have been updated/revised with incorporation of appropriate changes. Study material of IPCC has been revised by incorporating Practice Modules of Advanced Accounting, Cost Accounting, Financial Management, and Accounting, in the Study modules of IPCC. Practice Modules of Final (New) Course are under process.

10.6 Digest of Select cases

The digest of select cases in Direct and Indirect Taxes 2009 containing choice cases in Direct and Indirect Tax Laws has been published.

10.7 Supplementary Study Materials in Taxation subjects

Supplementary study material in Direct and Indirect Taxes is an annual publication containing amendments made by the Annual Finance Act with latest circulars and notifications issued in regard to Direct Taxes and Indirect Taxes. During the year, the Supplementary Study Paper-2009 containing the amendments made by the Finance (No. 2) Act, 2009 and important notifications/circulars issued between 1st May, 2008 and 30th April, 2009 was brought out for the benefit of the students.

10.8 List of Publications of Board of Studies

The publications brought out by the Board of Studies included Study Materials in respect of Common Proficiency Test (CPT), Professional Education (Course-II), Professional Competence Course (PCC), Integrated Professional Competence Course IPCC), Accounting Technician Course (ATC) and Final Examinations. The Board also brought out Course material on Information Technology Training Programme/Course, suggested Answers for Professional Education (Course-II), Professional Competence Course (PCC) and Final Examinations as well as compilation of Suggested Answers on Professional Examination (Course-II) and Final Examinations. CD of study material pertaining to PCC, IPCC, ATC, Final Course as well as of Self Assessment (CPT) were also released.

10.9 100 Hours Information Technology Training

Presently, 149 Information Technology Centres established by the ICAI are functioning and establishment of 5 more such Centres is in process. The details of computers installed in these Centres and the students trained during the year are as under :

Computer Labs fully functional	149
Labs establishment in process	5
Number of computers installed	4,940
Number of students trained from April, 2009 to March, 2010	66,243
Annual capacity to train students in ICAI labs	1,77,840

The study material on 100 Hours Information Technology Training has also been thoroughly revised and updated.

10.10 Course on General Management and Communication Skills

During the year, 317 batches of the 15 days' Course on General Management and Communication Skills were organized by Regional Councils and their Branches at 57 centres across the country (inclusive of Dubai Centre) and 13,168 students participated in these programmes, as compared to 10,870 during 2008-2009.

10.11 Orientation Programme for Integrated Professional Competence Course (IPCC) and Accounting Technician Course (ATC)

Students registered for Integrated Professional Competence Course (IPCC) and Accounting Technician Course (ATC) have to undergo mandatory Orientation Programme for 7 days spanning 35 Hours. The objective of this Orientation Programme is to give exposure to freshly qualified Common Proficiency Test (CPT) students in areas like Communication Skills, Presentation Skills, Office Procedures and General Commercial Knowledge. A comprehensive study material covering the course content for the Orientation Programme has been prepared and made available to the Regions and Branches for distribution to parties parts of the said Programme. During the year, 957 batches of Orientation Programme were organized at 86 centres and 52,606 students participated in these programmes.

10.12 Scholarships granted to students

The Board granted a total 220 Scholarships to the students under Merit, Merit-cum-Need, and Need-based and Weaker Sections categories during the year.

10.13 Students' Newsletter

The monthly CA Students' Newsletter – The Chartered Accountant Student, was upgraded to a full-fledged Journal in January 2010. The journal contains articles on topics relevant to the CA Students, academic updates, and important announcements. The journal continued to be popular and proved very useful to the student community, as well as members of the Institute.

10.14 Best Article Award

The 1st Prize was awarded to Shri Ashish Prabhakar Harkare for his article on 'Frauds - A Challenge before CA' published in April, 2009 issue of the Students' Newsletter and the 2nd Prize was awarded to Shri Mihir Jhaveri for his article 'Forensic Accounting: A Glimpse' published in November, 2008 issue of the Students' Newsletter - The Chartered Accountant Student.

10.15 Students Exchange Programme

12 students of the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka (ICASL) and 6 Students of the Institute of Chartered Accountants of Nepal (ICAN) came to India and participated in SAFA Students Exchange Programme held in Ernakulam on 21st and 22nd August, 2009.

10.16 Recognition of CA Course for Ph.D. Programme

With the constant follow up with various Universities, the Board of Studies has been successful in obtaining recognition for CA Course from 80 Universities, besides the 4 Indian Institutes of Management and the Association of Indian Universities for the purpose of pursuit of Ph.D. /Fellow Programme.

10.17 One Day Seminars

During the year, 48 One day seminars were organized by 14 branches.

10.18 Elocution Contests

The Branch Level Elocution Contests were organized by 41 Branches, including 5 Regional Councils. Apart from this, 5 Regional level Contests were organized. The All India Elocution Contest was conducted at Pune on 28th January, 2010.

10.19 Quiz Contests

The Branch Level Quiz Contests were organized by 43 Branches, including 5 Regional Councils. Apart from this, 5 Regional level Contests were organized. The All India Quiz Contest was conducted at Pune on 28th January, 2010.

10.20 All India CA Students' Conference

The 22nd All India CA Students' Conference was organized on 21st and 22nd August, 2009 at Ernakulam, Kerala.

10.21 National Convention of CA Students

During the year, 8 National Conventions were organized, viz., 10th National Convention on 10th and 11th July, 2009 at Baroda; 11th on 15th and 16th July, 2009 at Indore; 12th on 25th and 26th July, 2009 at Nagpur; 13th on 3rd and 4th August, 2009 at Kanpur; 14th on 29th and 30th August, 2009 at Kolkata; 15th on 31st August and 1st September, 2009 at Ghaziabad; 16th on 26th and 27th December, 2009 at Siliguri, and the 17th on 9th and 10th January, 2010 at Pune.

10.22 Regional/ Sub-Regional/ State Level Conferences

The State level Conference were organized on 1st and 2nd August, 2009 at Sivakasi CPE Study Circle (SIRC), on 28th and 29th July, 2009 at Bhilwara, on 5th September, 2009 at Guntur, on 29th and 30th August, 2009 at Nashik, and on 23rd August, 2009 at Coimbatore. The Regional level Conference was organized on 1st and 2nd February, 2010 at Hyderabad by SICASA.

10.23 Joint Seminars with Universities

During the year, 3 Joint Seminars were held by the Branches with the coordination of various Universities, viz., on 6th and 7th September, 2009 by Varanasi Branch with Faculty of

Management Studies, BHU, on 26th November, 2009 by Baroda Branch with M.S. University, Baroda, and on 27th July, 2009 by Tuticorin Branch with M.S. University, Tirunelveli.

10.24 Career Counseling Programmes

Career Counseling Programmes are being organized at Regional Headquarters and branches to popularize the CA course and also to help students for getting their academic queries in various subjects of the curriculum resolved. During the period from 1st April, 2009 to 31st March, 2010, 54 Career Counseling Programmes were organized at different locations throughout the country.

10.25 Three Months' (12 weeks) Residential Programme on Professional Skills Development

A three months' residential programme on Professional Skills Development (General Management, Personality Development and Communication Skills) has been initiated for the benefit of CA students and newly qualified Chartered Accountants. The programme is helping the CA students and newly qualified CAs in imbibing the professional skills required for effective functioning in business organisations and profession. The batches organized during the year are as follows :

Batch	Place	Date	Students Participated
6 th	IIM, Indore	April 13, 2009 to July 14, 2009	60
7 th	NIFM, Faridabad	July 6, 2009 to Sept. 25, 2009	60
8 th	IIM, Indore	Jan. 15, 2010 to April 16, 2010	60

10.26 Gyan Darshan Programme for students of CPT, PCC and Final

For the benefit of students pursuing Common Proficiency Test (CPT), Professional Competence Course (PCC), lectures by experts were arranged during the year through Gyandarshan Channel in collaboration with Indira Gandhi National Open University (IGNOU), New Delhi. Students from various parts of the country interacted with the faculty through the systems provided by ISRO. The number of such lectures conducted during the year for the CPT and PCC was 178 and 90 respectively.

10.27 Memorandum of Understanding with Bharathiar University

A Memorandum of Understanding between the ICAI and the Bharathiar University, Coimbatore was signed on 4th December, 2008. As per the MoU, CA students as well as qualified Chartered Accountants will have the opportunity to pursue B.Com., M.Com., BBA., and MBA degrees of the Bharathiar University. They would be given exemptions in respect of papers covered by the CA curriculum and would then be required to appear and pass only in the remaining papers to get these degrees.

10.28 Toll free numbers for answering students' queries

A toll free number 1800-200-2501 is dedicated to answer the queries from students. The said dedicated line functions from the Board of Studies and the academic queries are answered by the faculty members concerned.

10.29 Students' Counsellors

Student's counsellors have been appointed at the Decentralised offices at Delhi, Chennai, Kolkata, Mumbai and Jaipur to guide the students on various aspects of the Chartered Accountancy course.

10.30 Training to Trainers of IT students

The first round of FDP "Train the Trainers" for Information Technology Trainers was successfully completed as per detail hereunder:

Place	Date	No. of participants
Chennai	June 22, 2009 to June 26, 2009	23
Noida	June 29, 2009 to July 3, 2009	22
Mumbai	July 6, 2009 to July 10, 2009	26
Kanpur	July 13, 2009 to July 17, 2009	27
Kolkata	August 24, 2009 to August 28, 2009	18

The second round of FDP on Tally & CAAT Tools for Information Technology Trainers was successfully completed as per details hereunder:

Place	Date	No. of participants
Goa	October 5, 2009 to October 9, 2009	24
Hyderabad	January 11, 2010 to January 15, 2010	35
Delhi	January 18, 2010 to January 22, 2010	49
Kanpur	January 25, 2010 to January 29, 2010	40
Kolkata	February 1, 2010 to February 5, 2010	24

10.31 Teachers' Day Celebration

The Teachers' Day was celebrated in a grand manner in the Board of Studies, Noida on September 4, 2009, where Faculty members were given a memento.

10.32 Students' Statistics

The details in respect of students registered during the last five years from 2005-2006 to 2009-2010 are as under:

Year	Final (Old & New)	CPT	PCC	IPCC	ATC (Registered exclusively)
2005-2006	13,010	—	—	—	—
2006-2007	11,838	1,29,110*	24,041*	—	—
2007-2008	19,558	1,42,612	61,186	—	—
2008-2009	11,562	1,39,140	33,764	18,318**	8**
2009-2010	24,109	1,63,397	1,204	81,833	4
Total	80,077	5,74,259	1,20,195	1,00,151	12

*from 13th September, 2006 to 31st March, 2007

** from 10th December, 2008 to 31st March, 2009

11. REGIONAL COUNCILS AND THEIR BRANCHES

The Institute has five Regional Councils, namely Western India Regional Council, Southern India Regional Council, Eastern India Regional Council, Central India Regional Council and Northern India Regional Council with their Headquarters at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi respectively.

The total number of branches of Regional Councils is 126. Currently, there are 21 Chapters of the Institute outside India, and there are 27 Reference libraries all over India

11.1 Branch Building

During the period under Report, a number of branches of Regional Councils continued to evince interest in having their own premises. In all, 63 branches have their own premises.

11.2 Rotating Shield

The Institute awards each year Shield to the Best Regional Council. The award is given on the basis of overall performance. Similarly, a separate Shield is awarded to the Best Branch each year. The award is given on the basis of established norms. Rotating Shields to the Best C.A. Students' Association on all India basis and Best Branch of Students' Association on Regional Basis have been instituted from the year 1999. For the year 2009, these Shields were awarded at the Annual Function held on 11th February, 2010 to the following winners:-

- Best Regional Council-Western India Regional Council
- Best Branch of Regional Council
 - Small Size Branch Category — Bhilai Branch of CIRC
 - Medium Size Branch Category — Salem Branch of SIRC
 - Big Branch Category — Ludhiana Branch of NIRC and Indore Branch of CIRC
- Best Branch of Students' Association
 - Western Region — Baroda Branch of WICASA
 - Southern Region — Ernakulam Branch of SICASA
 - Eastern Region — Guwahati Branch of EICASA
 - Central Region — Indore Branch of CICASA
- Considering their performance, the following branches were separately awarded Highly Commended Performance Shield : -

Small Size Branch Category –

- Hubli Branch of SIRC
- Siliguri Branch of EIRC

Medium Size Branch Category:

- Guwahati Branch of EIRC
- Aurangabad Branch of WIRC

Big Branch Category

- Baroda Branch of WIRC

- Nagpur Branch of WIRC
- Ernakulam Branch of SIRC

11.3 Decentralised Offices

Recognising the value of expeditious and personalised service which are achievable through the process of decentralisation, the Council of the Institute has already set up five decentralised Offices at Bangalore, Hyderabad in Southern Region, Ahmedabad, Pune in Western Region and Jaipur in Central Region besides the decentralised offices already functioning from Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi. Considering the increasing volume of work/activities at the regional level eight more decentralized offices have been set up at Nagpur, Surat, Vadodara and Thane (Western Region), Ernakulam and Coimbatore (Southern Region), Indore (Central Region) and Chandigarh (Northern Region).

12. FINANCE AND ACCOUNTS

The Balance Sheet as on 31st March, 2010 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date as approved by the Council are enclosed.

13 APPRECIATION

- 13.1** The Council is grateful to members of the profession who functioned as co-opted members on its Committees, persons nominated on the Boards/Committees constituted under the Chartered Accountants Act, 2006 and to the non-members who assisted the Council during the year 2009-2010 in the conduct of its educational, technical and other developmental activities and in its examinations.
- 13.2** The Council wishes to place on record its appreciation of the continued assistance and support given by the Central Government and its nominees on the Council during the year 2009-2010.
- 13.3.** The Council wishes to place on records its heartfelt gratitude to CA. K. Rahman Khan, Hon'ble Deputy Chairman of Rajya Sabha, Shri Salman Khurshid, Hon'ble Minister of State (Independent Charge), Ministry of Corporate Affairs, Prof. Saugata Ray, Hon'ble Minister of State, Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation, Shri Shripakash Jaiswal, Hon'ble Union Minister for State for Coal, Statistics and Programme Implementation, Shri Rajkumar Dhoot, Hon'ble Member of Parliament (Rajya Sabha), Dr. A.K. Walia, Finance Minister, Government of Delhi, Shri Mahabal Mishra, Hon'ble Member of Parliament, Shri Ashok Chawla, Finance Secretary, Shri S.S.N. Moorthy, Chairman, CBDT, Shri R. Bandyopadhyay, Secretary, Ministry of Corporate Affairs, Shri Anurag Goel, Member, Competition Commission of India, and other dignitaries who were kind enough to grace the various programmes of the ICAI. The Council also desires to place on record its sincere appreciation to the various functionaries at State level who graced programmes organized by the organs of the ICAI.
- 13.4** The Council also acknowledges its appreciation of the sincere interest evinced by various State Governments in the numerous initiatives taken by the ICAI and the steps already/being initiated by them, pursuant to such initiatives.
- 13.5** The Council also acknowledges its appreciation of the sincere and devoted efforts put in during the year 2009-2010 and thereafter by all officers and staff of the ICAI.

MEMBERS
(From 1st April, 2000)
TABLE I

Year (As on)		Western Region	Southern Region	Eastern Region	Central Region	Northern Region	TOTAL
1 st April, 2000	Associate	17771	13023	5807	5057	8411	50069
	Fellow	12200	10369	4941	5617	9784	42911
	Total	29971	23392	10748	10674	18195	92980
1 st April, 2001	Associate	19243	12915	5732	5215	8498	51603
	Fellow	12868	10749	5077	5995	10100	44789
	Total	32111	23664	10809	11210	18598	96392
1 st April, 2002	Associate	20771	13456	5872	5493	9074	54666
	Fellow	13540	11248	5296	6400	10580	47064
	Total	34311	24704	11168	11893	19654	101730
1 st April, 2003	Associate	23194	14446	6374	6318	10287	60619
	Fellow	14279	11742	5572	6909	11135	49637
	Total	37473	26188	11946	13227	21422	110256
1 st April, 2004	Associate	24515	14943	6515	6714	10697	63384
	Fellow	15091	12377	5836	7557	11846	52707
	Total	39606	27320	12351	14271	22543	116091
1 st April, 2005	Associate	26351	15724	6785	7552	11640	68052
	Fellow	15834	12969	6146	8207	12338	55494
	Total	42185	28693	12931	15759	23978	123546
1 st April, 2006	Associate	28528	16700	7172	8480	12898	73778
	Fellow	16385	13358	6313	8539	12573	57168
	Total	44913	30058	13485	17019	25471	130946
1 st April, 2007	Associate	31159	18237	7829	9642	14182	81049
	Fellow	16896	13646	6488	8882	12880	58792
	Total	48055	31883	14317	18524	27062	139841
1 st April, 2008	Associate	32364	19203	7939	10045	14642	84193
	Fellow	17646	14034	6738	9472	13398	61288
	Total	50010	33237	14677	19517	28040	145481
1 st April, 2009	Associate	34294	20666	8193	10578	15951	89682
	Fellow	18442	14516	7002	10007	13951	63918
	Total	52736	35182	15195	20585	29902	153600
1 st April, 2010	Associate	36390	21733	8512	11252	17104	94991
	Fellow	19181	15076	7192	10615	14461	66525
	Total	55571	36809	15704	21867	31565	161516

MEMBERS
(From 1st April, 1950)

TABLE II

	Associate	Fellow	Total
As on 1 st April, 1950	1,120	569	1,689
As on 1 st April, 1951	1,285	672	1,957
As on 1 st April, 1961	4,059	1,590	5,649
As on 1 st April, 1971	7,901	3,326	11,227
As on 1 st April, 1981	16,796	8,642	25,438
As on 1 st April, 1991	36,862	22,136	58,998
As on 1 st April, 2001	51,603	44,789	96,392
As on 1 st April, 2002	54,666	47,064	1,01,730
As on 1 st April, 2003	60,619	49,637	1,10,256
As on 1 st April, 2004	63,384	52,707	1,16,091
As on 1 st April, 2005	68,052	55,494	1,23,546
As on 1 st April, 2006	73,778	57,168	1,30,946
As on 1 st April, 2007	81,049	58,792	1,39,841
As on 1 st April, 2008	84,193	61,288	1,45,481
As on 1 st April, 2009	89,682	63,918	1,53,600
As on 1st April, 2010	94,991	66,525	1,61,516

STUDENTS GROWTH PROFILE
(From 31st March, 1997)

Course → During the year	Foundatio n/ PE (Course- I)	Interme- diate/PE (Course- II)	Final	CPT	PCC	IPCC	ATC	Total
1996-97	28,209	21,354	9,275	-	-	-	-	58,838
1997-98	37,052	24,652	9,394	-	-	-	-	71,098
1998-99	43,809	28,253	12,227	-	-	-	-	84,289
1999-00	44,180	27,508	10,787	-	-	-	-	82,475
2000-01	35,999	23,405	9,026	-	-	-	-	68,430
2001-02	34,215*	29,403**	11,524	-	-	-	-	75,142
2002-03	35,524	33,283	11,102	-	-	-	-	79,909
2003-04	38,188	34,232	11,390	-	-	-	-	83,810
2004-05	39,000	34,190	11,061	-	-	-	-	84,251
2005-06	38,901	39,467	13,010	-	-	-	-	91,378
2006-07	45,617	32,339	11,838	1,29,110***	24,041***	-	-	2,42,945
2007-08	-	-	19,558	1,42,612	61,186	-	-	2,23,356
2008-09	-	-	11,562	1,39,140	33,764	18,318****	8****	2,02,792
2009-10			24,109,	1,63,397	1,204	81,833	4	2,70,547

* includes PE(Course I) students registration from 1.10.2001 to 31.3.2002 : 5006

** includes PE(Course II) students registration from 1.10.2001 to 31.3.2002 : 11848

*** from 13th September, 2006 to 31st March, 2007

**** from 10th December, 2008 to 31st March, 2009

COMPOSITION OF THE COUNCIL (2010 – 2011)

		Members of the Council (2010-11)	
	President CA. Amarjit Chopra	Elected Members CA. Abhijit Bandyopadhyay CA. Amarjit Chopra CA. Anuj Goyal CA. Atul Chunilal Bheda CA. Bhavna Doshi CA. Charanjot Singh Nanda CA. Devaraja Reddy M. CA. Dhinal Ashvinbhai Shah CA. G. Ramaswamy CA. J. Venkateswarlu CA. Jayant Gokhale CA. Jaydeep Narendra Shah CA. K. Raghu CA. Madhukar Narayan Hiregange CA. Mahesh P. Sarda CA. Manoj Fadnis CA. Naveen N.D. Gupta CA. Nilesh Shivji Vikamsey CA. Pankaj Inderchand Jain CA. Pankaj Tyagee CA. Rajendra Kumar P. CA. Rajkumar S. Adukia CA. Ravindra Holani CA. S. Santhanakrishnan CA. Sanjay Kumar Agarwal CA. Sanjeev Maheshwari CA. Shiwaji Bhikaji Zaware CA. Subodh Kumar Agrawal CA. Sumantra Guha CA. V. Murali CA. Vijay Kumar Garg CA. Vinod Jain	Kolkata New Delhi Ghaziabad Mumbai Mumbai New Delhi Hyderabad Ahmedabad Coimbatore Hyderabad Mumbai Nagpur Bangalore Bangalore Jamnagar Indore New Delhi Mumbai Mumbai New Delhi Chennai Mumbai Gwalior Chennai New Delhi Mumbai Pune Kolkata Kolkata Chennai Jaipur New Delhi
	Vice-President CA. G. Ramaswamy		
	Period 12 th February, 2010 onwards		
	Secretary Shri T. Karthikeyan		
	Auditors CA. Pushpendra Surana CA. Ashok Kumar Jain		
		Nominated Members Shri Anil K. Agarwal Shri Ashutosh Dikshit Shri Deepak Narain Shri K.P. Sasidharan Shri Prithvi Haldea Smt. Renuka Kumar (upto 31 st August, 2010) Shri Sidharth Kumar Birla Dr. T.V. Somanathan (from 1 st September, 2010) Smt. Usha Narayanan	New Delhi New Delhi New Delhi New Delhi New Delhi New Delhi New Delhi New Delhi Mumbai
	Joint Internal Auditors P.R. Mehra & Co. Bhasin Raghavan & Co.		


COMPOSITION OF THE COUNCIL (2009 – 2010)

		Members of the Council (2009-10)
President	Elected Members	
CA. Uttam Prakash Agarwal	CA. Abhijit Bandyopadhyay	Kolkata
	CA. Akshay Kumar Gupta	Kanpur
	CA. Amarjit Chopra	New Delhi
	CA. Anuj Goyal	Ghaziabad
Vice-President	CA. Atul Chunilal Bheda	Mumbai
CA. Amarjit Chopra	CA. Bhavna Doshi	Mumbai
	CA. Charanjot Singh Nanda	New Delhi
	CA. G. Ramaswamy	Coimbatore
	CA. Harinderjit Singh	New Delhi
Period	CA. J. Venkateswarlu	Hyderabad
5 th February, 2009 – 11 th February, 2010	CA. Jayant Gokhale	Mumbai
	CA. Jaydeep Narendra Shah	Nagpur
	CA. K. Raghu	Bangalore
	CA. K.P. Khandelwal	Kolkata
Secretary	CA. Mahesh P. Sarda	Jamnagar
Shri T. Karthikeyan	CA. Manoj Fadnis	Indore
	CA. Pankaj Inderchand Jain	Mumbai
	CA. Preeti Pradip Mahatme	Goa
	CA. Rajkumar S. Adukia	Mumbai
	CA. S. Gopalakrishnan	Hyderabad
	CA. S. Santhanakrishnan	Chennai
	CA. Sanjeev Maheshwari	Mumbai
	CA. Shanti Lal Daga	Hyderabad
Auditors	CA. Subodh Kumar Agrawal	Kolkata
CA. Pramod Jain	CA. Sunil H. Talati	Ahmedabad
CA. Pushpendra Surana	CA. Uttam Prakash Agarwal	Mumbai
	CA. V. Murali	Chennai
	CA. V.C. James	Kochi
	CA. Ved Jain	New Delhi
	CA. Vijay Kumar Garg	Jaipur
	CA. Vijay Kumar Gupta	Faridabad
	CA. Vinod Jain	New Delhi
	Nominated Members	
	Shri Anil K. Agarwal	New Delhi
	Shri Jitesh Khosla (upto May, 2009)	New Delhi
	Shri K.P. Sasidharan	New Delhi
	Shri K.R. Maheshwari	Jaipur
Internal Auditors	Shri Krishna Kant (from April, 2009)	New Delhi
Samynk & Co.	Shri Manoj K. Sarkar	Kolkata
Bhasin Raghavan & Co.	Shri O.P. Vaish	New Delhi
	Dr. Pritam Singh (upto April, 2009)	Gurgaon
	Shri R. Sekar	New Delhi
	Smt. Renuka Kumar (from May, 2009)	New Delhi

AUDITOR'S REPORT

1. We have audited the attached Balance Sheet of The Institute of Chartered Accountants of India as at 31st March, 2010 and also the annexed Income and Expenditure Account and the Cash Flow Statement for the year ended on that date. The accounts of the Institute's Decentralized Offices, Computer Centers, Regional Councils and their Branches audited by other auditors and that their reports have been incorporated and duly considered while preparing our report. These financial statements are the responsibility of the management of the Institute. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. We conducted the audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. We further report that :-
 - a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
 - b) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;
 - c) In our opinion, proper books of account are maintained in conformity with the requirements of the Chartered Accountants Act, 1949;
 - d) In our opinion the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Cash Flow Statement comply with relevant Accounting Standards;
 - e) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the statements together with the schedules attached and read with the Accounting Policies and Notes Forming Part of Accounts give a true and fair view in conformity with the Accounting Principles generally accepted in India:
 - i) In the case of Balance Sheet, of the state of the Institute's affairs, as at 31st March, 2010;
 - ii) In the case of Income & Expenditure Account, of the surplus for the year ended on that date; and
 - iii) In the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.


CA. PUSHPENDRA SURANA
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER-504087


CA. PRAMOD JAIN
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER-90358

Place : New Delhi

Date : 25/9/10

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2010

		Amount As At 31/03/2010	Rs. in Lacs Amount As At 31/03/2009
SOURCES OF FUNDS:			
Reserves and Surplus	I	35602.89	24896.60
Earmarked Funds	II	11369.16	9152.98
TOTAL		46972.05	34049.58
APPLICATION OF FUNDS:			
Fixed Assets:			
Gross Block	III	21162.34	15747.23
Less: Depreciation and Amortisation		6550.88	5275.28
Net Block		14611.46	10471.95
Capital Work in Progress (including capital advances)		8698.73	4324.02
Investments:			
Earmarked Fund Investments	IV	11369.16	9152.98
Employee Benefit Investments		2283.48	2206.13
Other Investments		16979.60	10290.74
Current Assets, Loans & Advances :		30632.24	21649.85
Inventories	V	701.72	679.84
Cash & Bank Balances	VI	6149.25	4072.47
Loans & Advances	VII	2147.08	2507.16
Interest Accrued on Investments		2463.36	2719.41
Sub - Total		11461.41	9978.88
Less: Current Liabilities & Provisions			
Current Liabilities	VIII	16252.24	10102.19
Provision for Employee Benefits		2179.55	2272.93
Sub - Total		18431.79	12375.12
Net Current Assets (Liabilities)		(6970.38)	(2396.24)
TOTAL		46972.05	34049.58
Statement of significant accounting policies XII			
Notes forming part of Accounts. XIII			
Schedules referred to above form an Integral Part of the Balance Sheet.			

CA. H. GHOSH
SR. DEPUTY DIRECTOR

SH. T. KARTHIKEYAN
SECRETARY

CA. G. RAMASWAMY
VICE PRESIDENT

CA. ANARJIT CHOPRA
PRESIDENT

As per our Report of even date attached

CA. PRAMOD JAIN
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER- 90358

CA. PUSHPENDRA SURANA
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER - 504087

Place : New Delhi

Date: 25/9/10

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2010**

		Amount Year ended 31/03/2010	Rs. in Lacs Amount Year ended 31/03/2009
Schedule			
INCOME			
Fees	IX	31643.56	20770.19
Seminars		3821.95	2454.68
Other Income	X	2526.24	2324.97
Prior Period Income		53.67	25.16
TOTAL		38045.42	25575.00
EXPENDITURE			
Salaries & Allowances		6258.58	3490.27
Printing & Stationery		4332.60	3033.06
Seminars		3382.87	2528.17
Other Operating Expenses	XI	10443.21	7350.67
Depreciation and Amortisation		1322.61	1057.91
Prior Period Expenses		71.80	59.87
TOTAL		25811.67	17519.95
NET SURPLUS		12233.75	8055.05
Appropriation to Funds / Reserves :			
Education Fund [Policy No. III (c)]	XII	4077.76	2711.67
Employees Benevolent Fund [Policy No. III (d)]	XII	22.86	21.69
General Reserve		8133.13	5321.69
TOTAL		12233.75	8055.05

Statement of significant accounting policies

XII

Notes forming part of Accounts.

XIII

Schedules referred to above form an Integral Part of the Income and Expenditure Account

CA. H. GHOSH
SR. DEPUTY DIRECTOR

Sh. T. KARTHIKEYAN
SECRETARY

CA. G. RAMASWAMY
VICE PRESIDENT

CA. AMARJIT CHOPRA
PRESIDENT

As per our Report of even date attached

CA. PRAMOD JAIN
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER- 90358

CA. PUSHPENDRA SURANA
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER - 504087

Place: New Delhi

Date : 2/4/10

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
CASH FLOW STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2010

	(Amount Rupees in Lacs)	
	2009-10	2008-09
A.Cash flows from operating activities		
Net Surplus	12233.75	8055.04
Adjustments for:		
Depreciation and Amortisation	1322.61	1057.91
Interest on investments	(1203.80)	(1216.82)
	118.81	(158.91)
Operating surplus before working capital changes	12352.56	7896.13
(Increase)/Decrease in Inventories	(21.88)	38.68
(Increase)/Decrease in Loans & advances	360.08	(859.58)
Increase/(Decrease) in Current Liabilities	6150.06	2680.17
Increase/(Decrease) in Provision of Employee Benefits	(93.38)	557.82
	6394.88	2417.09
Net cash from operating activities	18747.44	10313.22
B.Cash flows from investing activities		
Acquisition of Fixed Assets including Capital Work in Progress (Net)	(9836.84)	(5867.70)
Acquisition of Investments (Net)	(8982.40)	(3727.02)
Interest on investments	1513.53	1159.21
Capital Receipts	241.77	424.16
Net Cash from Investing Activities	(17063.94)	(8031.35)
C.Cash flows from financing activities		
Admission Fees from new members	117.14	103.49
Contribution from members	276.14	299.98
	393.28	403.47
Net Increase/Decrease in cash and cash equivalents	2076.78	2685.34
Cash and Cash equivalents at the beginning of the year	4072.47	1387.13
Cash and Cash equivalents at the end of the year-Refer Schedule No-VI	6149.25	4072.47

Note:

1.The above Cash Flow Statement has been derived using the Indirect method prescribed in AS-3 issued by the ICAI.

2.Enclosed Schedules I to XIII form an Integral Part of the Cashflow Statement

CA. H. GHOSH
SR. DEPUTY DIRECTOR

Sh. T. KARTHIKEYAN
SECRETARY

CA. G. RAMASWAMY
VICE PRESIDENT

CA. AMARJIT CHOPRA
PRESIDENT

As per our Report of even date attached

CA. PRAMOD JAIN
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER - 90358

CA. PUSHPENDRA SURANA
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER - 504087

Place: New Delhi

Date : 23/9/10

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE I

RESERVES AND SURPLUS

Rs. in Lacs

	EDUCATION		INFRASTRUCTURE		GENERAL		OTHERS *		TOTAL	
	Amount As At		Amount As At		Amount As At		Amount As At		Amount As At	
	31/03/2010	31/03/2009	31/03/2010	31/03/2009	31/03/2010	31/03/2009	31/03/2010	31/03/2009	31/03/2010	31/03/2009
Opening Balance	8,084.49	6,353.52	2,161.11	1,663.84	14,416.91	9,435.47	254.09	197.79	24,898.60	17,650.62
Appropriation from Income & Expenditure A/C	-	-	-	-	8,133.13	5,321.68	-	-	8,133.13	5,321.68
Transfer from/(to) General Reserve, Infrastructure Reserve and Other Reserves	-	-	50.00	83.91	(108.03)	(147.37)	58.03	63.46	-	-
Transfers from/(to) Earmarked Funds	2,707.56	1,710.97	-	9.89	(507.86)	(192.87)	27.02	(13.92)	2,226.72	1,514.07
Admission Fees & allocated Entrance Fees	-	-	117.14	103.49	-	-	-	-	117.14	103.49
Donation received for Buildings	-	-	276.14	299.98	-	-	-	-	276.14	299.98
Net (Depletion)/Addition	-	-	41.36	-	(144.40)	-	56.20	6.76	(46.84)	6.76
Total	10,772.05	8,064.49	2,845.75	2,161.11	21,789.75	14,416.91	395.34	254.09	35,602.89	24,898.60

*Note: Other Reserves are Reserves such as Library Reserves and Class Room Training Reserves as appearing in the books of Regional Councils and Branches.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE II
EARMARKED FUNDS

	Opening Balances		Appropriation from Income & Expenditure Account		Transfer from/(to) Reserves and Surplus		Contribution received/Addition during the year		Income during the year		Payments during the year		Total
	Amount As At		Amount As At		Amount As At		Amount As At		Amount As At		Amount As At		
	01.04.2009	01.04.2008	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	
RESEARCH FUNDS	1,140.44	981.31	-	-	-	-	-	61.23	93.29	97.90	-	-	1,233.73
ACCOUNTING RESEARCH BUILDING FUND	394.77	358.26	-	-	-	-	-	-	32.88	36.51	-	-	427.85
EDUCATION FUND	6,145.05	4,668.62	4,077.76	2,711.67	(2,707.56)	(1,710.97)	-	-	511.88	475.73	-	-	8,027.13
MEDALS AND PRIZES FUNDS	151.10	137.07	-	-	-	-	0.10	8.13	9.05	9.64	(4.01)	(3.74)	156.24
STUDENTS SCHOLARSHIP FUNDS	73.28	41.91	-	-	-	-	1.45	27.95	6.10	4.27	(2.12)	(0.85)	73.28
EMPLOYEES BENEVOLENT FUND	153.12	120.45	22.86	21.69	-	-	-	-	12.76	12.27	(1.18)	(1.28)	153.12
OTHER FUNDS (REGIONAL COUNCILS AND BRANCHES)	1,095.22	660.77	-	-	480.84	196.90	287.06	320.11	48.38	40.31	(651.36)	(122.87)	1,095.22
TOTAL	9,152.98	6,968.39	4,100.62	2,733.36	(2,226.72)	(1,514.07)	288.61	417.42	712.34	676.63	(658.67)	(128.75)	9,152.98

Rs. in Lacs

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE III

FIXED ASSETS

Ra. in Lacs

ASSETS	G R O S S B L O C K				DEPRECIATION AND AMORTISATION			N E T B L O C K		
	Cost as at 1.4.2009	Additions during the year	Adjustments /Transfers / Sale	Cost as at 31.3.2010	Upto 1.4.2009	For the year	Adjustments Transfers/ /Sale	Upto 31.3.2010	W.D.V. as on 31.3.2010	W.D.V. as on 31.3.2009
A.Tangible Assets:										
1.Land - Free Hold	1,318.38	1,449.48	-	2,767.86	-	-	-	-	2,767.86	1,318.38
2.Land -Lease Hold	3,252.31	7.44	-	3,259.75	179.03	40.23	-	219.26	3,040.49	3,073.28
3.Buildings	3,883.02	1,256.71	(20.66)	5,119.07	791.35	169.21	(7.39)	953.17	4,165.90	3,091.67
4.Electric Installations & Fittings	516.46	533.67	(6.18)	1,043.95	179.35	59.00	(1.43)	236.92	807.03	337.11
5.Computers	2,760.05	523.71	(41.03)	3,242.73	2,001.51	609.11	(25.48)	2,585.14	657.59	758.54
6.Air Conditioners	543.05	217.90	(3.24)	757.71	255.69	64.52	(0.35)	319.86	437.85	287.36
7.Furniture & Fixtures	1,404.94	631.99	(12.02)	2,024.91	465.07	117.80	(4.23)	578.64	1,446.27	939.87
8.Lifts	113.42	121.85	-	235.27	55.67	12.45	0.24	68.36	166.91	57.75
9.Office Equipments	848.89	702.37	(59.43)	1,491.83	328.56	126.60	(2.18)	452.98	1,038.85	520.33
10.Vehicles	66.89	0.28	-	67.17	32.30	6.97	0.06	39.33	27.84	34.59
11.Library Books	501.54	69.04	(2.86)	567.72	501.54	72.43	(6.25)	567.72	-	-
B.Intangible Asset:										
Software	538.28	46.09	-	584.37	485.21	44.29	-	529.50	54.87	53.07
TOTAL	15,747.23	5,560.53	(145.42)	21,162.34	5,275.28	1,322.61	(47.01)	6,550.88	14,611.46	10,471.95
Previous Year Figures	12,325.29	3,497.69	(75.75)	15,747.23	4,247.17	1,057.91	(29.80)	5,275.28	10,471.95	8,078.12

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE IV

INVESTMENTS

	Amount As At 31/03/2010	Rs. in Lacs Amount As At 31/03/2009
<u>A. LONG TERM INVESTMENTS (AT COST)</u>		
<u>Bonds</u>		
(I) Government of India-8% (taxable) Bonds-2003	3650.00	4750.00
<u>Others</u>		
(II) Fixed Deposits with Scheduled Banks	5400.00	3800.00
<u>B. OTHER INVESTMENTS</u>		
Short term deposits with scheduled banks (having duration upto one year)	21582.24	13099.85
Total Investments	30632.24	21649.85
ALLOCATED TO:-		
Earmarked Fund Investments	11369.16	9152.98
Employee Benefit Investments	2283.48	2206.13
Other Investments	16979.60	10290.74
Total	30632.24	21649.85

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE V

INVENTORIES

	Amount As At 31/03/2010	Rs. in Lacs Amount As At 31/03/2009
Publications and Study Materials	645.04	647.99
Consumables Stores	56.68	31.85
Total	<u>701.72</u>	<u>679.84</u>

SCHEDULE VI

CASH AND BANK BALANCES

	Amount As At 31/03/2010	Rs. in Lacs Amount As At 31/03/2009
Cash in Hand	13.13	25.38
Cash at Bank	6136.12	4047.09
Total	<u>6149.25</u>	<u>4072.47</u>

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE VII

LOANS & ADVANCES (Considered Good)

	Amount As At 31/03/2010	Rs. in Lacs Amount As At 31/03/2009
Loans and Advances-Staff	377.30	612.76
Interest Recoverable from Staff Loans	116.83	111.25
Security Deposits	110.26	340.65
Accounts Receivables	1133.22	605.27
Other - Advances & Pre-payments	409.47	837.23
Total	2147.08	2507.16

SCHEDULE VIII

CURRENT LIABILITIES

	Amount As At 31/03/2010	Rs. in Lacs Amount As At 31/03/2009
Fees Received in Advance		
Examination Fees	2044.98	701.81
Journal Subscription	29.24	50.39
Membership Fee	669.49	513.78
Education Fee	6338.36	5013.33
Post Qualification Courses (PQC)	114.50	110.15
Certificate Courses	11.75	17.50
Seminar Fees & Other Collections	956.18	730.02
Creditors for Expenses	5,097.37	2,180.97
Other Liabilities	990.37	784.24
Total	16252.24	10102.19

3783 G.I/10-30

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE IX

FEES	Amount	Rs. in Lacs
	Year ended 31/03/2010	Year ended 31/03/2009
Education	20933.31	13747.17
Examination	6269.88	2942.93
Membership	3126.23	3001.48
Students' Registration	181.23	270.88
Entrance	34.59	28.52
Students' Association	126.74	250.89
Post Qualification Courses (PQC)	219.24	176.11
Certificate Courses	752.34	352.21
Total	31643.56	20770.19

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE X

OTHER INCOME

	Amount	Rs. in Lacs
	Year ended 31/03/2010	Year ended 31/03/2009
Publications	750.99	533.14
Interest on Investments	1,203.80	1,216.82
Students' Newsletter	1.59	10.51
Journal -- Subscription	143.43	151.30
News Letters (Regional Councils and Branches)	51.20	68.32
Campus Interview (Net of Direct Expenses)	160.82	147.19
Expert Advisory Fee	11.99	12.65
Interest on Staff Loans	15.75	15.84
Provisions no longer required written back	0.90	2.23
Others	185.77	166.97

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE XI

OTHER OPERATING EXPENSES

	Amount Year ended 31/03/2010	Rs. in Lacs Amount Year ended 31/03/2009
Postage ,Telephone & Telegrams	1,221.43	955.34
Rent, Rates & Taxes	864.25	643.24
Traveling & Conveyance-Inland	1,069.43	958.77
Overseas Relations:		
-Traveling	129.19	104.20
-Membership Fee of Foreign Professional Bodies	60.14	57.36
-Other Expenses	23.66	4.72
Repairs & Maintenance	651.96	547.61
Publications	342.48	243.80
Fees & Expenses to Examiners,Consultants and Others	3169.80	1816.69
Class Room Training Expenses	1792.96	1185.35
Advertisements and Publicity	275.66	364.57
Office Meeting Expenses	76.91	90.57
Merit Scholarship	37.98	21.42
<u>Audit Fee</u>		
- Head Office	4.14	3.31
- Other Offices	11.76	10.98
Other Expenses	711.46	342.74
Total	10443.21	7350.67

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**SCHEDULE XII****STATEMENT ON SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES.****I ACCOUNTING CONVENTION**

These accounts are drawn up on historical cost basis and have been prepared in accordance with the applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and are on accrual basis unless otherwise stated.

II REVENUE RECOGNITION**a. Membership Fee:-**

- (i) The Entrance Fee is collected at the time of admission of a person as a member and one third thereof is recognized as income in that year.
- (ii) Annual Membership and Certificate of Practice Fee(s) are recognized in the year as and when these become due.

- b. Distant Education and Post Qualification Course Fee are recognized over the duration of the course.
- c. Examination Fee is recognized on the basis of conduct of examination.
- d. Subscription for Journal is recognized in the year as and when it becomes due.
- e. Revenue from Sale of Publication is recognized at the time of preparing the sale bill i.e. when the property in goods as well as the significant risks and rewards of the property get transferred to the buyer.
- f. Income on Interest bearing securities and fixed deposits is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.

III ALLOCATIONS/TRANSFER TO RESERVES & SURPLUS AND EARMARKED FUNDS

- a. Admission Fee from Fellow Members and 2/3rd portion of the Entrance Fee from persons admitted as Members are taken to Infrastructure Reserve.
- b. Donations received during the year for buildings and for Research purpose are accounted for directly under the respective Reserves Account.
- c. 25% of the Distant Education Fee not exceeding 50% of the net surplus of the year is transferred to Education fund.
- d. 0.75% of Membership Fee (Annual and Certificate of Practice Fee) received from the members during the year is allocated to the Employees' Benevolent Fund.

- e. Transfer to Education Reserve from the following earmarked funds:-
- | | |
|---|--|
| i. From Accounting Research Building Fund | 100% of the cost of additions (net of deductions) to Building relating to Accounting Research Building Fund. |
| ii. From Education Fund | 50% of the cost of additions (net of deductions) to other Fixed Assets. |
- f. Income from investments of Earmarked Funds is allocated directly to Earmarked Funds on opening balances of the respective Earmarked Funds on the basis of Weighted Average Method.

IV **FIXED ASSETS/DEPRECIATION AND AMORTISATION**

- a. Fixed Assets excluding land are stated at historical cost less depreciation.
- b. Free hold land is stated at cost. Leasehold land is stated at the amount of premium paid for acquiring the lease rights. The premium so paid is amortized over the period of the lease.
- c. Depreciation is provided on the written down value method at the following rates as approved by the Council, based on the useful life of the respective assets :
- | | |
|---|-----|
| Buildings | 5% |
| Air conditioners & Office Equipments | 15% |
| Lifts , Electrical Installations & Furniture & Fixtures | 10% |
| Vehicles | 20% |
| Computers | 30% |
- d. Depreciation on additions is provided on monthly pro-rata basis.
- e. Library Books are depreciated at the rate of 100% in the year of purchase.
- f. Intangible Assets (Software) are amortized equally over a period of three years.

V **INVESTMENTS**

- a. Long term Investments are carried at cost and diminution in value, other than temporary is provided for.
- b. Current investments are carried at lower of cost or fair value.

VI **INVENTORIES**

Inventories of paper, consumables, publications and study material are valued at lower of cost or net realizable value. The cost is determined on FIFO Method.

VII **FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS**

- a. Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount at the exchange rate prevailing on the date of transaction.
- b. All incomes and expenses are translated at average rate. All monetary assets/liabilities are translated at the year end rates where as non-monetary assets are carried at the rate on the date of transaction.

- c. Any income or expense on account of exchange rate difference is recognized in the Income and Expenditure Account.

VIII EMPLOYEE BENEFITS

- a. Short term employee benefits are charged off in the year in which the related service is rendered.
- b. Post employment and other long term employee benefits are charged off in the year in which the employee has rendered services. The amount charged off is recognized at the present value of the amounts payable determined on the basis of actuarial valuation. The Actuarial valuation is done as per Projected Unit Credit Method. Actuarial gain and losses in respect of post employment and other long term benefits are charged to Income & Expenditure Account and are not deferred.
- c. Retirement benefits in the form of Provident Fund are a defined contribution scheme and the contribution to the Provident Fund Trust is charged to the Income and Expenditure Account for the period when the contribution to the respective fund is due.

IX IMPAIRMENT OF ASSETS

- a. The carrying amounts of assets are reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal / external factors. An impairment loss is recognized wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is higher of asset's net selling price and value in use. In assessing the value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value at the weighted cost of capital.
- b. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying amount of the assets over its remaining useful life.

X PROVISIONS

A provision is recognized when an enterprise has a present obligation as a result of past events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimates required to settle the obligations at the Balance Sheet date. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current best estimates.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE XIII

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

1. CONTINGENT LIABILITIES

1.1 Claims against the Institute not acknowledged as debt:

	(Rs. In Lakhs)	
	2009-10	2008-09
i) Demand u/s 156 of the Income Tax Act, 1961		
- For the Assessment Year 2006-07	1497/-	1497/-
- For the Assessment Year 2007-08	1578/-	-
ii) Suit filed by the living Media India Ltd. and remained pending before the Honorable Delhi High Court	287/-	287/-

2. OTHER NOTES

- 2.1 Income tax demand amounting to Rs.3074.95 Lakhs pertaining to Assessment Year 2006-07 & 2007-08 has been raised, which is disputed before CIT (Appeals). The Institute has deposited Rs 300.54 Lakhs (including Rs.26.54 Lakhs as adjustment of refund against the said demand). The balance demand has been stayed by Director of Income Tax (Exemptions). The Institute has also filed Writ before Honorable Delhi High Court for cancellation of Assessment Orders for A.Y 2006-07 & 2007-08 and for restoring Exemption u/s 10(23C)(iv) of the Income Tax Act, 1961 which has been rejected by DGIT(Exemption). The Institute is registered as Charitable Trust u/s 12A of the Act and its Income is otherwise also exempted u/s 11 of the Income Tax Act, 1961. The Institute expects that the Appellate Authorities will grant appropriate relief and hence, no provision has been made for disputed liability.
- 2.2 Pending settlement with a section of employees of the Institute, an estimated amount of Rs. 2262 Lakhs (being arrears up to 31st March, 2009) has been provided for pay revisions and the advance amount of Rs. 507 Lakhs paid earlier to that effect has also been shown under the head salary and allowances.
- 2.3 A sum of Rs. 250 per student, registered with effect from 1st April, 2009, being portion of student's association fee, is remitted to Chartered Accountants Students Benevolent Fund.
- 2.4 There is an estimated amount of capital commitments (net of advances) Rs. 3943.50 Lakhs (Previous Year Rs. 7136.32 Lakhs).
- 2.5 Leasehold land includes Rs. 6.17 Lakhs relating to the land in I. P. Estate, Delhi adjacent to existing H.O. plot, allotted by Land and Development Authority, for which Memorandum of Agreement and Lease Deed execution is in progress.

- 2.6 The disclosures required under Accounting Standards -15 (Revised) on "Employee Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India are given below:-

Defined Contribution Plan

Contribution to defined contribution plan, recognized i.e. Employer's Contribution to Provident Fund is charged off for the year.

Defined Benefit Plan

The Employees Gratuity Fund Scheme managed by the Life Insurance Corporation of India is a defined Benefit Plan. The Present Value of Obligation is determined on Actuarial Valuation using the Projected Unit Credit Method to build up the final obligation. The obligation for Leave Encashment and Pension is also recognized on the same basis as Gratuity.

Status of Defined Benefit Plan

Status of the defined benefit plan as required by Revised Accounting Standards -15 is as follows:

Rs. in Lakhs

	Gratuity		Leave Encashment		Pension	
	(Funded)		(Un-Funded)		(Un-Funded)	
	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
Reconciliation of opening and closing balances of Defined Benefit obligation						
Defined Benefit obligation at beginning of the year	742.15	643.03	936.14	704.13	1224.76	851.81
Current Service Cost	75.89	70.45	162.23	165.07		
Interest Cost	59.89	47.07	75.12	50.64	100.94	63.83
Actuarial (gain)/loss	(73.52)	12.19	(82.91)	74.28	(159.44)	310.54
Benefits paid	(32.48)	(30.6)	(51.31)	(57.98)	(2.60)	(1.42)
Defined Benefits obligation at year end	771.82	742.15	1039.26	936.14	1163.65	1224.76
Reconciliation of opening and closing balances of fair value of plan assets						
Fair value of plan assets at beginning of the year	675.35	559.49	-	-	-	-
Expected return on plan assets	68.87	54.93	-	-	-	-
Actuarial gain/(loss)	1.22	(1.39)	-	-	-	-
Employer contribution	160.99	95.25	-	-	-	-
Benefits paid	(30.70)	(32.93)	-	-	-	-
Fair value of plan assets at year end	875.73	675.35	-	-	-	-
Reconciliation of fair value of assets and obligations						
Fair value of plan assets as at 31 st March, 2010	875.73	675.35	-	-	-	-
Present value of obligation as at 31 st March, 2010-Long Term	771.82	742.15	1039.26	936.14	1163.65	1224.76
Present value of obligation as at 31 st March, 2010-Short Term	-	-	80.57	45.23	-	-
Amount recognized in Balance Sheet as at 31 st March, 2009	(103.90)	66.8	1119.83	981.37	1163.65	1224.76
Expenses recognized during the year						
Current Service Cost	75.79	70.45	162.22	165.07	-	-
Interest Cost	59.89	47.08	75.12	50.63	100.94	63.83

Expected return on plan assets	(68.87)	(54.93)	-	-	-	-
Actuarial (gain)/loss	(74.74)	13.59	(82.91)	74.28	(159.44)	310.54
Short term liability	-	-	80.57	45.22	-	-
Net Cost	(7.93)	76.19	235.00	335.21	(58.50)	374.37
Actuarial assumptions						
Mortality Table	LIC 1994-96 Ultimate	LIC 1994-96 Ultimate	LIC 1994-96 Ultimate	LIC 1994-96 Ultimate	LIC 1994-96 Ultimate	LIC 1994-96 Ultimate
Attrition Rate	05.00% p.a.	05.00% p.a.	05.00% p.a.	05.00% p.a.	05.00% p.a.	05.00% p.a.
Imputed Rate of Interest	08.25 % p.a.	07.50 % p.a.	08.25 % p.a.	07.50 % p.a.	08.25 % p.a.	07.50 % p.a.
Salary Rise	Basic:03:00 % p.a. & D.A.: 06:00 % p.a.	Basic:03:00 % p.a. & D.A.: 06:00 % p.a.	Basic:03:00 % p.a. & D.A.: 06:00 % p.a.	Basic:03:00 % p.a. & D.A.: 06:00 % p.a.	Basic:03:00 % p.a. & D.A.: 06:00 % p.a.	Basic:03:00 % p.a. & D.A.: 06:00 % p.a.
Return on Plan Assets	09.30 % p.a.	09.30 % p.a.				
Average Remaining Working life	17.94 Years	18.23 Years	17.94 Years	18.23 Years	17.94 Years	18.23 Years
Investment Details						
	100% invested in LIC	100% invested in LIC	1119.83*	981.37*	1163.65*	1224.76*

* Investments are maintained by the Institute.

- 2.7 Campus Interview Income has been shown as net of directly attributable expenses and common expenses have been debited in the respective heads of expenditure.
- 2.8 Only directly attributable expenses on the activities of Publications and Seminars have been charged to these heads of expenditure respectively and indirect expenditure on these activities is charged to functional heads of expenditure.
- 2.9 Prior period Income includes the following:-

	2009-10 Rs. In Lakhs	2008-09 Rs. in Lakhs
Seminar Income	22.78	-----
Others	30.89	25.16
Total	53.67	25.16

Prior period expenses include the following:-

Printing & Stationery	0.82	0.40
Audit Fees	----	0.25
Examination Expenses	7.04	0.96
Repairs & Maintenance	2.05	0.63
Traveling & Conveyance	12.06	6.21
Salary & Allowances	0.51	2.45
Professional Services	6.80	0.17
Others	42.52	48.80
Total	71.80	59.87

- 2.10 The Institute operates predominantly in India and in one segment i.e. furtherance of the profession of Chartered Accountancy.
- 2.11 Previous year figures have been re-grouped and re-classified wherever considered necessary to make it comparable with those of current year.

T. KARTHIKEYAN, Secy.

[ADVT III/4/104/10/Ext.]